Website Link: mib.gov.in

G20 वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH ONE FAMILY ONE FUTURE

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 08 सितम्बर, 2022 को नई दिल्ली में 'कर्तव्य पथ' का उद्घाटन करते हुए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

विषय सूची

1. एक अवलोकन 9
2. नई पहल 13
3. उल्लेखनीय गतिविधियां 23
4. सूचना क्षेत्र 43
5. प्रसारण क्षेत्र 77
6. फ़िल्म क्षेत्र 97
7. अंतरराष्ट्रीय सहयोग 129
8. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 133
9. सेवाओं में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व 135
10. राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग 139
11. महिला कल्याण 141
12. सतर्कता संबंधी मामले 143
13. नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण 147
14. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन 151
15. लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा 155
16. लेखा पैरा 165
17. कैट के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन 167
18. योजना परिव्यय 169
19. मीडिया इकाई-वार बजट 171
20. सांगठनिक ढांचा 175

19 नवंबर, 2022 को पणजी, गोवा में भारत के अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (आईएफएफआई-2022) का 53वां संस्करण

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 25 जून, 2022 को केवड़िया, गुजरात के एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन, 'एफएम 90' में शिरकत करते हुए।

1 एक अवलोकन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जनसंचार के मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्रालय रेडियो, टेलीविज़न, फ़िल्मों, प्रेस तथा प्रिंट प्रकाशनों, विज्ञापनों, नए माध्यमों जिसमें डिजिटल और सोशल मीडिया के साथ-साथ जनसंचार के पारंपरिक तरीकों- नृत्य, नाटक, लोक गायन, कठपुतली शो के ज़रिए जनसामान्य तक जानकारी के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने में प्रभावी भूमिका निभाता है।

मंत्रालय विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा करने और राष्ट्रीय अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल तथा परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन और महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दों की ओर सरकार का ध्यानाकर्षित करता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय निजी प्रसारण क्षेत्र, लोक प्रसारण सेवा (प्रसार भारती), मल्टीमीडिया प्रचार और भारत सरकार के कार्यक्रमों की नीतियों, फ़िल्म प्रसार एवं प्रमाणन तथा प्रिंट और डिजिटल मीडिया के विनियमन से जुड़े नीतिगत मामलों का केंद्र भी है।

मंत्रालय को कार्यात्मक रूप से तीन विभागों- सूचना, प्रसारण और फ़िल्म विभाग में विभाजित किया गया है। मंत्रालय अपनी 7 मीडिया इकाइयों/संबंधित तथा अधीनस्थ कार्यालयों, 02 स्वायत्त निकायों, 03 प्रशिक्षण संस्थाओं और 02 सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से कार्य करता है। मंत्रालय के मुख्य, सचिवालय के प्रमुख सचिव होते हैं। सचिव की सहायता के लिए 01 विशेष सचिव तथा वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए), 01 अतिरिक्त सचिव, 01 वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, 04 संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार होते हैं। इनके अलावा निदेशक/उप सचिव/वरिष्ठ पीपीएस/पीएसओ स्तर पर 22 अधिकारी, अवर सचिव/उप निदेशक/पीपीएस स्तर पर 34 अधिकारी, 69 सहायक निदेशक/अनुभाग अधिकारी/पीएस स्तर के अधिकारी और 290 अराजपत्रित अधिकारी/पदाधिकारी होते हैं।

सूचना विभाग प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों तथा गतिविधियों की प्रस्तुति और व्याख्या, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सरकारी विज्ञापनों की दर तय करने के लिए नीति निर्देशों के निर्धारण और प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 तथा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 को लागू करने का कार्य करता है।

प्रसारण विभाग, मंत्रालय के ज़रिए सरकार की योजनाओं एवं पहलों को जन-सामान्य तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से कार्य करता है। प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण विभाग अधिनियम, 1990 के तहत देख-रेख का कार्य भी करता है।) केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और समय-समय पर जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से निजी उपग्रह चैनलों की सामग्री और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों तथा स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क को भी विनियमित करता है। यह डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटरों को संबंधित कार्यों के लिए लाइसेंस देता है। निजी एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी और ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन को भी नियंत्रित करता है।

फ़िल्म विभाग सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणन, विकास तथा संवर्धन गतिविधियों सहित फ़िल्म उद्योग से संबंधित मुद्दों, वृत्तचित्रों के निर्माण तथा वितरण, फ़िल्मों के संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय फ़िल्मोत्सवों के आयोजन और अच्छी फ़िल्म को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार प्रदान करने संबंधी कार्य करता है।

कार्य आवंटन नियमावली, 1961 में संशोधन के बाद 9 नवंबर, 2020 को जारी की गई अधिसूचना के माध्यम से (i) डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक घटनाक्रमों के प्रकाशकों की सामग्री और (ii) ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों से जुड़े विषयों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी, 2022 को अधिसूचित किया गया था, ताकि डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक घटनाक्रमों के

प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशकों (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के विनियमन के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान किया जा सके। इन नियमों का भाग-III, अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक घटनाक्रमों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता और ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है।

मंत्रालय का संगठनात्मक स्वरूप

मीडिया ईकाई/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय

1. पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
2. लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (सीबीसी)
3. भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक (आरएनआई)
4. प्रकाशन विभाग (डीपीडी)
5. न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू)
6. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)
7. केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)

स्वायत्त संगठन

1. भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई)
2. प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया)

शैक्षणिक संस्थान

1. भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी)
2. भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान, पुणे (एफटीआईआई)
3. सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, कोलकाता (एसआरएफटीआई)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी)
2. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल)

    - मंत्रालय 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेखित 03 मीडिया इकाइयों फ़िल्म प्रमाग, भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार, फ़िल्म समारोह निदेशालय को बन्द करके 31 दिसंबर, 2022 के राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम में समाहित कर दिया गया है।
    - इसी प्रकार 31 दिसंबर, 2022 को 01 स्वायत्त संगठन भारतीय बाल फ़िल्म सोसाइटी को राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम में शामिल कर दिया गया है।

■■■

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने 05 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में धारावाहिक 'स्वराज - भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा' का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 24 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में आज़ादी क्वेस्ट गेम लॉन्च करते हुए।

2 नई पहल

सूचना और प्रसारण मंत्रालय फरवरी, 2022 से **मन की बात** पुस्तिका प्रकाशित कर रहा है। यह पुस्तिका अंग्रेज़ी और हिन्दी में प्रकाशित होती है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के सम्बोधन में किए गए विशेष उल्लेखों के बारे में विवरण के साथ-साथ मंत्रियों तथा विशेषज्ञों के साक्षात्कार, लेख तथा मीडिया में छपी प्रतिक्रियाएं शामिल की जाती हैं। इसका ई-संस्करण, ई-संपर्क के माध्यम से देशभर में लगभग 6 करोड़ नागरिकों को वितरित किया जाता है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा इसकी मीडिया इकाइयों, माईगॉव, पीएम इंडिया की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है। मुद्रित पुस्तिका देश के सभी सांसदों, विधायकों और भारत सरकार के सभी सचिवों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पीआईबी से मान्यता प्राप्त पत्रकारों तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को वितरित की जाती है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने **आज़ादी का अमृत महोत्सव** के तहत विभिन्न अभिनव कार्यक्रम आयोजित किए। देशभर में आयोजित ये समारोह टेलीविज़न, डिजिटल, सोशल मीडिया और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से गतिविधियों/कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के साथ जनभागीदारी की भावना पर केंद्रित थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

- **'स्वराज- भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा'**, 75 एपिसोड का मेगा शो है, जिसका प्रसारण दूरदर्शन नेटवर्क पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर किया जा रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को दर्शाने वाली इस श्रृंखला की शुरुआत 14 अगस्त, 2022 को डीडी नेशनल पर हुई। भव्य निर्माण गुणवत्ता वाली इस कार्यक्रम श्रृंखला को 9 क्षेत्रीय भाषाओं- तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बांग्ला, असमिया और उड़िया में डब किया गया है। इसका श्रव्य संस्करण आकाशवाणी नेटवर्क पर उपलब्ध है।

- भारत की 75 साल की यात्रा और इसकी उपलब्धियों के उत्साह तथा संदेश का जश्न मनाने और विश्व स्तर पर इसकी सॉफ्ट पावर को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिस्कवरी इंडिया के सहयोग से तैयार किया है। **द जर्नी ऑफ इंडिया** छह एपिसोड वाली वृत्तचित्र फ़िल्म श्रृंखला है जो व्यापार, सिनेमा, संरक्षण, विश्वास और खाद्य जैसे विविध विषयों के संदर्भ में भारत को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है। यह श्रृंखला 10 अक्टूबर, 2022 से डिस्कवरी के लीनियर और डिजिटल प्लेटफॉर्म (डिस्कवरी प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित) पर दुनियाभर के 140 से अधिक देशों में अंग्रेजी और कई अन्य विदेशी भाषाओं में प्रसारित हो रही है। इसे 14 अक्टूबर, 2022 से पूरे देश में दूरदर्शन नेटवर्क पर भी प्रसारित किया जा रहा है। यह श्रृंखला अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा दस भारतीय भाषाओं- बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, तमिल तथा तेलुगू (प्रारंभ में), असमिया, गुजराती, मराठी, उड़िया और पंजाबी में उपलब्ध कराई जा रही है।

- दमनकारी ब्रिटिश शासन से मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले गुमनाम नायकों की कहानियों को उजागर करते हुए, भारत के बहादुर बेटों और बेटियों की गाथा को **आज़ादी का सफ़र आकाशवाणी के संग** को एक साल तक 16 अगस्त, 2021 से 15 अगस्त, 2022 तक आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार द्वारा उनके

राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इसे संविधान की आठवीं अनुसूची की 23 भाषाओं और कई अन्य बोलियों में प्रसारित किया गया था। प्रस्तुति को संक्षिप्त और प्रभावी तरीके से विदेश सेवाओं के माध्यम से दारी, पश्तो और फारसी जैसी विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया गया था।

5 मिनट की इस रोमांचक प्रस्तुति में नगालैंड की रानी गाइदिन्ल्यू से लेकर अरुणाचल प्रदेश के मोजे रिब, कर्नाटक की कित्तूर रानी चेन्नम्मा तथा रानी अब्बक्का से लेकर आंध्र प्रदेश के सरदार गौथु लचन्ना, ओडिशा के बाजी राउत और महाराष्ट्र के अच्युत पटवर्धन जैसे कई गुमनाम नायकों को दिखाया गया है। **आज़ादी का सफ़र** में कुल 980 हस्तियों और घटनाओं को शामिल किया गया था। आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाओं को समर्पित अपने 'अपराजिता' कार्यक्रम में गुमनाम महिला योद्धाओं की कई कहानियां भी प्रसारित कीं।

- आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए श्रृंखला **'आज़ादी की अमृत कहानियां'** सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा नेटफ्लिक्स के बीच साझेदारी का प्रतीक है। नेटफ्लिक्स महिला सशक्तीकरण एवं पर्यावरण और संधारणीयता सहित विभिन्न विषयों पर 25 लघु फ़िल्मों का निर्माण करेगा। शॉर्ट फ़िल्म हिन्दी/अंग्रेजी में बनाए जा रहे हैं और गुजराती, मराठी, बांग्ला, तमिल, मलयालम तथा अंग्रेजी में डब किए जा रहे हैं। निर्मित वीडियो सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसकी मीडिया इकाइयों के सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए गए और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया गया है। इस अवसर पर देशभर से महिला चेंजमेकर को दर्शाने वाले 07 वीडियो का पहला सेट जिसमें देशभर की 07 महिला चेंजमेकर शामिल हैं 26.04.2022 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा जारी किया गया था।

नेटफ्लिक्स के सहयोग से बनाई गई दूसरी लघु वीडियो श्रृंखला **'आज़ादी की अमृत कहानियां'** को नवंबर, 2022 में

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल तथा युवा मामलों के मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 26 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में प्रेरक कहानियों को प्रदर्शित करने वाली एक लघु वीडियो श्रृंखला, 'आज़ादी की अमृत कहानियां' के शुभारंभ के अवसर पर। मत्स्य, पशुपालन तथा डेयरी और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित हैं।

53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्मोत्सव के उद्घाटन समारोह में लॉन्च किया गया था। दूसरे संस्करण में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह जैसे बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों पर केंद्रित वीडियो का सेट है।

- फ्रांस में 17 से 28 मई, 2022 तक **कान फ़िल्म महोत्सव के 75वें संस्करण** के साथ आयोजित कान फ़िल्म मार्केट (मार्श डू फ़िल्म) में भारत को पहले आधिकारिक प्रतिष्ठित देश के रूप में चुना गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 17.05.2022 को कान फ़िल्म मार्केट के उद्घाटन समारोह में रेड कार्पेट पर एक साथ चलने वाली ग्यारह हस्तियों के सबसे बड़े भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

- 20 से 28 नवंबर, 2022 तक भारत के गोवा में आयोजित **53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (इफ्फी)** ने आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिह्नित करने के लिए कई नई शुरुआत की, जैसे कि India@100 लघु फ़िल्म बनाने के लिए 75 भावी सृजनात्मक प्रतिभाओं को 53 घंटे की चुनौती और **भारत-फ्रांस संबंधों के 75 साल** पूरे होने पर फ्रांस द्वारा भारत को *'कान्स कंट्री ऑफ ऑनर'* का दर्जा देने की परस्पर क्रिया के रूप में फ्रांस का चयन 'फ़ोकस देश' के तौर पर किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) द्वारा कैंपल फुटबॉल ग्राउंड, पणजी, गोवा में 'स्वतंत्रता आंदोलन और सिनेमा' विषय पर एक मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। आठ दिन की इस प्रदर्शनी में कई मल्टीमीडिया घटकों का उपयोग करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी दर्शाई गई थी।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फ़िल्म प्रभाग ने दक्षिण एशिया में गैर-फ़ीचर फ़िल्मों के लिए सबसे पुराना और सबसे बड़ा महोत्सव- 17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (एमआईएफएफ), 29 मई से 4 जून, 2022 तक फ़िल्म प्रभाग परिसर, मुंबई में आयोजित किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्तमान संस्करण ने India@75 विषय पर सर्वश्रेष्ठ लघु फ़िल्म के लिए एक विशेष पुरस्कार की शुरुआत की गई।

- आकाशवाणी ने 15.08.2022 से **'आज़ाद भारत की बात - आकाशवाणी के साथ'** नामक एक अनूठी पहल की शुरुआत की। 90 सेकेंड की यह श्रृंखला 100.1 एफएम गोल्ड चैनल, प्राइम टाइम समाचार बुलेटिन और सोशल मीडिया सहित आकाशवाणी के सभी प्लेटफार्मों पर प्रसारित की जा रही है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज़ादी के बाद से भारत की यात्रा को प्रदर्शित किया जा रहा है।

- सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 24.08.2022 को जिंगा इंडिया के सहयोग से विकसित ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम्स की एक शृंखला 'आज़ादी क्वेस्ट' का शुभारंभ किया। प्रकाशन विभाग (डीपीडी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और जिंगा इंडिया ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत मोबाइल गेम्स की एक शृंखला विकसित करने के लिए सालभर की इस साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। 'आज़ादी क्वेस्टः मैच 3 पहेली' और 'आज़ादी क्वेस्टः हीरोज ऑफ भारत' नाम के दो गेम भारत में एंड्रॉइड और आईओएस उपकरणों के लिए अंग्रेजी और हिन्दी में लॉन्च किए गए हैं और वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराए गए हैं।

- पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की अनुसंधान इकाई द्वारा **'अमृत यात्रा : आज़ादी से अब तक'** शीर्षक वाले दस्तावेजों की एक श्रृंखला बनाई गई है, जो आज़ादी के बाद से, दशकों तक फैली भारत की यात्रा को दर्शाने के लिए फैक्टशीट के हिस्से के रूप में है। इन फैक्टशीट का उपयोग मीडिया द्वारा सकारात्मक कहानियों को विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है और उनकी सामग्री का उपयोग सोशल मीडिया पर विस्तार के लिए इंफोग्राफिक्स और वीडियो बनाने के लिए किया जाता है। ये दस्तावेज https://pib.gov.in/akam_factsheet.aspx पर उपलब्ध हैं। इकाई द्वारा विषय पर **पॉडकॉस्ट सीरीज़** भी शुरू की है।

- विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. आर. के. रंजन ने गुमनाम मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए 21.09.2022 को लोकटक झील में सीबीसी द्वारा आयोजित **पहली तीन दिवसीय 'फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी'** का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में गुमनाम मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों पर 11 कृतियां प्रदर्शित की गईं।

एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी)

- वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में, चार विषयगत क्षेत्रों पर सिफ़ारिश करने के संदर्भ में **एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) पर कार्यबल** का गठन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में किया गया था। ये क्षेत्र हैं- नीति, उद्योग, शिक्षा और कौशल जिनमें भारत को आज अपनी विशाल क्षमता पहचानना है। इसके अलावा, निर्माण को सहयोग करने का बड़ा उद्देश्य, भारत के लिए एवीजीसी क्षेत्र को **'क्रिएट इन इंडिया'** और **'ब्रांड इंडिया'** का पथ-प्रदर्शक बनाना है। भारत में वर्ष 2025 तक वैश्विक बाज़ार की हिस्सेदारी में कम से कम 5 प्रतिशत (40 बिलियन डॉलर) पर कब्जा करने और लगभग 25-30 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि और सालाना 1,60,000 से अधिक नए रोज़गार सृजित करने की क्षमता है। एवीजीसी कार्यबल की रिपोर्ट 26 दिसंबर, 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने जारी की थी।

कार्यबल की ***प्रमुख सिफ़ारिशों*** में निम्नलिखित शामिल हैंः

क. क्षेत्र के एकीकृत संवर्धन और विकास के लिए बजट परिव्यय के साथ ***एक राष्ट्रीय एवीजीसी-एक्सआर मिशन***।

ख. **'क्रिएट इन इंडिया अभियान'** भारत में, भारत के लिए, विश्व के लिए।

ग. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत **5 क्षेत्रीय सीओई के साथ एक अंतर-मंत्रालयी राष्ट्रीय सीओई की स्थापना।**

घ. **एवीजीसी केंद्रित यूजी तथा पीजी डिग्री पाठ्यक्रम** और एवीजीसी के लिए मानक कौशल पहल।

ङ. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स के लिए सब्सक्रिप्शन-आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल को बढ़ावा देकर **एवीजीसी तकनीकों का लोकतंत्रीकरण**।

च. एवीजीसी हार्डवेयर निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए **पीएलआई योजना**।

छ. **एवीजीसी क्षेत्र में उन्नत ईओडीबी** अर्थात कर लाभ, आयात शुल्क और चोरी पर अंकुश लगाना।

ज. भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए **स्थानीय बाल चैनलों को बढ़ावा देना**।

झ. टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में युवाओं के लिए **लक्षित कौशल और उद्योग पहुंच**।

ञ. प्रसारकों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली **स्वदेशी सामग्री के लिए आरक्षण**।

त. समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न **सरकारी प्रोत्साहनों के**

माध्यम से समावेशिता और हैंडहोल्डिंग।

कार्यबल, एवीजीसी क्षेत्र के लिए संभावित कार्यान्वयन के लिए **राष्ट्रीय नीति का मसौदा** और राज्य स्तर पर एवीजीसी क्षेत्र की पहल के लिए **आदर्श सरकारी नीति का मसौदा** तैयार कर रहा है।

फ़िल्में

- **राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के साथ फ़िल्म मीडिया इकाइयों का विलयः** सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 30.03.2022 को तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से फ़िल्म प्रभाग, फ़िल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार और बाल चित्र समिति, भारत के वृत्तचित्रों और लघु फ़िल्मों का निर्माण, फ़िल्म समारोहों का आयोजन और फ़िल्मों के संरक्षण आदि का अधिकार मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को हस्तांतरित कर दिया। इन इकाइयों के पास उपलब्ध संपत्तियों का स्वामित्व भारत सरकार के पास रहेगा। एनएफडीसी में वृत्तचित्रों के निर्माण के लिए 'फ़िल्म प्रभाग' के ब्रांड नाम का प्रोडक्शन, वर्टिकल रूप में बनाए रखा जाएगा। भारत सरकार ने इन सभी गतिविधियों के लिए, 2026 तक 1304.52 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया है, जो एनएफडीसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी।

- सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 19 मई, 2022 को फेस्टिवल डे कान में बांग्ला देश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉ. हसन महमूद के साथ भारत और बांग्ला देश द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित **'मुजीब - द मेकिंग ऑफ नेशन'** संयुक्त प्रोडक्शन फ़िल्म का ट्रेलर जारी किया। यह फ़िल्म भारत गणराज्य और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्ला देश के बीच श्रव्य-दृश्य सह निर्माण समझौते के तहत बनाई जा रही है और इसके मार्च 2023 तक पूरा होने की आशा है।

- सूचना और प्रसारण मंत्री ने 05.05.2022 को पुणे में भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान (एफटीआईआई) तथा भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) की समीक्षा की और घोषणा की कि राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) के तहत लगभग 2,200 फ़िल्मों के पुनर्निर्माण के लिए **दुनिया की सबसे बड़ी फ़िल्म पुनर्निर्माण परियोजना** के लिए मंत्रालय द्वारा 363 करोड़ रुपये का बजट दिया गया।

दिशानिर्देश

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 09.11.2022 को **'भारत में टेलीविज़न चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश-** 2022 को मंजूरी दे दी। इन दिशानिर्देशों से भारत में पंजीकृत कंपनियों/एलएलपी को टीवी चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग, टेलीपोर्टर/टेलीपोर्ट हब की स्थापना, डिजिटल सैटेलाइट समाचार संग्रहण (डीएसएनजी)/सैटेलाइट समाचार संग्रहण (एसएनजी)/इलेक्ट्रॉनिक समाचार संग्रहण (ईएनजी) प्रणाली, भारतीय समाचार एजेंसियों द्वारा अपलिंकिंग और लाइव इवेंट की अस्थायी अपलिंकिंग के उपयोग के लिए अनुमति जारी करने में आसानी होगी।

संशोधित दिशानिर्देशों के फायदों में अनुमतिधारकों के लिए अनुपालन में आसानी, कारोबार सुगमता, सरलीकरण और युक्तिकरण आदि शामिल हैं।

- केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6(6) के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 30.11.2022 को भारत में **मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) द्वारा प्रस्तावित प्लेटफॉर्म सेवाओं (पीएस) के लिए दिशानिर्देश जारी किए।** ये दिशानिर्देश 'प्लेटफॉर्म सेवाओं' को परिभाषा प्रदान करते हैं और पीएस को चलाने में एमएसओ के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं। अब पीएस चैनल प्रदान करने वाले सभी एमएसओ और ऐसे पीएस चैनल उपलब्ध कराने के इच्छुक लोगों को अपने पीएस चैनल को सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ www.new.broadcastseva.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और 12 महीने की समयावधि के भीतर दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

- कैबिनेट के 28.09.2022 को लिए गए फैसले के अनुसरण में, सरकार ने निजी एफएम चरण-3 नीति दिशानिर्देशों के रूप में संदर्भित, **निजी एजेंसियों (चरण-3) के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार पर नीति दिशानिर्देशों** में संशोधन को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 04.10.2022 को जारी आदेश के तहत, सरकार ने 15 साल की लाइसेंस अवधि के दौरान एक ही प्रबंधन समूह के भीतर एफएम रेडियो अनुमति के पुनर्गठन के लिए 3 साल की विंडो अवधि को हटा दिया है और रेडियो उद्योग की लंबे समय से लंबित चैनल होल्डिंग पर 15 प्रतिशत राष्ट्रीय अधिकतम सीमा को हटाने की मांग को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा एफएम रेडियो नीति में वित्तीय पात्रता मानदंडों के सरलीकरण के साथ, आवेदक कंपनी अब 'ग' और 'घ' श्रेणी के शहरों के लिए पहले के 1.5 करोड़ रुपये के स्थान पर केवल 1 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति के साथ बोली में भाग ले सकती है। ये तीन संशोधन न केवल रोज़गार के नए अवसर पैदा करेंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एफटीए (फ्री टू एयर) रेडियो मीडिया पर संगीत और मनोरंजन देश के दूरस्थ स्थानों में आम आदमी के लिए उपलब्ध हों।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 25.10.2022 को **एवी (ऑडियो-विजुअल) निर्माताओं को केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के पैनल में शामिल करने के लिए बदलते समय के साथ तालमेल बिठाते हुए नए नीतिगत दिशानिर्देशों को मंजूरी** दी। नई नीति का उद्देश्य दृष्टिकोण में ताज़गी के साथ उभरती सृजनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है।

- 30.12.2020 को जारी संशोधित डीटीएच दिशानिर्देशों को आगे बढ़ाते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में **डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाओं के लिए परिचालन दिशानिर्देश** जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश लाइसेंस शुल्क के भुगतान, प्लेटफॉर्म सेवा (पीएस) चैनलों और डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के संबंध में परिचालन ढांचा प्रदान करते हैं और आदेश जारी होने की तारीख यानी 16.09.2022 से प्रभावी हैं।

- मंत्रालय ने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ.975 (ई), दिनांक 1 मार्च, 2021 को निरस्त करके राजपत्र अधिसूचना संख्या 2160 (ई), दिनांक 9 मई, 2022 के अंतर्गत खेल प्रसारण संकेत (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य रूप से साझा करने संबंधी) अधिनियम, 2007 (2007 का 11) और खेल प्रसारण संकेत (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य रूप से साझा करने संबंधी) नियम, 2007 के तहत कुछ खेल स्पर्धाओं को राष्ट्रीय महत्व के खेल के रूप में अधिसूचित किया है।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राजपत्र की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2467 (ई) दिनांक 31 मई, 2022 के तहत प्रधान

अधिसूचना एस.ओ. 2693 (ई) दिनांक 5 सितम्बर, 2013 में संशोधन किए हैं जिनके अनुसार डीडी रेट्रो चैनल को केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स (नियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) के अनुच्छेद 8 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य चैनल अधिसूचित किया है। तदनुसार, सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) जैसे कि एमएसओ/एलसीओ/डीटीएच/एचआईटीएस/आईपीटीवी ऑपरेटरों को अपने संबद्ध प्लेटफॉर्मों पर उपरोक्त चैनलों को चलना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31 मई, 2022 के अंतर्गत दूरदर्शन के 11 क्षेत्रीय चैनलों को भी अनिवार्य चैनल अधिसूचित किया है जिन्हें उन केबल ऑपरेटरों को अनिवार्य रूप से चलाना होगा जिनकी सेवाएं उसी राज्य में सीमित हैं तथा जिससे ये चैनल संबंधित हैं।

- मंत्रालय ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों और अन्य संस्थानों/निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही **प्रसारण और वितरण सेवाओं के संबंध में 21 अक्तूबर, 2022 को परामर्श (एडवाइज़री) जारी किया था।** इस परामर्श के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें या उनसे संबद्ध निकाय अथवा संस्थान प्रसारण या प्रसारण के वितरण कार्य नहीं कर सकते। शिक्षण के उद्देश्य से प्रसारण कार्य में केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें प्रसार भारती के माध्यम से प्रवेश कर सकती हैं और इसके लिए प्रसार भारती और संबद्ध केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के बीच उपयुक्त समझौता आवश्यक है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, राज्य/केंद्रशासित सरकारों के मंत्रालयों तथा अन्य संबद्ध निकायों को भी सभी वर्तमान प्रसारण प्रसार भारती के माध्यम से ही करने होंगे। उपर्युक्त एडवाइज़री भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरण (ट्राई) की 12 नवम्बर, 2008 और 28 दिसम्बर, 2012 तथा 22 जनवरी, 2015 की सिफ़ारिशों की समीक्षा के बाद जारी की गई थी।

प्रशासन

- **अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध** में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/9/2019-स्था.(डी) दिनांक 23.08.2021 के अनुपालन में, **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में ऐसे दावों को निपटाने में अधिक दक्षता और कम समय में,** अधिक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ तरीके से दावों की योग्यता का आकलन करने के लिए विभिन्न विशेषताओं/मापदंडों के आधार पर एक योग्यता बिंदु आधारित प्रणाली तैयार की गई है।
- **प्रसार भारती में कारोबार सुगमता** के तहत पहली बार 15.06.2022 को खरीद नीति जारी की गई। प्रसार भारती खरीद नीति, आकाशवाणी (एआईआर) और दूरदर्शन (डीडी) सहित प्रसार भारती के सभी कार्यक्षेत्रों में, सभी खरीद संस्थाओं के लिए एक निर्देश है कि वे निर्दिष्ट गुणवत्तापूर्ण और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामग्री, सेवाओं और कार्य की खरीद निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से करें।

प्रोग्रामिंग और प्रसारण

- प्रसारण क्षेत्र में कारोबार सुगमता में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, अनुमति, पंजीकरण आदि के लिए प्रसारकों के आवेदनों को तत्काल दाखिल करने और प्रसंस्करण के लिए 01.04.2022 को नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल **लॉन्च** किया। पोर्टल 900 से अधिक सैटेलाइट टीवी चैनलों, 70 से अधिक टेलीपोर्ट ऑपरेटरों, 1,750 से अधिक मल्टी-सर्विस ऑपरेटरों, 350 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस), 380 से अधिक निजी एफएम चैनलों और अन्य को 360 डिग्री समाधान प्रदान करेगा और पारिस्थितिकी-तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा।
- **आकाशवाणी के सभी वाणिज्यिक संचालनों के लिए ब्रॉडकास्ट एयर-टाइम शेड्यूलर (बीएटीएस) का कार्यान्वयनः**

प्रसार भारती के वाणिज्यिक संचालन को सुव्यवस्थित और स्वचालित करने की दृष्टि से, पूरी तरह से एकीकृत ट्रैफिक और बिलिंग एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर/ब्रॉडकास्ट एयर-टाइम शेड्यूलर (बीएटीएस) का उद्घाटन 07.11.2022 को किया गया था।

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 अप्रैल, 2022 को गुजरात के बनासकंठा में बना **बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन** राष्ट्र को समर्पित किया। यह केंद्र ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) ने टर्न-की आधार पर बनाया है। यह सामुदायिक रेडियो केंद्र किसानों को कृषि और पशुपालन के बारे में वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आशा है कि इस सामुदायिक रेडियो केंद्र से 1,700 गांवों के 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। बनास रेडियो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है और इसका सीधा प्रसारण उनकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स पर सुने जा सकते हैं।

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडेय के साथ 03.10.2022 को आकाशवाणी के रंग भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान **वार्षिक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम 'मतदाता जंक्शन'** का शुभारंभ किया। 'मतदाता जंक्शन' आकाशवाणी (एआईआर) के सहयोग से भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा निर्मित 52 एपिसोड की रेडियो श्रृंखला है। 'मतदाता जंक्शन' 15 मिनट का एक संवादात्मक कार्यक्रम है जिसे 23 भाषाओं में आकाशवाणी के नेटवर्क पर 07.10.2022 से प्रत्येक शुक्रवार को प्रसारित किया जा रहा है।

- **न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) द्वारा नई वीडियो श्रृंखला का शुभारंभः** हैशटैग **वीकनामा** और उपलब्धियों/नवाचारों/#एमआईबीईपॉजिटिव का उपयोग करके व्यक्तियों, नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय प्रशासन द्वारा नवाचारों/असाधारण प्रयासों से संबंधित सकारात्मक कहानियों के एक वीडियो कैप्सूल का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार और देश से संबंधित सप्ताह के मुख्य समाचारों और प्रमुख समाचारों का अभिग्रहण करने वाला एक वीडियो खंड न्यू मीडिया विंग द्वारा शुरू किया गया है।

- **क्षेत्रीय प्रसार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) का उपयोग करके वीडियो सामग्री का भाषा अनुकूलनः** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके व्यापक और अधिक प्रभावी आउटरीच प्राप्त करने के लिए, 8 भारतीय भाषाओं- कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, तेलुगू, बांग्ला, मराठी, गुजराती और तमिल में कई वीडियो का अनुवाद किया गया है।

- डीडी न्यूज़ द्वारा समाचार बुलेटिनों में एक नया खंड **'न्यूज़ लेंस'** पेश किया गया है जो दिन की बड़ी ख़बरों पर ध्यान

केंद्रित करता है और तथ्यों की गहराई तक जाता है तथा एक व्याख्यात्मक वीडियो के रूप में समाचारों को प्रस्तुत करता है। स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य, यूएनजीए में भारत की ऐतिहासिक भूमिका, सेमीकंडक्टर्स में भारत की बड़ी छलांग, नासा का डार्ट मिशन आदि जैसे विषयों को इस खंड के माध्यम से कवर किया गया है।

■■■

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 अप्रैल, 2022 को गुजरात में सामुदायिक रेडियो स्टेशन 'बनास रेडियो' का उद्घाटन किया।

3 उल्लेखनीय गतिविधियां

- महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने वर्ष 2020 के लिए 68वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 30 सितंबर, 2022 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन की उपस्थिति में प्रदान किए। इस अवसर पर महान अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। *'टेस्टिमनी ऑफ़ अना'* को सर्वश्रेष्ठ गैर-फ़ीचर फ़िल्म और 'सूराराई पोत्तरू' को सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार श्री सूरिया और श्री अजय देवगन को संयुक्त रूप से दिया गया तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सुश्री अपर्णा बालमुरली को प्रदान किया गया। श्री सच्चिदानंद के. आर. को मलयालम फ़िल्म 'अय्यपनम कोशियुम' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार और 'तान्हाजी : द अनसंग वॉरियर' को भरपूर मनोरंजन करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फ़िल्म का पुरस्कार दिया गया। मध्य प्रदेश ने फ़िल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता और उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश का विशेष उल्लेख किया गया।

- भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने अपनी मिज़ोरम यात्रा के दौरान 03.11.2022 को **आइज़ोल** में **भारतीय जनसंचार संस्थान के स्थायी पूर्वोत्तर परिसर** का

30 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु और केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 68वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह दिल्ली में पुरस्कार वितरण के अवसर पर। इस अवसर पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी उपस्थित रहे।

(वर्चुअल माध्यम) से उद्घाटन किया। यह परिसर छोटी अवधि के मीडिया और संचार पाठ्यक्रमों के साथ ही अंग्रेजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाएगा।

- माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 28 दिसंबर, 2022 को **भारत सरकार का वर्ष 2023 का आधिकारिक कैलेंडर** जारी किया। यह कैलेंडर 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' को परिलक्षित करता है और 'नया वर्ष, नया संकल्प' विषय पर आधारित है जिसमें सशक्त भारत के निर्माण में चुनी हुई सरकारी नीतियों और पहलों की अहम भूमिका दर्शायी गई है। यह कैलेंडर हिन्दी और अंग्रेजी सहित 13 अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं के कैलेंडरों को 2.5 लाख से अधिक पंचायतों तक पहुंचाने में सीबीसी ने भारतीय डाक विभाग का सहयोग लिया है।

- राष्ट्रपति भवन शृंखला के क्रम में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित तीन नई पुस्तकों – (i) मूड्स, मोमेंट्स और मेमोरीज़– भारत के पूर्व राष्ट्रपति (1950-2017)- सचित्र इतिहास, (ii) प्रथम नागरिक– राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के कार्यकाल का सचित्र रिकॉर्ड और (iii) भौगोलिक व्याख्या– राष्ट्रपति भवन की फर्श का 24 जुलाई, 2022 को राष्ट्रपति भवन में विमोचन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित थे।

- भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 23 सितम्बर, 2022 को '**सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास**' पुस्तक का विमोचन किया। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के चुने हुए भाषणों का संग्रह है। प्रकाशन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद खान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।

- भारत के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष के दौरान दिए गए चुनिंदा भाषणों के संग्रह पर आधारित पुस्तक और उसके ई-संस्करण – **'द रिपब्लिकन एथिक'** (संस्करण-IV) और **'लोकतंत्र के स्वर (खंड IV)'** का

केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान तथा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 8 जून, 2022 को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में 'लोकतंत्र के स्वर' और 'द रिपब्लिकन एथिक' नामक पुस्तकों का विमोचन करते हुए।

17 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'स्वराज - भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा' की विशेष स्क्रीनिंग देखी।

विमोचन 8 जून, 2022 को शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इन पुस्तकों की पहली प्रति भारत के तात्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविन्द को दी गई।

➢ प्रकाशन विभाग ने अगस्त, 2022 में अंग्रेजी पुस्तक **इंटरेक्टिंग इनवॉल्विंग इंस्पायरिंग – श्री एम. वेंकैया नायडू, भारत के उप राष्ट्रपति (2017-22)** प्रकाशित कीं।

आज़ादी का अमृत महोत्सव : भारत की आज़ादी के 75 वर्ष

भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 12 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में शुरू किए गए **'आज़ादी का अमृत महोत्सव'** के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय कई प्रमुख गतिविधियां चला रहा है। 'जन भागीदारी और जन आंदोलन' की भावना से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की दिशा में अनेक पहल की गई हैं।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 17 अगस्त, 2022 को संसद भवन के पुस्तकालय में प्रधानमंत्री के लिए **'स्वराज - भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा'** की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की जिसे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, गृह मंत्री श्री अमित शाह और अनेक केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों तथा भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी देखा। **'स्वराज'** की एक और विशेष स्क्रीनिंग 27 सितम्बर, 2022 को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित की गई थी जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और राज्य मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों, सांसदों, विधायकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा।

- केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने फोटो प्रदर्शनियां, समेकित संचार और आउटरिच कार्यक्रम (आईसीओपी), जागरूकता रैलियां, वेबिनार और रेडियो वार्ताएं आयोजित कीं। **'विभाजन की भयावह त्रासदी'** के बारे में सूचना भवन में बड़ी

मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आयोजित की गई थी जिसमें विगत आठ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विकास गतिविधियों को विस्तार से दर्शाया गया था। सीबीसी के प्रादेशिक/क्षेत्रीय अधिकारियों ने इस विषय पर 169 आईसीओपी, **02** प्रदर्शनियां, **11** रैलियां, **02** वेबिनार और 45 क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए।

- प्रकाशन विभाग ने डॉ. कस्तूरी पाईगुडे द्वारा लिखित मराठी पुस्तक '**पंडित भीमसेन जोशी**' का पुणे में 15 अक्तूबर, 2022 को विमोचन किया। यह पुस्तक प्रख्यात गायक भारत रत्न भीमसेन जोशी के जीवन और उपलब्धियों के बारे में है।

- **अमृत यात्रा : आज़ादी से अब तक** : स्वतंत्रता के बाद के दशकों में भारत की यात्रा की जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयासों के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की रिसर्च यूनिट ने '**अमृत यात्रा : आज़ादी से अब तक**' शीर्षक से पूरी शृंखला (सीरीज़) विकसित की है। इन तथ्यों को मीडिया ने रचनात्मक और सार्थक कहानियां तैयार करने और उनके कथानक को सोशल मीडिया पर प्रचारित-प्रसारित करने के उद्देश्य से इंफोग्राफिक्स और वीडियो बनाने में इस्तेमाल किया है। ये दस्तावेज pib.gov.in/akamfactsheet.aspx पर उपलब्ध हैं।

- **अमृत महोत्सव और अमृत काल पर डीडी में कार्यक्रम** : 76वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर '**राष्ट्रपति के** सम्बोधन **की प्रमुख बातें**' शीर्षक से महामहिम राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम सम्बोधन, स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन- '**अमृतकाल के पांच प्रण**' और '**स्वतंत्रता के 75 साल**' तथा गोवा में प्रधानमंत्री के सम्बोधन '**अमृतकाल के तीन पड़ाव**', आगामी 25 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं- '**अमृतकाल : स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताएं**', श्रम क्षेत्र में '**अमृतकाल में श्रमशक्ति**' तथा महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में '**तेज़स्विनी : वीरांगनाएं स्वतंत्रता संग्राम की**' शीर्षकों पर आधारित विशेष कार्यक्रम डीडी न्यूज़ (दूरदर्शन समाचार) से प्रसारित किए गए।

- **हर घर तिरंगा** : '**हर घर तिरंगा**' अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से डीडी न्यूज़ (दूरदर्शन समाचार) ने '**हर घर तिरंगा**' की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष चर्चा और ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम '**आज़ादी का झंडा-हर घर तिरंगा**' का प्रसारण किया।

आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अन्य गतिविधियां

- केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी प्रादेशिक कार्यालय, कोहिमा) ने '**आज़ादी का अमृत महोत्सव**' और '**सेवा, सुशासन और ग़रीब कल्याण के 8 वर्ष**' विषय पर विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में हॉर्नबिल उत्सव, जिसे **उत्सवों का उत्सव** कहा जाता है और जो नगालैंड में 10 दिनों का वार्षिक सांस्कृतिक आयोजन भी है के अवसर पर 10 दिन की मल्टी-मीडिया प्रदर्शनी आयोजित की गई। नगालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो ने 1 दिसम्बर, **2022** को इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

- सीबीसी ने देशभर में वॉट्सएप की इंफोग्राफिक्स शृंखला चलाई। इंफोग्राफिक्स सीरीज़ के माध्यम से 281 विस्मृत नायकों की यादें ताज़ा की गईं और उनके योगदान को याद किया गया।

- 3 दिसम्बर, **2022** को आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन समाचार ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला के वार्षिक संस्करण का प्रसारण किया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर '**अमृतकाल में भारतीयता**' विषय पर व्याख्यान दिया।

- विदेश और शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. आर.के.रंजन ने देश की **पहली, तीन दिनों की 'तैरती' फोटो प्रदर्शनी** का उद्घाटन किया। इसका आयोजन सरकार की आठ वर्ष की उपलब्धियों और मणिपुर के विस्मृत स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, लोगों तक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से सीबीसी ने 21 सितम्बर, **2022** को लोकटक झील में किया था।

- भारतीय सिनेमा के 'राष्ट्रीय संग्रहालय' (एनएमआईसी) को फिर से जनता के लिए खोले जाने के अवसर पर 13 मार्च, **2022** को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत फ़िल्म प्रभाग के एनएमआईसी परिसर में **75 विंटेज कारों** और **मोटरसाइकिलों की** खूबसूरत प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में फ़िल्म कलाकार श्री अक्षय कुमार और सुश्री कृति सेनन भी आए थे। संग्रहालय परिसर में एक सेल्फी प्वाइंट '**लव सिनेमा**' का भी शुभारम्भ किया गया।

- राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के सबसे पहले लोक संपर्क प्रयास के अंतर्गत देश के 22,000 स्कूलों के 8 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 2 करोड़ बच्चों के

केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी पालन राज्यमंत्री, गोवा में 21 नवम्बर, 2022 को 53वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में 'क्रिएटिव मांइड्स ऑफ़ टुमारो' के विजेताओं के साथ।

लिए भारत के 53वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह 2022 में पुरस्कृत फ़िल्म **53-ऑवर फ़िल्ममेकिंग चैलेंज** दिखाई गई जो **75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया** का हिस्सा भी थी।

- 53वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह-2022 के दौरान ही केंद्रीय संचार ब्यूरो, (सीबीसी) ने '**स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय सिनेमा**' के बारे में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आयोजित मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी में अठारह वृत्तचित्रों की स्क्रीनिंग की।

- मध्य प्रदेश सरकार और फ़िल्म समारोह निदेशालय ने मिलकर 5 दिसम्बर, 2022 से 11 दिसम्बर, 2022 तक मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित 8वें खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह 2022 में स्वतंत्रता सेनानियों और उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में सोलह वृत्तचित्र दिखाए।

- भारतीय जनसंचार संस्थान ने फ़िल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 4 मई, 2022 से 6 मई, 2022 तक तीन दिन का 'आईआईएमसी फ़िल्म समारोह 22' और राष्ट्रीय लघु फ़िल्म निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें पद्मभूषण श्रीमती शर्मिला टैगोर तथा अनेक कलाकारों, निर्माताओं, निर्देशकों, पटकथा लेखकों (स्क्रीन राइटर्स), फ़िल्म निर्माताओं और छायाकारों (सिनेमेटोग्राफर्स) ने भी भाग लिया।

- न्यू इंडिया समाचार (एनआईएस) के अगस्त, **2022** के पाक्षिक अंक में आवरण कथा में '**अमृत महोत्सव को जनभागीदारी आंदोलन बनाने और 75 सप्ताहों के दौरान देश-विदेश में 50 हज़ार से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने**' और सितम्बर 2022 के पाक्षिक अंकों में आवरण कथाओं में '**आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के प्रधानमंत्री के आगामी 25 वर्ष तक अमृत यात्रा जारी रखने के विज़न**' और **देश के *'नए भारत'* की अमृत यात्रा की दिशा में बढ़ने के दौरान राष्ट्रीय विकास को बल प्रदान करने वाले 100 निर्णय** 13 भाषाओं में प्रकाशित किए गए और इन्हें केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने देशभर में वितरित किया।

- प्रकाशन विभाग की पत्रिका 'योजना' का अगस्त, 2022 का अंक '**साहित्य और आज़ादी**' विषय पर था और 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' को समर्पित था। इस अंक में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की संहिता के महत्व को समझाने के लिए '**हर घर तिरंगा**' शीर्षक से अलग सेक्शन शामिल किया गया था। बच्चों की पत्रिका 'बाल भारती' का अगस्त, 2022 का अंक भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रति समर्पित था और इसमें, इससे जुड़े विषयों के ही लेख, कहानियां तथा चित्रकथा प्रकाशित की गई थीं।

- सीबीसी ने मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश में **मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी** की एक शृंखला आयोजित की थी जिसमें भारत के स्वाधीनता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की घटनाओं को दर्शाया गया था। हमीरपुर के समीप सुजानपुर में 15 मार्च, **2022** को सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। धर्मशाला, बिलासपुर, हमीरपुर और शिमला में '**भारत की यात्रा : स्वराज से विकास तक**' शीर्षक से प्रदर्शनियां आयोजित की गईं थीं। सीबीसी ने 17

सितम्बर, **2022** को अमृत महोत्सव के तहत रक्तदान का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था।

राष्ट्रीय एकता दिवस

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय और उसकी मीडिया यूनिटों/संगठनों और उनके शाखा/क्षेत्र/सहायक/संबद्ध कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने 31 अक्तूबर, **2022** को **'राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ'** ली और कई कार्यक्रम आयोजित किए।

- सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 31 अक्तूबर, 2022 को 'सक्षम भारत सशक्त भारत' **विषय पर वार्षिक सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान दिया** जिसे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन समाचार से प्रसारित किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात में केवड़िया स्थित **स्टेच्यू ऑफ यूनिटी** के पास आयोजित मुख्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम और **एकता के लिए दौड़** सहित देशभर में हुए सभी आयोजनों का दूरदर्शन समाचार द्वारा व्यापक कवरेज किया गया।

- दूरदर्शन समाचार से विशेष लाइव कार्यक्रम **'राष्ट्रीय एकता दिवस'**, विशेष सेगमेंट **'सरदार वल्लभ भाई पटेल : एकता के प्रणेता'**, विशेष डॉक्यूमेंट्री (लघुचित्र) **'सरदार'**, सरदार पटेल की उक्तियों के विशेष प्रोमो इत्यादि भी दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए गए। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने **'सरदार पटेल-राष्ट्रीय एकता के शिल्पी'** शीर्षक से विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जिसमें इस व्याख्यानमाला के पूर्व संस्करणों के चुने हुए अंश शामिल किए गए थे। फ़िल्म प्रभाग ने अपनी वेबसाइट और यू-ट्यूब चैनल पर 31 अक्तूबर, **2022** को सरदार पटेल की जयंती पर **'आयरन मैन सरदार पटेल'** फ़िल्म की विशेष स्क्रीनिंग की।

- 'एकता दिवस' यानी सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्पलेक्स में स्थित सूचना भवन में **'सरदार पटेल एकीकरण के शिल्पकार'** शीर्षक से प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। केंद्रीय संचार ब्यूरो-सीबीसी के प्रादेशिक और क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई और 'एकता दिवस' विषय पर 24 समेकित संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी), **05** विशेष कार्यक्रम, **01** वेबिनार और 23 क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स से **'राष्ट्रीय एकता दिवस 2022'** आयोजनों का #SardarVallabhbhaiPatel, #NationalUnityDay, #RashtriyaEktaDiwas2022, #RashtriyaEktaDiwas और #Amrit_Mahotsav के माध्यम से सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार किया गया। प्रकाशन विभाग से प्रकाशित एंप्लॉयमेंट न्यूज़ (रोज़गार समाचार) के अक्तूबर, 2022 के अंक में 'Remembering Sardar Patel, Unifier-Administrator of India' शीर्षक लेख भी प्रकाशित किया गया था।

सत्यजित रॉय जन्मशती

सत्यजित रॉय की जन्मशती मनाने के लिए भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय, ने नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और बेंगलुरु में 2 मई से 4 मई, **2022** तक तीन दिनों का फ़िल्मोत्सव, बड़ी स्क्रीन पर आयोजित किया। इसी प्रकार राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम-एनएफडीसी, चेन्नई और राष्ट्रीय फ़िल्म अर्काइव्स, पुणे ने भी सत्यजित रॉय के 3 फ़िल्म समारोह आयोजित किए।

8 साल सेवा, सुशासन और ग़रीब कल्याण

वर्तमान सरकार ने मई, **2022** में अपने कार्यकाल के **8** वर्ष पूरे कर लिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सरकार के **'सेवा, सुशासन और ग़रीब कल्याण'** के आठ वर्ष पूरे होने पर व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर डीडी न्यूज़ कॉन्क्लेव में।

- माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 3 जून, **2022** को सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर दूरदर्शन समाचार कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और सरकार द्वारा विगत 8 वर्षों में चलाई गईं गतिविधियों के बारे में आयोजित उद्घाटन सत्र में भाग लिया। '**आठ साल मोदी सरकार : सपने कितने हुए साकार**' शीर्षक से 3 जून से 11 जून, **2022** के बीच 11 पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं जिनमें कुल 47 वार्ताकारों ने भाग लिया। इन परिचर्चाओं में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ सामाजिक सशक्तीकरण, सबके लिए स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रक्षा उपकरणों का देश में ही निर्माण, आंतरिक सुरक्षा, भारत विश्व गुरू के रूप में आदि विषयों पर सीधी बातचीत हुई।

- केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने 'आठ साल सेवा, सुशासन, ग़रीब कल्याण' विषय पर 30 मई, 2022 को मल्टीमीडिया अभियान का शुभारंभ किया जिसमें भारत सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, रेल विभाग, हवाईअड्डों, डाकघरों इत्यादि के कार्यालयों के साथ सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आउटडोर क्रिएटिव साझा किए गए। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने से जुड़े सीबीसी के मल्टीमीडिया अभियान प्रिंट (समाचार-पत्रों), रेडियो, टेलीविज़न, आउटडोर और न्यू मीडिया पर 14 जून, **2022** तक चलते रहे।

- सीबीसी के प्रादेशिक/क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पॉकेट बुकलेट्स, लॉन्ग बुक और डॉकेट्स छपवाकर देशभर में वितरित किए गए और उनकी ई-बुक तथा फ्लिप बुक MyGov और सरकार की वेबसाइटों के ज़रिए प्रदर्शित की गईं। 'आठ साल सेवा, सुशासन, ग़रीब कल्याण' और 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' सहित विभिन्न विषयों पर पत्र-पत्रिकाओं में 07 विज्ञापन जारी किए गए और यू-ट्यूब के जरिए 20 सेकेंड के वीडियो स्पॉट चलाए गए तथा लोक संचार शाखा ने 370 कार्यक्रम आयोजित किए।

- आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और सरकार के आठ वर्ष पूरे होने पर देशभर के सिनेमागृहों में '**आज़ादी का अमृत महोत्सव का नया दौर**' शीर्षक जन सेवा घोषणा (पीएसए) फ़िल्म प्रदर्शित की गई और सरकार के आठ वर्ष पूरे होने सरकार की प्रमुख योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने हेतु विशेष आयोजन किए गए।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा narendramodi.in और नमो ऐप पर साझा की गई 'आठ वर्ष सेवा, सुशासन और ग़रीब कल्याण के' की मुख्य उपलब्धियों का दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया में लाइव कवरेज किया गया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से स्पॉटलाइट कार्यक्रम और प्रमुख समाचार बुलेटिनों में विशेष समाचार कैप्सूल के जरिए एनडीए सरकार के आठ वर्ष पर विशेष शृंखला प्रसारित की गई।

भारत का 53वां अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने गोवा सरकार की गोवा मनोरंजन सोसाइटी के साथ मिलकर पणजी में 20 नवंबर से 28 नवंबर, **2022** तक भारत के 53वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह का आयोजन किया। समारोह के उद्घाटन और समापन समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत और सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन उपस्थित थे। समापन समारोह में फ़िल्म जगत के जाने-माने कलाकारों- आशा पारेख, अक्षय कुमार, प्रोसेनजित चटर्जी, आयुष्मान खुराना, ईशा गुप्ता, मानुशी छिल्लर और शरमन जोशी को सम्मानित किया गया।

- भारत के 53वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में 282 फ़िल्में प्रदर्शित की गईं जिनकी कुल अवधि 35,000 मिनट की थी और इनमें विश्व के 78 देशों की 65 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं और 15 भारतीय भाषाओं में बनी 183 अंतरराष्ट्रीय और 97 भारतीय फ़िल्में शामिल थीं। समारोह में फ्रांस को 'कंट्री ऑफ़ फ़ोकस' चुना गया क्योंकि **कान** समारोह में फ्रांस ने भारत-फ्रांस मैत्री के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत को '**कंट्री ऑफ़ ऑनर**' का सम्मान दिया था। अभिनेता-निर्माता चिरंजीवी कोनिडेला को 2022 की भारतीय फ़िल्मी हस्ती अवार्ड प्रदान किया गया। स्पेन के निर्देशक कार्लोस सौरा को सत्यजित रॉय लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

- **भारत के 53वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में नई शुरुआतें** : भारत के 53वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में भविष्य

के 75 क्रिएटिव लोगों को **India@100** विषय पर 53 घंटे (निर्धारित) समय में लघुचित्र बनाने की चुनौती जैसी कई नई पहल की गईं। एफटीआईआई और टेक्नोलॉजिकल पार्क द्वारा आयोजित फ़िल्म टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी में सिनेमा जगत के नवीनतम नवाचार और नए आयाम दिखाए गए और इनमें दिव्यांगजन विशेष वर्ग और विशेष अकादमिक सत्र तथा विशेषकर, मणिपुरी सिनेमा के 50 शानदार वर्ष पूरे होने पर पैकेज़ के तहत प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के अनुरूप 42 मंडपों में '**फ़िल्म बाज़ार**' लगाया गया, **20** से ज्यादा मास्टर क्लास फ़िल्में प्रदर्शित की गईं जिनमें से कई फ़िल्में कनाडा के फ़िल्म स्कूलों की भागीदारी में बनाई गई थीं, ओटीटी प्लेयर्स और पहली बार ऑस्कर के लिए मनोनीत फ़िल्में, भारतीय फ़िल्म इतिहास की **पहली फ़ीचर फ़िल्म 'ढबरी कुरुबी' जिसमें केवल स्थानीय समुदायों के सितारे ही लिए गए थे,** का विश्व प्रीमियर आदि विशेष आकर्षण का केंद्र रहे।

- केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने गोवा में पणजी के कैंपल फुटबाल मैदान में '**स्वतंत्रता आंदोलन और सिनेमा**' विषय पर '**मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी**' आयोजित की जिसका उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 21 नवंबर, **2022** को किया। आठ दिन की इस प्रदर्शनी में विभिन्न मल्टीमीडिया माध्यमों से भारत के स्वाधीनता संग्राम की पूरी कहानी दिखाई गई थी।
- **शानदार प्रीमियर** : आईएफएफआई ने पहली बार भारतीय फ़िल्मों, विदेशी फ़िल्मों और ओटीटी प्लेटफार्मों की मूल (ओरिजनल) सीरीज के शानदार प्रीमियर आयोजित किए। इस कार्यक्रम में इन फ़िल्मों के कलाकार समर्थन के लिए गोवा आए थे।
- **'इफ्फी (भारत के अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह) के रंग, सिनेमा**

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर भारत के 53वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (आईएफएफआई) के दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा गोवा में 21 नवंबर, 2022 को 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' विषय पर आयोजित प्रदर्शनी के अवसर पर। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव श्री अपूर्व चन्द्रा भी उपस्थित रहे।

गोवा में 28 नवंबर, 2022 को भारत के 53वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के समापन समारोह में जानी-मानी अभिनेत्री आशा पारेख को सम्मानित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन।

के संग' का इस समारोह के दौरान दूरदर्शन समाचार से प्रतिदिन प्रसारण किया जाता था। पत्र सूचना कार्यालय ने विशेष वेबपेज https://pib.gov.in/newsite/iffi53.aspx डिज़ाइन करके प्रकाशित किया और अपने इन-हाउस ई-न्यूज़लेटर 'IFFILOID' को तैयार करके उसे सोशल मीडिया पर हर दिन साझा किया। पीआईबी ने आईएफएफआई 53 पर 72 वीडियोज की स्पेशल यू-ट्यूब प्लेलिस्ट तैयार की और एनएमडब्ल्यू ने व्यापक प्रसार किया और हैशटैग **#**आईएफएफआई53, **#**आईएफएफआईगोवा, **#**आईएफएफआई2022 के अंतर्गत चित्रों/ग्राफिक्स की श्रृंखला के जरिये व्यापक प्रचार और कवरेज किया। उद्‌घाटन और समापन समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मज़बूत बनाने की दिशा में

भारत के मूल्यों का मूल आधार 'वसुधैव कुटुंबकम्' है और इसकी प्राप्ति के लिए उसने हमेशा अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत बनाने और अपने विदेशी संबंधों को हरदम सर्वोच्च सम्मान देने का प्रयास किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की वैश्विक पहुंच को विस्तार देने, अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत बनाने, विदेशों में भारतीय नागरिकों से बराबर संपर्क बनाए रखने और विश्व को भारत की संस्कृति और मूल्यों से अवगत कराने के लिए अनेक पहल की हैं।

- भारत को 19-21 सितंबर के दौरान नई दिल्ली में, एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) की 47वीं वार्षिक बैठक और 20वां महासम्मेलन आयोजित करने का सम्मान प्राप्त हुआ और इस आयोजन में सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहें। प्रसार भारती के तत्कालीन सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) और एआईबीडी के अध्यक्ष मयंक अग्रवाल को 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। एआईबीडी

ने सर्वसम्मति से भारत की अध्यक्षता की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी।

- भारत ने नई दिल्ली में 25 नवंबर से 30 नवंबर, **2022** तक 59वीं एशिया प्रशांत प्रसारण यूनियन (एबीयू) की महासभा 2022 की मेजबानी की। इस वर्ष की महासभा का विषय 'लोगों की सेवा : संकट काल में मीडिया की भूमिका' था। महासभा का उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया।

- प्रसार भारती ने त्यागराज स्टेडियम में 21 अगस्त, **2022** को **एनबीयू रोबोकॉन 2022** की सफलतापूर्वक मेज़बानी की जिसमें भारत सहित 12 देशों की 13 टीमों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

- सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने नई दिल्ली में 4 अक्टूबर, **2022** को **ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022**-(वैश्विक समाचार मंच 2022) में मुख्य अभिभाषण दिया। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ (एबीयू) के तीन दिन के इस प्रमुख समाचार आयोजन में मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न प्रसारण संगठनों के लगभग 80 विदेशी प्रतिभागी आए थे। वैश्विक समाचार मंच का विषय '**संकट काल में सत्य और विश्वास**' था।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने 16 नवंबर, **2022** को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में प्रथम विश्व मीडिया कांग्रेस को संबोधित किया।

कान फ़िल्म समारोह में भारत की भागीदारी

- फ्रांस में 17 मई से 28 मई, **2022** तक हुए 75वें कान फ़िल्म समारोह के सिलसिले में आयोजित कान फ़िल्म बाज़ार (मार्चे टु फ़िल्म) में भारत को इस समारोह में पहली बार **फर्स्ट ऑफिशियल कंट्री ऑफ़ ऑनर** (पहला सम्मानित देश) चुना गया। भारत को 'कान नेक्स्ट' में भी कंट्री ऑफ़ ऑनर (सम्मानित देश) चुना गया जिसके अंतर्गत 5 नए स्टार्टअप्स को श्रव्य-दृश्य (ऑडियो विजुअल) उद्योग में शामिल करने का अवसर प्रदान किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में 11 जानी-मानी हस्तियों के शिष्टमंडल का 17 मई, **2022** को कान फ़िल्म मार्केट के उद्घाटन समारोह में भव्य स्वागत किया गया।

- 18 मई, 2022 को भारतीय मंडप के उद्घाटन के अवसर पर विदेशी फ़िल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने और भारत के साथ सहयोग से विदेशी फ़िल्मों का निर्माण करने के उद्देश्य से बनाई दो योजनाएं भी प्रस्तुत की गईं; ये योजनाएं थीं- '**श्रव्य दृश्य सह-निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना**' और '**भारत में विदेशी फ़िल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन**' देने की योजना।

- 19 मई, **2022** को सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कान **में पलाइस देस फेस्टिवल्स** में भारतीय फोरम को संबोधित किया और भारत और बांग्लादेश द्वारा मिलकर बनाई गई फ़िल्म 'मुजीब-द मेकिंग ऑफ़ नेशन' के ट्रेलर को बांग्लादेश के सूचना और प्रसार मंत्री डॉ. हसन महमूद के साथ संयुक्त रूप से जारी किया। डॉ. मसूद बंगलादेश के शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे थे।

जी20 शिखर सम्मेलन और भारत की अध्यक्षता

भारत ने 1 दिसंबर, **2022** को इंडोनेशिया से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी और 2023 में देश में पहली बार जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत की जी20 प्रेसीडेंसी की ब्रॉडिंग और प्रचार-प्रसार कर रहा है। मंत्रालय के तहत सीबीसी, आउटरीच गतिविधियां, मीडिया अभियान योजना, लोगो डिज़ाइन आदि सहित विदेश मंत्रालय के जी20 सचिवालय के लिए विज्ञापन/ब्रॉडिंग भागीदार की भूमिका निभा रहा है। मंत्रालय की अन्य मीडिया ईकाइयों जैसे पीआईबी, डीडी समाचार, एआईआर, प्रकाशन विभाग और न्यू मीडिया विंग भी समर्पित लेखों, समाचार आधारित प्रोग्रामिंग सोशल मीडिया प्रचार आदि के माध्यम से जी20 के प्रचार में लगे हैं।

- डीडी न्यूज़ ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी20 नेताओं के 17वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने और भारत की जी20 की

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 18 मई, 2022 को कान फ़िल्म समारोह में भारत के 53वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के पोस्टर का अनावरण करते हुए।

अध्यक्षता से जुड़े लोगो, थीम (विषय) और वेबसाइट जारी करने के कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कार्यक्रम का सीधा (लाइव) प्रसारण किया । शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में '**वसुधैव कुटुंबकम् की राह पर जी20**' और '**जी20 : एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य**' पर **Bharat@G20** दो विशेष चर्चाएं और एक विशेष सीरीज भी प्रसारित की गई। पत्र सूचना कार्यालय की अनुसंधान इकाई ने **भारत की जी20 अध्यक्षता के बारे में पॉडकास्ट भी शुरू किया।**

- डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया ने भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता ग्रहण किए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिखित ब्लॉग कवरेज सहित भारत की जी20 अध्यक्षता; राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उप-राज्यपालों की भारत की जी20 अध्यक्षता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए बैठक, पहली जी20 शेरपा बैठक, जी20 वित्त और सेंट्रल बैंक डिप्टीज़ (एफसीबीडी) की पहली बैठक के बारे में व्यापक कवरेज किया गया था। जी20 के सभी पहलुओं/घटनाओं/गतिविधियों के बारे में डीडी न्यूज़ पर '**भारत@20 : वसुधैव कुटुम्बकम्**' शीर्षक से विशेष कार्यक्रम प्रतिदिन प्रसारित किया जा रहा है जिसमें जी20 और भारत की अध्यक्षता के महत्व पर चर्चा की जाती है। सभी प्राइम टाइम समाचार कार्यक्रमों में विशेषज्ञों के पैनल और ग्राउंड रिपोर्टों के माध्यम से उभरते मुद्दों पर चर्चा कराई जाती है।

- मंत्रालय ने जी20 पर आवरण कथा शामिल करके प्रधानमंत्री की '**मन की बात**' पुस्तिका का नवंबर, **2022** अंक प्रकाशित किया था।

काशी तमिल संगमम

- काशी और तमिलनाडु के बीच युगों से चले आ रहे संबंधों का समारोह मनाने, उनकी फिर पुष्टि करने तथा उन्हें फिर

सबके समक्ष उजागर करने के उद्देश्य से वाराणसी में एक माह का 'काशी तमिल संगमम' आयोजित किया गया था और डीडी न्यूज़ नेटवर्क ने सीधे प्रसारण, ग्राउंट रिपोर्टों, विशेष कार्यक्रमों, पूर्व-प्रचार, उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण, प्रतिभागियों के इंटरव्यू आदि के माध्यम से व्यापक कवरेज किया।

- इस आयोजन के महत्व और इसकी गतिविधियों को दर्शकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से वाराणसी में 'काशी तमिल संगमम' के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन, '**काशी तमिल संगमम : एक भारत श्रेष्ठ भारत**' विषय पर विशेष परिचर्चा, काशी तमिल संगमम पर वृत्तचित्र और तेजस्विनी के विशेष एपीसोड का प्रसारण किया गया। सीबीसी ने डिजिटल मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव, काशी और तमिलनाडु के बीच अनेक क्षेत्रों में घनिष्ठ सांस्कृतिक/ ऐतिहासिक संपर्कों को दर्शाया गया था।

- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आठ दिन के '**काशी तमिल संगमम – खेल शिखर सम्मेलन**' का आयोजन किया गया था। सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल शिखर सम्मेलन के चौथे दिन 11 दिसंबर, 2022 को 'काशी तमिल संगमम' में आए लोगों को संबोधित किया और वाराणसी में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच खेले गए **फ्रेंडली क्रिकेट मैच** में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने 12 नवंबर, 2022 को आयोजित फ्रेंडली टेबल टेनिस मैच का उद्घाटन भी किया तथा वाराणसी के सिगरा स्टेडियम के आधुनिकीकरण कार्य की समीक्षा की और वाराणसी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न कार्यालय परिसरों का ऑडिट भी किया।

श्री अमरनाथजी यात्रा 2022

- **जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा का डीडी न्यूज़ से विशेष इंटरव्यू** प्रसारित किया गया था जिसकी बाइट्स 22 जून, 2022 से समाचार बुलेटिन में भी शामिल की गई थीं। श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अमरनाथ मंदिर में की गई '**प्रथम पूजा**', जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन हेलिकॉप्टर बुकिंग सेवा पोर्टल के शुभारम्भ और उपराज्यपाल द्वारा जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की ख़बर का डीडी न्यूज़ और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने बहुत व्यापक कवरेज किया।

- यात्रा से जुड़ी घटनाओं और तैयारियों के सिलसिले में सभी प्राइम टाइम न्यूज़ कार्यक्रमों और नियमित बुलेटिनों में ग्राउंड रिपोर्ट, विशेष भेंटवार्ताएं, इंफोग्रॉफिक्स, सोशल मीडिया कवरेज और '**श्री अमरनाथ यात्रा : नए आयाम**', '**श्री अमरनाथ यात्रा : रोजगार और सहकार**', '**स्वस्थ और सुरक्षित श्री अमरनाथ यात्रा 2022**' आदि विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए। आकाशवाणी ने बालताल में एफएम ट्रांसमिशन सुविधा और स्टूडियो सुविधा स्थापित की और 30 जून, 2022 से प्रतिदिन सवेरे 7 बजे से रात 10 बजे तक अमरनाथजी यात्रा के बारे में विशेष प्रसारणों की व्यवस्था की।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 11 दिसंबर, 2022 को वाराणसी के बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में आयोजित 'काशी तमिल संगमम्' को सम्बोधित करते हुए।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर 21 जून, 2022 को हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर टिहरा में आयोजित योग कार्यक्रम के अवसर पर। केंद्रीय मंत्री प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 'योग सचित्र' पुस्तक के साथ।

8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

भारत के प्रधानमंत्री के आग्रह और दुनिया की योग में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसम्बर, **2014** को घोषणा की कि 21 जून का दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। समूचे विश्व में योग के महत्व को स्वीकार किया जाना हमारे देश के लिए महान गर्व की बात है क्योंकि 'योग' मानवता के लिए भारत की अनुपम देन है और इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परम्परा का अभिन्न अंग है। विगत सात वर्षों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में विश्वव्यापी आंदोलन बन गया है।

8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य फ़ोकस 'ब्रांड **इंडिया**' पर था और सभी संभावित प्लेटफॉर्मों पर योग को प्रोत्साहन देने की गतिविधियां साझा की गईं और देशभर के सभी हितार्थियों को इससे जोड़ा गया। आयुष मंत्रालय ने नोडल मंत्रालय की भूमिका निभाते हुए, **100** दिन, **75** दिन, **50** दिन तथा **25** दिन के आयोजन किए। 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की विशेष उल्लेखनीय बातों में **'योग : द गार्जियन रिंग'** शीर्षक से विशेष रिले योग कार्यक्रम, देश के 75 अहम स्थानों में योग कार्यक्रम और 21 जून, **2022** को मैसूर में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जन योग प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन प्रमुख है।

- भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के समय ही होने के कारण अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 के सिलसिले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक/शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों ने 13 मई, 2022 के निर्धारित दिन पर अपने अधिकारियों और कर्मियों के लाभ की दृष्टि से योग कार्यशालाएं/प्रदर्शन किए और प्रतियोगिताएं/क्विज़/सेमिनार आदि का आयोजन किया। नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में मुख्य सचिवालय के अधिकारियों और कर्मियों के लिए योग प्रदर्शन आयोजित किया गया था।

- देशभर में **75** जाने-माने स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था जिनमें से **2** प्रमुख स्थानों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने योग प्रदर्शन आयोजित किए थे। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के टिहरा सुजानपुर (कटोच महल) में एकत्र लोगों का नेतृत्व सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। सूचना और प्रसारण, राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने पुदुचेरी की प्रोमोनेड बीच पर लगभग 3,500 प्रतिभागियों का नेतृत्व किया

और पुद्दुचेरी के उप राज्यपाल तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वहां योगाभ्यास आयोजन में भाग लिया।

- डीडी इंडिया ने 21 जून, **2022** को वन ऑफ़ ए कांइड '**गार्जियन रिंग फॉर योग**' कार्यक्रम के लिए बहुत व्यापक प्रबंध किए थे जो '**एक सूर्य, एक पृथ्वी**' अवधारणा पर ज़ोर देने के लिए मनाया गया था और इसमें सूर्योदय के समय पौ फटने से पहले एकत्र हुए विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोगों का लाइव टेलीकास्ट (सीधा प्रसारण) किया गया था। भारतीय समय के अनुसार प्रातः 3 बजे से रात 10 बजे तक लगातार चले प्रसारण में देश के 80 से अधिक मिशनों और दूतावासों द्वारा प्रमुख स्थलों में आयोजित योग कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर कवरेज किया गया।

- डीडी न्यूज़ ने माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की योग दिवस पर भागीदारी का सीधा प्रसारण किया। डीडी न्यूज़ पर 23 मई से 26 जून, **2022** तक **नया सवेरा सीरीज़** में विशेष सत्र के तहत '**योग सूत्र**' का दैनिक प्रसारण आयोजित किया गया था। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने 15 जून, **2022** को '**स्पॉटलाइट**' कार्यक्रम में आयुष मंत्री से विशेष भेंटवार्ता प्रसारित की। फ़िल्म प्रभाग ने अपनी वेबसाइट और यू-ट्यूब चैनल पर 21 जून, **2022** को **6** वृत्त चित्रों की विशेष स्क्रीनिंग की।

- न्यू मीडिया विंग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर 45 ग्राफिक्स/चित्र और वीडियो साझा किए गए।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को मनाने और महिलाओं के सशक्तीकरण पर बल देने के उद्देश्य से 8 मार्च का दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप डीडी न्यूज़ ने कच्छ में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक सेमीनार में भारत के माननीय राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करने और माननीय प्रधानमंत्री के आभासी सम्बोधन का सीधा प्रसारण किया।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों ने महिला अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं, पुरस्कार/सम्मान, परिचर्चाएं आयोजित कीं। डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया ने '**अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022**' के आयोजन पर विशेष कार्यक्रम, '**अपराजिता हूं मैं**' पर परिचर्चा और '**तेज़स्विनी-वीर नारियां**' के विशेष एपीसोड का प्रसारण किया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने 8 मार्च, 2022 को 'स्पॉटलाइट' और 'सुर्खियों में' कार्यक्रमों में विशेष प्रसारण किए थे। आकाशवाणी ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की कमेंट्री का देशभर में अपने सभी प्रमुख चैनलों से सीधा प्रसारण किया और विशेषज्ञों के साथ स्टुडियो आधारित चर्चाओं का आयोजन और प्रसारण भी किया गया।

- बिहार में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर 8 मार्च से 10 मार्च, **2022** तक फ़िल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से इंडिया पैनोरामा और राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के लिए चुनी गई फ़िल्मों का पैकेज़ स्क्रीन किया गया। फ़िल्म प्रभाग ने अपनी वेबसाइट और यू-ट्यूब चैनल पर 8 मार्च से 10 मार्च, **2022** तक 7 फ़िल्में स्क्रीन कीं (1,124 दर्शकों के लिए)। भारत की बाल फ़िल्म सोसाइटी ने महिला केंद्रित '**लाडली**' के 4 राज्यों- बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु में 7 शो आयोजित किए। महिला सिनेमा और कला अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (डब्ल्यूसीएआईएफएफ) ने 8 मार्च, 2023 को मुंबई में फ़िल्म प्रभाग की 12 फ़िल्मों की स्क्रीनिंग की थी।

- प्रकाशन विभाग (डीपीडी) और भारत के फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान (एफटीआईआई) ने कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में अपने मंडप में '**बैलेंसिंग द विज़डम ट्री - एंथोलॉजी ऑफ एफटीआईआईज़ विमेन एल्यूमनी**' शीर्षक विशेष पुस्तक को जारी किया। प्रकाशन विभाग की पत्रिका '**आजकल**' ने मार्च, **2022** में '**स्त्री लेखन की दिशा और चुनौतियां**' विषय पर विशेषांक निकाला था और '**कुरुक्षेत्र**' पत्रिका के अप्रैल, **2022** के अंक का विषय था '**ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण**'। न्यू इंडिया समाचार के मार्च, **2022** के पाक्षिक संस्करण की आवरण कथा का शीर्षक '**महिला शक्ति ही है राष्ट्र की समृद्धि का मुख्य आधार**' था। सीबीसी ने इस पाक्षिक पत्रिका का 13 भाषाओं में प्रकाशन कर के देशभर में वितरित किया था।

- पत्र सूचना कार्यालय और उसके प्रादेशिक/शाखा कार्यालयों

ने इस अंक के बारे में 158 प्रेस विज्ञप्तियां और 7 लेख जारी किए, 6 वेबिनार आयोजित किए और सोशल मीडिया अभियान चलाया। सीबीसी के प्रादेशिक/क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस विषय पर 21 आईसीओपी और 5 वेबिनार आयोजित किए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नारी शक्ति पुरस्कार से जुड़े ग्राफिक्स/चित्र और वीडियो साझा किए गए थे।

नोवेल कोरोना वायरस और कोविड-19

- दूरदर्शन, आकाशवाणी और न्यूज़ मीडिया विंग ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की सहभागिता और 12 मई, **2022** को प्रारंभिक सत्र में उनकी टिप्पणियों; कोरोना के कारण अपने माता-पिता को गंवा देने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत 30 मई, **2022** को जारी लाभों और सुविधाओं का व्यापक रूप से कवरेज किया।

- सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने डीडी न्यूज़, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और अपनी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (आरएनयू) के माध्यम से कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करने का व्यापक अभियान चलाया और लोगों को इससे बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार और प्रोटोकोल की जानकारी देने तथा बचाव और सुरक्षा के उपाय अपनाने और टीकाकरण अभियान के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने में महती भूमिका अदा की। '**राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस**' पर 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को एहतियाती खुराक़ देने के बारे में डीडी न्यूज़ से आधे घंटे का विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। विशेषज्ञों के पैनल के साथ 'डॉक्टर्स स्पीक', 'आरोग्य भारत' और 'टोटल हेल्थ' कार्यक्रम के माध्यम से कोविड-19 के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा आयोजित करके लोगों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाई गई। न्यूज़ नाइट, मिड डे प्राइम जैसे प्राइम टाइम शोज़ में भी टीकाकरण प्रयासों के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाकर चर्चाएं हुईं। पत्र सूचना कार्याल (पीआईबी) ने दैनिक कोविड-19 बुलेटिन जारी किए, प्रेस या मीडिया ब्रीफिंग (चर्चा) आयोजित कीं और कोविड फैक्ट चेक यूनिटों की मदद से अफवाहों और भ्रामक प्रचार पर अंकुश लगाया।

- डीडी न्यूज़ (दूरदर्शन समाचार) ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड-19 के बारे में हुई उच्चस्तरीय बैठक, देशभर के अस्पतालों में आयोजित मॉक ड्रिल, न्यूज़ नाइट में '**कोविड के नए वेरिएंट (संक्रमण) पर भारत हुआ अलर्ट**', '**कोरोना पर वार-एक्शन में सरकार**', जैसे नियमित कार्यक्रमों में आयोजित परिचर्चाओं का व्यापक प्रसारण किया गया।

- देश ने जब 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पार करके एक और नया इतिहास रचा तो केंद्रीय संचार ब्यूरो ने 17 जुलाई, **2022** को '**सामूहिक सामर्थ्य से रचा इतिहास**' शीर्षक से जन अभियान शुरू कर दिया जिसके अंतर्गत नई दिल्ली के मुख्य चौराहों, केंद्र सरकार के कार्यालयों, आवासीय परिसरों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में होर्डिंग/पोस्टर लगाए गए। सीबीसी (प्रादेशिक/क्षेत्रीय कार्यालयों) ने '**200 करोड़ कोविड टीकाकरण/कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव**' विषय पर देशभर में **4,000** से अधिक होर्डिंग/बैनर/पोस्टर लगाए। डीडी न्यूज़/डीडी इंडिया से '**टीकाकरण का आंकड़ा 200 करोड़ के पार**' और '**भारत ने 2 अरब टीकाकरण खुराक़ देने की उपलब्धि प्राप्त की**' शीर्षकों से विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

स्वच्छता अभियान 2.0 और बकाया मामलों के निपटान का विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 2.0

सूचना और प्रसारण मंत्रालय और उसके सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों ने बकाया मामलों (कामकाज) के निपटान, पुरानी/फालतू फाइलों को नष्ट करने और कार्यालयों में अच्छी तरह सफाई करके उपलब्ध स्थान का उपयुक्त प्रबंधन करने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, **2022** से 31 अक्तूबर, **2022** तक देशभर में विशेष अभियान 2.0 चलाया था।

- 'मन की बात' के दिसंबर 2022 अंक में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ कार्यालय स्थान सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। मासिक संबोधन में मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों पर प्रकाश डाला गया जिनके प्रयासों के परिणामस्वरूप अनावश्यक वस्तुओं को हटाने के फलस्वरूप कार्यालयों को अधिक स्थान प्राप्त हुए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित गतिविधियों से संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ कार्यालयों के लिए तीन मंजिलों में स्थान खाली हो गया।

- इस स्वच्छता अभियान के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने **4,735** क्विंटल कबाड़ और अन्य बेकार सामग्री का निपटान किया; **1,08,298** फाइलों की समीक्षा की गई जिनमें से **66,938** फाइलों की छंटाई कर दी गई; **2,217** ई-फाइलों की समीक्षा के बाद उनमें से **1,868** बंद कर दी गईं; **336** आउटडोर अभियान चलाए गए, **3,766** स्पॉट साफ किए; **14** सांसद संदर्भ, **320** सार्वजनिक शिकायतें, **181** पीजी अपील और **4** संसदीय आश्वासन भी निपटाए गए और कुल मिलाकर **1,75,447** वर्गफुट स्थान की सफाई की गई तथा **3,71,66,846** रुपये की आमदनी भी हुई।

- डीडी न्यूज़ ने कार्यालयों में सफाई अभियान के बारे में '**स्वच्छता अभियान 2.0**' शीर्षक से विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया। 'स्वच्छता के बारे में विशेष अभियान 2.0' का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 'विशेष अभियान 2.0' और 'स्वच्छता' के तहत व्यापक प्रचार किया गया। फ़िल्म प्रभाग ने विशेष अभियान 2.0 के तहत अपनी वेबसाइट और यू-ट्यूब चैनल पर 27 अक्तूबर, **2022** को '**स्वच्छता**' पर 7 फ़िल्मों की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया था।

- फिर, सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 14 नवंबर, **2022** को मुंबई जाकर आकाशवाणी, दूरदर्शन, फ़िल्म प्रभाग और प्रेस सूचना ब्यूरो के वहां स्थित प्रादेशिक कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा की और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि देश में अच्छी गति पकड़ चुके स्वच्छता अभियान को जारी रखा जाए।

अन्य उपलब्धियां

- **अंतरराष्ट्रीय मिलेट (श्रीअन्न) वर्ष 2023** : डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद में आयोजित 'स्पेशल मिलेट ओनली लंच' (विशेष श्रीअन्न एकमात्र भोजन) कार्यक्रम, जिसमें राज्यसभा के माननीय सभापति, प्रधानमंत्री और सांसदगण उपस्थित थे; संसद में मोटे अनाज (श्रीअन्न) प्रदर्शनी, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इटली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मिलेट (श्रीअन्न) वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाने जैसी गतिविधियों का व्यापक कवरेज किया था। आकाशवाणी स्टेशनों ने अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के बारे में निरंतर प्रचार/कवरेज चलाया और श्रीअन्न की खेती के विभिन्न पहलुओं इसके पोषक मूल्य, प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात और विपणन क्षमता और इसके पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरुकता पैदा की।

- **राष्ट्रमंडल खेल 2022** : डीडी स्पोर्ट्स ने 2022 में 28 जुलाई, **2022** से इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के भव्य उद्घाटन समारोह के साथ ही प्रतिदिन के खेल आयोजनों का सीधा प्रसारण किया। 29 जुलाई, **2022** से केवल डीडी फ्रीडिश पर 20 खेल श्रेणियों की खेल स्पर्धाओं का प्रसारण किया गया था। डीडी न्यूज़ से '**राष्ट्रमंडल खेल 2022 : जोश, जज्बा और जुनून**' विषय पर विशेष बुलेटिन प्रसारित किया गया और डीडी इंडिया से विशेष अंग्रेजी बुलेटिन '**सीडब्ल्यूजी 2022 : गौरव के मार्ग पर**' का प्रसारण हुआ था। विभिन्न स्थलों से भारतीय खिलाड़ियों और टीमों के मुकाबलों का व्यापक कवरेज किया गया था और उनकी सफलताओं के समाचार डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में प्रकाशित किए गए। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के एफएम गोल्ड से स्पोर्ट्स स्कैन पर 21 जुलाई, **2022** से प्रतिदिन ''**एआईआर न्यूज़ के साथ राष्ट्रमंडल खेल क्विज़**'' का प्रसारण किया गया था। बड़ी ख़बरें डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया, डीडी स्पोर्ट्स और एआईआर स्पोर्ट्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा की गईं।

- **खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल (केआईयूजी) 2021** : इन खेलों का लोगो, मैस्कॉट (शुभंकर), गान और जर्सी का शुभारम्भ तथा खेलों का उद्घाटन भारत के माननीय उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था और डीडी न्यूज़ से इस पूरे समारोह का सीधा प्रसारण किया गया था। खेलों के पहले दिन डीडी न्यूज़ ने विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया और डीडी न्यूज़ तथा डीडी इंडिया से प्रतिदिन आधे घंटे का '**खेलो इंडिया**' बुलेटिन भी प्रसारित किया गया था। नियमित बुलेटिनों और न्यूज़ शोज़ में खेलों की सभी विशेष घटनाओं को खिलाड़ियों के साथ विशेष इंटरव्यू और चर्चाओं के साथ कवर किया गया और संवाददाताओं ने खासतौर पर इन खेलों में भाग ले रहे ओलम्पिक खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया था। मल्लखंब, योगासन और पोषाहार से जुड़ी खास ख़बरें भी काफी सुर्खियों में रहीं।

- **पोषण माह** : आम लोगों को पोषण के महत्व के प्रति जागरूक

बनाने के उद्देश्य से सीबीसी (प्रादेशिक कार्यालयों) ने देशभर में अनेक लोक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 60 समेकित संचार और लोकसंपर्क कार्यक्रम (आईसीओपी), **20** विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम (एसओपी), **3** वेबिनार और 37 क्षेत्रीय कार्यक्रम शामिल थे। एआईआर द्वारा सितंबर 2022 में आयोजित पोषण माह के दौरान देशभर में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को व्यापक कवरेज दिया गया। पोषण के महत्व और स्वस्थ भारत के लिए कुपोषण उन्मूलन की आवश्यकता पर चर्चा भी आयोजित की गई।

- **चीता परियोजना** : डीडी न्यूज़ ने भारत में विलुप्त हो चुकी चीतों की प्रजाति को फिर से बसाने की 'चीता परियोजना' का विशेष कवरेज किया और 17 सितम्बर, 2022 को विशेष लाइव कार्यक्रम प्रसारित किया जिसमें प्रधानमंत्री ने नामीबिया से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाए गए आठ चीतों को छोड़ा था।

- **राष्ट्रीय खेल** : प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन का टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया था। डीडी न्यूज़ से उद्घाटन समारोह, परिणाम, पदक तालिका, इत्यादि का हर बुलेटिन में समाचार दिया गया। अंग्रेजी/हिन्दी में इंटरव्यू, लाइव ग्राउंड रिपोर्ट इत्यादि शामिल करके विशेष कार्यक्रम '**राष्ट्रीय खेल 2022**' का प्रसारण किया गया था।

- **दुबई एक्सपो में भागीदारी** : दुबई एक्सपो के भारतीय मंडप में मीडिया और मनोरंजन सप्ताह का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता श्री आर. माधवन की उपस्थिति में 18 मार्च, **2022** को दुबई में किया गया था। इसी अवसर पर **आरआरआर फ़िल्म** का विश्वभर में प्रीमियर हुआ, गोलमेज़ चर्चा आयोजित की गई और दुबई स्थिति चैनल-2 ने भारत में एक स्पोर्ट्स रेडियो स्टेशन शुरू करने की इच्छा व्यक्त की। सूचना और प्रसरण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 27 मार्च, 2022 को दुबई एक्सपो देखने गए और तेज़स (ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स) का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षण देना है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने 28 मार्च, **2022** को भारतीय मंडप में अभिनेता रणवीर सिंह से '**भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग की वैश्विक पहुंच**' विषय पर चर्चा की। मंत्री महोदय ने पर्यटन तथा मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में निवेश और सहयोग की संभावनाओं पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के इन उद्योगों के जाने-माने नेताओं के साथ अनेक चर्चाएं भी कीं।

- **टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (टीआईएफएफ) में सहभागिता** : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने टोरंटो में 8 सितंबर से 18 सितंबर, **2022** तक हुए टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (टीआईएफएफ) में भाग लिया। भारतीय मंडप का विषय था '**सामग्री हब के रूप में भारत**' और फ़िल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) को ब्रांड बनाया गया।

- प्रकाशन विभाग ने 2 से 12 नवंबर 2022 तक एक्सपो सेंटर शारजाह में आयोजित 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले एसआईबीएफ 2022 में भाग लिया। डीपीडी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कला और संस्कृति, महात्मा गांधी जैसे विषयों की विस्तृत श्रृंखला पर 135 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित कीं। इसके अलावा डीपीडी के द्वारा आज़ादी क्वेज़ गेम को बढ़ावा दिया गया।

- **17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (एमआईएफएफ)** : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फ़िल्म प्रभाग ने 29 मई, **2022** से 4 जून, **2022** तक वृत्तचित्र, लघु चित्र और एनीमेशन फ़िल्मों का 17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह छोटे रूप में आयोजत किया। बांग्लादेश की स्वाधीनता के 50 वर्ष पूरे होने पर उसे '**कंट्री ऑफ़ फोकस**' अर्थात् मुख्य देश का सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 मई, **2022** को '**मन की बात**' कार्यक्रम में भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से बनाई पहली एनीमेशन फ़िल्म '**रामायण : द लेजेंड ऑफ़ प्रिंस राम**' का उल्लेख किया जिसने अपनी रिलीज के 30 वर्ष पूरे कर लिये थे और एमआईएफएफ में इसकी विशेष स्क्रीनिंग की गई थी। **India@75** विषय पर सर्वश्रेष्ठ लघु चित्र के लिए विशेष पुरस्कार भी शुरू किया गया। एमआईएफएफ में पहली बार बच्चों की दो एनीमेशन फ़िल्मों के लिए निःशुल्क प्रविष्टि भी प्रदान की गई। समारोह में 12,000 से अधिक दर्शक उपस्थित रहे और कुल 385 फ़िल्में दिखाई गई थीं। जाने-माने वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंटरी) निर्माता-लेखक श्री संजीत नार्वेकर को डॉ. वी. शांताराम लाइफ़टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया।

- **प्रसार भारती आर्काइव्ज ने प्रधानमंत्री संग्रहालय को पुनः सक्रिय किया** : प्रसार भारती आर्काइव्ज ने लगभग 206

घंटे की ऑडियो और 53 घंटे की वीडियो सामग्री जुटाकर '**प्रधानमंत्री संग्रहालय**' के विकास में उल्लेखनीय योगदान किया है। देश के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए इस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल, **2022** को किया था।

- भारतीय प्रेस परिषद् ने 16 नवम्बर, **2022** को दिल्ली के स्कोप कॉन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि थे और उन्होंने ''**पत्रकारिता आवरण के मानक 2022**'' जारी किए। समारोह में माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन गेस्ट ऑफ़ ऑनर (सम्मानित अतिथि) थे और जाने-माने पत्रकार श्री स्वप्न दास गुप्ता ने मुख्य भाषण दिया था। सभापति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने समारोह की अध्यक्षता की। गणमान्य व्यक्तियों ने '**राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका**' विषय पर विचार-विनिमय किया और भारतीय मीडिया के मानकों को बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 23 जुलाई, **2022** को आकाशवाणी भवन में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन की उपस्थिति में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस समारोह का उद्घाटन किया। श्री ठाकुर ने इस अवसर पर दूरदर्शन के नए धारावाहिकों- कॉर्पोरेट सरपंच, बेटी देश की, जय भारती, सुरों का एकलव्य और ये दिल मांगे मोर के प्रोमो जारी किए और साथ ही स्टार्टअप चैंपियन्स 2.0 का प्रोमो भी जारी किया गया। डीडी न्यूज़ पर विशेष कार्यक्रम '**नए भारत की नई वाणी –दूरदर्शन और आकाशवाणी**' का प्रसारण भी किया गया था।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 16 जुलाई, **2022** को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के अधिकारियों के तीसरे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो दिन के इस सम्मेलन में देशभर के भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। समापन सत्र को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने संबोधित किया।
- केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 25

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली में 23 जुलाई, 2022 को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर दीप प्रज्ज्वलित करते हुए।

मई, 2022 को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से 17वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। मंत्री ने लोगों को कोविड-19 के बारे में शिक्षित करने के लिए भारतीय मीडिया की सराहना की और कहा कि मीडिया ने सशक्तीकरण के एक प्रभावी रूप में सही सार्वजनिक धारणाओं और दृष्टिकोणों को आकार देने की अपार क्षमता है।

- विश्व प्रसिद्ध फ़िल्म निर्देशक और हंगरी के फ़िल्म निर्माता बेला तार्र ने भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान (एफटीटीआई) के निर्देशन और स्क्रीनप्ले लेखन विभाग के अंतिम वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए 5 दिन का कार्यक्रम '**मास्टरक्लास इन फ़िल्म डायरेक्शन**' आयोजित किया।

- **प्रसार भारती द्वारा उत्कृष्ट किस्म की सामग्री का निर्माण** : डीडी नेशनल प्रसारित पालतू पशुओं की देखभाल पर आधारित टीवी सीरीज़ '**सदैव सर्वश्रेष्ठ मित्र**' ने एक्सचेंज4मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग पुरस्कार 2021 जीता, जो उसे ईएनबीए के 14वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ इन-डेप्थ हिन्दी सीरीज़ के लिए प्रदान किया गया।

- भारत के सार्वजनिक प्रसारक और स्वायत्त संवैधानिक निकाय प्रसार भारती ने 11 जुलाई, **2022** को अपना नया लोगो जारी कर दिया। जहां मध्य वाले गोले (वृत्त) के घटक और भारत का नक्शा देश के प्रति विश्वास, सुरक्षा और श्रेष्ठता को दर्शाते हैं तथा इसका गहरा सामान्य नीला रंग आकाश और समुद्र तथा खुले अंतरिक्ष, स्वतंत्रता, अंतर्ज्ञान कल्पना, प्रेरणा और संवेदनशीलता का प्रतीक है।

- नई दिल्ली में 30 सितंबर, 2022 को पुस्तक प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए 42वें वार्षिक पुरस्कार आयोजित किए गए थे जिनमें प्रकाशन विभाग को भारतीय प्रकाशक परिसंघ की ओर से विभिन्न श्रेणियों की पुस्तकों के लिए नौ पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इनमें छह प्रथम पुरस्कार, एक द्वितीय पुरस्कार और दो तृतीय पुरस्कार थे।

- प्रकाशन विभाग ने अत्यन्त लोकप्रिय पत्रिकाओं- '**योजना**' और '**कुरुक्षेत्र**' के नए लोगो अपने सोशल मीडिया हैंडलों पर जारी किए।

- **डिजिटल डीडी, आकाशवाणी समाचार पर अटूट भरोसा:** रॉयटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा भारतीय समाचार ब्रांडों के सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि आकाशवाणी और डीडी न्यूज द्वारा समाचारों की प्रामाणिकता और सटीकता पर निरंतर भरोसा यानी 'सबका विश्वास' क्रमशः 72 प्रतिशत और 71 प्रतिशत है। भारत ने समाचारों पर भरोसे में थोड़ी वृद्धि दर्ज की, जिससे 46 बाजारों में उसकी समग्र स्थिति में सुधार हुआ।

ऑपरेशन गंगा और यूक्रेन-रूस संकट

- रूस-यूक्रेन संकट और ऑपरेशन गंगा के बारे में प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय बैठकों, भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक, तत्कालीन वैश्विक स्थिति और उनकी रूस, यूक्रेन, यूरोपीय परिषद्, फ्रांस और पोलैंड के राष्ट्रपतियों के साथ फोन पर हुई बातचीत की भी डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से व्यापक कवरेज की गई।

- डीडी न्यूज़ ने '**ऑपरेशन गंगा : लौट रहे भारतीय स्वदेश**' विषय पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया, रक्षा विभाग की पाक्षिक पत्रिका '**रक्षक**' और पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया से ग्राउंड रिपोर्टें भी प्रसारित की गई थीं। डीडी इंडिया ने '**रशियन-यूक्रेन फेस ऑफ : द एनर्जी क्राइसिस**' (रूस-यूक्रेन गतिरोध : ऊर्जा संकट), '**रशिया-यूक्रेन क्राइसिस रोल ऑव मर्सिनरीज़**' (रूस-यूक्रेन संकट – आतंकवादियों की भूमिका); '**इंडियन डिप्लोमेसी – इंडिया**' (भारतीय कूटनीति – भारत), '**जियो पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी**' (भू-राजनीति और अर्थव्यवस्था), इंडिया दिस वीक, डीडी डायलॉग, मीडिया स्कैन वगैरह विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हंगरी से ऑपरेशन गंगा तथा भारत में यूक्रेन/स्लोवाकिया/रोमानिया/पोलैंड और हॉलैंड के राजदूतों के साथ विशेष इंटरव्यू (भेंटवार्ता)/बातचीत का प्रसारण किया गया।

■■■

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु तथा पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 'मूड्स, मोमेंट्स और मेमोरीज़, - फॉर्मर प्रेज़िडेन्ट्स ऑफ़ इंडिया (1950-2017) अ विज़ुअल हिस्ट्री' का 24 जुलाई, 2022 को विमोचन करते हुए।

4 सूचना क्षेत्र

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और उपलब्धियों पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह सरकार तथा मीडिया के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और मीडिया में परिलक्षित आम जन की प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराता है।

यह मीडिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त संचार रणनीतियों पर सरकार को सलाह देता है।

पीआईबी विभिन्न माध्यमों जैसे- प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, फ़ीचर लेख, पृष्ठभूमि, प्रेस ब्रीफिंग, साक्षात्कार, संवाददाता सम्मेलन, प्रेस टूर सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से सूचना प्रसारित करता है। सूचना अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू के साथ 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की जाती है जो पूरे देश के समाचार-पत्रों और मीडिया संगठनों तक पहुंचती है।

पीआईबी में एक समाचार कक्ष/समाचार निगरानी प्रकोष्ठ है जो सूचना प्रसार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालभर काम करता है। पीआईबी मीडियाकर्मियों को मान्यता की सुविधा भी प्रदान करता है ताकि सरकारी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो सके।

पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख प्रधान महानिदेशक (मीडिया और संचार) हैं। पीआईबी के पांच जोन है। जिनमें 19 क्षेत्रीय कार्यालय और 17 शाखा कार्यालय हैं जिनमें एक सूचना सेंटर भी है, जो क्षेत्रीय मीडिया इकाइयों की सूचना ज़रूरतों को पूरा करता है।

पीआईबी की सूचना प्रसार संबंधी गतिविधियां

(क) मंत्रालय/विभागवार सूचना प्रसार

पीआईबी अधिकारी किसी मंत्रालय/विभाग से जुड़े होते हैं और उसी के अधिकृत प्रवक्ता होते हैं। वह मंत्रालय/विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हैं, सूचनाओं का प्रसार करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और जब भी आवश्यकता होती है, स्पष्टीकरण या प्रतिवाद प्रदान करते हैं। पीआईबी अधिकारी मीडिया में संपादकीय, लेखों और टिप्पणियों में परिलक्षित सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं और मंत्रालय/विभाग को जनता की राय से अवगत कराते हैं तथा मंत्रालय/विभाग को उसकी मीडिया और सूचना, शिक्षा और संचार रणनीति पर सलाह देते हैं।

(ख) क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा सूचना प्रसार संबंधी गतिविधियां

क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में पीआईबी अधिकारी, मुख्यालय से दी जाने वाली सूचनाओं के प्रसार के अलावा, केंद्रीय मंत्रालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कवरेज भी सुनिश्चित करते हैं। ये कार्यालय निरंतर आधार पर सूचना प्रसार पर केंद्रित प्रचार के लिए केंद्र सरकार के उन निर्णयों को भी लेते हैं जो एक क्षेत्र विशेष के लिए खास महत्व के हो सकते हैं। पीआईबी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के किसी क्षेत्र/राज्य के आधिकारिक दौरे पर मीडिया कवरेज को सुविधाजनक बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

सूचना प्रसार के लिए अपने जनादेश को पूरा करने के लिए पीआईबी द्वारा निम्नलिखित संचार रणनीतियां नियोजित की जाती हैं:

i) संचार के पारंपरिक रूप जैसे- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस (वीडियो कॉन्फ्रेंस सहित);

ii) महत्वपूर्ण घटनाओं और घोषणाओं की प्रेस विज्ञप्तियां और तस्वीरें जारी करना। इसके बाद मीडियाकर्मियों को एसएमएस अलर्ट, ट्वीट और टेलीफोन कॉल द्वारा सूचित करना।

iii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर साक्षात्कार, विशेष चर्चा आदि की व्यवस्था।

iv) वेबसाइटों पर नियमित अपडेशन के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे- ट्विटर, यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का उपयोग।

v) पीआईबी द्वारा सूचना प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है। ऐप के माध्यम से पीआईबी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए पत्रकारों और अन्य व्यक्तियों द्वारा पीआईबी ऐप- एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड और उपयोग किया जा रहा है। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर ऐप को पांच लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।

vi) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू के अलावा प्रमुख भारतीय भाषाओं जैसे- मलयालम, उड़िया, कन्नड़, तेलुगू, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मणिपुरी, असमिया और बंगाली में पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से अखिल भारतीय कवरेज सुनिश्चित करना।

vii) स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, आम बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (इफ्फी), राष्ट्रीय एकता दिवस, योग दिवस का अंतरराष्ट्रीय दिवस और स्वच्छ भारत सप्ताह जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए मीडिया कवरेज की विशेष व्यवस्था की जाती है।

viii) पीएमओ को हिन्दी और अंग्रेजी में दैनिक मीडिया रिपोर्ट के रूप में मीडिया से फीडबैक, प्रत्येक मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके मंत्रालयों को मीडिया का दैनिक फीडबैक तथा महत्वपूर्ण अवसरों पर विशेष फीडबैक।

ix) जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों सहित दूरदराज के क्षेत्रों में मीडिया आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से पीआईबी अंतिम छोर तक पहुंचता है।

मीडिया उत्पाद/सेवा	सं. (1 जनवरी, 2022-31 दिसम्बर 2022)
सभी 14 भाषाओं में कुल प्रेस विज्ञप्तियां	88,689
फोटो रिपोर्टें	18,418
एसएमएस	मीडिया को बल्क एसएमएस
वीडियो रिपोर्टें	76
मीडिया निमंत्रण रिपोर्टें	530
पत्रकारों को जारी किए गए कुल कार्ड	4,020
वार्तालाप	80
प्रेस यात्राएं	6
राष्ट्रव्यापी मीडिया फीडबैक	दैनिक
विशिष्ट मुद्दों पर विश्लेषणात्मक मीडिया रिपोर्ट	दैनिक/साप्ताहिक

(ग) पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट

फैक्ट चेक यूनिट (दिसंबर 2019 में प्रायोगिक आधार पर स्थापित) की स्थापना पीआईबी द्वारा समाचार मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विभिन्न माध्यमों पर तथ्यात्मक रूप से गलत/भ्रामक ख़बरों तथा सूचनाओं के प्रसार तथा उसकी निगरानी और रोकथाम के लिए की गई थी, जो अक्सर लोगों को विभिन्न मुद्दों पर गुमराह करते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट का काम पब्लिक डोमेन में तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी उपलब्ध करा कर विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही किसी भी ख़बर का आधिकारिक/प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध कराना है।

यह इकाई स्वप्रेरणा से या विभिन्न विधियों- समर्पित ई-मेल आईडी, वेबसाइट पोर्टल और व्हाट्सऐप नंबर पर उपयोगकर्ता शिकायतें; वास्तविक समय के आधार पर ईएमएमसी से जानकारी के रूप में टेलीविज़न पर गलत सूचना की घटनाओं की रिपोर्टिंग, पीआईबी द्वारा अपने कर्मियों के माध्यम से समाचार-पत्रों और वेब पोर्टल्स पर झूठी सूचना की रिपोर्टिंग और विभिन्न उप-इकाइयों के माध्यम से राज्यों से इनपुट एकत्र करके फर्जी समाचारों की पहचान करती है। इसके अलावा, यह इकाई प्रामाणिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है जिसका उपयोग निजी मीडिया

द्वारा किया जाता है, जिससे इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। विशेष रूप से देशभर के विभिन्न राजधानी शहरों में पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित क्षेत्रीय तथ्य जांच इकाइयों की गतिविधियों में वृद्धि के साथ, यह इकाई समय के साथ विकसित हुई है।

31 मार्च, 2023 तक एफसीयू फैक्ट चेक यूनिट द्वारा 38,966 कार्रवाई योग्य प्रश्नों का उत्तर दिया। कुल फैक्ट चेक 1,213 व 1,700 पोस्ट थे, जिनके लिए जहां भी आवश्यकता हुई स्पष्टीकरण के साथ जारी किए गए।

घ. प्रधानमंत्री की प्रचार और संदर्भ इकाई

पीआईबी के पास प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रचार और मीडिया सहयोग के लिए एक समर्पित इकाई है। यह सालभर काम करती है। यह भारत के माननीय राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिवालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के प्रचार से भी संबंधित है।

ङ सोशल मीडिया आउटरीच

i. पीआईबी इंडिया और पीआईबी हिन्दी

- **पीआईबी** इंडिया ट्विटर - पत्र सूचना कार्यालय, दिल्ली;/(@PIB_India) का अंग्रेजी ट्विटर हैंडल 27 दिसंबर, 2010 को बनाया गया था। तब से कुल फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 2.7 मिलियन हो गई है, जिसमें एक महीने में **20 हजार से अधिक फॉलोअर** की औसत वृद्धि हुई है। मासिक आधार पर भेजे गए ट्वीट्स की औसत संख्या लगभग **11 मिलियन** इंप्रेशन जेनरेट कर रही है।

- **पीआईबी हिन्दी ट्विटर** - (@PibHindi) का हैंडल जनवरी, 2015 में शुरू किया गया था। फिलहाल पीआईबी हिन्दी के 304.5 हज़ार फॉलोअर हैं, जिसमें एक महीने में 6,000 हज़ार नए लोग जुड़ रहे हैं। हैंडल से प्रतिमाह औसतन 900 ट्वीट किए जा रहे हैं और आंकड़ों के अनुसार हर महीने हिन्दी हैंडल पर 1.52 मिलियन इंप्रेशन जेनरेट किए गए।

ii. फेसबुक - वर्तमान वर्ष में फेसबुक पर पीआईबी के प्रशंसकों में लगभग **649 हज़ार फॉलोअर** के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। संचार और जुड़ाव के रचनात्मक साधनों को अपनाने से इसे बढ़ावा मिला है।

iii. इंस्टाग्राम - पीआईबी इंस्टाग्राम के **1 मिलियन** से ज्यादा फॉलोअर्स थे।

iv. यू-ट्यूब- पीआईबी यू-ट्यूब मई 2011 में बनाया गया था। इस चैनल के कुल **1.65 मिलियन** सब्सक्राइबर्स हैं।

v. पीआईबी फैक्ट चेक (31.12.2022 तक)

- **ट्विटर**-पीआईबी फैक्ट चेक (@PIBFactCheck) का ट्विटर हैंडल दिसंबर, 2019 में बनाया गया था। तब से, प्रति माह औसतन 3.5 हज़ार फॉलोअर्स की वृद्धि के साथ इनकी कुल संख्या बढ़कर 284.8 हज़ार हो गई है। पीआईबी फैक्ट चेक नागरिकों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने के लिए नए प्रकार की सामग्री और प्रस्तुति को अपना रहा है, जैसे कि जीआईएफ, पोल्स, जागरूकता पोस्ट, मोमेंट मार्केटिंग और अभियान, जिसके परिणामस्वरूप प्रति माह औसतन 1.60 मिलियन इंप्रेशन प्राप्त होते हैं।

- **फेसबुक**: पीआईबी फैक्ट चेक के फेसबुक पर 58,818 लाइक्स हैं।

- **इंस्टाग्राम**: इस प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ाने के लिए क्रॉस-प्रमोशन के उद्देश्य से पीआईबी फैक्ट चेक इंस्टाग्राम पर सामग्री प्रकाशित की जाती है। पीआईबी फैक्ट चेक इंस्टाग्राम के 79.6 हज़ार फॉलोअर्स हैं।

- **हॉटलाइन नंबर**- पीआईबी फैक्ट चेक, कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र व्हाट्सएप में शामिल हो गया, ताकि बढ़ती फ़र्ज़ी ख़बरों के ख़तरे पर अंकुश लगाया जा सके जो व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्लिकेशन पर जंगल की आग की तरह फैलती हैं। लोग अपने प्रश्न यूनिट को (+) 918799711259 पर भेज सकते हैं। यूनिट को 97,664 से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं और इस प्लेटफार्म पर 22,519 से अधिक कार्रवाई करके योग्य प्रश्नों का जवाब दिया गया है।

- **जीमेल और पोर्टल**- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, दो खाते, socialmedia@pib.gov.in और pibfactcheck@gmail.com, कोविड-19 संबंधित फ़र्ज़ी ख़बरों का मुक़ाबला करने के लिए शुरू किए गए थे। कोविड-19 पर किसी भी

समाचार का आधिकारिक संस्करण इन ईमेल से निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त किया जा सकता है। एफसीयू ने जी मेल और पोर्टल पर 15,029 से अधिक प्रश्न प्राप्त किए हैं और उनका जवाब दिया है।

च. मीडिया आउटरीच प्रोग्राम और विशेष आयोजनों के लिए मीडिया कवरेज

i विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)

डीसीआईडी योजना का जनादेश नागरिकों में सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना है ताकि लक्षित लाभार्थियों को विकासात्मक योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके, विकास और शासन की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सके और व्यवहार तथा सोच परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा सके। मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष आयोजनों के लिए प्रचार मंत्रालय की व्यापक योजना डीसीआईडी के तहत एक उप-योजना है। यह क्षेत्रीय मीडिया तक पहुंचता है जो लक्षित आबादी के साथ सीधे संपर्क में है। योजना में निम्नलिखित घटक हैं:

(क) मीडिया इंटरैक्टिव सत्र (राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संपादकों का सम्मेलन)

मीडिया इंटरैक्टिव सत्र के तहत, पीआईबी पूरे भारत के संपादकों/पत्रकारों को आमंत्रित करते हुए राष्ट्रीय (सामाजिक/आर्थिक) संपादकों का सम्मेलन आयोजित करता है। सामाजिक-आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं आदि जैसे मुद्दों पर चयनित राज्यों की राजधानियों में सत्रों की योजना बनाई जाती है। इन सत्रों में, केंद्रीय मंत्रियों और संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल के बारे में राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया के साथ बातचीत में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

(ख) वार्तालाप

पीआईबी के नवीनतम सूचना प्रसार माध्यमों और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा की जा रही पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए देशभर में जिला/तालुका स्तर पर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों के साथ मीडिया सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। वार्तालाप का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सूचना का प्रसार करना है और ग्रामीण मीडिया पीआईबी के आउटरीच प्रयासों में एक बड़ा गुणक है। इन वार्तालापों के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं से संबंधित साहित्य/पैम्फ्लेट मीडियाकर्मियों को वितरित किए जाते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान 63 वार्तालाप आयोजित किए गए।

(ग) प्रेस टूर

पीआईबी द्वारा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को देखने के लिए पत्रकारों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य के प्रेस टूर आयोजित किए जाते हैं। पत्रकारों का समूह विभिन्न योजनाओं, प्रमुख कार्यक्रमों और विकासात्मक परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत कर सकता है। पीआईबी संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत की सुविधा भी प्रदान करता है। ये दौरे सरकार की विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन की सफलता की कहानियों के बारे में मीडिया को सुग्राही बनाते हैं और इन्हें उनके मूल राज्य के मीडिया में और अधिक उजागर किया जाता है। 2022-23 में, अब तक छह प्रेस टूर आयोजित किए गए।

ii फीडबैक इकाई और समाचार कक्ष

पत्र सूचना कार्यालय का एक समाचार कक्ष/नियंत्रण कक्ष है जो किसी भी आकस्मिकता से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्षभर चालू रहता है। कम समय के नोटिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और देशभर में पीआईबी केंद्रों के माध्यम से एक साथ वेबकास्ट करने की व्यवस्था को भी, किसी भी अचानक हुए घटनाक्रम और अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। आपात स्थिति और संकट के समय नियंत्रण कक्ष 24x7 आधार पर कार्य करता है। महत्वपूर्ण समाचार चैनलों पर नज़र रखी जाती है और समय पर मीडिया हस्तक्षेप के लिए नवीनतम घटनाओं, तथ्यों की गलत रिपोर्टिंग आदि के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाता है।

यह इकाई दैनिक क्षेत्रीय मीडिया डाइजेस्ट और प्रेस क्लिपिंग्स, विशेष आयोजनों पर प्रेस क्लिपिंग्स तथा मीडिया डाइजेस्ट और डेली इंटरनेशनल मीडिया डाइजेस्ट सहित विभिन्न फीडबैक उत्पाद प्रदान करके दैनिक आधार पर सरकार की विभिन्न पहलों, नीतियों और कार्यक्रमों पर जनता की धारणा से सरकार को अवगत

कराती है। रीजनल मीडिया डाइजेस्ट देशभर के 35 क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से फीडबैक एकत्र करके तैयार किया जाता है, जिसमें 19 भाषाओं में लगभग 400 समाचार-पत्रों की स्क्रीनिंग की जाती है। 1 अप्रैल, 2022 से 20 मार्च, 2023 तक लगभग 700 मीडिया डाइजेस्ट और 24 से अधिक विशेष डाइजेस्ट भेजे गए।

iii. प्रत्यायन प्रणाली

नई दिल्ली में पीआईबी मुख्यालय में विदेशी मीडिया के सदस्यों सहित मीडिया प्रतिनिधियों को प्रेस मान्यता प्रदान की जाती है। प्रेस प्रत्यायन की ऑनलाइन प्रणाली वर्ष 2010 में परिचालित की गई थी जिसे प्रत्यायन के लिए अनुरोधों की बढ़ती संख्या के साथ लगातार अद्यतन किया जाता है। 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के लिए, दिल्ली/एनसीआर में रहने वाले पत्रकारों को कुल 2,283 कार्ड जारी किए गए।

iv. पत्रकार कल्याण योजना

पत्रकारों को गंभीर बीमारियों और उनकी मृत्यु के कारण गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना पीआईबी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसके तहत तत्काल आधार पर एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। 5 लाख रुपये तक की यह सहायता राशि मृतक पत्रकार के परिवार को या उसे उसकी स्थायी विकलांगता के मामले में दी जाती है। कैंसर, गुर्दे का काम करना बंद करने, हृदय रोग आदि जैसी बड़ी बीमारियों के मामले में पत्रकारों को 03 लाख रुपये तक की सहायता और अस्पताल में भर्ती होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में 02 लाख रुपये दिए जाते हैं। वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों को पीआईबी द्वारा विचार के लिए पत्रकार कल्याण योजना समिति के समक्ष रखा जाता है। 1 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि तक, इस योजना के तहत 34 पत्रकारों/परिवारों को 1.49 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। इसके अलावा, 32 लाख रुपये की सहायता राशि की मांग करने वाले 08 आवेदन समिति द्वारा भुगतान अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन हैं।

v. 2022-23 के दौरान पीआईबी द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां

(क) भारत का अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव

पत्र सूचना कार्यालय, उस टीम का हिस्सा था, जिसने गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (इफ्फी-2022) स्थल पर मीडिया सेंटर में मीडिया मान्यता, सुविधाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित कामकाज संभाला। समारोह के दौरान गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न हैः

- पीआईबी द्वारा 744 प्रयायन प्राप्त किए गए आईएफएफआई मीडिया को स्थापित किया गया।
- मीडिया प्रत्यायनः समारोह को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली लागू की गई थी और डीजी (पश्चिम क्षेत्र), पीआईबी मुंबई द्वारा कुल 744 प्रत्यायन प्रदान किए गए थे।
- पीआईबी ने देशभर के 28 वरिष्ठ फ़िल्म और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ें पत्रकारों को शामिल करते हुए एक प्रेस टूर का आयोजन किया ताकि उन्हें उद्घाटन समारोह और समारोह के अन्य पहलुओं को कवर करने में मदद मिल सके।
- सार्वजनिक संचारः आईएफएफआई-2022 के लिए अकेले अंग्रेजी में रिकॉर्ड 163 मल्टी मीडिया रिलीज जारी किए गए। पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी अपनी-अपनी भाषाओं में विज्ञप्तियां जारी कीं।
- मीडिया फीडबैकः दैनिक मीडिया फीडबैक के माध्यम से क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से प्राप्त 1,200 से अधिक क्लिपिंग्स को पीआईबी द्वारा साझा किया गया।

सोशल मीडिया सेल ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इफ्फी53 को व्यापक दृश्यता प्रदान की है। जानकारी फैलाने के लिए पीआईबी के ट्वीट और पोस्ट कई व्यक्तियों और संगठनों द्वारा साझा किए गए थे। #IFFI53, #IFFIAwards, #IFFILOID और #IFFI ऐसे हैशटैग हैं जिनका इस्तेमाल इफ्फी53 से संबंधित पोस्ट के साथ सोशल मीडिया पर किया गया।

(ख) 76वां स्वतंत्रता दिवस

प्रधानमंत्री के भाषण को कई भारतीय भाषाओं में लिप्यांतरित और अनुवादित किया गया था। पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया

गया। विशेष ग्राफिक्स बनाए गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए। पूर्व-प्रचार के लिए एक प्रोमो वीडियो के अलावा पीआईबी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। प्रधानमंत्री के भाषण की तस्वीरों और वीडियो बाइट्स का लाइव ट्वीट भी किया गया।

(ग) अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

पीआईबी मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों ने आठवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग के संबंध में प्रासंगिक जानकारी का व्यापक प्रसार किया। पीआईबी मुख्यालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कई प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं, जिनका कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया और देशभर में अधिकतम प्रसार सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालयों और क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा मीडिया के साथ साझा किया गया। सोशल मीडिया सेल ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को व्यापक दृश्यता प्रदान की।

vi. बजट आवंटन और उपयोगिता

पीआईबी के संबंध में बजट अनुमान/संशोधित अनुमान (2022-23) में निधियों के आवंटन तथा स्थापना व्यय और केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत किए गए व्यय का विवरणः

(राशि करोड़ में)

व्यय की श्रेणी	बजट अनुमान 2022-23	संशोधित अनुमान 2022-23	व्यय (28.02.23 तक)
स्थापना व्यय (श्रेणी i)	107.48	104.06	96.47
केंद्रीय क्षेत्र योजना (श्रेणी ii) उप-योजनाः डीसीआईडी योजना के तहत मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष आयोजनों के लिए प्रचार	9.55	9.55	6.79

vii. 2022-23 के दौरान 'स्वच्छता कार्ययोजना' का कार्यान्वयन

वर्ष 2022-23 के दौरान 'स्वच्छता कार्ययोजना' के कार्यान्वयन के लिए समग्र रूप से पीआईबी को संशो. अनु. - 2022-23 में 37 लाख (संशोधित अनुमान 2022-23 के लिए 40 लाख) रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां की जा रही हैंः -

i) कार्यालय उपकरणों की सफाई और रखरखाव।

ii) पानी के डिस्पेंसर और अन्य वस्तुओं को बदलना।

iii) कोविड-19 की रोकथाम के लिए वस्तुओं जैसे- मास्क/सैनिटाइजर आदि की खरीद।

iv) वेंटिलेशन के लिए निकास पंखे।

v) धूल साफ करने वाले उपकरण जैसे- इलेक्ट्रॉनिक एयर फिल्टर/वैक्यूम क्लीनर आदि।

vi) फर्नीचर, कुर्सी, अलमारी (स्टील) बुक शेल्फ, ऑफिस मिरर इत्यादि।

viii. पीआईबी मुख्यालय में राजभाषा हिन्दी का प्रगतिशील उपयोग

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) और राजभाषा नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के तहत राजभाषा हिन्दी के प्रगतिशील उपयोग की दिशा में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों सहित विभिन्न आदेशों और निर्देशों के पालन और कार्यान्वयन के लिए पत्र सूचना कार्यालय में हर संभव प्रयास किए जाते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) ब्यूरो कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करती है। समिति की त्रैमासिक बैठकें प्रधान महानिदेशक (एम एंड सी) की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। बैठक में विभिन्न मुद्दों जैसे- हिन्दी प्रशिक्षण, प्रेस विज्ञप्ति, हिन्दी के उपयोग के संबंध में क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के निरीक्षण आदि पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा, पीआईबी मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों का दौरा किया जाता है ताकि उन्हें राजभाषा नीति और नियमों से अवगत कराया जा सके और इन कार्यालयों में इसके कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जा सके। पीआईबी की वेबसाइट द्विभाषी रूप में

उपलब्ध है। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति द्वारा समय-समय पर कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है। राजभाषा पर संसद की मुख्य साक्ष्य उपसमिति ने 28 अप्रैल, 2022 को पीआईबी, नई दिल्ली का निरीक्षण किया।

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 से 29 सितंबर, 2022 तक पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) में **हिन्दी पखवाड़ा** का आयोजन किया गया। इस दौरान निबंध लेखन, अनुवाद, नोटिंग एवं प्रारूपण, सामान्य हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता एवं हिन्दी टंकण जैसी विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एमटीएस के लिए हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई।

ix. महिला कल्याण गतिविधियां

यौन उत्पीड़न के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार महिला स्टाफ सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए पीआईबी (मुख्यालय)/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। कार्यस्थलों पर उत्पीड़न को नियम-3सी के तहत सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 में शामिल किया गया है।

x. हिन्दी और उर्दू इकाइयों की गतिविधियां

हिन्दी और उर्दू इकाइयों की मुख्य गतिविधियों में दैनिक प्रेस राउंडअप की तैयारी शामिल है जिसमें हेडलाइंस और हिन्दी/उर्दू दैनिक समाचार-पत्रों के संपादकीय का अंग्रेजी अनुवाद, प्रेस विज्ञप्तियों, फ़ीचर, पृष्ठभूमि और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के भाषण का हिन्दी/उर्दू अनुवाद और मैनुअल तथा बुकलेट आदि का अनुवाद तथा पुनरीक्षण शामिल है। हिन्दी और उर्दू दोनों इकाइयों ने 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक की अवधि के लिए हिन्दी और उर्दू में 16,639 प्रेस विज्ञप्तियां, पृष्ठभूमि और लेख जारी किए हैं।

अनुसंधान इकाई

पीआईबी के तत्वावधान में कार्यरत अनुसंधान इकाई (आरयू) सबसे नया डिवीजन है। यह बदलते परिदृश्यों और आवश्यकताओं के आधार पर राष्ट्रीय महत्व और प्रासंगिकता के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक रूप से किए गए शोध के दस्तावेजों की एक शृंखला बनाकर प्रभावी संचार और जनता तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। पृष्ठभूमि, व्याख्याकार, तथ्य पत्रक, एफएक्यू और फ़ीचर के रूप में ये दस्तावेज नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए क्षेत्र विशेष के साथ-साथ संबंधित विषय क्षेत्र के बारे में समग्र अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

निर्मित दस्तावेज (जनवरी, 2022 से - दिसंबर, 2022 तक)

क्र. सं.	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेजों की सं.
1.	व्याख्याकार	158
2.	तथ्य पत्रक	205
3.	पूछे जाने वाले प्रश्न	31
4.	फ़ीचर	12
5.	हिन्दी दस्तावेज	90
कुल		**496**

इकाई द्वारा **राज्य-विशिष्ट दस्तावेज** भी तैयार किए जा रहे हैं जो विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र/प्रायोजित योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं। इन दस्तावेजों को क्षेत्रीय एडीजी/डीजी के साथ उनके संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय मीडिया के प्रसार के लिए आगे साझा किया जाता है।

अनुसंधान इकाई ने भारत की **जी20 अध्यक्षता** और **अमृत यात्राः आज़ादी से अब तक** पर दो पॉडकास्ट शृंखलाएं भी शुरू की हैं।

फोटो डिवीजन

फोटो डिवीजन को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार की विभिन्न गतिविधियों के फोटो कवरेज के माध्यम से दृश्यता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। अक्टूबर, 1959 में स्थापित, यह देश का शायद एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके पास स्वतंत्रता-पूर्व युग से लेकर आज तक डिजिटल प्रारूप में संरक्षित लगभग 10 लाख नेगेटिव/ट्रांसपेरैंसी का समृद्ध भंडार है।

उत्पादन के आंकड़े

कवर किए गए असाइनमेंट की संख्या, प्राप्त की गई छवियां,

अपलोड किए गए प्रिंट, तैयार किए गए एलबमः

1.	कवर किए गए समाचार और फ़ीचर	3,158
2.	पीआईबी की वेबसाइट पर भेजे/अपलोड किए गए चित्र	25,742/6,540
3.	फोटो डिवीजन की वेबसाइट पर अपलोड किए गए चित्र	7,081
4.	इनहाउस अधिगृहीत डिजिटल छवियां	4,41,840
5.	डिजिटल प्रिंट बनाए गए/आपूर्ति किए गए	6,680
6.	तैयार किए गए वीवीआईपी फोटो एलबम	4

न्यू मीडिया विंग

सोशल मीडिया नागरिकों के बीच विविध अंतःक्रियाओं का एक प्रभावी साधन बन गया है। अपनी संवादात्मक प्रकृति के कारण, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नागरिकों को जानकारी प्रदान करने और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनके साथ सरकार के जुड़ाव को कुशल बनाया गया है। मंत्रालय का न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) बड़े पैमाने पर सरकार और जनता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करके इन संवादों को सक्षम कर रहा है।

क) ट्विटर हैंडल @COVIDNewsByMIB,

न्यू मीडिया विंग व्यापक स्तर पर आम जन को केंद्रित करते हुए सोशल मीडिया के प्रत्येक उपयोगकर्ता तक सूचना उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।

मंत्रालय का ट्विटर हैंडल @MIB_India प्रति माह 2.2 मिलियन इंप्रेशन प्राप्त करता है और यू-ट्यूब चैनल को प्रति माह 341.8 हजार से अधिक बार देखा जाता है। मंत्रालय के फेसबुक पेज पर पोस्ट की गई सामग्री प्रति माह 57,324 से अधिक इंप्रेशन तक पहुंच गई है। सार्वजनिक ऐप पर @mib_india को प्रति माह लगभग 85.2 मिलियन व्यूज मिलते हैं।

न्यू मीडिया विंग सोशल मीडिया के नए-नए तरीकों जैसे इंस्टाग्राम रील्स और मीमस के ज़रिए प्रभावशाली और आकर्षक मैसेज का बेहतर उपयोग करते हुए लोगों में व्यापक समझ पैदा करने का प्रयास कर रहा है।

न्यू मीडिया विंग में वॉइस ऑवरस (टेक्स टू स्पिच) को विडियो पैकेज के ज़रिए हिन्दी और इंग्लिश भाषाओं में उभरती हुई तकनीक जैसे आर्ट्रिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी बेहतर तरीके से कर रहा है।

ख) सोशल मीडिया संवाद

न्यू मीडिया विंग टॉकथॉन, #FaceToFace, फेसबुक लाइव, ट्विटर लाइव आदि जैसे विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न सोशल मीडिया संवादों का आयोजन करता है। इसने आम जनता के साथ मंत्रियों और निर्णय लेने वालों के बीच बातचीत के लिए एक मंच प्रदान किया है।

मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल से संबंधित आंकड़े :

प्लेटफार्म	हैंडल	ग्राहक / फॉलोअर्स
ट्विटर (अंग्रेजी)	@MIB_India	1.7M
ट्विटर (हिन्दी)	@MIB_Hindi	127.3K
फेसबुक	@inbministry	1.48M
इंस्टाग्राम	@MIB_India	363K
यू-ट्यूब	@inbministry	210K
पब्लिक ऐप्प	@MIB_India	990.1K

ग) घटनाओं और कार्यक्रमों का कवरेज

न्यू मीडिया विंग, भारत सरकार के कई कार्यक्रमों और कार्यक्रमों के प्रचार तथा सूचना प्रसार के लिए मंत्रालय के सोशल मीडिया माध्यम का लाभ उठाने में सक्षम रहा है। विंग ने सरकार के विभिन्न सोशल मीडिया अभियानों जैसे- आज़ादी का अमृत महोत्सव, पोषण सप्ताह, स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नारी शक्ति, इफ्फी 53, पद्म पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार और कोविड-19 पीढ़ी में जागरूकता में सहयोग दिया है।

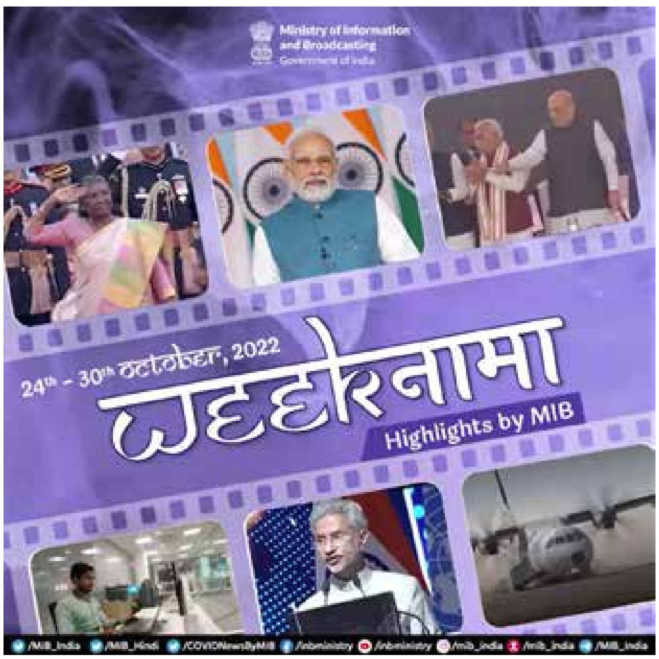

सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सोशल मीडिया पर प्रचार, 76वां इन्फैन्ट्री दिवस, रोज़गार मेला, पुलिस स्मृति दिवस और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम जैसे- गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और मन की बात आदि को न्यू मीडिया विंग द्वारा नियमित आधार पर कवर किया जाता है। विंग अपनी सोशल मीडिया टीम द्वारा बनाए गए ग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से कैबिनेट ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस विज्ञप्ति को सोशल मीडिया कवरेज और प्रचार भी प्रदान करता है।

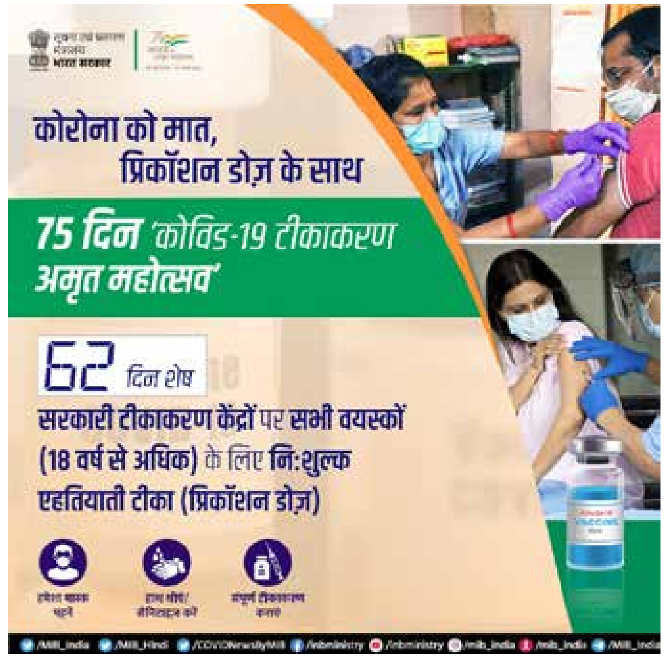

न्यू मीडिया विंग द्वारा अपनी सोशल मीडिया पहुंच को और बढ़ाने के लिए किए गए कुछ अभिनव उपायों में शामिल हैं:

- **महत्वपूर्ण दिन और मीम-आधारित ग्राफिक्स** के उपयोग में वृद्धि।
- **दिखने में आकर्षक सामग्री जैसे- इंस्टाग्राम रील्स** और एआई-निर्मित वीडियो।
- टियर-3, टियर-4 शहरों और छोटे शहरों में भी नागरिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए **पब्लिक ऐप** सहित सभी प्लेटफार्मों पर पोस्ट की गई **हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं** में सामग्री का उपयोग बढ़ाना।

संवाद एकीकृत डैशबोर्ड - सोशल मीडिया फीडबैक टूल

निर्णय लेने के लिए मीडिया व्यूज का सिस्टेमिक एसिमिलेशन (संवाद) इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड 15 मार्च, 2020 को लॉन्च किया गया था। मीडिया में प्रकाशित विचारों/राय को एकीकृत डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाता है और साथ ही संबंधित हितधारकों को भेजा जाता है।

BUREAU OF OUTREACH & COMMUNICATION

केंद्रीय संचार ब्यूरो

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) जिसे पहले लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के रूप में जाना जाता था, का गठन 2017 में तात्कालीन विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) और गीत और नाटक प्रभाग (एसएंडडीडी) के एकीकरण द्वारा किया गया था। **सीबीसी का उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/ स्वायत्त निकायों को 360 डिग्री संचार समाधान प्रदान करना है।** 23 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और 148 फील्ड कार्यालयों (एफओ) के साथ, सीबीसी ग्रामीण और शहरी लोगों को विकासात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी हासिल करने के लिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचित करने में लगा हुआ है। यह ब्यूरो द्वारा संचार के विभिन्न साधनों-प्रिंट मीडिया, ऑडियो-विजुअल, प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार, आउटडोर, न्यू मीडिया आदि का उपयोग करके सुनिश्चित किया जाता है।

सीबीसी को भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीसी का **विज्ञापन और दृश्य संचार प्रभाग** भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तथा स्वायत्त निकायों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी के प्रसार में लगा हुआ है।

सीबीसी का लोक संचार प्रभाग नाटक, नृत्य-नाटक, समग्र-कार्यक्रम, कठपुतली, बैले, ओपेरा, लोक तथा पारंपरिक गायन और अन्य स्थानीय लोक और पारंपरिक रूपों जैसी प्रदर्शन कलाओं की विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करके लाइव मीडिया के माध्यम से अंतः वैयक्तिक संचार करता है। मुख्य कार्य जागरूकता पैदा करना और अपनत्व तथा स्वामित्व की भावना के साथ भावनात्मक ग्रहणशीलता सुनिश्चित करना है।

फील्ड कम्युनिकेशन डिवीजन जनता के बीच, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्यक्ष और पारस्परिक संचार कार्यक्रम चलाता है। यह एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी) के रूप में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ग्राउंड एक्टिवेशन और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है।

भारत के तत्कालीन माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 01.04.2022 को एनटीआर स्टेडियम, हैदराबाद में 'आजादी का अमृत महोत्सव - तेलंगाना के स्वतंत्रता सेनानियों' पर केंद्रित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए।

सीबीसी स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सतत विकास, पोषण, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, मतदाता भागीदारी आदि जैसे कई क्षेत्रों में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने में सहायक रहा है।

महत्वपूर्ण गतिविधियां:

आज़ादी का अमृत महोत्सव/हर घर तिरंगा अभियान

- आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह और हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में, सीबीसी ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाते हुए अगस्त के महीने के दौरान फोटो प्रदर्शनियों, आईसीओपी, जागृति रैलियों, वेबिनार और रेडियो वार्ताओं का आयोजन किया।

- आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सूचना भवन में एक बड़ी मल्टी-मीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में पिछले 8 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा की गई विकासात्मक गतिविधियों का विवरण प्रदर्शित किया गया।

- सीबीसी के फील्ड प्रदर्शनी विंग ने मेरठ के प्रसिद्ध नौचंदी मेला, में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया।

- सीबीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ), फील्ड कार्यालयों (एफओ) ने 169 आईसीओपी, 22 प्रदर्शनियों, 11 रैलियों, 02 वेबिनार और 45 फील्ड कार्यक्रमों का आयोजन किया।

आठ वर्षों में सरकार की पहल और उपलब्धियों पर अभियान

केंद्र सरकार के आठ साल पूरे होने पर, सीबीसी ने लोगों के कल्याण के लिए सरकार की पहल और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए 30 मई, 2022 से एक मल्टीमीडिया अभियान शुरू किया। 'आठ साल सेवा, सुशासन और ग़रीब कल्याण' विषय पर आउटडोर क्रिएटिव भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रेलवे, हवाईअड्डों, डाकघरों के साथ पूरे भारत में प्रदर्शित करने के लिए साझा किए गए थे। अभियान की बेहतर पहुंच के लिए क्रिएटिव को विभिन्न सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया गया।

हिन्दी और अंग्रेजी में पॉकेट बुकलेट, लॉन्ग बुक और डॉकेट (सरकारों की विभिन्न योजनाओं पर विवरण वाले 14 फ्लायर्स) सीबीसी के क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से देशभर में मुद्रित और वितरित किए गए थे। माह के दौरान लोक संचार विंग ने '8 साल सेवा, सुशासन और ग़रीब कल्याण' तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सहित विभिन्न विषयों कार्यक्रम आयोजित किए।

विकसित भारत अभियान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2022 को अपने स्वतंत्रता दिवस के सम्बोधन में 'विकसित भारत' के निर्माण पर

जोर दिया और इस परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री की इस परिकल्पना के आधार पर, सीबीसी ने सितंबर, 2022 में 'विकसित भारत' अभियान शुरू किया। 'जय अनुसंधान', 'अंत्योदय' तथा 'पुरानी सोच से मुक्ति', 'सभी के लिए स्वास्थ्य', 'हमारी विरासत हमारा गौरव' और 'विकसित भारत के लिए बड़ा संकल्प' जैसे विषय शामिल थे। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं पर प्रकाश डालने वाली रचनाओं का उपयोग करते हुए आठ विषयों पर पूरे भारत में एक महीने के लिए एक आउटडोर अभियान भी चलाया गया।

सामूहिक सामर्थ्य से रचा इतिहास अभियान

100 वर्षों में सबसे बड़ी महामारी से लड़ते हुए, राष्ट्र ने 17.07.2022 को 200 करोड़ टीकाकरण का मील का पत्थर पार करके एक और इतिहास रचा। टीकाकरण के महत्व को और प्रचारित करने तथा लोगों को बूस्टर खुराक़ के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सीबीसी ने इस विषय पर व्यापक अभियान चलाया। नई दिल्ली के मुख्य चौराहों, केंद्र सरकार के कार्यालयों, आवासीय परिसरों, अस्पतालों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर 'सामूहिक सामर्थ्य से रचा इतिहास' विषय पर होर्डिंग्स/बैनर प्रदर्शित किए गए।

सीबीसी के क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों ने '200 करोड़ कोविड टीकाकरण/कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव' की थीम पर 4,000 से अधिक होर्डिंग/बैनर/पोस्टर प्रदर्शित किए। 200 करोड़ के टीकाकरण के सफल समापन पर सीबीसी और व्हाट्सऐप समूहों के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार किया गया था, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सहयोगी मीडिया इकाइयों के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा आगे बढ़ाया गया था।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम की फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए।

काशी तमिल संगमम

काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक अनूठी पहल थी, जो वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को उजागर करती है। काशी तमिल संगमम के हिस्से के रूप में, सीबीसी ने एक डिजिटल मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता आंदोलन में तमिलनाडु के बड़े नेताओं और गुमनाम नायकों जैसे विभिन्न विषयों को दर्शाया गया। संगीत, कला, नृत्य, सिनेमा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काशी और तमिलनाडु के बीच समृद्ध सांस्कृतिक/ऐतिहासिक संबंधों की व्याख्या करने वाले घटक भी थे।

इफ्फी, गोवा में स्वतंत्रता आंदोलन और सिनेमा की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी

सीबीसी ने 21 से 28 नवंबर, 2022 तक भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, आईएफएफआई के स्थल से सटे कैंपल फुटबॉल ग्राउंड, पणजी, गोवा में 'स्वतंत्रता आंदोलन और सिनेमा' नामक एक मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का विषय आज़ादी का अमृत महोत्सव के व्यापक विषय के तहत 'भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और सिनेमा' संकल्पित किया गया था, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में फ़िल्मों और सिनेमाई सामग्री की भूमिका के बारे में जनता, विशेष रूप से फ़िल्म प्रेमियों के बीच जागरूकता पैदा करता है।

आठ दिवसीय प्रदर्शनी में सिनेमा में स्वतंत्रता आंदोलन के चित्रण को दिखाने वाली फ़िल्म क्लिप सहित कई मल्टीमीडिया घटकों का उपयोग करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी दिखाई गई।

पुरी रथ यात्रा

भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान, ग्रांड रोड,

पुरी में 09 दिनों की अवधि (01-09 जुलाई, 2022 तक) के लिए 'सेवा, सुशासन और ग़रीब कल्याण तथा आज़ादी का अमृत महोत्सव के आठ साल' पर एक बड़े आईसीओपी का आयोजन किया गया था।

स्वतंत्रता दिवस प्रिंट अभियान

सीबीसी ने देशभर के प्रमुख समाचार-पत्रों और चयनित पत्रिकाओं में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आधे पृष्ठ का रंगीन तथा क्वाटर पृष्ठ का श्वेत-श्याम विज्ञापन जारी किया।

पीएम मेमेंटोस ई-नीलामी पर अभियान

लोगों को 'पीएम मेमेंटोस ई-नीलामी' के बारे में जागरूक करने के लिए, सीबीसी ने संस्कृति मंत्रालय की ओर से सितंबर, 2022 को विज्ञापन जारी किए।

चीता इवेंट पर अभियान

नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में आठ चीतों के आगमन के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए, सीबीसी ने पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से 17.09.2022 को विज्ञापन जारी किया।

हॉर्नबिल फेस्टिवल, 2022

सीबीसी कोहिमा ने इस साल उत्सव में शामिल होकर, आज़ादी का अमृत महोत्सव और सेवा, सुशासन तथा ग़रीब कल्याण के 8 साल की थीम पर 10 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में उत्तर-पूर्व के लिए विशेष प्रासंगिकता के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तियों को दिया गया तथा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आठ वर्षों के रचनात्मक कार्यों पर प्रकाश डाया गया।

मणिपुर संगाई महोत्सव, 2022

सीबीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, इंफाल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव, विज़न @2047 जी20 की भारत की अध्यक्षता, सुशासन आदि जैसे विभिन्न विषयों को कवर करते हुए उत्सव में भाग लिया।

पुष्कर मेला

प्रदर्शनी का विषय अमृत यात्रा - कर्तव्य पथ की ओर (India@2047) था। एलईडी पैनल, आभासी वास्तविकता, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी और 360 डिग्री वीडियो का उपयोग भविष्य में भारत को दिखाने के लिए किया गया था।

सोनपुर महोत्सव

सीबीसी पटना ने 13.11.2022 से 07.12.2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव, विज़न @ 2047, सुशासन आदि जैसे विभिन्न विषयों को कवर करते हुए प्रसिद्ध पशु मेला/सोनपुर महोत्सव में भाग लिया।

बाली यात्रा

सीबीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर ने कटक में ऐतिहासिक बाली यात्रा में दिनांक 08-16 नवंबर, 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव और सेवा, सुशासन तथा ग़रीब कल्याण पर प्रदर्शनी लगाई।

कैलेंडर, 2023

भारत सरकार के फिजिकल कैलेंडर को दो साल के अंतराल के बाद केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 28.12.2022 को लॉन्च किया। यह 'नया वर्ष, नए संकल्प' के थीम वाला कैलेंडर था।

न्यू इंडिया समाचार

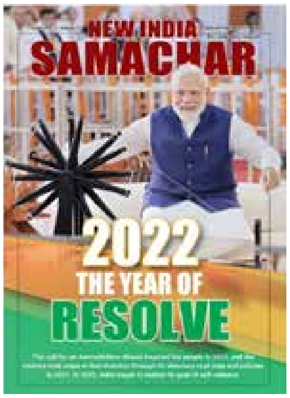

भारत सरकार की पहलों और योजनाओं की जानकारी का प्रसार करने के लिए अगस्त, 2020 में सीबीसी द्वारा 'न्यू इंडिया समाचार' शीर्षक से एक पाक्षिक शुरू किया गया था। 'न्यू इंडिया समाचार' आम लोगों के लाभ के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में सही जानकारी प्रदान करने का एक प्रयास है। यह पाक्षिक 13 भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है।

कोविड-19 जागरूकता अभियान

इस अवधि के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने कोविड-19 ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए वेबिनार आयोजित किए। साथ ही टेलीफोनिक्स सेल्फ तथा एसएमएस के ज़रिए भी लोगों को जागरूक किया।

एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी)

जनवरी, 2022 से दिसंबर, 2022 के दौरान, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और फील्ड कार्यालयों ने 1,231 आईसीओपी, 35 प्रदर्शनियों, 92 वेबिनार्स, 62 विशेष आउटरीच कार्यक्रमों, 572 फील्ड कार्यक्रमों, 19 रेडियो वार्ताओं का आयोजन किया और भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अलावा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) और टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार किया।

की गई टेलीफोन कॉलों की कुल संख्या	भेजे गए एसएमएस की कुल संख्या	फेसबुक पोस्ट की कुल संख्या	ट्वीट्स और री ट्वीट्स की कुल संख्या (इंप्रेशनश् के साथ)	व्हाट्सएप् पर प्रसारित पोस्टरों/संदेश/वीडियो की कुल संख्या	इंस्टाग्राम पोस्ट की कुल संख्या	वेबिनार की कुल संख्या	आयोजित आईसीओ-पीएफ की संख्या	आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रम की कुल संख्या
9,403	5,154	14,231	25,170 (6,71,019)	13,135	4,972	15	123	84

सांख्यिकीय डेटा (अप्रैल से दिसंबर, 2022 तक उपलब्धियां)

1.	आईसीओपी की कुल संख्या	1,231
2.	विशेष आउटरीच कार्यक्रमों की कुल संख्या	62
3.	प्रदर्शनियों की कुल संख्या	35
4.	अन्य कार्यक्रमों की कुल संख्या	572
5.	वेबिनार की कुल संख्या	92
6.	रेडियो वार्ताओं की कुल संख्या	19
7.	योग सत्रों की कुल संख्या	42

भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक (आरएनआई)

भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय- आरएनआई की स्थापना 1 जुलाई, 1956 में प्रथम प्रेस आयोग की 1953 की सिफ़ारिश के आधार पर प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 में संशोधन करके की गई थी। आरएनआई सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है और यह विधायी तथा ग़ैर-विधायी दायित्वों का निर्वहन करता है।

कार्य

आरएनआई भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों और प्रकाशनों की पंजिका रखता है, समाचार-पत्रों और प्रकाशनों को पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करता है, समाचार-पत्रों और प्रकाशनों के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत प्रसार संख्या पर वार्षिक विवरणों की जांच और विश्लेषण करता है। आरएनआई हर साल 31 दिसंबर तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय को **'प्रेस इन इंडिया'** शीर्षक से देश में प्रिंट मीडिया परिदृश्य पर एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है।

अपने गैर-सांविधिक कार्यों के तहत, आरएनआई के साथ पंजीकृत वास्तविक उपयोगकर्ता प्रकाशनों के अख़बारी कागज़ के आयात के लिए स्व-घोषणा प्रमाण-पत्रों को प्रमाणित करता है। कार्यालय प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर या विशिष्ट शिकायतों और अपीलों या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर, पीआईबी के नामित अधिकारियों के माध्यम से, पंजीकृत प्रकाशनों की प्रसार संख्या का सत्यापन भी करता है।

शीर्षक सत्यापन

अप्रैल, 2022 से दिसंबर, 2022 की अवधि में आरएनआई ने शीर्षकों के सत्यापन के 10,509 आवेदनों की जांच की जिनमें से 2,842 शीर्षकों को स्वीकृति दी गई। इन सभी स्वीकृत शीर्षकों

की सूची आरएनआई की वेबसाइट www.rni.nic.in पर उपलब्ध है। शीर्षक सत्यापन स्थिति पत्र भी आरएनआई की वेबसाइट पर है जिसे आवेदक डाउनलोड कर सकते हैं।

शीर्षकों पर से रोक हटाई गई

अप्रैल, 2022 से दिसंबर, 2022 के बीच 3,046 शीर्षकों पर से रोक हटा ली गई जिनकी आवेदक चाहें तो स्वयं पुष्टि कर सकते हैं।

प्रकाशनों का पंजीकरण

31 मार्च, 2022 को पंजीकृत कुल प्रकाशनों की संख्या 1,46,045 थी जिनमें 20,821 दैनिक समाचार-पत्र और 1,25,224 अन्य पत्रिकाएं हैं। 1 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि में 1,698 (नए और संशोधित) प्रकाशन पंजीकृत किए गए हैं। आरएनआई की पंजिका में भी इस आशय की प्रविष्टि की जाती है। सभी पंजीकृत समाचार-पत्रों और प्रकाशनों का विवरण भी आरएनआई की वेबसाइट www.rni.nic.in उपलब्ध है।

वार्षिक विवरण

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19डी के अनुसार प्रकाशक को अपना वार्षिक विवरण हर वर्ष 31 मई को या उससे पहले प्रेस पंजीयक को समाचार-पत्र पंजीकरण (केंद्रीय) नियम, 1956 में निर्दिष्ट फॉर्म 2 में भरकर सौंपना अनिवार्य है। प्रकाशकों को हर वर्ष फरवरी के अंतिम दिन के बाद के पहले प्रकाशन में फॉर्म IV में अपने प्रकाशन के स्वामित्व के बारे में पूरा विवरण छापना होगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31.12.2022 तक 34,148 प्रकाशनों की ओर से वार्षिक विवरण भरा गया है। वार्षिक विवरण ऑनलाइन भेजने की 2013-14 में शुरू की गई व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू की जा रही है।

'प्रेस इन इंडिया' रिपोर्ट का प्रकाशन

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19 (जी) के अनुसार, प्रेस रजिस्ट्रार केंद्र सरकार को हर साल 31 दिसंबर तक 'प्रेस इन इंडिया' शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आरएनआई प्रकाशकों द्वारा दायर वार्षिक विवरण के आधार पर देश में प्रिंट मीडिया के विकास का विश्लेषण और संकलन करके 'प्रेस इन इंडिया' रिपोर्ट प्रकाशित करता है। 2013-14 से इसे भी डिजिटल प्रारूप में प्रकाशित किया जा रहा है और यह आरएनआई की वेबसाइटः www.rni.nic.in. पर उपलब्ध है।

प्रसार सत्यापन

आरएनआई, प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोधों या विशिष्ट शिकायतों और अपीलों के आधार पर प्रकाशनों का प्रसार सत्यापन करता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति के अनुसार 01.08.2020 से 25,000 से अधिक प्रतियों के प्रसार का दावा करने वाले प्रकाशनों के लिए भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार कार्यालय (आरएनआई) सर्कुलेशन ऑडिट ब्यूरो (एबीसी) द्वारा प्रसार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया। प्रकाशकों की सुविधा के लिए और निर्बाध तथा मानक प्रसार सत्यापन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देशों के तहत 14.10.2022 को एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई। इसके अलावा, आरएनआई ने प्रसार सत्यापन के लिए 13.10.2022 को सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/सीए फर्मों की एक सूची की घोषणा की है। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों में पीआईबी अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ प्रसार सत्यापन के विभिन्न पहलुओं पर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए विशेष ऑनलाइन संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए हैं।

अख़बारी कागज़

आरएनआई और पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के क्षेत्रीय शाखा कार्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक्जिम नीति के अनुसार वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति के आधार पर अख़बारी कागज़ के आयात के लिए आरएनआई के साथ पंजीकृत प्रकाशनों के स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र को प्रमाणित करते हैं। आरएनआई अब न्यूज़प्रिंट के आयात के मामले में ई-संचित के माध्यम से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के साथ समन्वय में काम कर रहा है और यह प्रक्रिया आरएनआई में स्वचालन परियोजना का हिस्सा है।

प्रकाशन विभाग

राष्ट्रीय महत्व और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं के भंडार, प्रकाशन विभाग की स्थापना 1941 में की गई थी। प्रकाशन विभाग सरकार के ऐसे प्रतिष्ठित विभाग के रूप में उभरकर सामने आया है जो भारत भूमि और यहां के लोगों, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास, कला और इतिहास, जीव-जंतुओं और वनस्पतियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों और भारत के निर्माताओं की जीवनियों तथा संस्कृति, दर्शन, विज्ञान और साहित्य आदि क्षेत्रों की **महान हस्तियों के बारे में श्रेष्ठ पुस्तकें प्रकाशित करके भारत की विरासत को प्रदर्शित** और संरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय ज्ञान संपदा को समृद्ध बना रहा है।

प्रकाशन विभाग भारतीय समाज और पठनीयता पर विशेष ध्यान रखने के साथ राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री के भाषणों, समकालीन विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास और अन्य विविध विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है। इनके अतिरिक्त, विभाग कथात्मक और ग़ैर-कथात्मक बाल साहित्य भी प्रकाशित करता है।

प्रकाशन विभाग गांधी साहित्य का प्रमुख प्रकाशक है। इसने **गांधीवादी विचारों पर अंग्रेजी में 100 खंडों में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (सीडब्ल्यूएमजी) सहित** कई किताबें प्रकाशित की हैं। इस संग्रह को गांधीजी के लेखन का सबसे व्यापक और प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। प्रकाशन विभाग ने गुजरात विद्यापीठ के सहयोग से और गांधीवादी विद्वानों की देखरेख में, महात्मा गांधी के कलेक्टेड वर्क्स (ई-सीडब्ल्यूएमजी) का ई-संस्करण भी तैयार किया है, जो अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए सेट के रूप में पूरी तरह से खोजी जा सकने वाली मास्टर कॉपी है जिसे गांधी हेरिटेज पोर्टल पर भी डाला गया है। प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली के सहयोग से महात्मा गांधी 'डिजिटल युग के लिए गांधी' पर एक व्यापक ई-संकलन पूरा किया।

प्रकाशन विभाग चार मासिक पत्रिकाएं- योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल तथा साप्ताहिक पत्र रोज़गार समाचार प्रकाशित करता है। इन पत्र-पत्रिकाओं में आर्थिक विकास, संस्कृति, बाल साहित्य और रोज़गार से जुड़े अवसरों पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

संगठनात्मक तंत्र

प्रकाशन विभाग के प्रमुख महानिदेशक (डीजी) हैं और अपर महानिदेशक तथा संपादकीय, व्यवसाय, उत्पादन तथा प्रशासन प्रभागों और रोज़गार समाचार के निदेशक स्तर के अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। इसका मुख्यालय सूचना भवन, नई दिल्ली में और बिक्री इम्पोरिया नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में हैं तथा क्षेत्रीय योजना कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम तथा बेंगलुरु में हैं।

विशेषताएं और उपलब्धियां

- प्रकाशन विभाग ने अपनी प्रतिष्ठित राष्ट्रपति भवन श्रृंखला के अंतर्गत तीन नए शीर्षक प्रकाशित किए हैं। **ये किताबें- मूड्स, मोमेंट्स एंड मेमोरीज- फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया (1950-2017) - ए विजुअल हिस्ट्री; प्रथम नागरिक- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के कार्यकाल का सचित्र रिकॉड और इंटरप्रेटिंग जीओमेट्रिस-फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन को राष्ट्रपति भवन** में आयोजित समारोह में 24.07.2022 को जारी किया गया। समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय पूर्व राष्ट्रपति

श्री राम नाथ कोविंद और माननीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित थे।

- **"सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास"** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के चयनित भाषणों के संग्रह का अनावरण माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ दिनांक 23.09.2022 को प्रकाशन विभाग द्वारा आयोजित समारोह में किया।

यह पुस्तक विभिन्न विषयों पर मई, 2019 से मई, 2020 तक माननीय प्रधानमंत्री के 86 भाषणों पर केंद्रित है। दस विषयगत क्षेत्रों में विभाजित, ये भाषण 'नये भारत' के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ये खंड हैं– आत्मनिर्भर भारत, अर्थव्यवस्था, पीपुल-फर्स्ट गवर्नेंस, फाइट अगेंस्ट कोविड-19, इमर्जिंग इंडियाः फॉरेन अफेयर्स, जय किसान, टेक इंडिया, न्यू इंडिया, ग्रीन इंडिया, रीज़िलिएंट इंडिया, क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, एफिशिएंट इंडिया, इटर्नल इंडिया, मॉडर्न इंडियाः कल्चर हेरिटेज और मन की बात।

- प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित **गुरु तेग बहादुरः हिज लाइफ, ट्रेवल्स एंड मैसेज** नामक पुस्तक का विमोचन 25.05.2022 को पंजाबी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अरविंद द्वारा पटियाला में किया गया।

- प्रकाशन विभाग ने **2022** के लिए **पुस्तक प्रकाशन उत्कृष्ट हेतु नौ पुरस्कार जीते**। ये पुरस्कार फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा नई दिल्ली में एक समारोह में दिए गए।

- प्रकाशन विभाग को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 26वें दिल्ली पुस्तक मेले, 2022 में, **उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक** प्रदान किया गया।

23 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' (प्रधानमंत्री के भाषण) शीर्षक पुस्तक का विमोचन करते हुए। इस अवसर पर केरल के राज्यपाल श्री आरिफ़ मोहम्मद खान और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित थे।

26वें दिल्ली पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग की अपर महानिदेशक श्रीमती शुभा गुप्ता उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार ग्रहण करती हुई।

- प्रकाशन विभाग ने **लोक संपर्क और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण** पहल के रूप में जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में एक मीडिया और प्रकाशन सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन 26 सितंबर, 2022 को कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से, विश्वविद्यालय परिसर में गांधी भवन में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो. नीलोफर खान थे। सम्मेलन में प्रशासकों, भाषाविदों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों सहित प्रख्यात वक्ताओं और प्रकाशन विभाग के अधिकारियों के साथ क्षेत्र के पीआईबी, सीबीसी तथा एआईआर के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सीबीसी जम्मू-कश्मीर, जनसंपर्क केंद्र और कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रकाशन विभाग द्वारा एक पुस्तक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी।

- प्रकाशन विभाग ने 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया' शीर्षक पर पुस्तक चर्चा कार्यक्रम भी आयोजित किया। यह पुस्तक प्रसिद्ध लेखक, अनुभवी पत्रकार और असम सरकार के सूचना आयुक्त श्री समुद्र गुप्ता कश्यप द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव शृंखला के तहत लिखी गई है और प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है। लेखक ने पुस्तक के बारे में विस्तार से चर्चा की।

- प्रकाशन विभाग ने अपने सम्मानित लेखकों के साथ जुड़ने के लिए एक आउटरीच गतिविधि के रूप में, 'ऑथर्स कनेक्ट' की शुरुआत की, जो सामयिक मुद्दों पर हमारी पत्रिकाओं और पुस्तकों के लेखों के साथ जुड़ने का एक मंच है। शृंखला का पहला सत्र फरवरी 2023 में 'मोटा अनाज' विषय पर आयोजित किया गया था क्योंकि 'योजना' पत्रिका का जनवरी 2023 अंक इसी विषय पर आधारित था। दूसरा सत्र नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 के दौरान 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' विषय पर आयोजित किया गया था, जिसमें प्रसिद्ध गांधीवादी डॉ. वर्षा दास और लेखक श्री राजेंद्र भट्ट ने प्रकाशन विभाग के साथ अपने कार्यों पर विस्तार से चर्चा की।

प्रमुख गतिविधियां

पुस्तकों का प्रकाशन

वर्ष 2022-23 में प्रकाशन विभाग ने 331 पुस्तकें प्रकाशित कीं। इनमें से 95 अंग्रेजी में, 181 हिन्दी में और 55 क्षेत्रीय भाषाओं में थीं। कुछ प्रमुख पुस्तकें हैः सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, (माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का संग्रह); प्रकाशन विभाग की राष्ट्रपति भवन शृंखला के तहत तीन पुस्तकें- (i) मूड्स, मोमेंट्स एंड मेमोरीज - फॉर्मर प्रेज़ीडेंट ऑफ इंडिया (1950-2017) - ए विजुअल हिस्ट्री (ii) प्रथम नागरिक- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद

के कार्यकाल का सचित्र रिकॉर्ड और (iii) इंटरप्रेटिंग जीओमिट्रिस – फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन; भारत के राष्ट्रपति के चौथे वर्ष में दिए गए चुनिंदा भाषण– द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम (iv) (अंग्रेजी) और लोकतंत्र के स्वर खंडों में चार अन्य प्रमुख शीर्षकों में शामिल हैं: लाइफ एंड लीजेंड ऑफ भगत सिंह: ए पिक्टोरियल वॉल्यूम; अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया; नेताजी: ए लाइफ इन पिक्चर्स; एनी बेसेंट; पं. भीमसेन जोशी (मराठी); सुब्रमण्यम भारती (तमिल); रानी लक्ष्मीबाई; इंडिया अर्ली हिस्ट्री; लुकिंग अगेन एट इंडियन आर्ट; इंडिया – आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड्स; आवर स्काउट्स एंड गाइड्स और 1857 के भूले बिसरे शहीद (उषा चंद्रा) (गुजराती, तेलुगू, कन्नड़, बंगाली और मराठी भाषाओं में अनुवादित)।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रकाशन विभाग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव शृंखला के तहत आज़ादी के गत 75 वर्षों के दौरान गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पहलुओं और उपलब्धियों के विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन जारी रखा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम और अंडमान, द स्टोरी ऑफ पार्टीशन, द स्टोरी ऑफ रिहैबिलिटेशन (अंग्रेज़ी में) और भारत विभाजन की कहानी, ज़ब्तशुदा गीत और जब्तशुदा तराने (हिन्दी में) प्रकाशित की गईं।

योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल ने कई विशेष लेख, सचित्र कोलाज और स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अभिलेखीय तस्वीरें प्रकाशित कीं।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

साप्ताहिक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार के अलावा विभाग कुल 18 पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है, जिनमें योजना अंग्रेजी, हिन्दी और 11 अन्य भाषाओं में, कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी और हिन्दी में), आजकल (हिन्दी और उर्दू में) और बाल भारती (हिन्दी में) शामिल हैं। ये पत्र-पत्रिकाएं अपनी-अपनी विधाओं के अनुरूप प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन सभी पत्र-पत्रिकाओं में निरंतर अमृत महोत्सव और गांधीजी के जीवन, आदर्शों तथा विचारों पर लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

क) योजना (अंग्रेजी, हिन्दी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में)

1957 से प्रकाशित योजना, आर्थिक विकास से संबंधित विषयों को समर्पित पत्रिका है। इसे 13 भाषाओं यथा- अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू में प्रकाशित किया जाता है।

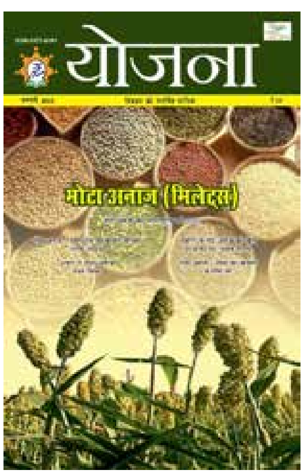

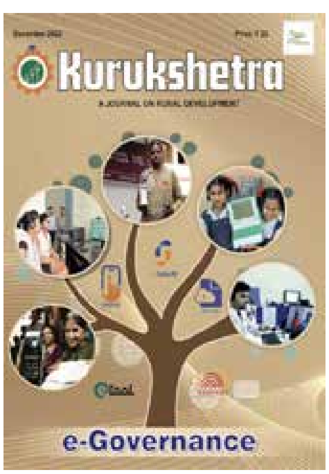

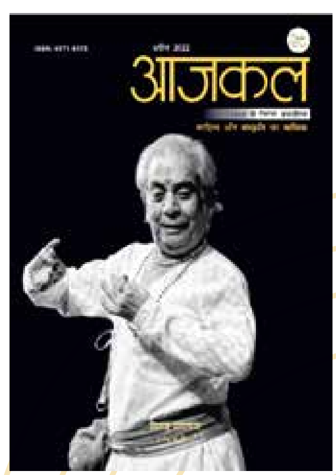

इस वर्ष योजना के कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया जैसे मोटा अनाज के अंतरराष्ट्रीय वर्ष (आईवाईएम 2023) जी-20, केंद्रीय बजट 2023-24, में प्रकाशन विभाग के 'ऑथर्स कनेक्ट' के पहले सत्र में योजना के जनवरी, 2023 के अंक का विषय 'मोटा अनाज' पर चर्चा की गई।

योजना ने 'भारत में आदिवासी', 'जम्मू कश्मीर और लद्दाख', 'साहित्य और आज़ादी', 'फिन टेक', 'आर्किटेक्चर' और 'मिलेट्स' जैसे विषयों पर कुछ संग्रहणीय अन्य अंक भी निकाले हैं।

ख) कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी और हिन्दी)

कुरुक्षेत्र का प्रकाशन 1952 से हो रहा है। वर्तमान में प्रकाशन विभाग अंग्रेजी और हिन्दी में इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। पत्रिका प्रभावी रूप से ग्रामीण विकास के संदेश को जन-जन तक पहुंचाती है। अप्रैल-मार्च, 2023 के दौरान, कुरुक्षेत्र ने 'केंद्रीय बजट' 2023-24 और 'जल संसाधन', भी प्रकाशित किए गए।

सहकारिता, आदिवासियों के जीवन और संस्कृति कृषि उद्यमिता, ई-गवर्नेंस, कृषि पर केन्द्रित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा ग्रामीण संपर्क, ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण उद्योग, महिला सशक्तीकरण जैसे विषय शामिल थे।

ग) आजकल (हिन्दी और उर्दू)

साहित्य, कला और संस्कृति को समर्पित 1945 से नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली आजकल (हिन्दी), एक प्रतिष्ठित मासिक साहित्यिक पत्रिका है। आजकल ने वर्ष के दौरान विभिन्न अंकों में भारतीय संस्कृति और साहित्य के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया। आजकल अपने विभिन्न अंकों में बिरजू महाराज, चंद्रकिशोर जायसवाल, शेखर जोशी, ममता कालिया, मदन वात्स्यायन और रांगेय राघव जैसे साहित्यिक और सांस्कृतिक व्यक्तित्वों पर केंद्रित अंक प्रकाशित किए।

आजकल (उर्दू) का गौरवशाली इतिहास रहा है और इससे जाने-माने लेखक, कवि और पत्रकार जुड़े रहे हैं। इस साहित्यिक पत्रिका में लघु कथाओं, कविताओं या ग़ज़लों के अलावा रोचक लेख भी प्रकाशित किए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और ग़ालिब पर केंद्रित विशेष अंक भी निकाले गए।

घ) बाल भारती (हिन्दी)

बाल भारती बच्चों पर केंद्रित एक मासिक पत्रिका है, जो 1948 से लगातार प्रकाशित हो रही है। यह पत्रिका बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन करने के अलावा ज्ञानवर्द्धक लेख, साक्षात्कार, लघु कथाएं, कविताएं, प्रश्नोत्तरी और चित्रात्मक कहानियों की एक शृंखला के माध्यम से सामाजिक मूल्य प्रदान करने में मदद करती है। इस वर्ष मुख्य फ़ोकस आज़ादी का अमृत महोत्सव पर रहा।

पत्रिका में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के अलावा **बाल भारती** ने 10 नवम्बर को एक स्कूल में दिव्यांग बच्चों के साथ 'स्वच्छता हमारे आस-पास' विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की। पत्रिका द्वारा विभाग में 12 जनवरी को बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। 23 से 28 फरवरी 2023 तक MyGov पर 'कचरा हटाओ-पृथ्वी बचाओ पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और विजेता प्रविष्टियां पत्रिका में प्रकाशित की गईं।

ङ) एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार (अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू)

रोज़गार समाचार

1976 में शुरू किया गया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रमुख रोज़गार समाचार पत्र, अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित होता है। यह केंद्र तथा राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों में नौकरियों के लिए सूचना की एकल खिड़की के रूप में कार्य करता है। यह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, परीक्षा सूचनाओं और यूपीएससी, एसएससी और अन्य भर्ती निकायों जैसे संगठनों के लिए प्रवेश नोटिस और परिणाम भी प्रकाशित करता है।

इसके अलावा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार में एक संपादकीय खंड है जो युवाओं को उनके व्यावसायिक और सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ावा देने के साथ उनके भविष्य के निर्माण और बाज़ार में उपलब्ध विभिन्न नौकरियों की तैयारी में मदद करता है। यह करियर मार्गदर्शन हेतु प्रख्यात लेखकों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेखों द्वारा मार्गदर्शन करता है। समय-समय पर नीति विशेषज्ञों, उद्योग निकायों आदि के साक्षात्कार शामिल किए जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल उम्मीदवारों/स्टार्ट-अप की सफलता की कहानियां आदि भी शामिल की जाती हैं। 'ईएन एक्सप्लेन्स' कॉलम में विभिन्न सरकारी नीतियों और योजनाओं की जानकारी संक्षिप्त रूप से दी जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं की झलकियां और उनके महत्व का विश्लेषण शामिल होता है। इसमें एक 'न्यूज़ डाइजेस्ट' भी होता है, जिसमें महत्वपूर्ण समाचार घटनाओं का साप्ताहिक राउंडअप होता है तथा 'सप्ताह का प्रश्न' स्तंभ के माध्यम से यह वर्तमान मुद्दों पर पाठकों की राय आमंत्रित करता है।

इसके ई-संस्करण और प्रिंट संस्करण दोनों को इसकी वेबसाइट www.eneversion.nic.in/membership/login पर जाकर ऑनलाइन सब्सक्राइब किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है।

च) 'इंडिया 2023' और 'भारत 2023'

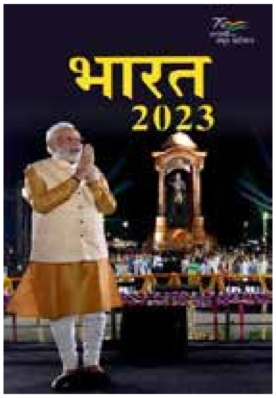

'इंडिया 2023' और 'भारत 2023', विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति के बारे में एक व्यापक संदर्भ वार्षिक ग्रन्थ है। अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित यह पुस्तक ग्रामीण एवं शहरी विकास, उद्योग, बुनियादी ढांचे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला तथा संस्कृति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा तथा शिक्षा और जनसंचार तक के सभी पहलुओं से संबंधित है। सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषयों, खेल और महत्वपूर्ण घटनाओं पर विस्तृत जानकारी के साथ, यह विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों आदि के लिए अवश्य पढ़ने योग्य है।

छ) मन की बात

सूचना और प्रसारण मंत्रालय फरवरी, 2022 से मन की बात पुस्तिका निकाल रहा है। यह पुस्तिका हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री के सम्बोधन में किए गए विशेष उल्लेखों पर कहानियां और प्रशंसा पत्र, साथ ही मंत्रियों और विशेषज्ञों के साक्षात्कार तथा लेख और सम्बोधन पर मीडिया में छपी प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती हैं। यह परियोजना प्रकाशन विभाग द्वारा सीबीसी के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है।

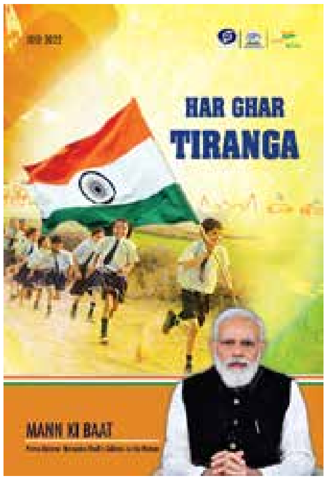

ई-कॉमर्स

भारत और दुनिया के डिजिटीकरण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, प्रकाशन विभाग ने ई-बुक्स और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में भी कदम रखा है। वर्तमान में प्रिंट पुस्तकें भारतकोष पोर्टल और प्रकाशन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ई-पुस्तकों के विपणन और बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (अमेजन किंडल, गूगल प्ले, गूगल बुक्स) और ई-रिसोर्स एग्रीगेटर्स (जीआईएसटी) लगे हुए हैं।

पत्रिकाएं (योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती) अब इन पोर्टलों पर डीआरएम सुरक्षा के साथ डिजिटल प्रारूप में भी उपलब्ध हैं। वर्तमान में प्रकाशन विभाग की 18 पत्रिकाएं ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। 'योजना 13 क्षेत्रीय भाषाओं में पोर्टल पर उपलब्ध है। कुरुक्षेत्र को अंग्रेजी, हिन्दी में अपलोड किया जाता है और आजकल पत्रिका हिन्दी और उर्दू में अपलोड की जाती है। बाल भारती केवल हिन्दी भाषा में उपलब्ध है।

ई-पुस्तकों की बिक्री विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है। अमेजन किंडल पर 789 ईबुक टाइटल लाइव हैं। आज की तारीख में 923 ई-पुस्तक गूगल प्ले पर लाइव हैं। पी-बुक्स और ई-बुक्स की ऑनलाइन बिक्री प्रकाशन विभाग के वेबसाइट से की जाती है। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं 'भारतकोष पोर्टल' और अन्य ई-प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध हैं। प्रकाशन विभाग की 31 मार्च, 2023 तक बिक्री से कुल आय 5,145.02 लाख तथा रोज़गार समाचार कुल आय 1,116.32 लाख रुपये है।

सरकारी संस्थानों/पुस्तकालयों/स्कूलों से थोक ऑर्डर

इस वित्तीय वर्ष में प्रकाशन विभाग ने चंडीगढ़, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के एसपीडी कार्यालयों से प्राप्त बल्क ऑर्डर के कार्य निष्पादित किए हैं। शैक्षिक विभागों के अलावा, प्रकाशन विभाग को केंद्रीय विद्यालयों, यूएचबीवीएन, जवाहर नवोदय विद्यालय सरकारी संस्थानों, राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रपति भवन, नेताजी अनुसंधान ब्यूरो आदि से भी थोक ऑर्डर प्राप्त हुए। इन थोक ऑर्डर की कुल राशि 31 मार्च, 2023 तक लगभग 26.88 करोड़ (लगभग) रुपये है।

पुस्तक मेलों/कार्यक्रमों/प्रदर्शनियों में भागीदारी

क) **शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला** : प्रकाशन विभाग ने 2 से 13 नवंबर, 2022 तक एक्सपो सेंटर, शारजाह में आयोजित 41वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 (एसआईबीएफ) में भाग लिया। शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले ने नई पीढ़ी के पाठकों को अपने प्रतिष्ठित प्रकाशनों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रकाशन विभाग को अनूठा अवसर प्रदान किया। विभाग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव, कला, संस्कृति और महात्मा गांधी सहित विभिन्न विषयों पर 135 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित कीं। इसके अलावा, शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले के माध्यम से आज़ादी क्वेस्ट गेम्स को बढ़ावा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रकाशन विभाग द्वारा एसआईबीएफ के माध्यम से 'आज़ादी क्वेस्ट' गेम्स को बढ़ावा दिया गया। सीजीआई दुबई के कॉन्सल (दूतावास) (पासपोर्ट) के श्री रामकुमार थंगराज ने इंडिया पवेलियन और प्रकाशन विभाग के स्टॉल का उद्घाटन किया।

ख) **दिल्ली पुस्तक मेला 2022** : प्रकाशन विभाग ने 22 से 26 दिसंबर, 2022 तक प्रगति मैदान, दिल्ली में आयोजित 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में भाग लिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोहों के अंतर्गत प्रकाशन विभाग ने आगंतुकों और पुस्तक प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों पर पुस्तक संग्रह प्रदर्शित किया। प्रकाशन विभाग ने भारतीय सिनेमा, कला, संस्कृति, भारतीय इतिहास, प्रख्यात हस्तियों और बाल साहित्य पर बहुप्रतीक्षित पुस्तकों का भी प्रदर्शन किया है। प्रकाशन विभाग द्वारा विशेष रूप से प्रकाशित राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के भाषणों के पुस्तकों को भी पत्रिकाओं के साथ प्रदर्शित किया गया था।

ग) **भारत का 53वां अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव** : प्रकाशन विभाग ने 20–28 नवंबर, 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (इफ्फी) में भाग लिया। इसके विभिन्न प्रकाशनों के साथ, राष्ट्रीय फ़िल्मों के फ़िल्म बाज़ार और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ़ गोवा में, प्रकाशन विभाग स्टालों का मुख्य आकर्षण 'आज़ादी क्वेस्ट गेम' था। कुछ फ़िल्मी हस्तियों सहित सैंकड़ों आगंतुक, आज़ादी क्वेस्ट गेम खेलने के लिए स्टॉलों पर उमड़ पड़ें।

घ) **जश्न-ए-रेख्ता** : मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 2 दिसंबर से 4 दिसंबर, 2022 तक आयोजित तीन दिवसीय उर्दू साहित्य महोत्सव में प्रकाशन विभाग ने हिस्सा लिया।

ङ) **साहित्य अकादमी पुस्तक मेला** : साहित्य अकादमी ने 11–18 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के रवीन्द्र भवन में आठ दिवसीय पुस्तक मेले– पुस्तकायन का आयोजन किया।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले, 2023 के दौरान प्रकाशन विभाग की पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर (बाएं से) अपर महानिदेशक, श्री एल. मधु नाग, महानिदेशक प्रकाशन विभाग श्रीमती अनुपमा भटनागर, लेखक और वक्ता सुश्री वर्षा दास और श्री राजेन्द्र भट्ट तथा अपर महानिदेशक प्रकाशन विभाग श्रीमती शुभा गुप्ता।

च) **नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023** : प्रकाशन विभाग ने 25 फरवरी से 5 मार्च, 2023 तक आयोजित 31वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 में हिस्सा लिया। इसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया था। 'आजादी का अमृत महोत्सव' को पूरे जोश के साथ मनाते हुए, प्रकाशन विभाग ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर पुस्तकों के अपने समृद्ध संग्रह के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर अपनी पुस्तकों, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्री के भाषणों पर प्रीमियम पुस्तकों और पत्रिकाओं तथा रोज़गार समाचार का प्रदर्शन किया। उपर्युक्त पत्र-पत्रिकाओं ने आगंतुकों और पुस्तक प्रेमियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान 'मन की बात' पुस्तिकाएं निःशुल्क वितरित की गईं। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में आगंतुक आएं, जिन्होंने प्रदर्शन की सराहना की और प्रकाशन विभाग की पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के प्रति अपनी उत्सुकता व्यक्त की। प्रदर्शनी के दौरान आज़ादी क्वेस्ट गेम्स को भी बढ़ावा दिया गया।

छ) 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' को चिह्नित करने के लिए, प्रकाशन विभाग ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, आधुनिक भारत के निर्माताओं आदि पर पुस्तकों का प्रदर्शन करने वाली भौतिक तथा आभासी पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन प्रकाशन विभाग की बुक्स गैलरी, सूचना भवन, नई दिल्ली और कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद तथा पटना में किया।

ज) योजना (कन्नड़) ने 13 से 17 अगस्त, 2022 तक आयोजित 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह में एक पुस्तक प्रदर्शनी में भाग लिया। वहां योजना (कन्नड़) का अगस्त विशेषांक जारी किया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रकाशन विभाग के अधिकारी (कन्नड़) योजना का अक्टूबर 2022 अंक भेंट करते हुए।

झ) प्रकाशन विभाग ने अगस्त, 2022 में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनी, चेन्नई में 'इरोड बुक फेस्टिवल' और पटना तथा कोलकाता में प्रदर्शनी सहित कई अन्य प्रदर्शनियों में भाग लिया। विभाग (मुख्यालय) ने 13 से 17 सितंबर, 2022 तक दिल्ली पुस्तक मेला 2022 के आभासी संस्करण में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, मुंबई में 'मराठवाड़ा मुक्ति दिन' और 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' पुस्तक प्रदर्शनी चेन्नई में त्रिची पुस्तक मेला 2022, में 19वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला (राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022), लखनऊ में, कोच्चि में 2022, पुणे पुस्तक मेला 2022, शिमला में अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2022, चेन्नई में नागापट्टिनम पुस्तक मेला 2022, कोयम्बटूर पुस्तक मेला 2022, दिल्ली में साहित्य अकादमी पुस्तक मेला, भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), लखनऊ में एनबीटी द्वारा आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव, भुवनेश्वर में 25वां कलिंग पुस्तक मेला, हॉर्नबिल महोत्सव 2022 और प्रयागराज पुस्तक मेला में भी अपनी पुस्तकें प्रस्तुत कीं।

जनवरी 2023 में इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशन विभाग का मंडप

सोशल मीडिया

प्रकाशन विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार करना जारी रखा। प्रकाशन विभाग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मौजूद है। नवंबर 2022 में अपने पाठकों और सभावित ग्राहकों के लिए पत्रिका से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए एक समर्पित ट्विटर हैंडल शुरु किया गया। इसकी सामग्री को आकर्षक और जानकारीपूर्ण मानने वाले उपयोगकर्ताओं ने इस नई पहल का स्वागत किया है। वर्तमान सिविल सेवकों ने भी पत्रिका से अपना जुड़ाव साझा करते हुए लिखा कि पत्रिका ने उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे मदद की है। सूचनाप्रद जानकारी पाने के इच्छुक पाठकों द्वारा इस पहल का स्वागत किया गया। इसमें सिविल सेवकों ने भी अपने विचार इस सभा व्यक्त किए कि किस तरह से जर्नल प्रतिस्पार्धात्मक परिक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए MyGov के सहयोग से योजना और कुरुक्षेत्र के लिए नए लोगो आमंत्रित करते हुए प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सभी प्रमुख अभियानों को मूल पोस्ट और रीट्वीट के माध्यम से उचित कवरेज दी गई। जश्न-ए-आज़ादी पॉडकास्ट, जिसमें प्रभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों की समीक्षा और बातचीत है, उसे जारी रखा गया। ये एपिसोड स्पॉटिफाई और अमेज़न प्राइम म्यूज़िक जैसे प्रमुख पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ-साथ प्रकाशन विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं।

विभिन्न पुस्तक मेलों में प्रकाशन विभाग की उपस्थिति का सभी सोशल मीडिया हैंडल पर विधिवत रूप से विस्तार किया गया और 'दिल्ली पुस्तक मेले' के प्रशंसा-पत्रों को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया। विशेष दिनों को चिह्नित करने के लिए नई और पुरानी पुस्तकों के वीडियो जारी किए गए।

रोज़गार समाचार के महत्वपूर्ण लेखों को इसके समर्पित ट्विटर (एम्प्लॉयमेंट न्यूज़) और फेसबुक के साथ-साथ प्रकाशन विभाग के इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से प्रचारित किया गया। विभाग ने आकाशवाणी-पुस्तक समीक्षा और रोज़गार समाचार के साथ अपना सहयोग भी जारी रखा। इन्हें आकाशवाणी की दैनिक संध्या समाचार पत्रिका 'परिक्रमा' में स्थान मिला है।

प्रकाशन विभाग ने लगभग 70,000 सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं- ट्विटर (13 हज़ार से अधिक), फेसबुक (25 हज़ार से अधिक) और इंस्टाग्राम (32 हज़ार से अधिक) को जोड़ा है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के फॉलोअर्स की संख्या एक लाख बीस हज़ार से ज़्यादा है।

भारतीय जनसंचार संस्थान

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), 17 अगस्त, 1965 को अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत संस्थान के रूप में की गई थी। इसे मीडिया और जनसंचार के क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण और उपक्रम अनुसंधान के मूल उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया था। पिछले 57 वर्षों में, संस्थान ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों की सूचना और प्रचार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक समय में तेज़ी से विस्तार और बदलते मीडिया उद्योग की विविध और मांग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने मूल जनादेश को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं।

2022 में, भारतीय जनसंचार संस्थान को एक बार फिर इंडिया टुडे ग्रुप, आउटलुक-केयर और द वीक मैगजीन-हंसा रिसर्च सर्वे द्वारा मास कम्युनिकेशन कॉलेजों के क्षेत्र में नंबर-1 संस्थान के रूप में स्थान दिया गया। संस्थान की एक सत्यापित फेसबुक पेज, एक सक्रिय ट्विटर अकाउंट और एक यू-ट्यूब चैनल के साथ सोशल मीडिया पर जीवंत उपस्थिति है।

शासी संरचना

भारतीय जनसंचार संस्थान को 50 सदस्यीय सोसायटी द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसका गठन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। सोसायटी के सदस्यों को सामाजिक सेवा संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्तियों आदि में से चुना जाता है। सोसायटी के मामलों का प्रशासन कार्यकारी परिषद में निहित है, जिसमें 15 सदस्य शामिल हैं। कार्यकारी परिषद के सदस्यों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय) और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के अलावा, शैक्षिक संस्थानों, सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और स्वयं संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हैं।

पी.जी. डिप्लोमा कोर्स

भारतीय जनसंचार संस्थान प्रिंट पत्रकारिता (अंग्रेजी, हिन्दी, उड़िया, उर्दू, मराठी और मलयालम), रेडियो और टेलीविज़न पत्रकारिता, विज्ञापन, जनसंपर्क और डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। 09.11.2022 से सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं ऑफलाइन शुरू हो गई हैं।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए इस संस्थान के सभी पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा में कुल 5,675 उम्मीदवार शामिल हुए, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा सितंबर, 2022 में 269 शहरों में 570 केंद्रों पर ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से आयोजित की गई थी। अंत में, 529 उम्मीदवारों ने इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया।

भारतीय जनसंचार संस्थान ने 21 से 25 नवंबर, 2022 तक शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए सभी पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम 2022 का आयोजन किया। अनुकूलन व्याख्यान, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से दिग्गजों और बुद्धिजीवियों द्वारा दिए गए और इसके साथ ही, नया अकादमिक सत्र प्रारंभ हुआ।

2020-21 के विभिन्न पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए आईआईएमसी का 54वां दीक्षांत समारोह 06.06.2022 को आयोजित किया गया था। दीक्षांत समारोह में, लगभग 400 छात्रों को डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए और 32 छात्रों को विभिन्न निर्धारित पुरस्कार प्राप्त हुए।

भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण

1965 में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय जनसंचार संस्थान, भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) की प्रशिक्षण अकादमी

के रूप में कार्य कर रहा है, जो भारत सरकार की केंद्रीय सिविल सेवाओं में से एक है। यह आईआईएस ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिनकी भर्ती यूपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। यह आईआईएस ग्रुप 'बी' अधिकारियों के लिए फाउंडेशन ट्रेनिंग भी आयोजित करता है, जिन्हें पूर्व पत्रकारिता अनुभव के आधार पर भर्ती किया जाता है।

व्यापक परामर्श के माध्यम से, आईआईएस अधिकारियों जो सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, के प्रशिक्षण कार्यक्रम, को नया रूप दिया गया है और सरकार के कामकाज और इसकी संचार व्यवस्था का अवलोकन करने के लिए व्यापक आधार दिया गया है, ताकि अधिकारियों को भारत में मीडिया उद्योग की व्यापकता से परिचित कराया जा सके और वे सार्वजनिक संचार की बारीकियों को समझ सकें।

आईआईएस ग्रुप ए के लिए दो साल के इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में सैंडविच ट्रेनिंग मॉडल का पालन किया जाता है। अधिकारी (प्रशिक्षु), जो अपना फाउंडेशन कोर्स पूरा करने के बाद आईआईएमसी में शामिल होते हैं, संस्थान में सार्वजनिक संचार में साढ़े नौ महीने के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस चरण में कक्षा व्याख्यान, प्रयोग, सिमुलेशन अभ्यास, साइट का दौरा और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों तथा प्रमुख मीडिया पेशेवरों के साथ बातचीत शामिल है। आईआईएमसी में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, अधिकारी प्रशिक्षुओं को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के माध्यम से नौकरी का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया निदेशालयों से जोड़ा जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 2020 और 2021 बैच के 10 आईआईएस ग्रुप 'ए' अधिकारी प्रशिक्षुओं ने आईआईएमसी में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण लिया, जो जनवरी, 2023 के पहले सप्ताह में समाप्त हुआ। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, महत्वपूर्ण गतिविधि थी- असम राइफल्स के साथ रक्षा अटैचमेंट, एफटीआईआई, पुणे और इफ्फी, गोवा के साथ चार सप्ताह का अटैचमेंट और तीन सप्ताह का अखिल भारतीय 'अध्ययन दौरा' जिसे भारत दर्शन भी कहा जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर इन अधिकारियों का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण दिया जाना था।

इस बीच, 2019 बैच के 5 और 2020 बैच के 3 अधिकारी प्रशिक्षुओं ने क्रमशः सितंबर और दिसंबर, 2022 के महीनों में अपना ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और उन्हें चरण-I के सफल समापन पर उनकी पहली नियमित पोस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। दिसंबर 2022 में, 2022 बैच के 18 अधिकारी प्रशिक्षुओं के नए बैच के साथ 2021 बैच के कुछ प्रशिक्षु अधिकारियों ने आईआईएमसी में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण शुरू किया।

लघु पाठ्यक्रम

भारत और अन्य विकासशील देशों के संदर्भ में मीडिया और जनसंचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों की बेहतर समझ की दिशा में योगदान करने और उभरती प्रवृत्तियों और तकनीकों के बारे में विभिन्न क्षेत्रों के कर्मियों की जागरूकता बढ़ाने और उनके मीडिया कौशल को तेज़ करने के लिए, संस्थान मीडिया और संचार से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है।

वर्ष 2022-23 के दौरान रक्षा सेवाओं, तट रक्षक अधिकारियों, भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क अधिकारियों सहित कुल 189 अधिकारी/प्रशिक्षु इन पाठ्यक्रमों से लाभान्वित हुए। अपनी स्थापना के बाद से, संस्थान ने 800 से अधिक ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है और 16,603 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया है।

विकास पत्रकारिता

विकासशील देशों, अफ्रीकी-एशियाई देशों के मध्यम स्तर के कामकाजी पत्रकारों के लिए पत्रकारिता में पाठ्यक्रम, समाचार कवरेज में असंतुलन और विकृति के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं। यह भारत सरकार की आईटीईसी योजनाओं के तहत प्रमुख पाठ्यक्रमों में से एक है। इन वर्षों में, आईआईएमसी ने 127 देशों के 1,706 से अधिक विदेशी पत्रकारों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें अफगानिस्तान से जिम्बाब्वे तक वर्णानुक्रमानुसार शामिल हैं।

2022 में आयोजित विकास पत्रकारिता में 72वें डिप्लोमा कोर्स के बाद, विभिन्न प्रतिबंधों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा और वीजा प्रतिबंधों के कारण संस्थान द्वारा ऐसा कोई कोर्स आयोजित नहीं किया जा सका।

संचार अनुसंधान

आईआईएमसी का संचार अनुसंधान विभाग संस्थान के अनुसंधान एजेंडे के अभिन्न अंग के रूप में संचार और मीडिया के व्यवस्थित अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। विभाग ने पिछले विभिन्न विषयों पर 200 से अधिक शोध अध्ययनों के साथ संचार अनुसंधान में बेंचमार्क स्थापित किया है।

अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 के दौरान की प्रमुख अनुसंधान गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाएं

1. **मेघालय के स्वदेशी समुदायों के बीच व्यवहार परिवर्तन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत संचार रणनीति विकसित करना।**

यह एक चालू परियोजना है, जिसे तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाना है। अध्ययन ने वर्तमान में अपना पहला चरण पूरा कर लिया है, जिसमें व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण और डेटा संग्रह शामिल है।

2. **डाकघरों के माध्यम से, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित *जागो ग्राहक जागो* अभियान का प्रभाव।**

इस अध्ययन ने नवीनतम अभियान *जागो ग्राहक जागो* के प्रभाव का मूल्यांकन किया जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताओं तथा धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं की सुरक्षा में इसकी उपयोगिता; अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ स्मार्ट उपभोक्ता कैसे बनें और उपभोक्ता शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में सूचनात्मक संदेश शामिल थे।

अपना रेडियो 96.9 एफएम

भारतीय जनसंचार संस्थान 2015 से, सामुदायिक रेडियो चला रहा है जिसे 'अपना रेडियो 96.9 एफएम' के नाम से जाना जाता है। इसने 2022 के दौरान समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण, सहायक, मनोरंजक और सूचनात्मक भूमिका निभाई है। 75वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के जश्न के दौरान, अपना रेडियो 96.9 एफएम ने 'हर घर तिरंगा' पर 11 विशेष कार्यक्रम किए, जिनमें हमारी स्वतंत्रता के महत्व को शामिल किया गया।

पत्रिकाओं, समाचार पत्रिकाओं और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संचार

आईआईएमसी के प्रकाशन विभाग सहकर्मी–समीक्षित दो शोध पत्रिकाएं प्रकाशित करता है: कम्युनिकेटर (अंग्रेजी, त्रैमासिक) और संचार माध्यम (हिन्दी, छमाही) जो भारत में प्रकाशित होने वाली सबसे पुरानी संचार पत्रिकाएं हैं। ये प्रमुख पत्रिकाएं यूजीसी–सीएआरई सूचीबद्ध पत्रिकाएं हैं।

प्रकाशन विभाग जुलाई, 2021 से 'आईआईएमसी समाचार' भी प्रकाशित कर रहा है, जिसमें आईआईएमसी मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय परिसरों द्वारा की गई सभी गतिविधियों की जानकारी शामिल होती है। समसामयिक मीडिया मुद्दों पर केंद्रित 'संचार सृजन' (द्विभाषी) और राजभाषा को समर्पित 'राजभाषा विमर्श' (हिन्दी) भी विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं।

विभिन्न हितधारकों को पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने के लिए संस्थान ने हिन्दी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में 'पाठ्य पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रम' शुरू किया है।

पं. युगल किशोर शुक्ल लाइब्रेरी एंड नॉलेज रिसोर्स सेंटर

वर्ष 2021 के दौरान भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के पुस्तकालय का नाम पं. युगल किशोर शुक्ल पुस्तकालय और ज्ञान संसाधन केंद्र कर दिया गया है। संस्थान के पास देश में जनसंचार का सबसे बड़ा विशिष्ट पुस्तकालय है। इसने जनसंचार के विभिन्न पहलुओं और प्रिंट मीडिया, प्रसारण, विज्ञापन, संचार, संचार अनुसंधान, जनसंपर्क आदि जैसे संबद्ध विषयों पर लगभग 37,608 पुस्तकों और जिल्दबद्ध पत्रिकाओं का संग्रह किया है।

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 03 नवंबर, 2022 को भारतीय जन संचार संस्थान के आइजोल के स्थायी कैम्पस का वर्चुअल उद्घाटन करती हुई।

प्लान स्कीम और बुनियादी ढांचा विकास

11वीं पंचवर्षीय योजना में 'आईआईएमसी का अंतरराष्ट्रीय मानक में उन्नयन' योजना शामिल थी और इसमें आईआईएमसी का उन्नयन, यानी आईआईएमसी मुख्यालय, नई दिल्ली में अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण, साथ ही महाराष्ट्र, मिज़ोरम, केरल और जम्मू में चार नए क्षेत्रीय परिसरों की शुरुआत शामिल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन आईआईएमसी मुख्यालय, नई दिल्ली में नए अतिरिक्त संस्थागत भवनों के निर्माण की अनुमति दी। इस योजना के तहत, आईआईएमसी का डी नोशे श्रेणी के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय में प्रस्तावित रूपांतरण भी विचाराधीन है और एक बार प्रस्ताव आगे बढ़ने के बाद, इसमें विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का निर्माण शामिल होगा।

उपरोक्त योजना के तहत वर्ष 2011 में आइजॉल (मिज़ोरम) और अमरावती (महाराष्ट्र) में दो क्षेत्रीय परिसर शुरू किए गए थे और अन्य दो क्षेत्रीय परिसर 2012 में जम्मू (जम्मू और कश्मीर) और कोट्टायम (केरल) में शुरू किए गए थे। निर्माण गतिविधियों के पूरा होने पर आइजॉल कैंपस का उद्घाटन 3 नवंबर, 2022 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। शीघ्र ही नए भवन में कक्षाएं शुरू होंगी। इसी तरह, जम्मू परिसर में निर्माण गतिविधियां भी पूरी हो चुकी हैं और परिसर कक्षाएं शुरू करने और उद्घाटन के लिए तैयार है। बडनेरा, अमरावती में पश्चिमी क्षेत्रीय परिसर के निर्माण के संबंध में, मंत्रालय के अनुमोदन से निर्माण कार्य सीपीडब्ल्यूडी को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है और जल्द काम शुरू करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को आशय पत्र दिया गया है।

नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण-तंत्र

अद्यतन नागरिक चार्टर आईआईएमसी वेबसाइट पर उपलब्ध

है। संस्थान के एक अधिकारी को लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। प्राप्त शिकायतों की संस्थान द्वारा जांच की जाती है और उसका तुरंत निवारण किया जाता है।

अन्य प्रमुख गतिविधियां

2021 बैच के भारतीय सूचना सेवा ग्रुप 'ए' के अधिकारी प्रशिक्षुओं के नए बैच के लिए चरण-I की भर्ती 21.03.2022 से शुरू हुई और इसका औपचारिक उद्घाटन 25.03.2022 को सचिव (सूचना प्रसारण मंत्रा.) और अध्यक्ष, आईआईएमसी द्वारा किया गया। वर्तमान में 21 अधिकारी, प्रशिक्षु प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और प्रशिक्षण की अवधि 20 महीने है।

आईआईएमसी ने 05.05.2022 को, दो संस्थानों के बीच ज्ञान, संसाधनों और अनुसंधान गतिविधियों को साझा करने के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के साथ और भारतीय भाषाओं में अनुसंधान के साथ अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सत्यमेव जयते
भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना देश में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा करने और समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों का स्तर बनाए रखकर उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से संसद में पारित प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत एक अर्ध-न्यायिक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में 1979 में की गई थी।

संसद के अधिनियम के अंतर्गत गठित होने के कारण परिषद् को अपने कोष का एक भाग संसद में विनियोग के बाद केंद्र सरकार से सहायता-अनुदान के रूप में प्राप्त होता है और समाचार-पत्रों से लिए जाने वाले श्रेणीवार शुल्क और अन्य प्राप्तियों से भी परिषद को कोष मिलता है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए परिषद का कुल स्वीकृत बजट 27.18 करोड़ रुपये था।

परिषद के समक्ष शिकायतें

समीक्ष्य वर्ष में 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर 2022 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1,172 शिकायतें दर्ज की गई थीं। इस दौरान इनमें से 790 मामलों (पिछले वर्ष के लंबित मामलों सहित) का निपटारा किया गया जिन्हें या तो अधिनिर्णय के माध्यम से या अध्यक्ष की मध्यस्थता से सहमति होने पर अध्यक्ष द्वारा संक्षिप्त निपटान के जरिए या पूछताछ के लिए पर्याप्त आधार न होने या गैर-अनुपालन के कारण मामला वापस लेने या विचाराधीन होने के कारण निपटाया गया।

स्वतः संज्ञान

परिषद ने मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और प्रेस की स्वतंत्रता के ख़तरे से जुड़े 6 मामलों में स्वतः संज्ञान लिया।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022

राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष 16 नवंबर को देश में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष, स्कोप कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में 'राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका' विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस अवसर पर, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री और सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने क्रमशः मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाईं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारिता आचरण के मानदंड, 2022 भी जारी किए।

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां

भारतीय प्रेस परिषद ने 24 अगस्त, 2022 को एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ग्रेटर नोएडा के सहयोग से मालदीव मीडिया काउंसिल (एमएमसी) से जुड़े संपादकों और पत्रकारों के लिए एक संवाद सत्र आयोजित किया।

परिषद के सचिवालय में 21 जून, 2022 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सत्र के दौरान योग प्रशिक्षक की देख-रेख में योगाभ्यास करने में कर्मचारियों ने काफी उत्साह दिखाया।

मालदीव मीडिया काउंसिल (एमएमसी) से जुड़े संपादकों और पत्रकारों के लिए संवाद सत्र

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख स्थानों पर बैनर चिपकाए गए थे।

परिषद की नई वेबसाइट का शुभारंभ अगस्त, 2022 को किया गया।

भारतीय प्रेस परिषद में दिनांक 02 से 31 अक्टूबर, 2022 तक स्वच्छता अभियान 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद ने पुरानी रद्दी सामग्री को निपटाया, फाइलों/पुराने अभिलेखों की छंटाई की और परिषद के परिसर में तथा आस-पास सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत कार्रवाई की।

डिजिटल मीडिया प्रभाग

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को दिनांक 25.02.2021 की अधिसूचना के तहत इंटरमीडियरी से संबंधित नियमों के भाग-2 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक सामग्री के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों से संबंधित नियमों का भाग-3, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है और अन्य बातों के साथ-साथ आचार संहिता का प्रावधान करता है जिसका डिजिटल मीडिया पर समाचारों और करंट अफेयर्स के और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों द्वारा अनुपालन किया जाना है। नियमों की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं:

I. डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए आचार संहिता

II. तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र निम्नानुसार है:

स्तर-I - प्रकाशक

स्तर-II - प्रकाशकों का स्व-नियामक निकाय और

स्तर-III - केंद्र सरकार का निगरानी तंत्र जिसमें अंतर विभागीय समिति शामिल है।

III प्रकाशकों द्वारा सरकार को जानकारी प्रस्तुत करना।

समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए लागू आचार संहिता के लिए (i) भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंड (ii) केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता और (iii) उस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए जो इस समय लागू करने के लिए किसी भी कानून के तहत निषिद्ध है।

ओटीटी प्लेटफार्म के लिए आचार संहिता के तहत

(i) उस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए जो उस समय लागू करने के लिए किसी भी कानून के तहत न्यायालय द्वारा निषिद्ध है।

(ii) भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कारकों

को उनके प्लेटफार्मों पर प्रकाशित करने के लिए विषयवस्तु तय करने पर विचार करें।

(iii) नियमों में निर्धारित इस उद्देश्य के लिए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए पांच श्रेणियों में सामग्री का स्व-वर्गीकरण।

(iv) इस तरह के वर्गीकरण को विषयवस्तु वर्णनकर्ता के साथ मिलकर सामग्री की प्रकृति के बारे में उपयोगकर्ता को सूचित करना और प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शकों के विवेक पर सलाह देना, उपयोगकर्ता को कार्यक्रम देखने से पहले सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना।

(v) उपयुक्त अभिगम नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से बच्चों द्वारा उच्च आयु वर्गीकरण के साथ पहुंच सामग्री को प्रतिबंधित करने के सभी प्रयास करना और

(vi) उचित पहुंच सेवाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को इसके द्वारा ऑनलाइन प्रेषित क्यूरेट की गई सामग्री की पहुंच में सुधार के लिए उचित प्रयास करना।

दिनांक 25.2.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरर दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की अधिसूचना के बाद नियमों के कार्यान्वयन की दिशा में निम्नलिखित कार्रवाई/घटनाक्रम हुए हैंः

15.12.2022 की स्थिति के अनुसार, 57 ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित 2,809 प्रकाशकों ने नीचे दिए गए ब्रेक-अप के अनुसार नियमों के तहत आवश्यक जानकारी मंत्रालय को प्रस्तुत की हैः

ओटीटी प्लेटफॉर्म	57
डिजिटल समाचार प्रकाशक (स्टैंड अलोन)	2,209
समाचार-पत्रों की डिजिटल आर्म	456
टीवी चैनलों की डिजिटल आर्म	87
कुल	**2,809**

मंत्रालय ने 9 स्व-नियामक निकायों (एसआरबी) को पंजीकृत किया है, जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र के स्तर-II के रूप में कार्य करते हैं

डिजिटल समाचार

1. भारतीय डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद (ऑनलाइन मीडिया का परिसंघ)।
2. वेब पत्रकार मानक प्राधिकरण (वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया)।
3. व्यावसायिक समाचार प्रसारण प्राधिकरण (एनबीए)।
4. मीडिया9 डिजिटल मीडिया फेडरेशन (एमडीएमएफ)।
5. डिजीपब न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन।
6. वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल।
7. डिजिटल मीडिया प्रकाशक और समाचार पोर्टल। भारतीय शिकायत परिषद का पंजीकरण।
8. प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन (पीएडीएमए)।

ओटीटी प्लेटफॉर्म

1. डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद (आईएएमएआई)

मंत्रालय द्वारा प्राप्त शिकायतों को नियमों के तहत प्रकाशकों को उनके निवारण के लिए भेजा जा रहा है। सीधे मंत्रालय में या लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त डिजिटल समाचार प्रकाशकों से संबंधित 620 शिकायतों/परिवेदनाओं और ओटीटी प्लेटफार्मों से संबंधित 265 शिकायतों/परिवेदनाओं का या तो सीधे उत्तर दिया गया है या नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए संबंधित प्रकाशकों को अग्रेषित किया गया है।

अंतर विभागीय समिति (आईडीसी), नियमों के तहत गठित की गई है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधि तथा न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पीसीआई, सीआईआई तथा फिक्की के डोमेन विशेषज्ञ शामिल हैं। मंत्रालय में संयुक्त सचिव को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है जो आईडीसी की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69क सामग्री पर रोक लगाने के निर्देशः सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69क के तहत संदर्भित सामग्री को डिजिटल मीडिया पर देने पर रोक लगाने का प्रावधान, भारत की संप्रभुता या अखंडता, भारत की रक्षा, देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या प्रभावी प्रक्रियात्मक कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के साथ उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कृत्य को रोकने के लिए है।

दिसंबर, 2021 से, मंत्रालय ने यू-ट्यूब और अन्य सोशल

मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69क में संदर्भित सामग्री के प्रसार वाले ऐसे सौ से अधिक एकाउंट और चैनलों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।

डिजिटल समाचार प्रकाशक

प्लेटफॉर्म	संख्या
यू-ट्यूब	104 यू-ट्यूब चैनल और 45 व्यक्तिगत वीडियो
फेसबुक	4 अकाउंट और 2 पोस्ट
इंस्टाग्राम	3 अकाउंट
ट्विटर	5 अकाउंट
ऑडियो स्ट्रीमिंग	3 पॉडकास्ट चैनल
ऐप्स	2
वेबसाइटें	6

ओटीटी प्लेटफॉर्म

प्लेटफॉर्म	सोशल मीडिया अकाउंट/ वेबसाइट
1. ओटीटी प्लेटफॉर्म	इसकी 1 वेबसाइट के साथ 2 मोबाइल ऐप्लीकेशन, 1 टीवी ऐप्लीकेशन और यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 1-1 सोशल मीडिया एकाउंट

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाने वाली विभिन्न वेब सीरीज/फ़िल्मों में भारत के मानचित्र के गलत चित्रण के संबंध में सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त अनुरोधों जिन्हें संबंधित ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ मामला उठाया गया था, के आधार पर वेबसीरीज/फ़िल्मों को प्रासंगिक अंश सुधारा/हटा दिया गया।

नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करना

मंत्रालय ने नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैंः

- आईटी नियम, 2021 पर विभिन्न पहलुओं को सरल भाषा में समझाते हुए एक सूचना पुस्तिका तैयार की गई है और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।
- आईटी नियम, 2021 के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक एफएक्यू भी तैयार किया गया है और मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। नागरिकों के फायदे के लिए एफएक्यू का हिन्दी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, खासी, गुजराती, पंजाबी, असमिया, मराठी, बांग्ला और मणिपुरी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

आईआईएस डिवीजन

महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/विधान/उपलब्धियां/घटनाएं

मंत्रालय ने 16 से 17 जुलाई, 2022 के दौरान भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) का तीसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का उद्‌घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के प्रमुखों और देश भर में आईआईएस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आईआईएस अधिकारियों के निष्पादन की व्यापक समीक्षा करने और महत्वपूर्ण कार्यात्मक तथा संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में सेवा के लिए जनादेश से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं इंडिया@2047 के लिए संचार, भारत की छवि को विदेशों में प्रदर्शित करना, सरकारी संचार की उभरती भूमिका आदि को शामिल किया गया।

सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों जैसे विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, क्षमता निर्माण आयोग, MyGov आदि के प्रख्यात वक्ताओं ने वर्तमान डिजिटल युग में सरकारी संचार के लिए अपने विचार व्यक्त किए और सरकारी संचार तथा सूचना प्रसार की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए प्रभावी ढंग से कार्यनीति बनाने के लिए आईआईएस अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 16 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में स्कोप कन्वेंशन सेन्टर में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चन्द्रा नई दिल्ली में 11 जुलाई, 2022 को प्रसार भारती के लोगो का अनावरण करते हुए।

5 प्रसारण क्षेत्र

प्रसारण क्षेत्र को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 'सामग्री' और 'कैरिज सेवाएं'। यह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और समय-समय पर जारी नीति दिशानिर्देशों के माध्यम से निजी उपग्रह चैनलों की सामग्री और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों तथा स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क को नियंत्रित करता है। ब्रॉडकास्टिंग कैरिज सेवाओं में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)/लोकल केबल ऑपरेटर (एलसीओ), डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटर, हेडएंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता शामिल हैं। यह मंत्रालय डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटरों को उनके संबंधित कार्यों के लिए लाइसेंस/अनुमति देता है।

बीपी एंड एल अनुभाग के संबंध में प्रसारण क्षेत्र के तहत गतिविधियां और मंत्रालय की भूमिका तथा कार्य

1. डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच)

डीटीएच एक एड्रेसेबल सैटेलाइट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और पूरे देश को कवर करता है। डीटीएच सेवा में बड़ी संख्या में टेलीविज़न चैनल केयू बैंड में बहुत उच्च शक्ति वाले उपग्रहों से डिजिटली कम्प्रेस्ड, इनक्रिप्टेड और बीम्ड होते हैं। डीटीएच के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों को भवनों में सुविधाजनक स्थानों पर छोटे डिश एंटेना स्थापित करके सीधे घरों में प्राप्त किया जा सकता है। पहले डीटीएच सेवा प्रदाता ने वर्ष 2003 में अपनी सेवाओं का संचालन किया और निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं की संख्या वर्ष 2007 तक बढ़कर छह हो गई थी। चूंकि छह निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं में से दो डीटीएच सेवा प्रदाताओं का वर्तमान में एक में विलय हो गया है, इसलिए निजी डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या घटकर चार हो गई है। इसके अलावा, दूरदर्शन अपनी डीटीएच सेवाएं फ्री टू एयर आधार पर भी प्रदान कर रहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 16.09.2022 के आदेश के तहत भारत में डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान, प्लेटफॉर्म सर्विस चैनल और डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के संबंध में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। लाइसेंस शुल्क के भुगतान के संबंध में परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, लाइसेंस शुल्क समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 8 प्रतिशत पर लिया जाएगा {जहां एजीआर = सकल राजस्व (जीआर) - जीएसटी} और तिमाही आधार पर देय होगा। न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस शुल्क प्रवेश शुल्क का 10 प्रतिशत होगा। डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के संबंध में, इन दिशानिर्देशों में डीटीएच ऑपरेटरों के बीच बुनियादी ढांचे की साझेदारी के प्रावधान जोड़े गए हैं। प्लेटफॉर्म सर्विस चैनलों के संबंध में, परिचालन संबंधी दिशानिर्देश डीटीएच ऑपरेटर को प्लेटफॉर्म सर्विसेज (पीएस) चैनल संचालित करने की अनुमति देते हैं, जो डीटीएच ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म की कुल चैनल वहन क्षमता का अधिकतम 5 प्रतिशत है और डीटीएच ऑपरेटरों को एक बार गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क के लिए 10,000 रुपये प्रति पीएस चैनल का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

वित्तीय वर्ष 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक सभी डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा लाइसेंस शुल्क के रूप में भारत कोष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 903,27,13,220/- रुपये जमा किए गए हैं।

2. हेडएंड इन द स्काई (एचआईटीएस)

हेडएंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सेवा, उपग्रह और केबल टीवी का मिश्रण है। हेडएंड इन द स्काई ऑपरेटर टी.वी. प्रसारण को एक उपग्रह से अपलिंक करता है, जो एमएसओ/एलसीओ द्वारा डाउन-लिंक किया जाता है और एक केबल नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तिगत उपभोक्ता के परिसर में वितरित किया जाता है। इस प्रकार हेडएंड इन द स्काई ऑपरेटर ग्राहकों को केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से सिग्नल की आपूर्ति करते हैं। हेडएंड इन द स्काई ऑपरेटर और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) के बीच आवश्यक अंतर यह है कि हेडएंड इन द स्काई, उपग्रह का उपयोग करके चैनलों को केबल ऑपरेटरों तक पहुंचाता

है, जबकि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर केबल के माध्यम से ऐसा करता है। हेडएंड इन द स्काई ग्राहकों को किफ़ायती मूल्य पर डिजिटल चैनलों के व्यापक विकल्प, बेहतर पिक्चर क्वालिटी और मूल्यवर्द्धित सेवाओं का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। केवल दो हेडएंड इन द स्काई ऑपरेटर हैं, जिन्हें इस मंत्रालय द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है, जिनमें से एक ऑपरेटर वर्तमान में कार्यरत हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 06.11.2020 के आदेश के माध्यम से 'भारत में मौजूदा हेडएंड इन द स्काई प्रसारण सेवा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों' में संशोधन किया है। ये संशोधन हेडएंड इन द स्काई ऑपरेटर को मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)/ हेडएंड इन द स्काई ऑपरेटर के साथ हेडएंड इन द स्काई इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने की अनुमति देते हैं।

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न (आईपीटीवी)

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न (आईपीटीवी) सेवा इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग द्वारा केबल ऑपरेटरों के अलावा पात्र दूरसंचार या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने नेटवर्क पर अनुमत उपग्रह टीवी चैनलों के वितरण का एक अन्य तरीका है। आईपीटीवी प्रदाताओं को परिभाषित दूरसंचार और केबल ऑपरेटरों के लिए आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें एक स्व-घोषणा करनी होगी।

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007 को भारत या विदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में सबसे बड़ी संख्या में श्रोताओं और दर्शकों को फ्री-टू-एयर आधार पर पहुंच प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 2(1)(एस) केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों की कवरेज के लिए अधिसूचित करने का अधिकार देती है। यह मंत्रालय समय-समय पर कुछ खेल आयोजनों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों के रूप में अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना जारी करता है ताकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को फ्री-टू-एयर आधार पर अधिकतम संख्या में श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाया जा सके।

मंत्रालय द्वारा अनुमत टेलीविज़न चैनलों की संख्या

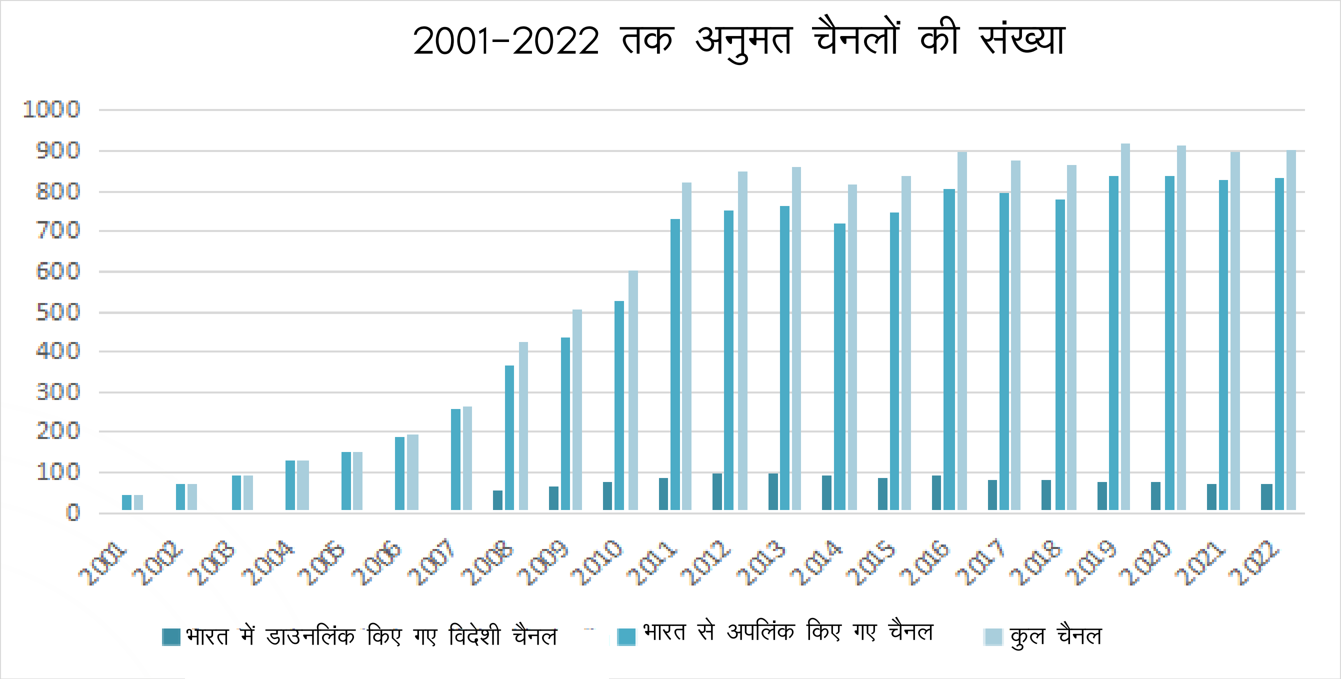

श्रेणीवार अनुमत चैनल

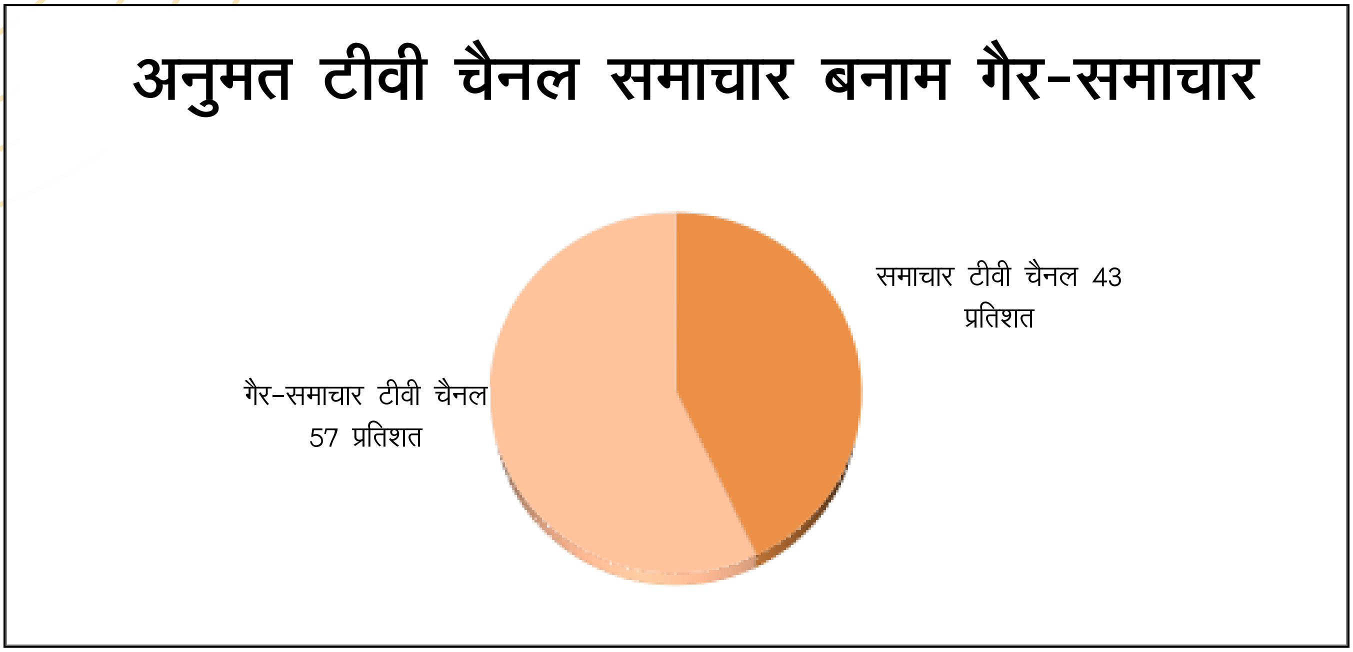

भारत में निजी उपग्रह टीवी चैनल

भारत में पहले निजी सैटेलाइट टीवी चैनल को वर्ष 2000 में भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी गई थी। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वृद्धि के साथ, भारत से टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की मांग कई गुना बढ़ गई जिससे 2002 में अपलिंकिंग और 2005 में डाउनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करना आवश्यक हो गया। इन दिशानिर्देशों को दिसंबर, 2011 में फिर से संशोधित किया गया और अंतिम संशोधन नवंबर, 2022 में किया गया। ये दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

टीवी चैनल का विकास

मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2022 तक भारत में 901 चैनलों को स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रालय द्वारा टीवी चैनल की दो श्रेणियों समाचार और चैनल तथा गैर-समाचार और करेंट अफेयर को स्वीकृति प्रदान की है जिसके 387 टीवी चैनल समाचार तथा 514 चैनलों का गैर-समाचार में हिस्सा है।

प्रसारण सेवा पोर्टल

प्रसारण सेवा पोर्टल शुरू में मंत्रालय द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के तहत प्रसारण विंग योजना के स्वचालन के तहत 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य कंप्यूटरीकृत वेब आधारित प्रणाली स्थापित करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल समाधान (सॉल्यूशन) विकसित करना था ताकि विभिन्न प्रसारण लाइसेंसों/अनुमतियों/पंजीकरण आदि के लिए आवेदनों की तेज़ी से प्रोसेसिंग की जा सके। इस योजना का फ़ोकस आवेदक को कारोबार सुगमता के लिए एकल बिंदु सुविधा थी। पोर्टल के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाओं को शामिल किया गया थाः

- निजी सैटेलाइट टीवी चैनल
- टेलीपोर्ट ऑपरेटर
- बहु-सेवा ऑपरेटर (केबल ऑपरेटर)
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस)
- निजी एफएम चैनल

अब प्रसारण सेवा पोर्टल को मंत्रालय द्वारा और अधिक सुविधाओं को शामिल करने तथा प्रसारकों द्वारा इस तरह के आवेदनों की प्रोसेसिंग में शामिल एजेंसियों के साथ सहज इंटरफेस की अनुमति देने और मंत्रालय में इस तरह के आवेदन की कुशल

प्रोसेसिंग के लिए नया रूप दिया गया है। प्रसारण सेवा पोर्टल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैंः

i. नई अनुमति, नवीनीकरण, नाम/लोगो/टेलीपोर्ट/सैटेलाइट आदि में परिवर्तन के लिए अनुप्रयोगों की शुरू से अंत तक प्रोसेसिंग सक्षम करना।

ii. भुगतान प्रणाली (भारत कोष), ई-ऑफिस, अन्य मंत्रालयों के पोर्टलों के साथ एकीकरण।

iii. विश्लेषिकी, रिपोर्टिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)।

iv. एकीकृत हेल्पडेस्क, डाटा सेंटर।

v. डीटीएच ऑपरेटरों, स्थानीय केबल ऑपरेटरों और डिजिटल मीडिया के लिए विस्तार।

vi. उपयोगकर्ता पंजीकरण और उन्नयन।

vii. शुल्क गणना तथा भुगतान, आवेदन प्रपत्र और ट्रैकिंग, पत्र/आदेश डाउनलोड करना, हितधारकों को अलर्ट करना (एसएमएस/ई-मेल)।

आवेदक कंपनियां (प्रसारक/टेलीपोर्ट ऑपरेटर) अब वेब पोर्टलः https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app पर दाखिल ऑनलाइन आवेदनों की लाइव ट्रैकिंग/स्थिति देख सकते हैं। कंपनी से सूचना मांगने और कंपनी के प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। तदनुसार, अनुमोदन की समयावधि कम कर दी गई है।

टीवी चैनलों की सामग्री का विनियमन

केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अनुसार, निजी टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों के लिए केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 और केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियमों तथा 1994 केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करना आवश्यक है।

केबल टेलीविज़न नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत शिकायत निवारण संरचना

कार्यक्रम और विज्ञापन सहिताओं के उल्लंघन से संबंधित नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक अंतर मंत्रालय सचिव के माध्यम से एक संस्थागत तंत्र था। हालांकि शिकायत निवारण ढांचे सुदृढ़ करने के लिए एक संविधिक तंत्र स्थापित करने की महसूस की गई।

केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 को 17 जून, 2021 की अधिसूचना द्वारा केबल टेलीविज़न नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के रूप में संशोधित किया गया है, जिससे सामग्री प्रसारण से संबंधित नागरिकों की शिकायतों / शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक तंत्र टेलीविज़न चैनल, केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

इन नियमों में प्रावधान है कि प्रसारक द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिवेदना या संबंधित शिकायत को दूर करने के लिए एक तीन-स्तरीय संरचना (शिकायत निवारण संरचना) निम्नानुसार होगीः

(i) स्तर 1 – प्रसारकों द्वारा स्व-नियमन;

(ii) स्तर 2 – प्रसारकों के स्व-नियामक निकायों द्वारा स्व-नियमन; और

(iii) स्तर 3 – केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षण तंत्र।

केबल टेलीविज़न नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसरण में मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.07.2021 के आदेश के तहत एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया गया है। आईडीसी के अध्यक्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव होते हैं तथा इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वर्ष 2022 के दौरान, आईडीसी ने 6 बैठकें कीं।

वर्ष 2022 और चालू वर्ष के दौरान, जहां कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन पाया गया, वहां मंत्रालय द्वारा 77 मामलों (15.02.2023 तक) में सलाह, चेतावनी, माफ़ी स्क्रॉल वगैरह के लिए आदेश जारी करके उचित कार्रवाई की गई।

टीवी चैनलों को जारी सामान्य परामर्श

क्र.सं.	विषय मामले	परामर्श की तिथि
1.	टीवी चैनलों को सलाह दी गई कि वे किसी भी तरह से यौन उत्पीड़न की शिकार लड़कियों/महिलाओं की पहचान उजागर करने से, सख्ती से बचें और संयम, जिम्मेदारी तथा संवेदनशीलता बरतें।	10.01.2022
2.	सांकेतिक भाषा में व्याख्या के साथ गणतंत्र दिवस समारोह/परेड का प्रसारण	25.01.2022
3.	डी.बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 37/2022 में पारित राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.3.2022 का अनुपालन। प्रेस और प्रिंट मीडिया को अदालती कार्यवाही या मामले की जांच से जुड़े किसी भी मामले के बारे में रिपोर्ट करने से रोकता है।	07.04.2022
4.	टीवी चैनलों को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।	11.04.2022
5.	टीवी चैनलों को सलाह दी गई थी कि वे ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचें जो अप्रामाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का उपयोग करने वाली प्रतीत होती हैं।	23.04.2022
6.	डिजिटल मीडिया पर टीवी चैनलों, समाचार-पत्रों, समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशकों को सलाह दी गई कि वे ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रदर्शित न करें।	13.06.2022
7.	सांकेतिक भाषा व्याख्या के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह/टिप्पणी का प्रसारण 12.08.2022	12.08.2022
8.	टीवी चैनलों को सलाह दी गई थी कि वे ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म और/या उनकी सरोगेट न्यूज़ वेबसाइटों के विज्ञापन प्रसारित करने से बचें।	03.10.2022
9	टीवी चैनलों को सलाह दी गई कि वे अपराध, दुर्घटना और हिंसा आदि की घटनाओं से संबंधित समाचारों की रिपोर्टिंग करते समय प्रोग्राम कोड का पालन करें।	09.01.2023
10	सांकेतिक भाषा में व्याख्या के साथ गणतंत्र दिवस समारोह/परेड का प्रसारण	20.01.2023

पीजी पोर्टल पर शिकायत याचिकाएं

01.01.2022 से 15.02.2023 की अवधि के दौरान, निजी उपग्रह टीवी चैनलों पर सामग्री प्रसारण से संबंधित 442 शिकायत याचिकाओं का निपटान किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत 2008 में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी), केबल के तहत कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोड के किसी भी उल्लंघन के लिए देश के भीतर टी.वी. समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित की जा रही सामग्री की निगरानी करता है। टेलिविज़न नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995, ईएमसी के पास 900 चैनलों की सामग्री को रिकार्ड करने के तकनीकी सुविधा उपलब्ध है।

भारत के निर्वाचन आयोग ने ईएमएमसी को चुनाव के दौरान मीडिया निगरानी का काम भी सौंपा है। ईएमएमसी, निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सामग्री की निगरानी करता है और उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वर्ष 2022 के दौरान दिसंबर के महीने तक, ईएमएमसी ने हिमाचल प्रदेश, गुजरात के विधानसभा चुनाव और ओडिशा, केरल, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और झारखंड विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के दौरान चुनाव संबंधी समाचारों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज की निगरानी की। मतदान के दिन और उससे पहले की घटनाओं पर व्हाट्सएप अलर्ट के साथ-साथ विशेष रिपोर्ट भी निर्वाचन आयोग को भेजी गई थी।

मीडिया निगरानी का महत्व

टेलीविज़न चैनलों की पहुंच बहुत विशाल और असाधारण है। ये संचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेलीविज़न कार्यक्रम विभिन्न आयु, संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं और इसलिए इनमें विविध प्रकृति की सामग्री शामिल होती है। टेलीविज़न चैनलों द्वारा प्रसारित की जा रही अवांछनीय सामग्री से उपभोक्ताओं को बचाना, दुनिया के लगभग सभी प्रमुख लोकतंत्रों द्वारा पालन किया जाने वाला एक मानक है।

सामुदायिक रेडियो

रेडियो प्रसारण में सामुदायिक रेडियो एक महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है, जो लोक सेवा रेडियो प्रसारण और वाणिज्यिक रेडियो

से अलग है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। दिसंबर, 2002 में भारत सरकार ने सुस्थापित शैक्षणिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना की अनुमति देने के लिए एक नीति को मंजूरी दी। विकास और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर अधिक से अधिक भागीदारी की अनुमति देने के लिए 2006 में नीति दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया था, जिसमें आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, पंजीकृत समितियों, सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों आदि जैसे समुदाय-आधारित संगठनों को विकास और सामाजिक परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर अधिक भागीदारी के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति दी गई थी। सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए 2017, 2018 और 2022 में नीति दिशानिर्देशों में और संशोधन किया गया। सामुदायिक रेडियो के लिए नीति दिशानिर्देश और वर्तमान में चल रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सूची, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइटःwww.mib.gov.in. पर देखी जा सकती है।

सामुदायिक रेडियो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय समुदाय के लिए उपयोगी सामग्री प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा, सामुदायिक रेडियो समाज के हाशिए के वर्गों के लिए उनकी चिंताओं को आवाज देने का एक शक्तिशाली माध्यम है। चूंकि प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होता है, इसलिए लोग इससे तुरंत जुड़ जाते हैं। सामुदायिक रेडियो में अपने समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को मजबूत करने की क्षमता है। भारत जैसे देश में, जहां हर राज्य की अपनी भाषा और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, सामुदायिक रेडियो स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत का भंडार भी है। कई सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय गीतों को भावी पीढ़ी के लिए रिकॉर्ड और संरक्षित करते हैं और स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा समुदाय को दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की अनूठी स्थिति इसे सामुदायिक सशक्तीकरण के लिए एक आदर्श माध्यम बनाती है।

सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन करने के लिए, 'भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन'नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत, उपकरणों की खरीद/उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए मौजूदा और साथ ही नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक रेडियो क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य गतिविधियों, जैसे- स्टेशनों की क्षमता निर्माण, पात्र संगठनों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय सम्मेलन, सामुदायिक रेडियो पुरस्कार शामिल हैं।

भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थिति

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश में सामुदायिक रेडियो क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नए सीआरएस की शुरुआत में काफी वृद्धि हुई है। अब तक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की अनुमति प्रदान करने के लिए कुल 674 आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं, जिनमें से 547 संगठनों ने ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (जीओपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं और 400 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू हैं। (16-12-2022 तक)

आज की तारीख में, देश में 400 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू हैं, जिनमें से 218 गैर-सरकारी संगठनों, 162 शैक्षणिक संस्थानों और 20 केवीके द्वारा संचालित हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 64 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को चालू किया गया है।

सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के संबंध में, सूचना प्रसारण मंत्रालय पात्र संगठनों को सामुदायिक रेडियो स्थापित करने के लिए प्रसारण सब पोर्टल (www.new.broadcastseva.gov.in) सरल पोर्टल के जरिए सरल कला इसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदनों की सुविधा के लिए एमआईपी पोर्टल को सरल संचार पोर्टल के साथ एकत्रित कर दिया गया है।

एफएम रेडियो

एफएम रेडियो पूरे देश में युवाओं और वयस्कों के बीच मनोरंजन के पसंदीदा साधनों में से एक है। स्थानीय भाषाओं में विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनों द्वारा पेश की जाने वाली विविधता का जनता स्वागत करती है, जैसा कि हाल के वर्षों में चैनलों की संख्या में वृद्धि और निजी एफएम प्रसारकों द्वारा एफएम चरण-3 के तहत आयोजित ई-नीलामी के दो बैचों में नए एफएम रेडियो चैनलों को प्राप्त करने के लिए दिखाए गए उत्साह से स्पष्ट है। यह स्थानीय व्यवसायों के लिए रेडियो विज्ञापनों के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक संभावित माध्यम के रूप में भी विकसित हुआ है।

मंत्रालय का एफएम प्रकोष्ठ भारत में निजी एफएम रेडियो

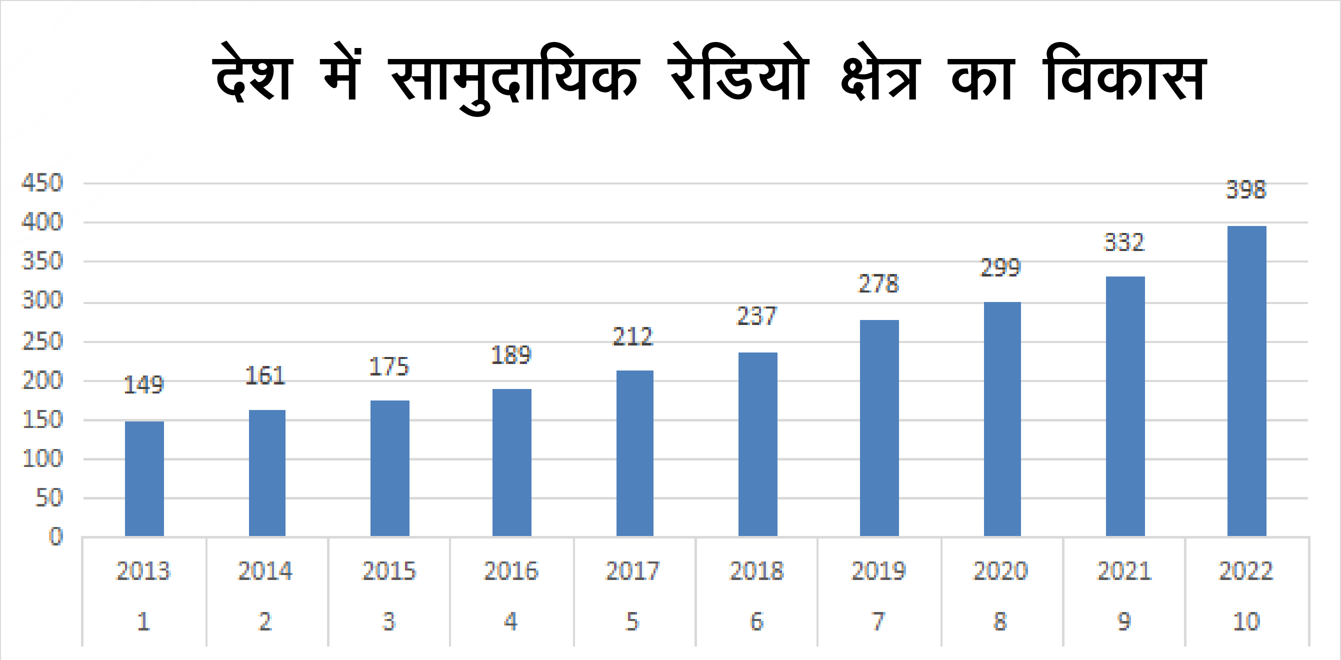

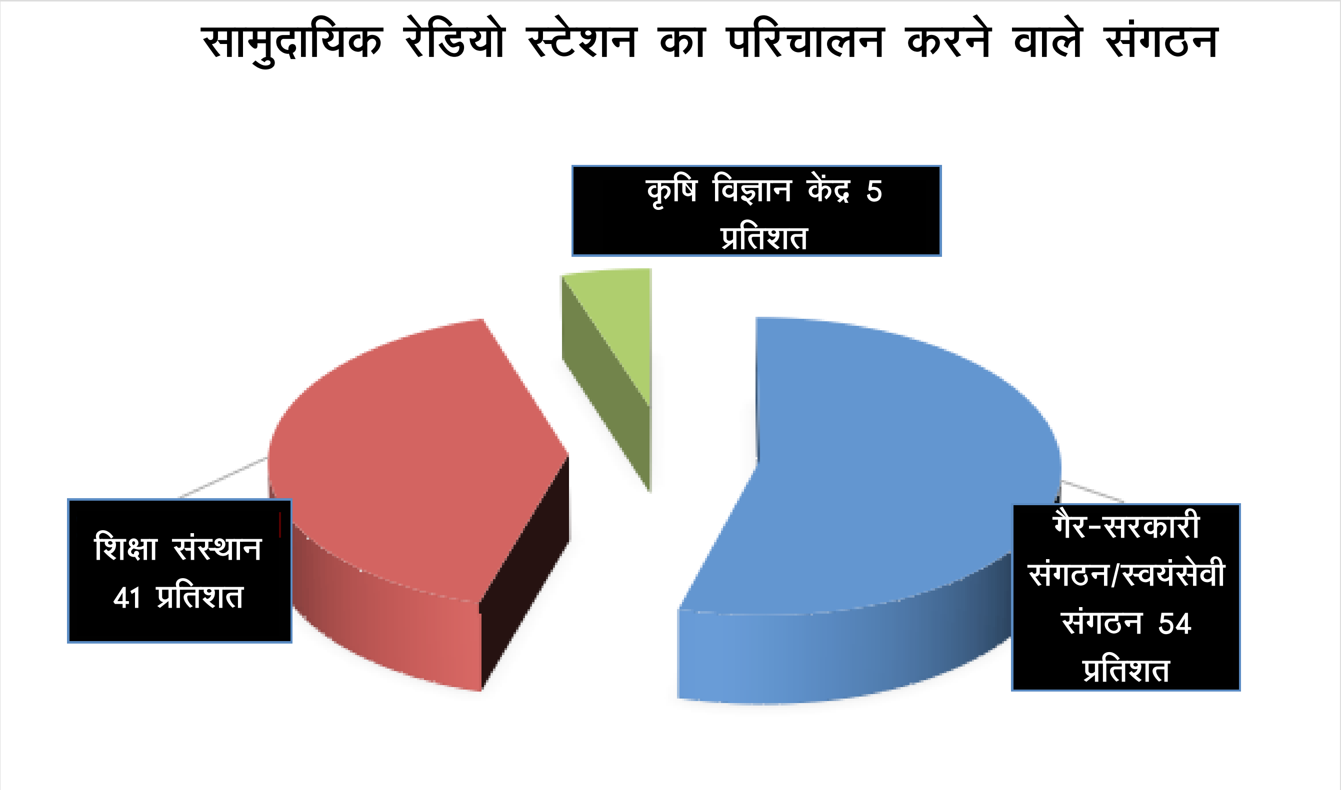

प्रसारण से संबंधित सभी मामलों को 7 जुलाई, 2011 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निजी एजेंसियों के चरण-3 के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार पर नीति दिशानिर्देशों के अनुसार देखता है। ये नीति दिशानिर्देश नवीनतम जानकारी के साथ मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निजी एफएम रेडियो चैनलों को केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के लेह तथा करगिल और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के भद्रवाह, कठुआ तथा पुंछ में चालू किया गया है। इस मंत्रालय से प्राप्त अनुरोध पर, ट्राई ने 284 शहरों में 807 चैनलों के लिए ताजा आरक्षित मूल्य प्रस्तुत किया है, जिनकी नीलामी एफएम चरण-III के बाद के बैचों में की जानी है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरकार के विकासात्मक एजेंडे

को आगे बढ़ाने के लिए जनता तक पहुंच बनाने के मंच के रूप में निजी एफएम रेडियो का भी उपयोग कर रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान निजी एफएम रेडियो स्टेशनों ने टीका लगवाने और मास्क पहनने, 2 गज की दूरी रखने और हाथों की सफ़ाई आदि जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार को अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशंसनीय प्रयास किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक सामान्य सलाह भी जारी की थी। निजी एफएम रेडियो प्रसारकों ने सभी सरकारी केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों में मुफ्त वैक्सीन 'बूस्टर खुराक़' के बारे में जागरूकता फैलाई। एफएम रेडियो चैनलों ने समय-समय पर विभिन्न सरकारी पहलों जैसे- आज़ादी का अमृत महोत्सव, नया दौर और अग्निवीर योजना को उचित कवरेज दिया है।

31.12.2022 तक, 26 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों में फैले देशभर के 113 शहरों में 388 एफएम रेडियो चैनल चालू थें।

पारदर्शिता, उपाय और पर्यवेक्षण

कंपनियों को एफएम रेडियो चैनलों की अनुमति आरोही ई-नीलामी के आधार पर दी जाती है। निजी प्रसारकों से त्रैमासिक लाइसेंस शुल्क के रूप में राजस्व, भारतकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एकत्र किया जाता है।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, प्रसारकों से विभिन्न अनिवार्य दस्तावेजों और लाइसेंस शुल्क तथा अन्य वित्तीय दस्तावेजों के संग्रह के लिए, एक ऑनलाइन पोर्टल 'ब्रॉडकास्ट सेवा' के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से प्रसारण सेवाओं का डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है।

निजी प्रसारकों द्वारा हस्ताक्षरित अनुमति प्रदान करने के समझौते (जीओपीए) और एफएम चरण-III नीति दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रावधान के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, इस मंत्रालय के एफएम प्रकोष्ठ के अधिकारी रेडियो स्टेशनों और सामान्य ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर (सीटीआई) सुविधाओं का निरीक्षण करते हैं।

सरकार को राजस्व उपार्जन

सरकार निजी प्रसारकों से गैर-वापसी के माध्यम से एक बार प्रवेश शुल्क, गैर-वापसी योग्य एकमुश्त प्रवासन शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क और टावर किराया तथा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त करती है।

वर्ष 2000 में निजी एफएम रेडियो प्रसारण की शुरुआत के बाद से सरकार को प्रसारकों से गैर-वापसी के माध्यम से एक बार प्रवेश शुल्क, गैर-वापसी योग्य एकमुश्त प्रवासन शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क और टावर किराया तथा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में पिछले 22 वर्षों में 6415.48 करोड़ रुपये राजस्व में मिला है जिसे आगे तालिका में दर्शाया गया हैः

डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम

डीएएस डिवीजन को सौंपे गए कार्य

क. केबल टीवी क्षेत्र में डीएएस का कार्यान्वयन।

ख. केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 को लागू करना।

ग. मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) पंजीकरण और संबंधित मामले।

घ. केबल टीवी क्षेत्र, एमएसओ और एलसीओ से संबंधित विशिष्ट नीतिगत मुद्दे

ङ. केबल टीवी सेगमेंट में विभिन्न हितधारकों के नियंत्रण, निगरानी और शिकायत निवारण के लिए केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत प्रसार भारती और अधिकृत अधिकारियों के साथ समन्वय।

वर्ष 2022-23 की प्रमुख गतिविधियां

- वर्ष के दौरान 40 एमएसओएस पंजीकरण प्रदान किए गए। साथ ही वर्ष के दौरान 26 एमएसओएस पंजीकरण रद्द कर दिया गया।

- एमएसओ द्वारा प्रदान की जाने वाली प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे के संबंध में ट्राई की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और इस संबंध में प्रासंगिक दिशानिर्देश डीएएस डिवीजन के आदेश दिनांक 30 नवंबर, 2022 द्वारा जारी कर दिए गए थे। केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994, मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को अपनी स्वयं की प्रोग्रामिंग सेवा को या तो सीधे अपने ग्राहकों को या एक या अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटरों के माध्यम से प्रसारित करने की अनुमति देता है। ये प्रोग्रामिंग सेवाएं जिन्हें 'प्लेटफॉर्म सर्विसेज (पीएस)' कहा जाता है, जिसमें अधिकांश स्थानीय

चैनल भी शामिल हैं, एमएसओ द्वारा पेश की जाने वाली स्थानीय स्तर पर उत्पन्न की जाने वाली विशिष्ट प्रोग्रामिंग सेवाएं हैं। ये दिशानिर्देश प्लेटफॉर्म सेवाएं चलाने वाले एमएसओ के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं।

- डीएएस डिवीजन ने एमएसओएस के पंजीकरण को संशोधित प्रसारण सेवा पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया है। तेज़ी से और पारदर्शी तरीके से आवेदनों पर काम करने के लिए पोर्टल और ई-ऑफिस के बीच निर्बाध एकीकरण है। आवेदक पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकेंगे। आंतरिक रूप से, कमियों को दूर करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करके अधिकारियों के अपने विवेक के आधार पर निर्णय के अधिकार को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक सुसंगत और उद्देश्यपूर्ण बन सके।

प्रसार भारती

प्रसार भारती (भारत का लोक सेवा प्रसारक) देश का एकमात्र लोक सेवा प्रसारक है, जिसके दो घटक आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन हैं। यह 23 नवंबर, 1997 को अस्तित्व में आया। इसे जनता को सूचित करने, शिक्षित करने , मनोरंजन करने के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को व्यवस्थित तथा संचालित करने और रेडियो तथा टेलीविज़न पर प्रसारण के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए जनादेश दिया गया था।

प्रसार भारती ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सामग्री की लाइव स्ट्रीमिंग, सूचनात्मक नई वेबसाइटें, यू-ट्यूब पर कार्यक्रमों की उपलब्धता, मोबाइल ऐप और एलेक्सा ने इन प्लेटफार्मों पर प्रसार भारती की जीवंत उपस्थिति सुनिश्चित की है। ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया परं सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। प्रसार भारती जैसे लोक सेवा प्रसारक की आवश्यकता 800 से अधिक चैनलों को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण है जो मुख्य रूप से व्यावसायिक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अत्यधिक व्यावसायीकृत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण में प्रसार भारती एकमात्र काउंटर-बैलेंसिंग बल है। वास्तव में, प्रसार भारती द्वारा विकसित किए गए नैतिक मानदंड और दिशानिर्देश उद्योग के लिए बेंचमार्क के रूप में काम कर रहे हैं।

उद्देश्य

प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में निर्धारित प्रसार भारती के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1) देश की एकता, अखंडता और संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखना।
2) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
3) जनहित के सभी मामलों पर सूचित होने और सूचना के उचित तथा संतुलित प्रवाह को प्रस्तुत करने के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना।
4) शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना।
5) महिलाओं के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना और बच्चों, वृद्धों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।
6) विविध संस्कृतियों, खेल और खेल तथा युवा मामलों को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना।
7) सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, श्रमिक वर्गों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना।
8) प्रसारण प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रसारण सुविधाओं तथा विकास का विस्तार करना।

प्रसार भारती बोर्ड

यह निगम प्रसार भारती बोर्ड द्वारा शासित है। बोर्ड में अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य (मुख्य कार्यकारी अधिकारी), सदस्य (वित्त) तथा सदस्य (कार्मिक), छह अंशकालिक सदस्य, सूचना और प्रसारण

मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के महानिदेशक इसके पदेन सदस्य हैं। प्रसार भारती बोर्ड की आम तौर पर वर्ष में कम से कम छह बार बैठकें होती हैं।

संगठनात्मक संरचना

आकाशवाणी का प्रमुख परंपरागत रूप से एक महानिदेशक होता है जिसकी सहायता कार्यक्रम, प्रशासन और वित्त विंग में अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) करते हैं और इंजीनियरिंग विंग में एक इंजीनियर-इन-चीफ होता है। समाचार विंग का नेतृत्व महानिदेशक (समाचार) करता है। महानिदेशालय, आकाशवाणी पर नीति निर्माण, योजना तथा विकास, बुनियादी ढांचे तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, बजटीय योजना तथा नियंत्रण, मानव संसाधन प्रबंधन तथा संचालन और रखरखाव गतिविधियों की देख-रेख का दायित्व है।

पहले आकाशवाणी में प्रोग्रामिंग को ग्यारह प्रोग्रामिंग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था; दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र-i और ii), मुंबई (पश्चिमी क्षेत्र- i और ii), बेंगलुरु (दक्षिणी क्षेत्र- i और ii), लखनऊ (मध्य क्षेत्र- i), भोपाल (मध्य क्षेत्र- ii), कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र- i और ii) और गुवाहाटी (उत्तर पूर्वी क्षेत्र) और परियोजना तथा रखरखाव इंजीनियरिंग गतिविधियों के लिए दिल्ली (उत्तर क्षेत्र), कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र), मुंबई (पश्चिम क्षेत्र), गुवाहाटी (उत्तर-पूर्व क्षेत्र) और चेन्नई (दक्षिण क्षेत्र) में स्थित पांच क्षेत्र। इन क्षेत्रों को अब भौगोलिक आधार पर उत्तर क्षेत्र (दिल्ली में), दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई में), पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता में), पश्चिम क्षेत्र (मुंबई में) और उत्तर पूर्व क्षेत्र (गुवाहाटी में) के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इसके अलावा, दूरदर्शन और आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनलों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय क्षेत्र भी बनाया गया है। इनमें से प्रत्येक जोन में एडीजी स्तर के अधिकारियों को जोनल हेड (कंटेंट ऑप्स), जोनल हेड (ब्रॉडकास्ट ऑप्स) और जोनल हेड (एडमिन) के रूप में तैनात किया गया था।

दूरदर्शन का संगठनात्मक ढांचा

दूरदर्शन का नेतृत्व महानिदेशक द्वारा किया जाता है। उनकी सहायता कार्यक्रम, प्रशासन और वित्त विंग में अतिरिक्त महानिदेशक और इंजीनियरिंग विंग में एक इंजीनियर-इन-चीफ करते हैं। समाचार विंग का नेतृत्व महानिदेशक (समाचार) करता है।

महत्वपूर्ण गतिविधियां और उपलब्धियां

आकाशवाणी

- ट्रांसमिशनः

क. 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरः 2 नग।

ख. एफएम ट्रांसमीटर कमीशन्ड : 2 स्थान

ग. आकाशवाणी के 79 स्टेशनों पर सर्वर और रेडियो ऑटोमेशन का एसआईटीसी पूरा किया गया। डिजिटल कंसोल की आपूर्ति की गई और 29 आकाशवाणी स्टेशनों पर स्थापना की जा रही है। गुवाहाटी में क्षेत्रीय अभिलेखीय सुविधा से संबंधित विभागीय कार्य पूर्ण किए गए हैं।

- **'रोज़गार मेला'** के अवसर पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में 71,000 नियुक्ति-पत्रों के वितरण और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सभी नई नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल 'कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल' के शुभारंभ का सीधा प्रसारण 22 नवंबर 2022 को किया गया।

- **जम्मू-कश्मीर एक नई सुबहः** (एनएसडी) आकाशवाणी ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर प्रशासन की उपलब्धियों को उजागर करने और कश्मीर घाटी में विभिन्न विकास गतिविधियों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी ने पिछले 2 वर्षों में एक विशेष श्रृंखला 'जम्मू-कश्मीर एक नई सुबह' चलाई।

- **हर घर तिरंगा और स्वतंत्रता दिवस 2022ः** एनएसडी आकाशवाणी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर ने एक विशेष श्रृंखला 'नो यूअर तिरंगा' चलाई, जिसके तहत तिरंगे से संबंधित विभिन्न पहलुओं और महत्वपूर्ण क्षणों को कवर करते हुए ट्वीट, ग्राफिक्स और वीडियो पोस्ट किए गए।

- **मन की बातः** प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को एनएसडी मुख्यालय के सभी प्रमुख समाचार बुलेटिनों और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (आरएनयू) के बुलेटिनों में शामिल किया गया। न्यूज़ऑनएआईआर वेबसाइट के जरिए कार्यक्रम की लाइव वेबकास्टिंग भी की गई। कार्यक्रम पर विशेष चर्चा भी आयोजित की गई।

- **महात्मा गांधी की जयंती और स्वच्छ भारत दिवसः**

महात्मा गांधी की 153वीं जयंती और स्वच्छ भारत दिवस को एनएसडी मुख्यालय और आरएनयू बुलेटिनों में व्यापक कवरेज दिया गया।

- **एक भारत श्रेष्ठ भारतः** (एनएसडी) आकाशवाणी, इसके आरएनयू और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) से संबंधित गतिविधियों और कार्यक्रमों को कवरेज दिया।

दूरदर्शन

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण विकासात्मक गतिविधियां इस प्रकार हैं

क. भुवनेश्वर, जम्मू और जालंधर में अर्थ स्टेशनों का आधुनिकीकरण ताकि उन्हें एचडी अनुरूप और स्पेक्ट्रम कुशल बनाया जा सके और मौजूदा अर्थ स्टेशन की सभी सेवाओं को पुराने पीडीए के साथ उन्नत अर्थ स्टेशन में स्थानांतरित किया जा सके।

ख. डीडीके देहरादून में मल्टी कैमरा मोबाइल उत्पादन सुविधा (ईएफपी वैन) का एसआईटीसी पूरा हुआ। हाई डेफिनेशन मल्टी-कैमरा मोबाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी (ईएफपी वैन) वीआईपी कवरेज/लाइव टेलीकास्ट/रिकॉर्डिंग सहित ओबी कार्यक्रमों की उत्पादन गुणवत्ता में वृद्धि की सुविधा प्रदान करती है।

ग. एचडी गुणवत्ता में कार्यक्रमों के उत्पादन के लिए 4 स्थानों (मुंबई, कोलकाता, रायपुर और लखनऊ) को 2 एम/ई (मिक्स इफेक्ट्स) हाई डेफिनिशन डिजिटल प्रोडक्शन स्विचर प्रदान किए गए।

घ. मोजो किट (20 संख्या), एनएलई और डेस्कटॉप आरएनयू/डीडीके को प्रदान किए गए हैं।

ङ 'वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर प्रसारण के तहत सामग्री वितरण नेटवर्क प्रदान किया गया है।

प्रसार भारती का ग्लोबल आउटरीच विंग

प्रसार भारती का ग्लोबल आउटरीच विंग, विदेशों के सार्वजनिक सेवा प्रसारकों/संगठनों के साथ समझौतों और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने जैसी अंतरराष्ट्रीय संबंध गतिविधियों से संबंधित है। यह प्रसार भारती के सभी कार्यक्षेत्रों में विदेशी प्रसारकों की आधिकारिक यात्रा की सुविधा प्रदान करता है, विदेशी एमओयू भागीदारों के साथ-साथ एबीयू, एआईबीडी आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रसारण संघों के लिए देश में/उप-क्षेत्रीय कार्यशालाओं/सम्मेलनों/कार्यक्रमों का आयोजन करता है; अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों/सम्मेलनों में अपने अधिकारियों की भागीदारी की व्यवस्था करता है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)/वर्ष के दौरान हस्ताक्षरित करारः

1. इस वर्ष के दौरान समझौता ज्ञापनों/ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए

क्र. सं.	देश	प्रसारक/संगठन	हस्ताक्षर/टिप्पणियों की तिथि	उद्देश्य
1	कोरिया	केबीएस कोरिया	21.12.2021 को आपसी सहमति से एक और साल के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया (01.01 .2022 से 31.12.2022 तक वैध)	ओटीटी प्लेटफॉर्म माईकेके पर डीडी इंडिया का प्रसारण
2	अमरीका	यप्प टीवी	07.03.2022	ओटीटी प्लेटफार्म पर डीडी इंडिया की मेजबानी। एमओयू के अनुसार, यप्प टीवी अमरीका, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और मध्य पूर्व में डीडी इंडिया को प्रसारित करेगा

क्र. सं.	देश	प्रसारक/संगठन	हस्ताक्षर/टिप्पणियों की तिथि	उद्देश्य
3	जर्मनी	डॉयचे वेले इको इंडिया समझौता ज्ञापन	14.03.2022	डीडी नेटवर्क पर इको इंडिया कार्यक्रम के प्रसारण के लिए
4	ऑस्ट्रेलिया	स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (एसबीएस)	17.03.2022	सामग्री आदान-प्रदान सह उत्पादन और प्रशिक्षण
5	फिजी	फिजी ब्रॉडकास्टिंग कोओपरेशन लि. (एफबीसी)	प्रसार भारती और एफबीसी फिजी के बीच समझौता ज्ञापन के अनुशेष पर हस्ताक्षर किए गए 18.03.2022	सामग्री आदान-प्रदान सह उत्पादन और प्रशिक्षण
6	अर्जेंटीना	रेडियो और टेलीविज़न अर्जेंटीना	22.04.2022	सामग्री आदान-प्रदान सह उत्पादन और प्रशिक्षण
7	मेडागास्कर	ओआरटीएम (ऑफिस डी ला रेडियो एट डे ला टेलिविज़न पब्लिक यूई डे मेडागास्कर)	10.05.2022	सामग्री का आदान-प्रदान, सह उत्पादन और प्रशिक्षण
8	फिजी	फिजी टेलीविज़न लि. (एफटीएल), फिजी	04.05.2022	सामग्री का आदान-प्रदान, सह उत्पादन और प्रशिक्षण
9	ब्राजील	एम्प्रेसा ब्राजील डे कोम्मन इकाको, (ईबीसी)	24.08.2022	सामग्री आदान-प्रदान सह उत्पादन और प्रशिक्षण
10	थाईलैंड	थाई पीबीएस	17.08.2022	सामग्री आदान-प्रदान सह उत्पादन और प्रशिक्षण

क्र. सं.	देश	प्रसारक/संगठन	हस्ताक्षर/टिप्पणियों की तिथि	उद्देश्य
11	बांग्लादेश	बीटीवी, बांग्लादेश	06.09.2022	डीडी इंडिया चैनल को बांग्लादेश में और बीटीवी चैनल को डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म पर पारस्परिक आधार पर दिखाने के लिए
12	सर्बिया	पिंक टीवी सर्बिया	26.10.2022	सामग्री आदान-प्रदान सह उत्पादन और प्रशिक्षण
13	पराग्वे	परागुआयन नेशनज ऑडियो वीडियो संस्थान, एमओआईसीटी, पराग्वे गणतंत्र	12.12.2022	सामग्री का आदान-प्रदान, सह उत्पादन और प्रशिक्षण
14	जर्मनी	डॉयचे वेले (मंथन समझौता ज्ञापन)	12.12.2022	डीडी नेटवर्क पर मंथन वेब कार्यक्रम के प्रसारण के लिए

टीवी कार्यक्रमों का सह-निर्माण : ईबीएस, कोरिया के साथ 'बीस्ट्स ऑफ़ एशिया' नामक चौथा अंतरराष्ट्रीय सह-निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और 23 और 24 अप्रैल 2022 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया।

संयुक्त कार्य समूह का गठन : एक संयुक्त कार्य समूह जिसमें प्रसार भारती, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे, का गठन किया गया था ताकि दुनिया भर में डीडी इंडिया चैनल के वितरण की संभावनाओं की खोज सहित अंतरराष्ट्रीय प्रसारकों के साथ प्रसार भारती के सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार की जा सके। संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक 24.01.2022 को आयोजित की गई।

सीईओ, प्रसार भारती और एडीजी (जीओ) की राजदूतों/ विदेशी प्रसारकों के साथ बैठकें

डीडीआई चैनल को बढ़ावा देने और प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए, विभिन्न देशों के राजदूतों/ भूटान, फ्रांस, एमबीसी मॉरीशस, एनएचके जापान, एटीएन कनाडा, वीओवी वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस आदि जैसे विभिन्न विदेशी प्रसारकों के प्रमुखों के साथ सीईओ, प्रसार भारती/एडीजी (जीओ) की ऑनलाइन/ऑफलाइन बैठकें प्रसारण के क्षेत्र में आपसी सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा और पता लगाने के लिए आयोजित की गईं।

अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी

- **एबीयू रोबोकॉन 2022** : प्रसार भारती ने त्यागराज स्टेडियम में 21 अगस्त, 2022 को एबीयू रोबोकॉन 2022 की मेजबानी सफलतापूर्वक पूरी की। 12 देशों (भारत सहित) की 13 टीमों

ने वर्चुअली भाग लिया।

- **एआईबीडी महा सम्मेलन (19-21 सितंबर 2022)**: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्रसार भारती ने 19 और 21 सितंबर, 2022 को '47वीं वार्षिक सभा/20वीं एआईबीडी जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एसोसिएटेड मीटिंग्स 2022' की मेजबानी। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा किया गया था। 19 सितंबर 2022 को आयोजित उद्घाटन समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यक्रम ने भाग लिया। 16 एआईबीडी सदस्य देशों के लगभग 30 विदेशी प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में इस कार्यक्रम में भाग लिया।

- **एबीयू ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 (3-5 अक्टूबर 2022)** प्रसार भारती ने 3-5 अक्टूबर 2022 तक सफलतापूर्वक ग्लोबल न्यूज़ फोरम (जीएनएफ) 2022 की मेजबानी की है। इस कार्यक्रम में एबीयू सदस्य देशों के लगभग पचास विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में स्थानीय मीडिया इकाइयों और भारत में विदेशी समाचार एजेंसी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

- **एबीयू महासभा और संबद्ध बैठकें 2022 (25-30 नवंबर 2022)**: प्रसार भारती ने 25-30 नवंबर 2022 तक 59वीं एबीयू महासभा और संबद्ध बैठकों की मेजबानी की। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिनांक 29.11.2022 को आयोजित समारोह में किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री के अलावा सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। 43 एबीयू सदस्य देशों के सीईओ/डीजी रैंक के लगभग 330 विदेशी प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री सुनील, एडीजी को 30.11.2022 को आयोजित एबीयू महासभा के सीमित सत्र के दौरान एबीयू का नया उपाध्यक्ष चुना गया।

बीआईएनडी योजना के अंतर्गत निधि आवंटन के संबंध में प्रसार भारती का विवरण

1. वर्ष 2022-23 के लिए बीआईएनडी योजना के लिए स्वीकृत धनराशि- 315 करोड़ रुपये।

2. दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक किया गया व्यय - 69.98 करोड़ रु.

वर्ष 2022-23 के लिए बीआईएनडी योजना के तहत शुरू की गई दूरदर्शन की परियोजनाओं की स्थिति

कार्यान्वयनाधीन प्रमुख परियोजनाएं, जिनके चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरी होने की संभावना हैः

क. कोलकाता, लखनऊ और जयपुर में अर्थ स्टेशनों का आधुनिकीकरण उन्हें एचडी अनुरूप और स्पेक्ट्रम कुशल बनाने के लिए।

ख. बेहतर दक्षता और विश्वसनीयता के लिए (चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, भुवनेश्वर और अहमदाबाद) में अपलिंक एंटीना सिस्टम का एसआईटीसी।

ग. सीमावर्ती क्षेत्रों सहित दूरस्थ, जनजातीय और वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में डीटीएच रिसीव सेट (1,20,000 नग) का वितरण, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डिजिटल युग की पहुंच के भीतर लाने के लिए, जो मुख्य रूप से गुणवत्ता की जानकारी से कटे रहते हैं।

घ. बेहतर दक्षता और विश्वसनीयता के लिए डीटीएच पीतमपुरा (सी-बैंड), दिल्ली अर्थ स्टेशन का उन्नयन।

ङ सीमा क्षेत्रों में बेहतर टैरेस्ट्रियल कवरेज के लिए पटनीटॉप और ग्रीन रिज (जम्मू और कश्मीर) में एचपीटी स्थापित किए गए हैं।

च. सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर टैरेस्ट्रियल कवरेज के लिए राजौरी (जम्मू और कश्मीर) में एचपीटी (दो नग) की स्थापना।

छ. डीडीके शिमला के लिए एनआरसीएस और विविध उपकरणों की 24x7 संचालन आई/सी स्थापना के लिए स्क्रिप्ट न्यूज़ ऑटोमेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित एकीकृत समाचार उत्पादन सुविधा। इससे डीडीके शिमला में तकनीकी सुविधाएं बढ़ेंगी।

ज. डीडीके/आरएनयू के लिए एलईडी वीडियो वॉल। वीडियो वॉल सेट और समग्र उत्पादन गुणवत्ता के रूप और अनुभव में व्यापक सुधार करती है।

झ. डीडीके हैदराबाद में फाइल आधारित वर्क फ्लो सुविधा का प्रावधान। यह भौतिक मीडिया की आवश्यकता के बिना निर्बाध प्रसारण/रिकॉर्डिंग में मदद करेगा।

ञ. समाचार मुख्यालय, दिल्ली में स्वचालित समाचार उत्पादन प्रणाली का प्रावधान।

फ्री-टू-एयर डीटीएच 'डीडी फ्री डिश'

दूरदर्शन ने दिसंबर, 2004 में 33 टीवी चैनलों के साथ अपनी फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा 'डीडी फ्री डिश' (पहले की डीडी डायरेक्ट) शुरू की। डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता को बाद में 59 टीवी चैनलों तक बढ़ाया गया। डीटीएच सिग्नल देश में कहीं भी (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) छोटे आकार के डिश रिसीव यूनिट की मदद से प्राप्त किए जा सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए, 10 चैनलों के साथ सी-बैंड में डीटीएच सेवा सितंबर, 2009 से शुरू की गई थी। दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म 'डीडी फ्री डिश' का 59 से 104 चैनलों तक उन्नयन दिसंबर, 2014 में पूरा हुआ, जिसे बाद में बढ़ाकर 112 कर दिया गया। दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म के 128 एसडीटीवी चैनलों तक उन्नयन, दूरदर्शन की स्वीकृत 3-वर्षीय (2017-20) विस्तार योजना के हिस्से के रूप में पूरा कर लिया गया है।

वर्तमान में प्रसार भारती की फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा 'डीडी फ्रीडिश' बीआईएसएजी गांधीनगर द्वारा चलाए जा रहे 51 शैक्षिक चैनलों सहित 160 से अधिक टीवी चैनलों को बिना किसी मासिक सदस्यता के मुफ्त में चला रहा है।

डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म एमपीईजी-2 डीवीबी-एस और एमपीईजी-4 डीवीबी डीवीबी-एस 2 तकनीक का उपयोग कर रहा है। ऐप आधारित/कॉल आधारित/एसएमएस आधारित प्राधिकरण और सक्रिय सुविधा के प्रावधान के साथ 1.2 लाख एफटीए डीटीएच, गैर-सीएएस, गैर-आरपीडी रिसीव सेट (एसटीबी के साथ) खरीदने की मंजूरी दी गई है। विवरण वेबसाइट www.doordarshan.gov.in और www.prasarbharati.gov.in उपलब्ध है।

ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड

ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल), सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। इसे 1995 में रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण इंजीनियरिंग के संपूर्ण सरगम, प्रसारण सुविधाओं की स्थापना अर्थात सामग्री उत्पादन सुविधाएं, टैरेस्ट्रिल जैसे भारत और विदेशों में उपग्रह तथा केबल प्रसारण को शामिल करते हुए परियोजना परामर्श सेवाएं और टर्नकी समाधान प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।

बेसिल ने अब कार्यनीतिक परियोजनाओं जैसे- सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (अर्थात् सीसीटीवी, अभिगम नियंत्रण, घुसपैठ, अग्नि सुरक्षा, हाइड्रेंट्स, आदि), फ़िल्मों, सेंटिनल एनालिटिक्स, काउंटर ड्रोन/यूएवी आदि सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सामग्री के क्षेत्रों में विविधता ला दी है। गतिविधियों में आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण तथा कमीशनिंग, परामर्श सेवाएं, तकनीकी लेखा परीक्षा, मीडिया विश्लेषण, आर एंड डी, डिजिटल इंडिया से संबंधित परियोजनाएं, शहर निगरानी, सुरक्षित शहर, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया विनिर्माण, ऑडियो वीडियो और डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, इंजीनियरिंग, खरीद तथा निर्माण, परियोजना प्रबंधन सेवाएं, संचालन तथा रखरखाव, जनशक्ति प्लेसमेंट, एएमसी और महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के लिए कुल टर्नकी परियोजना और अन्य सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

बेसिल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा में और क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु तथा कोलकाता में हैं। बेसिल व्यापार पोर्टफोलियो में विविधीकरण के कारण कई राज्यों में भौगोलिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है।

1. **मंत्रालय तथा उसकी मीडिया इकाईयों के लिए निष्पादित प्रमुख परियोजनाएं/व्यावसायिक गतिविधियां**

एफएम प्रसारण के लिए परामर्श और टर्नकी समाधान : बेसिल स्थापना और सामग्री निगरानी के लिए भारत में निजी एफएम प्रसारकों को सेवाएं प्रदान करने में शामिल रहा है। बेसिल निजी एफएम प्रसारकों की विभिन्न एफएम प्रसारण साइटों के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में भी काम कर रहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केबल टीवी मॉनिटरिंग सेल की स्थापना : कार्य के दायरे में एक केंद्रीय इकाई की स्थापना, केंद्रीय इकाई के लिए अनुबंध कर्मचारियों की भर्ती, ऑनलाइन केबल टीवी निगरानी प्रणाली का विकास, एसटीबी सीडिंग की निगरानी के लिए एमआईएस ऐप्लीकेशन का रखरखाव और केबल टीवी उद्योग के सभी हितधारकों को अद्यतन तथा आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित वेबसाइट का

रखरखाव शामिल है।

भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय का स्वचालन : कार्य के दायरे में वेब सक्षम ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन के लिए भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय की सहायता करने के लिए जनशक्ति, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और संबंधित सेवाएं प्रदान करना शामिल है। परियोजना के हिस्से के रूप में – शीर्षक सत्यापन और ई–फाइलिंग ऐप्लिकेशन को विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

डीपीडी के सीआईएम सिस्टम का वार्षिक रखरखाव : बेसिल, इन–हाउस जनशक्ति की सहायता के साथ, प्रकाशन विभाग निदेशालय की कम्प्यूटरीकृत इन्वेंटरी प्रबंधन (सीआईएम) प्रणाली का रखरखाव कर रहा है।

प्रसारण सेवा पोर्टल का नवीनीकरण और उन्नयन : सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बेसिल को प्रसारण सेवा पोर्टल के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए नियुक्त किया है। बेसिल ने सफलतापूर्वक विभिन्न विभागों के साथ बातचीत की है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुसार पोर्टल के विकास को प्रबंधित किया है।

2. **टीवी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों के डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट करना**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विनियम के अनुसार लेखापरीक्षा : बेसिल, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम 2017 के तहत आवश्यक वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीटीएच, एमएसओ, एचआईटीएस) के डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (सीएएस, एसएमएस और एसटीबी) का ऑडिट कर रहा है। दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण के निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षण।

दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय न्यायाधिकरण के दिशानिर्देशों अनुसार लेखा परीक्षा : बेसिल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) के विशिष्ट निर्देशों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीटीएच, एमएसओ, एचआईटीएस) का ऑडिट कर रहा है।

3. **सीसीटीवी निगरानी अभिगम नियंत्रण प्रणाली**

बेसिल ने सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, इसरो टेलीमेट्री में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु, नेशनल मीडिया सेंटर, रक्षा मंत्रालय (डवक्) के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम– गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि. जैसे विभिन्न सरकारी ग्राहकों को सीसीटीवी सर्विलांस एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की नियोजन और स्थापना की सेवाएं प्रदान की हैं।

4. **विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के लिए व्यावसायिक सोशल मीडिया प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना**

बेसिल को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने काम की दृश्यता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नियुक्त किया गया है।

5. **पेशेवर ऑडियो-विजुअल सेवाओं के लिए परामर्शी सेवाएं**

बेसिल नालंदा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, झारखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे विभिन्न ग्राहकों के लिए ऑडियो–विजुअल समाधानों के लिए आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए सेवाएं प्रदान करने में शामिल है।

6. **निगरानी और विश्लेषिकी सेवाएं**

बेसिल ने केंद्रीकृत निगरानी–तंत्र की स्थापना के साथ 900 टीवी चैनलों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर का विस्तार किया है।

7. **वास्तविक समय सत्यापन के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के बायोमेट्रिक इंप्रेशन और चेहरे की तस्वीरें लेने की सेवाएं**

8. **परिचालन और रखरखाव सहायता**

भारतीय खेल प्राधिकरण में कॉल सेंटर : बेसिल ने आईटी और कॉल सेंटर प्रणाली के दैनिक संचालन और रखरखाव के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए आईटी सक्षम फीडबैक और निगरानी कॉल सेंटर की स्थापना की थी।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), सीरिया : बेसिल ने भारत–सीरिया नेक्स्ट जेनरेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, स्थापना,

कमीशनिंग और ऑन-साइट वारंटी समर्थन के लिए परियोजना को निष्पादित किया है।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना : बेसिल ने कर्नाटक सरकार की राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के घटक 'क' के तहत अंतिम मील के लिए आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और सेवाओं के लिए परियोजना को क्रियान्वित किया है।

33/11 केवी सब-स्टेशन और एलटी/एचटी वितरण लाइनों का संचालन और रखरखाव : बेसिल ने मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न सर्किलों में 33/11 केवी सब स्टेशनों और एलटी/एचटी वितरण लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए परियोजना को निष्पादित किया है।

9. कर्मचारियों की जनशक्ति नियुक्ति और तैनाती के बाद का प्रबंधन

बेसिल देशभर में विभिन्न सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकायों में राष्ट्रीय महत्व की ई-गवर्नेंस परियोजनाओं और विभिन्न श्रेणियों जैसे- पेशेवर, तकनीकी, गैर-तकनीकी, कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल, अत्यधिक कुशल के लिए जनशक्ति सेवाएं प्रदान करने वाला अग्रणी सरकारी संगठन है। बेसिल लगभग 40 सरकारी संगठनों को जनशक्ति प्रदान कर रहा है जिसमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, एम्स, निर्वाचन आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं।

10. अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं

- पूरे अफगानिस्तान में टीवी ट्रांसमीटरों की स्थापना के अलावा काबुल में सैटेलाइट टेलीपोर्ट। काबुल में शॉर्टवेव रेडियो ट्रांसमीटर की स्थापना।
- मालदीव रेडियो प्रसारण निगम के लिए सी-बैंड अपलिंक उपग्रह प्रणाली की स्थापना।
- ढाका में बांग्लादेश टीवी के लिए दो टीवी स्टूडियो की स्थापना की
- काबुल में 'एरियाना प्राइवेट टीवी चैनल' की स्थापना।
- फिजी, कुक आइलैंड्स, नाउरू, जॉर्डन, पापुआ, न्यू गिनी में आईटी में उत्कृष्टता केंद्र में आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और ऑनसाइट सहायता।
- म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मांडले और माइटकीना, म्यांमार के लिए क्लास रूम इक्विपमेंट, नेटवर्क इक्विपमेंट, वर्क स्टेशन और वीएमवेयर आदि के लिए आपूर्ति, इंस्टालेशन, कमीशनिंग और ऑन-साइट सपोर्ट

11. रोज़गारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

बेसिल गुणवत्तापूर्ण नौकरी उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश कर रहा है। गुणवत्ता कुशल पेशेवरों की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बेसिल ने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग, मल्टीमीडिया, दूरसंचार और मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी, आंतरिक डिज़ाइन, फ़ैशन प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन, डेटा विज्ञान, शिक्षक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग, लेखा और वित्त, रसद आदि में अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से व्यापक पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है।

12. भावी व्यावसायिक गतिविधि

कंपनी, आने वाले वर्षों में लाभ बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नए व्यावसायिक क्षेत्रों में विविधता लाई है:

कार्यनीतिक परियोजनाएं

(1) **ड्रोन-साइबर और एयरोस्पेस सुरक्षा:** बेसिल संगठनों के आधुनिकीकरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए और ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि के लिए परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करते हुए ड्रोन और काउंटर ड्रोन में टर्नकी परियोजनाएं चलाता है।

(2) **बेसिल डिजिटल फोरेंसिक लैब** : डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला को नवीनतम उपकरणों और सॉफ्टवेयर की खरीद के साथ स्थापित किया गया है। वैज्ञानिक अधिकारियों, जिन्होंने विभिन्न संस्थानों में विशेषज्ञता प्रशिक्षण प्राप्त किया है और विभिन्न फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का अनुभव रखते हैं, को प्रयोगशाला में नियुक्त किया गया है। प्रयोगशाला अब कंप्यूटर फोरेंसिक, मोबाइल फोरेंसिक, आईओएस और एंड्रॉइड विश्लेषण, फोरेंसिक डेटा रिकवरी, ईमेल फोरेंसिक,

क्लाउड और आईओटी फोरेंसिक, सीसीटीवी फोरेंसिक और ड्रोन फोरेंसिक जैसे कार्य लेने के लिए तैयार है।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के 55,589.72 लाख रुपये के कुल कारोबार की तुलना में 35.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 75,420.02 लाख रुपये का कारोबार किया है। इसके अलावा, कंपनी का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2020-21 में 50.45 लाख रुपये से बढ़ कर वित्त वर्ष 2021-22 में 1,762.87 लाख रुपये हो गया है। बेसिल की 27 वर्षों की यात्रा में टर्नओवर के साथ-साथ शुद्ध लाभ सबसे अधिक दर्ज किया गया है और क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से राजस्व में 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी वित्त वर्ष 2020-21 के 101.06 लाख रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 1851.58 लाख रुपये हो गई है।

बेसिल ने रणनीतिक परियोजनाओं में भी विविधता के साथ प्रवेश किया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में निष्पादन के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर बुक किए हैं, जो कंपनी राजस्व की मजबूती दर्शाता है।

■■■

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 19 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) की 47वीं वार्षिक सभा और 20वें सामान्य सम्मेलन तथा संबद्ध बैठक के दौरान एप्रीशिएशन अवॉर्ड प्रदान करते हुए। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी उपस्थित थे।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 17 मई, 2022 को फ्रांस में कान फ़िल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अब तक के सबसे बड़े भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करते हुए।

6 फ़िल्म क्षेत्र

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (आईएफएफआई), अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों के आयोजन, फ़िल्मों का प्रमाणन, फ़िल्म शूटिंग की अनुमति, राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के आयोजन सहित फ़िल्म सामग्री के उत्पादन, प्रसार और संरक्षण आदि जैसे फ़िल्म क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों को फ़िल्म स्कंध द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

इस संबंध में, सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में प्रभावी ढंग से सूचना का प्रसार करने के लिए मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करना मंत्रालय का दृष्टिकोण है।

फ़िल्म क्षेत्र से संबंधित मंत्रालय का मिशन है:

- सभी उम्र के लोगों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए अच्छे और मूल्य-आधारित सिनेमा को बढ़ावा देना और विकसित करना तथा इसे पूरा करने के लिए एक नीतिगत संरचना तैयार करना।
- फ़िल्मों, वीडियो और ऑडियो संसाधनों की अभिलेखीय संपदा तक सार्वजनिक पहुंच को पुनर्स्थापित, डिजिटलीकृत, संरक्षित और सार्वजनिक पहुंच तक विस्तारित करना।
- फ़िल्म महोत्सवों और समारोहों के माध्यम से अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना और फ़िल्म संस्कृति का प्रचार करना।

फ़िल्म प्रभाग

भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत 1948 में फ़िल्म प्रभाग की स्थापना की गई थी। सिनेमा के माध्यम से अनगिनत परिदृश्यों में राष्ट्र के इतिहास, उसकी यात्रा और सर्वांगीण विकास से अवगत कराना इस प्रभाग उद्देश्य था। फ़िल्म प्रभाग की कहानी स्वतंत्रता के बाद से देश के घटनापूर्ण वर्षों के साथ समकालिक है और पिछले 74 वर्षों में, फ़िल्म प्रभाग राष्ट्र निर्माण से जुड़ी गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी को सूचीबद्ध करने की दृष्टि से भारतीय जनता के विशाल समूह को प्रेरित कर रहा है। यह प्रभाग देश में फ़िल्म निर्माण की संस्कृति को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने में सक्रिय रहा है, जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण और सामाजिक प्रतिबद्धता का सम्मान करती है। यह मीडिया इकाई सेल्युलाइड और डिजिटल प्रारूप में अमूल्य सामग्री का भंडार है और इसके पुस्तकालय में 9,000 से अधिक टाइटल हैं।

राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लोगों को शिक्षित और प्रेरित करना और देश की छवि और देश की विरासत को भारतीय और विदेशी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना प्रभाग का लक्ष्य और उद्देश्य है। फ़िल्म प्रभाग का उद्देश्य वृत्तचित्र फ़िल्म आंदोलन के विकास को बढ़ावा देना है, जो सूचना, संचार और लोकसंपर्क क्षेत्रों में देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान में यह मुद्दों और विषयों के व्यापक परिदृश्य को कवर करने वाले वृत्तचित्र, ऐनिमेशन फ़िल्मों और सार्वजनिक सेवा जागरूकता (पीएसए) फ़िल्मों का निर्माण करता है। यह सिनेमा घरों द्वारा स्क्रीनिंग के लिए सामयिक महत्व की पीएसए सामग्री वितरित करता है, पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों, फ़िल्म सोसाइटियों और स्वयंसेवी संगठनों की मदद से फ़िल्म समारोहों और विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था करता है, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू फ़िल्म समारोहों में भाग लेता है, टेलीविज़न चैनलों और विदेश मंत्रालय को ऋण के रूप में फ़िल्में देता है, डिजिटल प्रारूप में ऑनलाइन और ऑफलाइन फ़िल्मी सामग्री का विपणन करता है तथा भारत और विदेशों में प्रोडक्शन हाउसों द्वारा अभिलेखीय फुटेज की आवश्यकता को पूरा करता है।

फ़िल्म प्रभाग हर साल पीएसए फ़िल्मों के साथ-साथ कला, संस्कृति, उद्योग, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कृषि, जीवनी, इतिहास, खेल, महिला सशक्तीकरण, भूमि, वनस्पति और जीव और सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों और

विविधताओं आदि विषयों पर 100 से अधिक वृत्तचित्र, लघु और ऐनिमेशन फ़िल्मों का निर्माण करता है। फ़िल्म प्रभाग के पास मौजूद रचनात्मक जनशक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग इन-हाउस फ़िल्म निर्माण के साथ-साथ स्वतंत्र फ़िल्म निर्माताओं और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वृत्तचित्रों के निर्माण में सहायता के लिए किया जाता है।

1. फ़िल्म प्रभाग के स्कंध

फ़िल्म प्रभाग को तीन स्कंधों में विभाजित किया गया है:

(1) प्रोडक्शन (उत्पादन)

(2) वितरण और लोकसंपर्क

(3) प्रशासन और वित्त

(क) प्रोडक्शन स्कंध (उत्पादन स्कंध)

यह स्कंध सार्वजनिक सूचना, शिक्षा और शिक्षण और सांस्कृतिक उद्देश्यों को लेकर प्रेरणा के लिए भारत सरकार द्वारा आवश्यक वृत्तचित्रों और अन्य फ़िल्मों के उत्पादन और वितरण के लिए उत्तरदायी है।

स्कंध ने 1 जनवरी, 2022 से 29 दिसंबर, 2022 तक कला और संस्कृति, शिक्षा, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वच्छता तक विभिन्न विषयों तथा अवधि पर आधारित इन-हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ बाहरी निर्माताओं के माध्यम से 53 वृत्तचित्र, ऐनिमेशन और पीएसए फ़िल्मों का निर्माण पूरा कर लिया।

2022-23 के दौरान उल्लेखनीय पहल

1. **महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय** द्वारा प्रायोजित **आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)** पर 5 पीएसए फ़िल्में पूरी हो चुकी हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज और प्रसारित की जाएंगी।

2. उल्लेखनीय विषयों जैसे **चित्रमौली, दिलीप कुमार, एचएस दोरेस्वामी - गांधीवादी और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, धोबी घाट, इंडिया@75, योग दिवस, फर्स्ट इंक (स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्री श्याम सरन नेगी पर फ़िल्म), रेवन्ना उमादेवी - विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन, आपदा प्रबंधन जीवन और पर्यावरण की रक्षा, तेनजिंग बोडोसा - एक आदिवासी उद्यमी की कहानी, पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे, टाइगर आर्मी, वार विडोज डिक्लियर पीसः परिवार पुनर्वास कार्यक्रम, हर स्टोरी ऑफ स्काई - डॉ. श्रुति महापात्रा** पर फ़िल्में पूरी हो चुकी हैं।

3. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती विषय पर **वार एंड वरशिप** शीर्षक के तहत बाहरी फ़िल्म निर्माता को सौंपी गई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म पूरी हो गई है।

4. आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत, प्रभाग अभिलेखागार और अन्य स्रोतों से प्राप्त फुटेज के आधार पर फ़िल्म प्रभाग की टीम द्वारा 5 पीएसए फ़िल्मों का निर्माण किया गया।

5. उल्लेखनीय विषयों जैसे- **देविका रानी, वसीम बरेलवी, इसरो, बापू का आखिरी घर, जे. एल. कौल - ए मैन ऑफ एक्शन, पद्मश्री वरप्पा नाबा - फोक टू मेनस्ट्रीम, कैमेलिया, ट्री मैन ऑफ़ राजस्थान पद्मश्री हिम्मत राम भंभु, भज्जू श्याम और गोंड 'आदिवासी' पेंटिंग का रहस्य, श्री के.के मुहम्मद के धर्म और कर्म** पर फ़िल्मों का निर्माण किया जा रहा है।

6. स्वच्छता विषय पर बाहरी फ़िल्म निर्माताओं को सौंपी गई 2 एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में निर्माणाधीन हैं।

प्रोडक्शन एवं लोक संपर्क पहल - इंडिया@75

(i) भारत की आज़ादी के 75 सालों में 'विकास, शासन, प्रौद्योगिकी, सुधार, प्रगति और नीति' को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ और (ii) आम पुरुषों और महिलाओं की सफलता की कहानियां, जिन्होंने समाज में असाधारण योगदान किया है और जिन्हें पिछले पांच से छह वर्षों के दौरान पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, इन विषयों पर 21 वृत्तचित्र फ़िल्में बाहरी फ़िल्म निर्माताओं को सौंपी गई हैं, जिनमें से 5 फ़िल्में पूरी हो चुकी हैं और 16 फ़िल्में निर्माणाधीन हैं।

भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय

भारत के समृद्ध सिनेमा के इतिहास को प्रदर्शित करने के साथ-साथ सिनेमा के विकास के माध्यम से प्रकट होने वाले देश के सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास को समाहित करने के लिए मुंबई में फ़िल्म प्रभाग परिसर में भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय (एनएमआईसी) स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय दृश्य और ग्राफिक, फ़िल्म क्लिपिंग, कलाकृतियों, प्रचार सामग्री,

इंटरैक्टिव प्रदर्शन, आदि की मदद से दर्शकों को भारतीय सिनेमा की एक सदी से अधिक की दिलचस्प यात्रा के माध्यम से एक कहानी कहने की विधा में ले जाता है। संग्रहालय के हिस्से के रूप में 'गांधी और सिनेमा' विषय पर एक विशेष गैलरी स्थापित की गई है।

भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय के नए भवन (फेज-II) का निर्माण और गुलशन महल (फेज-I) की रेट्रो-फिटिंग नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा की गई है। श्री श्याम बेनेगल की अध्यक्षता वाली संग्रहालय सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस द्वारा गैलरियों की कल्पना, डिज़ाइन और क्यूरेटिंग की गई है। संग्रहालय के निर्माण, क्यूरेशन और डिज़ाइनिंग की कुल लागत 156.39 करोड़ रुपये है।

एनएमआईसी के संचालन और रखरखाव को मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में 31 दिसंबर, 2021 से राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम को स्थानांतरित कर दिया गया है।

(बी) वितरण और लोकसंपर्क स्कंध

फ़िल्म प्रभाग के छह वितरण शाखा कार्यालय कोलकाता, विजयवाड़ा, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और बेंगलुरु में स्थित हैं। मुंबई और नई दिल्ली में इसके प्रदर्शक प्रकोष्ठ हैं। शाखा कार्यालय और प्रदर्शक सेल अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सिनेमा घरों द्वारा पीएसए फ़िल्मों की अनिवार्य स्क्रीनिंग की निगरानी करते हैं, फ़िल्म समारोह और विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करते हैं और फ़िल्म डिवीजन की सामग्री के विपणन की निगरानी करते हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों का नियंत्रण और निगरानी फ़िल्म प्रभाग मुख्यालय, मुंबई में डीएचओ द्वारा की जाती है।

लोकसंपर्क गतिविधियां

(I) फ़िल्म समारोहों में पुरस्कृत/चयनित/प्रविष्ट/प्रदर्शित की गई फ़िल्में

1. पुरस्कारः 68वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार

1. व्हीलिंग द बॉल - बेस्ट एक्सप्लोरेशन फ़िल्म (स्पोर्ट्स सहित) - मुकेश शर्मा

2. पबुंग स्याम - सर्वश्रेष्ठ जीवनी फ़िल्म - हौबम पबन कुमार

क्र. सं.	फ़िल्म पुरस्कार/ फ़िल्म महोत्सव का नाम	फ़िल्मों की सं.
1.	ब्राजील इंटरनेशनल मंथली इंडिपेंडेंट फ़िल्म फ़ेस्टिवल (बीआईएसआईएफएफ)	1
2.	फेस्टिवल इंटरनेशनल डे सिने ऑस्ट्रेलिया - अर्जेंटीना	1
3.	17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, 2022	2
4.	शिमला का 8वां अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, 2022	2
5.	14वां मणिपुर राज्य फ़िल्म पुरस्कार, 2022	1

2. चयनित फ़िल्में: 24 फ़िल्में/ 11 महोत्सव

क्र. सं.	फ़िल्म पुरस्कार/फ़िल्म महोत्सव का नाम	फ़िल्मों की सं.
1.	8वां शिमला अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव-2022	2
2.	17वां मुंबई इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल-2022	12
3.	एर्नाकुलम, केरल में 15वां साइन्स फ़िल्म फ़ेस्टिवल-2022	7
4.	केरल का 14वां अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघु फ़िल्म समारोह (आईडीएसएफके)-2022	3
5.	चेन्नई में पहला फ्रीडम फ़िल्म फ़ेस्टिवल-2022	3
6.	18वां सांताक्रूज फ़िल्म फ़ेस्टिवल, अमेरिका	1
7.	9वां सिलीगुड़ी शॉर्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म फ़ेस्टिवल (एसएसडीएफएफ)	1
8.	जयपुर इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल (जेआईएफएफ) 2022	2
9.	एनएफडीसी फ़िल्म बाज़ार, 53वां इफ्फी, गोवा	1
10.	कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव 2022	2
11.	12वां क्वींस वर्ल्ड फ़िल्म फ़ेस्टिवल, अमेरिका	1

3. प्रविष्ट फ़िल्में: 47 फ़िल्में/10 महोत्सव

क्र. सं.	फ़िल्म पुरस्कार/फ़िल्म महोत्सव का नाम	फ़िल्मों की सं.
1.	15वां विज्ञान फ़िल्म महोत्सव-2022, केरल	8
2.	जम्मू-कश्मीर का पहला राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (एनएफजेके)	1
3.	17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव-2022	26
4.	इंडियन पैनोरमा-2022, 53वां इफ्फी, गोवा	5
5.	पहला फ्रीडम फ़िल्म फ़ेस्टिवल 2022, चेन्नई	15
6.	कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव	1
7.	केरल का 14वां अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र और लघु फ़िल्म समारोह (आईडीएसएफ एफ के)-2022	10
8.	एनएफडीसी फ़िल्म बाज़ार, 53वां आईएफएफआई, गोवा	4
9.	बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, जर्मनी	4
10.	कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव कोलकाता में	13

4. प्रदर्शित फ़िल्में: 133 फ़िल्में/14 महोत्सव

क्र.सं.	फ़िल्म महोत्सव का नाम	फ़िल्मों की सं.
1.	एर्नाकुलम, केरल में 15वां साइन्स फ़िल्म फ़ेस्टिवल-2022	1
2.	चेन्नई में पहला फ्रीडम फ़िल्म फ़ेस्टिवल 2022	3
3.	शिमला का 8वां अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, 2022	3
4.	9वां सिलीगुड़ी शॉर्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म फ़ेस्टिवल (एसएसडीएफएफ) 2022	1
5.	भुवनेश्वर का तीसरा भारतीय वृत्तचित्र फ़िल्म महोत्सव (आईडीएफएफबी)	1
6.	सुतनुती शॉर्ट फ़िल्म फ़ेस्टिवल, कोलकाता	5
7.	जयपुर इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल (जेआईएफएफ) 2022	2
8.	आज़ादी का अमृत महोत्सव" पर 53वें इफ्फी, गोवा के मौके पर एक मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी 'स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय सिनेमा' पर केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित	18
9.	ढाका अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, 2022	6
10.	24वां मदुरै अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, 2022	3
11.	"विज्ञान फ़िल्म महोत्सव" दीघा विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय विज्ञान शिविर, एनसीएसएम, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मिदनापुर (पूर्व) में आयोजित	30
12.	13वां बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (बीआईएफएफईएस)	13
13.	भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा आईआईएमसी फ़िल्म महोत्सव, 2022 (आईआईएमसीएफएफ'22)	6
14.	17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, 2022	52

(II) वृत्तचित्र, लघु कथा और ऐनिमेशन के लिए मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव

मुंबई अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और ऐनिमेशन फ़िल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) फ़िल्म निर्माताओं, प्रोड्यूसरों, वितरकों, प्रदर्शकों और फ़िल्म समीक्षकों को दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फ़िल्में देखने, विचारों और अवधारणाओं का आदान-प्रदान करने और बेहतर फ़िल्म संस्कृति के लिए नेटवर्क बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह द्विवार्षिक प्रतिस्पर्धी फ़िल्म महोत्सव 1990 से मुंबई में फ़िल्म प्रभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। एमआईएफएफ को दुनिया भर में प्रमुख वृत्तचित्र, लघु कथा और ऐनिमेशन फ़िल्म समारोहों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

एमआईएफएफ का 17वां आयोजन 29 मई, 2022 से 4 जून, 2022 तक फ़िल्म प्रभाग परिसर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। महोत्सव निदेशालय को 30 देशों से 808 फ़िल्म प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जो अभूतपूर्व है, जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 158 प्रविष्टियां और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 650 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। लगभग 12,000 सिने प्रेमियों की उपस्थिति के साथ लगभग 7,000 उत्साही लोगों ने पंजीकृत प्रतिनिधि के रूप में उत्सव में भाग लिया।

एमआईएफएफ-2022 का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया गया था, जिससे भारत और विदेश के सिनेप्रेमी ऑफलाइन कैंपस स्क्रीनिंग के अलावा फ़िल्मों और फ़ेस्टिवल का ऑनलाइन आनंद ले सकें। उत्सव के दौरान चयनित फ़िल्मों की स्क्रीनिंग के अलावा, अन्य कार्यक्रम जैसे निजी भागीदारों के साथ एक कारोबारी से दूसरे कारोबारी के बीच संपर्क से जुड़ी गतिविधियां, एमआईएफएफ हब, कार्यशालाएं, मास्टर क्लास, श्रद्धांजलि, पूर्वव्यापी क्रियाकलाप, खुला मंच, संगोष्ठी, विशेष पैकेज, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि आयोजित किए गए। स्वर्ण शंख ट्रॉफी के साथ डॉ. वी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अनुभवी भारतीय वृत्तचित्र फ़िल्म निर्माता श्री संजीत नरवेकर को प्रदान किया गया।

(III) राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के सहयोग से फ़िल्म महोत्सव

1. कोलकाता में एमआईएफएफ पुरस्कार विजेता फ़िल्म महोत्सव

फ़िल्म प्रभाग कोलकाता शाखा कार्यालय ने 10-12 अगस्त, 2022 तक नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के सहयोग से कोलकाता में सर्वश्रेष्ठ एमआईएफएफ/एमआईएफएफ पुरस्कार विजेता फ़िल्मों का आयोजन किया।

2. शिलांग, मेघालय में एमआईएफएफ पुरस्कार विजेता फ़िल्म महोत्सव

फ़िल्म प्रभाग, कोलकाता शाखा कार्यालय ने 18-20 अक्टूबर, 2022 को नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय के सहयोग से शिलांग में बेस्ट ऑफ एमआईएफएफ/मिनी एमआईएफएफ पुरस्कार विजेता फ़िल्म सह मास्टर क्लास का आयोजन किया।

(सी) प्रशासन और वित्त स्कंध

प्रशासन स्कंध में वित्त, कार्मिक, भंडार, लेखा, कारखाना प्रबंधन और सामान्य प्रशासन शामिल हैं। यह स्कंध प्रशासन के निदेशक के नियंत्रण में है, जिनकी सहायता सहायक प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक प्रबंधन, खरीद, सामान्य प्रशासन, सतर्कता और सुरक्षा से संबंधित मामलों में) और लेखा अधिकारी (वित्त और लेखा के मामलों में) द्वारा की जाती है।

बाल फ़िल्म सोसायटी, भारत

'हर बच्चे के मनोरंजन के अधिकार को बढ़ावा देना' आदर्श वाक्य को पूरा करने के लिए, चिल्ड्रेन्स फ़िल्म सोसाइटी, इंडिया (सीएफएसआई) की फ़िल्मों को राज्य या जिला प्राधिकरणों और सरकार के पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन के सहयोग से पूरे भारत में निःशुल्क प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शनी के पैटर्न को मोटे तौर पर नाट्य और गैर-नाटकीय कार्यक्रमों में विभाजित किया जा सकता है।

सीएफएसआई ने जिला बाल संरक्षण इकाइयों के तहत विभिन्न जिला बाल संरक्षण इकाइयों और एनजीओ दर्पण/ नीति आयोग पोर्टल में पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से विशेष / महत्वपूर्ण दिनों पर भारत भर में कई स्थानों पर अनाथालयों में बच्चों के मनोरंजन के लिए अपने बच्चों की फ़िल्मों का ऑनलाइन शो आयोजित किया।

1 अप्रैल, 2022 से 30 नवंबर, 2022 तक, सीएफएसआई

ने सफलतापूर्वक 496 मुफ्त शो आयोजित किए, जिससे एक लाख बीस हजार से अधिक दर्शक लाभान्वित हुए। ये शो विश्व स्वास्थ्य दिवस, अम्बेडकर जयंती, विश्व कला दिवस, पृथ्वी दिवस, विश्व हंसी दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, मातृ दिवस, रवींद्रनाथ टैगोर जयंती, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, विश्व साइकिल दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित किए गए थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से सीएफएसआई की देशभक्ति वाली फ़िल्मों की स्क्रीनिंग की गई।

भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान, पुणे

भारतीय फ़िल्म संस्थान की स्थापना 1960 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी। 1971 में टेलीविज़न स्कंध के शामिल होने के बाद, संस्थान को भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान (एफटीआईआई) के रूप में फिर से नामित किया गया। संस्थान को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत अक्टूबर 1974 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। एफटीआईआई सोसाइटी में फ़िल्म, टेलीविज़न, संचार, संस्कृति से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, संस्थान के पूर्व छात्र और पदेन सरकारी सदस्य शामिल हैं। यह संचालक मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में शासित है। श्री शेखर कपूर इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं।

संस्थान में दो खंड - फ़िल्म और टेलीविज़न खंड हैं, जो दो वर्षीय और तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। ये कोर्स डायरेक्शन, सिनेमैटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड डिज़ाइन, एडिटिंग और आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिज़ाइन, स्क्रीन एक्टिंग, स्क्रीनप्ले राइटिंग और टीवी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं।

मुख्य बातें

- **फ़िल्म उस्ताद सत्यजीत रे का जन्म शताब्दी समारोहः** एफटीआईआई, पुणे ने सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में 6-11 जून, 2022 तक छह दिवसीय मास्टर क्लास शृंखला का आयोजन किया।

- **एफटीआईआई ने ज्ञान साझीदार (नॉलेज पार्टनर) के रूप में लद्दाख विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किएः** एफटीआईआई के मार्गदर्शन में लद्दाख विश्वविद्यालय अपने परिसरों में फ़िल्म और टेलीविज़न प्रस्तुतियों में पाठ्यक्रम चलाएगा।

- 1 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक **'अमृत महोत्सव पाठ्यक्रम'** के तहत विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रतिभागियों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

- अप्रैल 2022 में लद्दाख कौशल विकास मिशन (एलएसडीएम) के सहयोग से लेह, लद्दाख में **वॉयस ओवर और डबिंग (ऑफलाइन) में एक शुरुआती पाठ्यक्रम** आयोजित किया गया था।

- एफटीआईआई ने 2-6 मई, 2022 से **फंडामेंटल्स ऑफ फ़िल्म डायरेक्शन कोर्स** का आयोजन किया। पाठ्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फ़िल्म निर्माता और एफटीआईआई के पूर्व छात्र अविनाश रॉय और जैस्मीन कौर रॉय ने किया। 5 दिवसीय पाठ्यक्रम में फ़िल्म निर्देशन तकनीक, फ़िल्म व्याकरण, फ़िल्म शूटिंग प्रक्रिया, विचारों पर काम करना आदि शामिल थे।

- ग्रीष्म अवकाश के दौरान एसआरएफटीआई ने **बच्चों के बुनियादी फ़िल्म उन्मुखीकरण** पाठ्यक्रम का आयोजन किया। 5 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन 16-20 मई, 2022

(बैच 1) और 23-27 मई, 2022 (बैच 2) से किया गया था।

- 16 जुलाई, 2022 से 25 सितंबर, 2022 तक **पटकथा लेखन** में 10-सप्ताह का लंबा ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पाठ्यक्रम निदेशक के रूप में पटकथा लेखक और एफटीआईआई के पूर्व छात्र समवर्त साहिल थे।

- 19-29 जुलाई, 2022 तक एलएसडीएम के सहयोग से कारगिल, लद्दाख में **वॉयस ओवर और डबिंग** पर 10-दिवसीय लघु पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था।

- एफटीआईआई ने एनएफडीसी, एसआरएफटीआई और ईएसजी के सहयोग से आईएफएफआई-53 में संयुक्त रूप से **मास्टर क्लास** और **इन-कन्वर्सेशन** सत्रों का आयोजन किया। फ़िल्म निर्माण के हर पहलू में छात्रों और सिनेमा के प्रति उत्साही लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुल 23 सत्र आयोजित किए गए।

फ़िल्म उत्सवों में एफटीआईआई फ़िल्मों की भागीदारी

1. फ़िल्म स्कंध के छात्रों के 2018 बैच की दो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्मों को इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म फ़ेस्टिवल, एम्स्टर्डम के 35वें आयोजन में प्रस्तुत किया गया।

2. 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, भारतीय पैनोरमा 2022 में टीवी स्कंध के छात्रों के 2019 बैच की पांच डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में प्रस्तुत की गईं।

- जयेश जोशी द्वारा *डैंगलिंग कैरट रनिंग हॉर्स*
- अपूर्वा दुआ द्वारा *गिव मी अ प्लेस, ओ मदर!*
- मयंक पटेल द्वारा *नाका सोदुन जौ रंगमहल*
- अंकुर अभिषेक द्वारा *प्रवास*
- सिसिरा अनिल द्वारा *वॉयड एंड द ब्लूज़*

3. सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में नवंबर 2022 में सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ फ़िल्म एंड टेलीविज़न फ़ेस्टिवल द्वारा अंतरराष्ट्रीय छात्र फ़िल्म महोत्सव पीटर्सबर्ग आयोजित किया गया।

4. राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा 7 से 12 नवंबर, 2022 तक राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद में छठा अल्पविराम अंतरराष्ट्रीय युवा फ़िल्म महोत्सव आयोजित किया गया।

5. 14-18 नवंबर, 2022 तक रूसी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिनेमैटोग्राफी द्वारा 42वां वीजीआईके इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़ेस्टिवल आयोजित किया गया।

6. डिजिटल फ़िल्म निर्माण और वीएफएक्स टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल, भारत में बीएफए विभाग द्वारा 24 सितंबर, 2022 को प्रथम अंतरराष्ट्रीय छात्र फ़िल्म महोत्सव - फ्रेम-ओ-लोजी आयोजित या गया।

7. फ़िल्म समारोह निदेशालय, एनएफडीसी, भारत द्वारा 69वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार आयोजित।

सत्यजीत रे फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान

सत्यजीत रे फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान (एसआरएफटीआई) की स्थापना 1995 में एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में हुई थी और यह पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत है। महान फ़िल्म उस्ताद सत्यजीत रे के नाम पर यह संस्थान सिने-शिक्षाशास्त्र का एक राष्ट्रीय केंद्र है। फ़िल्मों के क्षेत्र में छह विशेषज्ञताओं - निर्देशन और पटकथा लेखन, छायांकन, संपादन, ध्वनि रिकॉर्डिंग और डिज़ाइन, फ़िल्म और टेलीविज़न और ऐनिमेशन सिनेमा के लिए निर्माण में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल

मीडिया (ईडीएम) में छह विशेषज्ञता क्षेत्रों – ईडीएम प्रबंधन, ईडीएम के लिए छायांकन, ईडीएम के लिए लेखन, ईडीएम के लिए निर्देशन और निर्माण, ईडीएम के लिए संपादन और ईडीएम के लिए ध्वनि में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमापाठ्यक्रम संस्थान द्वारा चलाए जाते।

मुख्य बातें

- मई के महीने में **सत्यजीत रे के सालभर चलने वाले शताब्दी समारोह** का समापन हुआ। 2 मई, 2022 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव और एसआरएफटीआई के अध्यक्ष श्री अपूर्व चंद्रा ने सत्यजीत रे के घर का औपचारिक दौरा किया। सत्र के बाद परिसर में रे रेनेसां आर्ट गैलरी का उद्घाटन एसआरएफटीआई के अध्यक्ष और इस अवसर के मुख्य अतिथि श्री अपूर्व चंद्रा और विशिष्ट अतिथि श्री रेसुल पुकुट्टी द्वारा किया गया। परिसर में रे की एक पूर्ण आकृति वाली कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया।

- 2 मई, 2022 स्नातक बैच के लिए दीक्षांत दिवस के रूप में एसआरएफटीआई के लिए भी विशेष था। बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत काफी धूमधाम और एक पर्दे की फ़िल्म के साथ हुई।

- 16-29 सितंबर, 2022 तक एसआरएफटीआई में हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

- 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 के अवसर पर, संस्थान ने 'मानवता के लिए योग' विषय के तहत परिसर में गतिविधियों का आयोजन किया।

- एसआरएफटीआई का अंतरराष्ट्रीय छात्र फ़िल्म महोत्सव - छठा क्लैपस्टिक का आयोजन 25-27 मार्च, 2022 तक आयोजित किया गया था। इस गैर-प्रतिस्पर्धी फ़िल्म समारोह में 25 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म संस्थानों की 74 फ़िल्मों ने भाग लिया।

- 4 अगस्त, 2022 को श्री हिमांशु शेखर खटुआ ने एसआरएफटीआई के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। 8 अगस्त, 2022 को कई पुरस्कार विजेता फ़िल्म निर्माता, पटकथा लेखक, वीडियो कलाकार और फ़िल्म अकादमिक श्री विपिन विजय ने एसआरएफटीआई के डीन के रूप में पदभार ग्रहण किया।

- एसआरएफटीआई ने एनएफडीसी, एफटीआईआई और ईएसजी के सहयोग से संयुक्त रूप से 53वें आईएफएफआई में मास्टर क्लास और इन-कन्वर्सेशन सत्रों का आयोजन किया। फ़िल्म निर्माण के हर पहलू में छात्रों और सिनेमा के प्रति उत्साही लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष कुल 23 सत्र आयोजित किए गए।

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहल के तहत, एसआरएफटीआई ने 22 जुलाई, 2022 को राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक-दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की।

- ऐनिमेशन सिनेमा विभाग ने 24 नवंबर, 2022 को विश्व प्रसिद्ध ऐनिमेशन निर्देशक और चित्रकार श्री डेविड पोलोनस्की के साथ एक सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन किया।

- राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एसआरएफटीआई द्वारा दो सप्ताह का एफएलएम ओरिएंटेशन कोर्स आयोजित किया गया था।

- 'एसआरएफटीआई आउटरीच प्रोग्राम' के तहत डीवीसी (दामोदर घाटी निगम) के लिए एक परियोजना के निर्माण में कई संकाय सदस्य शामिल थे। फ़िल्म 7 जुलाई, 2022 को पूरी हुई और डीवीसी के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों को प्रस्तुत की गई, जिन्होंने परिसर का दौरा किया।

- फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान, ईटानगर द्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग के सहयोग से 10 मार्च 10-22, 2022 तक 'एक्टिंग फॉर स्क्रीन' नामक लघु अभिनय पाठ्यक्रम का दूसरा सत्र आयोजित किया गया था।

फ़िल्म समारोहों में भागीदारी

नाम	विभाग	शीर्षक	पुरस्कार/महोत्सव
महर्षि तुहिन कश्यप	निर्देशन और पटकथा लेखन (छात्र)	मुर घुरार दुरंतो गोटी (स्वर्ग का घोड़ा)	वीजीआईके इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़िल्म फ़ेस्टिवल 2022, मॉस्को में बेस्ट फिक्शन शॉर्ट फ़िल्म अवार्ड
			अकादमी पुरस्कार में एक प्रवेशक के रूप में योग्य
			बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय लघु फ़िल्म महोत्सव (भारतीय प्रतियोगिता वर्ग में विजेता)
तान्या यादव	ईडीएम (छात्र)	विरह (लॉन्गिंग)	एमआईएफएफ 2022
ऋत्विक सिन्हा	निर्देशन और पटकथा लेखन (छात्र)	ऑल्टर	एमआईएफएफ 2022
हिमांशु तोमर	निर्देशन और पटकथा लेखन (छात्र)	गुरु दत्त की कोई फ़िल्म	आईडीएसएफएफके 2022 (प्रतियोगिता में)
ईशान शर्मा	निर्देशन और पटकथा लेखन (छात्र)	ए सीजन ऑफ मैंगोज	आईडीएसएफएफके 2022 (प्रतियोगिता में)
शेखर दास	निर्देशन और पटकथा लेखन (छात्र)	इनसाइड द बेली	आईडीएसएफएफके 2022 (फ़ोकस श्रेणी)
सूचना साहा	ऐनिमेशन सिनेमा (छात्र)	प्रियो अमी	आईडीएसएफएफके 2022 (फ़ोकस श्रेणी)
			ऐनिमेटर्स गिल्ड, मुंबई इमामी आर्ट एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म फ़ेस्टिवल, 2022
			बुसान अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव
			वीजीआईके अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, मास्को
			फ़िल्म स्कूल फ़ेस्ट म्यूनिख 2022
			बीजिंग इंटरनेशनल शॉर्ट फ़िल्म फ़ेस्टिवल 2022
			द मिक्स ब्राज़ील फ़ेस्टिवल ऑफ डाइवर्सिटी
			आईएडी पोलैंड

विवेक प्रकाश	ऐनिमेशन सिनेमा (छात्र)	टॉयइंग बॉक्स	ग्लोबल यूनिवर्सिटी फ़िल्म अवाड्र्स, हॉन्गकॉन्ग आईडीएसएफएफके 2022 स्टूडेंट वर्ल्ड इम्पैक्ट फ़िल्म फ़ेस्टिवल
सुबर्णा दास	ऐनिमेशन सिनेमा (छात्र)	अमयी (मां)	मॉन्स्ट्रा ऐनिमेशन फ़िल्म फ़ेस्टिवल
सिद्धांत नाग	ऐनिमेशन सिनेमा (छात्र)	ऑबस्क्युरा	स्टूडेंट वर्ल्ड इम्पैक्ट फ़िल्म फ़ेस्टिवल, एथेंस डिजिटल आर्ट्स फ़ेस्टिवल और इंटोनेशन 2022

अरुणाचल प्रदेश में फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान

देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार की पहल के तहत और फ़िल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में पूर्वोत्तर के युवाओं के बीच प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रालय ने एफटीआईआई, पुणे और एसआरएफटीआई, कोलकाता की तर्ज पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को अरुणाचल प्रदेश में फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान के निर्माण कार्य को पूरा करने का काम सौंपा गया है। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण कार्य प्रगति पर है (75 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया है)।

वर्तमान में अस्थायी परिसर में फ़िल्म एवं टेलीविज़न क्षेत्र से संबंधित लघु अवधि के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार

मौजूदा विलय की प्रक्रिया के तहत, भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई), पुणे और भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय की गतिविधियों को एनएफडीसी ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। इससे भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) में किए जा रहे आर्काइव (अभिलेखीय) और रेस्टोरेशन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एनएफडीसी के पास पिक्चर और साउंड रिस्टोरेशन के लिए निर्धारित प्रक्रिया है, जिसके परिणामस्वरूप मानकों में एकरूपता आती है। सभी पांच संस्थानों द्वारा आयोजित त्योहारों/बाज़ारों को अब इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल से लैस एक टीम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

2022 में, एनएफडीसी-एनएफएआई ने अपने संग्रह की फ़िल्मी विषय-सामग्री से संबंधित गतिविधियों का संचालन किया। राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) के हिस्से के रूप में, एनएफडीसी-एनएफएआई के परिसर में एक हज़ार से अधिक फ़िल्मों (फ़ीचर्स, लघु और वृत्तचित्र) को 2के और 4के दोनों रिज़ॉल्यूशन में डिजिटाइज किया गया है। इसके अतिरिक्त, सत्यजीत रे की कई फ़िल्मों को मूल कैमरा निगेटिव से 4के रिज़ॉल्यूशन में परिवर्तित किया गया था और विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों जैसे कान, वेनिस और टीआईएफएफ में प्रदर्शित किया गया था। एनएफडीसी-एनएफएआई में सेल्युलाइड रीलों के संरक्षण के लिए निवारक संरक्षण परियोजना शुरू की गई है। एक संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जो भौतिक और रासायनिक रूप से क्षतिग्रस्त और बिगड़ती फ़िल्म रीलों पर सावधानीपूर्वक संरक्षण कार्य शुरू करने के लिए तैयार है। 'द फ़िल्म सर्कल' के हिस्से के रूप में, एनएफडीसी-एनएफएआई प्रत्येक शनिवार को फ़िल्म सर्कल के सदस्यों के लिए फ़िल्म स्क्रीनिंग का आयोजन करता है, ताकि इसके समृद्ध संग्रह से सिनेमा का नियमित प्रसार किया जा सके।

योजना का निष्पादन 2022-23

(राशि करोड़ में)

कार्यक्रम/ योजना	एस.बी.जी. 2022-23	संशोधित अनुमान 2022-23	01.04.2022 से 31.12.2022 तक वास्तविक व्यय दिनांक
विकास संचार और फ़िल्मी सामग्री का प्रसार (डीसीडीएफसी)	101.51	101.35	73.55
पूंजीगत परिव्यय (प्रमुख कार्य) (एनएफएचएम)	25.65	25.65	20.06

फ़िल्म समारोह निदेशालय

भारतीय फ़िल्मों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1973 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फ़िल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) की स्थापना की गई थी।

मुख्य बातें

- **हैबिटेट इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल** का आयोजन नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में मई, अगस्त और सितंबर 2022 में डीएफएफ के सहयोग से किया गया था। 1983 (संस्कृत) और *मंजादी कुरु* फ़िल्में मई में उत्सव के दौरान प्रदर्शित की गईं। अगस्त में *बरसात* (हिन्दी), *पाथेर पांचाली* (बंगाली), *चेमीन* (मलयालम), *अंकुर* (हिन्दी), *जाने भी दो यारों* (हिन्दी), *रोजा* (तमिल), *हरिश्चंद्रची फैक्ट्री* (मराठी) प्रदर्शित की गईं। सितंबर संस्करण में *आक्रोश* (हिन्दी), *कनूरू हेग्गादिथी* (कन्नड़), *मुक्ता* (मराठी), *पार्टी* (हिन्दी), *मम्मो* (हिन्दी), *एक दिन अचानक* (हिन्दी) की स्क्रीनिंग की गई।

- **17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव** (एमआईएफएफ) का आयोजन 29 मई, 2022 से 4 जून, 2022 तक मुंबई, महाराष्ट्र में डीएफएफ के सहयोग से आयोजित किया गया था। सात दिनों तक चलने वाले इस फ़ेस्टिवल में डीएफएफ आर्काइव की निम्नलिखित फ़िल्में थीं– *अहिंसा – गांधी: द पावर ऑफ द पावरलेस* (अंग्रेजी), *ड्रामा क्वींस* (अंग्रेजी), *ग्रीन ब्लैकबेरी* (नेपाली), *हाईवे ऑफ लाइफ* (मणिपुरी), *होली राइट्स* (हिन्दी) *इन्वेस्टिंग लाइफ* (अंग्रेजी), *शांताबाई* (हिन्दी), *बबलू बेबीलोन से* (हिन्दी), *भारत प्रकृति का बालक* (हिन्दी), *पाबंग स्याम* (मणिपुरी), *चुनौतियों पर काबू पाना* (अंग्रेजी), *तीन अध्याय* (हिन्दी), *बैक स्टेज* (ओडिया), *वेद... द विजनरी* (अंग्रेजी), *वीरांगना* (असमिया)।

- डीएफएफ ने नई दिल्ली में 4-25 जुलाई, 2022 तक **इंडिया इंटरनेशनल सेंटर** द्वारा आयोजित फ़िल्म समारोह में भाग लिया। फ़िल्में *ओथा सेरुप्पु सेज 7* (तमिल), *पिंगारा* (कन्नड़), *कल्ला नोट्टम* (मलयालम), *फोटो प्रेम, अविजात्रिक* (बंगाली), *ब्रिज* (असमिया), *पिंक ऐली?* (कन्नड़) उत्सव के दौरान प्रदर्शित की गई।

- 8वां **शिमला अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव** (आईएफएफएस) 26-28 अगस्त, 2022 को डीएफएफ के सहयोग से शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। तीन-दिवसीय चले उत्सव में डीएफएफ आर्काइव से निम्नलिखित फ़िल्में थीं – *अल्फा बीटा गामा* (हिन्दी), *21 एमयू टिफिन* (गुजराती), *बिटरस्वीट* (मराठी), *सनपत* (गढ़वाली), *द स्पेल ऑफ पर्पल* (गुजराती), *फ्यूनरल* (मराठी), *नीली हक्की* (कन्नड़),

मुरमुर्स ऑफ द जंगल (मराठी), *पाबंग स्याम* (मणिपुरी), *द नॉकर* (हिन्दी), *विच* (संथाली), *नाट्यम* (तेलुगू), *वीरांगना* (असमिया), *बैक स्टेज* (ओडिया), *जुगलबंदी* (हिन्दी), *और डोलू* (कन्नड़)।

- डीएफएफ के सहयोग से पुदुचेरी में 9-13 सितंबर, 2022 तक **भारतीय पैनोरमा फ़िल्म महोत्सव** आयोजित किया गया। डीएफएफ आर्काइव से कूझगल (तमिल), अल्फ़ा बीटा गामा (हिन्दी), नाट्यम (तेलुगू), सन्नी (मलयालम), कालकोक्खो (बंगाली) को प्रदर्शित किया गया।

- **68वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार**

माननीय राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह में 30 सितंबर, 2022 को विभिन्न श्रेणियों में वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष के राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुछ प्रमुख विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म श्रेणी में तमिल फ़िल्म *सोरारई पोटरू* शामिल हैं। *तान्हाजी द अनसंग वारियर* ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फ़िल्म का पुरस्कार जीता, मराठी फ़िल्म *फ्यूनरल* को सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार मिला, सच्चिदानंदन केआर ने *अय्यप्पनम कोशियुम* के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता, अजय देवगन और सूर्या शिव कुमार ने संयुक्त रूप से अपनी फ़िल्मों *तान्हाजी : द अनसंग वॉरियर* और *सोरारई पोटरू* में प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अपर्णा बालमुरली ने तमिल फ़िल्म *सोरारई पोटरू* में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की ट्रॉफी जीती। तमिल फ़िल्म *मंडेला* को एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फ़िल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला, जबकि कन्नड़ फ़िल्म *तलेदंडा* ने पर्यावरण संरक्षण/संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार जीता। टेस्टिमोनी ऑफ एना (डांगी) सर्वश्रेष्ठ गैर-फ़ीचर थी और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार *द लॉन्गेस्ट किस* को मिला। मध्यप्रदेश को मोस्ट फ़िल्म फ्रेंडली स्टेट का सम्मान दिया गया। इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सुश्री आशा पारेख को प्रदान किया गया।

- डीएफएफ ने 9 से 20 नवंबर, 2022 तक नई दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 68वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार से सम्मानित फ़ीचर और गैर-फ़ीचर फ़िल्मों की सार्वजनिक स्क्रीनिंग का आयोजन किया।

- डीएफएफ के सहयोग से बेंगलुरु में 6-9 अक्टूबर, 2022 तक **5वां इनोवेटिव इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल** आयोजित किया गया। तीन दिवसीय उत्सव में डीएफएफ आर्काइव से निम्नलिखित फ़िल्में थीं - *भगवदजुकम* (संस्कृत), *बिटरस्वीट* (मराठी), *मी वसंत राव* (मराठी), *सिजौ* (असमिया), *तलेदंडा* (कन्नड़), *नाट्यम* (तेलुगू), *नीली हक्की* (कन्नड़), *फ्यूनरल* (मराठी), *21एमयू टिफिन* (मराठी), डोलू (कन्नड़), *एट डाउन तूफान मेल* (हिन्दी), *नितांटोई सहज सरल* (बंगाली), *एक्ट-1978* (कन्नड़), *गंगा पुत्र* (हिन्दी), *नादः द साउंड* (बंगाली), *सैनबारी संदेशखाली* (बंगाली), *सरमाउंटिंग चैलेंज* (अंग्रेजी), *तीन अध्याय* (हिन्दी), *बैक स्टेज* (उड़िया), *द स्पेल ऑफ पर्पल* (गुजराती), *पाबंग स्याम* (मणिपुरी), द *नॉकर* (हिन्दी), *वीरांगना* (असमिया)।

- **53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव**

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने 20-28 नवंबर, 2022 तक 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (आईएफएफआई) का आयोजन किया। महोत्सव की शुरुआत *अल्मा एंड ऑस्कर* की स्क्रीनिंग के साथ हुई। स्पेनिश फ़िल्म निर्देशक श्री कार्लोस सौरा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से

सम्मानित किया गया।

53वें आईएफएफआई में 24 नवंबर, 2022 को मिड फेस्ट फ़िल्म फिक्सेशन सहित 78 देशों की 182 फ़िल्में, 94 इंडियन प्रीमियर, 10 वर्ल्ड प्रीमियर और 13 इंटरनेशनल प्रीमियर, 34 एशिया प्रीमियर और 94 इंडिया प्रीमियर दिखाए गए। भारतीय पैनोरमा ने 25 विभिन्न भाषाओं में 25 फ़ीचर और 19 गैर-फ़ीचर फ़िल्मों का प्रदर्शन किया।

सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सुश्री आशा पारेख के योगदान का जश्न मनाते हुए, आईएफएफआई ने उनकी तीन फ़िल्मों- *दो बदन* (1966), *तीसरी मंजिल* (1966) और *कटी पतंग* (1971) को प्रदर्शित किया।

समापन समारोह में आईएफएफआई के पुरस्कार खंड की भी घोषणा की गई।

पुरस्कार श्रेणी	विजेता
गोल्डन पीकॉक अवार्ड	आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार	नो एंड
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष पुरस्कार	श्री वाहिद मोबाशेरी
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला पुरस्कार	सुश्री डेनिएला मारिन नवारो
विशेष जूरी पुरस्कार	श्री लव डियाज
एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फ़ीचर फ़िल्म	सुश्री असिमिना प्रोएड्रोउ फ़िल्म (बिहाइंड द हेस्टैक्स) के लिए
विशेष उल्लेख	सिनेमाबंदी
आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी मेडल	नरगेसी

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 30 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह में अनुभवी अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करती हुईं। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।

53वें इफ्फी के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देती अभिनेत्री मृणाल ठाकुर।

सुश्री अन्ना सौरा (श्री कार्लोस सौरा की बेटी अपनी मां की तरफ से) गोवा के मुख्यमंत्री, श्री प्रमोद सावंत से लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करती हुई। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे।

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड

केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 3 के तहत फ़िल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने के उद्देश्य से की गई थी। बोर्ड मुंबई में अपने मुख्यालय और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कार्य करता है।

बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्य और एक अध्यक्ष (जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है) होते हैं। मंत्रालय की 11 अगस्त, 2017 की अधिसूचना के तहत नियुक्त वर्तमान बोर्ड में 10 गैर-सरकारी सदस्य हैं और श्री प्रसून जोशी इसके प्रमुख हैं।

फ़िल्मों का प्रमाणन

भारत दुनिया के प्रमुख फ़िल्म निर्माता देशों में से एक है। हालांकि, एसएआरएस कोविड-2 रोग के प्रकोप के कारण, पिछले वर्षों की तुलना में फ़िल्मों के निर्माण की संख्या में गिरावट आई और इसके परिणामस्वरूप कम प्रमाणपत्र मिले। फिर भी, 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में 2022-23 की पहली तीन तिमाहियों में लगभग 56 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो देशभर में फ़िल्म निर्माण गतिविधि के फिर से पटरी पर लौटने का संकेत है।

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (दिसंबर '22 तक)
भारतीय लंबी फ़िल्में (डिजिटल और वीडियो)	3,295	2,258	3,184	3,010
विदेशी लंबी फ़िल्में (डिजिटल और वीडियो)	1,171	917	722	493
भारतीय लघु फ़िल्में (डिजिटल और वीडियो)	15,329	4,945	8,326	10,328
विदेशी लघु फ़िल्म (डिजिटल और वीडियो)	798	179	487	352
कुल	**20,593**	**8,299**	**12,719**	**14,183**

वित्तीय वर्ष 2022-23 (22 दिसंबर तक) के दौरान, बोर्ड ने कुल **14,183** प्रमाणपत्र जारी किए, जिनमें से **5,594** प्रमाणपत्र वीडियो फ़िल्मों को जारी किए गए, और **8,589** प्रमाणपत्र डिजिटल फ़िल्मों को जारी किए गए।

डिजिटल

इस अवधि के दौरान, डिजिटल फ़िल्मों को जारी किए गए **8,589** प्रमाणपत्रों में से **2,058** प्रमाणपत्र भारतीय लंबी फ़िल्मों को, **126** विदेशी लंबी फ़िल्मों को, **6,152** प्रमाणपत्र भारतीय लघु फ़िल्मों को और **253** विदेशी लघु फ़िल्मों को जारी किए गए। भारतीय लंबी डिजिटल फ़िल्मों में, **कन्नड़ इस वर्ष फ़िल्मों में सबसे अधिक उत्पादन वाली भाषा बन गई,** इसके बाद तेलुगू, तमिल, हिन्दी, मलयालम, भोजपुरी, बंगाली का स्थान है।

वीडियो

इसी तरह, **5,594** प्रमाणपत्रों में से, **952** प्रमाणपत्र भारतीय फ़ीचर लंबी फ़िल्मों को, **367** विदेशी लंबी फ़ीचर फ़िल्मों को, **4,176** भारतीय लघु फ़िल्मों को और **99** विदेशी लघु फ़िल्मों को जारी किए गए हैं।

ई-सिनेप्रमाणः प्रणाली में सुधार

आवेदकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सीबीएफसी द्वारा कई पहलें और प्रणालीगत सुधार किए गए, जैसे:

i. वेबसाइट की गुणवत्ता और सामग्री प्रबंधन मानदंडों के अनुपालन के लिए जीआईजीडब्ल्यू/एसटीक्यूसी प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण।

ii. स्क्रीनिंग शुल्क और प्रमाणन शुल्क के भुगतान की एकल खिड़की प्रणाली।

iii. एनआईसी के समन्वय से फाइल वर्क के लिए ई-ऑफिस का क्रियान्वयन।

iv. पूर्ण प्रक्रिया स्वचालन और न्यूनतम मानव हस्तक्षेप।

v. प्रभावी सूचना प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग (एसएमएस/ईमेल गेटवे)।

vi. तत्क्षण प्रगति के ट्रैकिंग के लिए डैशबोर्ड।

vii. निष्पादन का पता लगाने के लिए सशक्त एमआईएस और एसएलए प्रबंधन।

viii. इनबिल्ट वर्कफ्लो और ऑटो एस्केलेशन मैकेनिज्म।

ix. रिकॉर्ड और फ़िल्म स्क्रिप्ट का प्रभावी अभिलेख।

x. प्रभावी शिकायत प्रबंधन।

xi. सूचना तक पहुंच में वृद्धि।

राजस्व आमद

सीबीएफसी प्रमाणन शुल्क/शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त करता है। पिछले चार वर्षों के दौरान राजस्व संग्रह का विवरण तालिका में है:

क्र.सं.	अवधि	राजस्व संग्रह (रुपये में)
1.	वित्त वर्ष 2019-20	13,67,45,463
2.	वित्त वर्ष 2020-21	8,40,92,178
3.	वित्त वर्ष 2021-22	12,21,40,116
4.	वित्त वर्ष 2022-23 (दिसंबर 2022 तक)	11,67,28,402

महत्वपूर्ण विज्ञप्ति/आदेश

i) फ़िल्मों की कुछ श्रेणियों को मंत्रालय के दिनांक 24 सितंबर, 2007 के आदेश संख्या 807/3/2007 द्वारा फ़िल्मों के प्रमाणीकरण से संबंधित प्रावधान से छूट दी गई है।

ii) दिनांक 11 अप्रैल, 2022 की विज्ञप्ति के माध्यम से ब्रांड विस्तार उत्पादों को बढ़ाने के संबंध में सलाह।

iii) ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापनों के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की दिनांक 13 जून, 2022 की सलाह।

1-4-2022 से 31-12-2022 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित फ़िल्मों का समेकित विवरण

वीडियो								
	यू	यू*	यूए	यूए*	ए	ए*	एस	कुल
भारतीय फ़ीचर फ़िल्में	167	73	411	294	4	3	-	952
विदेशी फ़ीचर फ़िल्में	59	2	265	39	2	-	-	367
भारतीय लघु फ़िल्म	2722	54	1306	63	29	2	-	4176
विदेशी लघु फ़िल्म	42	-	57	-	-	-	-	99
कुल	2990	**129**	**2039**	**396**	**35**	**5**	-	**5594**
डिजिटल								
	यू	यू*	यूए	यूए*	ए	ए*	एस	कुल
भारतीय फ़ीचर फ़िल्में	489	157	479	755	52	126	-	2058
विदेशी फ़ीचर फ़िल्में	27	6	57	8	16	12	-	126
भारतीय लघु फ़िल्म	4881	19	1150	64	31	7	-	6152
विदेशी लघु फ़िल्म	87	1	164	-	1	-	-	253
कुल	5484	**183**	**1850**	**827**	**100**	**145**	-	**8589**
कुल योग	8474	312	**3889**	**1223**	**135**	**150**	-	**14183**

बोर्ड की वित्तीय व्यवस्था

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करने वाला एक वैधानिक निकाय है। हालांकि, प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, बोर्ड को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में माना जाता है।

बोर्ड का राजस्व सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 में प्रदान किए गए मानदंडों के अनुसार प्रमाणन शुल्क के संग्रह के माध्यम से होता है। बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय में की गई फ़िल्मों के प्रदर्शन के संबंध में प्रोजेक्शन शुल्क भी लगाता है। 1 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान उपार्जित कुल आय **11,67,28,402 रु.** है। एकत्रित राजस्व को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है।

NFDC
cinemas of india

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राष्ट्रीय आर्थिक नीति के अनुसार भारतीय फ़िल्म उद्योग के एक एकीकृत और कुशल विकास की योजना बनाने, प्रचार करने और व्यवस्थित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। एनएफडीसी के साथ फ़िल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन (एफएफसी) और इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (आईएमपीईसी) का विलय करके वर्ष 1980 में एनएफडीसी को फिर से शामिल किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से, एनएफडीसी ने 21 से अधिक भारतीय भाषाओं में 300 से अधिक फ़िल्मों का वित्तपोषण/ निर्माण किया है, जिनमें से कई ने व्यापक प्रशंसा अर्जित की है और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।

फ़िल्मों के निर्माण के अलावा, एनएफडीसी सरकारी एजेंसियों के लिए चहुंमुखी एकीकृत विपणन समाधान भी प्रदान करता है और विज्ञापन, वृत्तचित्र, लघु फ़िल्म, टीवी शृंखला, वेब विज्ञापन, रेडियो शृंखला और विषयगत संगीत तैयार करता है।

चार मीडिया इकाइयों का विलय

भारत सरकार के 23 दिसंबर, 2020 के चार फ़िल्म मीडिया इकाइयों: फ़िल्म प्रभाग, फ़िल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार और बाल फ़िल्म सोसाइटी, इंडिया का राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के साथ विलय के निर्णय के आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 दिसंबर, 2021 और 30 मार्च, 2022 को कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इन चार फ़िल्म मीडिया इकाइयों के शासनादेश के तहत सभी गतिविधियां 01.01.2023 से एनएफडीसी को स्थानांतरित करके उसे सौंप दिया जाएगा। 1 जनवरी, 2023 को यह निर्णय लिया गया था कि चार फ़िल्म मीडिया इकाइयों द्वारा अपने-अपने शासनादेशों के निर्वहन से उत्पन्न होने वाले सभी अधिकार, दायित्व और देनदारियां (वर्तमान आदेश जारी करने से पहले चारों फ़िल्म मीडिया इकाइयों द्वारा की गई कार्रवाई सहित) राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के लिए 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा। राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम अधिदेश को पूरा करने के लिए फ़िल्म प्रभाग, फ़िल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार और बाल फ़िल्म सोसाइटी की हस्तांतरित गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व का उपयोग करेगा। इस तरह की सभी गतिविधियों में शामिल फ़िल्म प्रभाग, फ़िल्म समारोह निदेशालय और भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार के कर्मचारियों को अगले आदेश तक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर एनएफडीसी से जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम को यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करना है ताकि यह शासनादेश को सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम हो सके।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अपनी क्षमता में निरंतर वृद्धि कर रहा है, जिसमें ब्रांड सिनेमाज ऑफ इंडिया के तहत फ़िल्मों का निर्माण और वितरण, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लिए विज्ञापन, लघु और कॉर्पोरेट फ़िल्मों का निर्माण, फ़िल्म प्रदर्शनी, फ़िल्म प्रदर्शनी, जीर्णोद्धार, फ़िल्म बाज़ार, डिजिटल नॉन-लाइनर संपादन, सिनेमैटोग्राफी, सबटाइटलिंग आदि में प्रशिक्षण सहित कौशल विकास आदि शामिल हैं। इस संबंध में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है कि वितरण से जुड़े क्रियाकलाप,

फ़िल्म के वितरण और प्रदर्शन के लिए विभिन्न स्थापित और उभरते हुए स्वरूपों में फैले हुए हैं, जिसमें से वीओडी जैसे डिजिटल प्रारूपों में पारंपरिक नाटकीय रिलीज़, उच्च गुणवत्ता वाले सिनेमा को भारतीय दर्शकों के लिए उचित दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फ़िल्म सुविधा कार्यालय ने अपना वेब पोर्टल www.ffo.gov.in लॉन्च किया, जो दिसंबर 2022 तक एनएफडीसी के परिचालन के तहत था। इस प्रकार इसने भारत को सभी फ़िल्म निर्माताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर प्रस्तुत किया।

एक फ़िल्म विकास एजेंसी के रूप में, एनएफडीसी फ़िल्म उद्योग के उन क्षेत्रों/खंडों में विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार है, जिनका न केवल सांस्कृतिक प्रभाव है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी है, जिन्हें व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण निजी उद्यमों द्वारा नहीं लिया जा सकता है, जिससे फ़िल्म उद्योग के संतुलित विकास की सुविधा मिलती है। हालांकि, भले ही भारतीय फ़िल्म उद्योग में इसकी भूमिका काफी हद तक विकासात्मक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में, एनएफडीसी के पास एक कॉर्पोरेट शासनादेश भी है और यह एक स्वस्थ बैलेंस शीट बनाने के लिए जिम्मेदार है।

वर्ष 2022-2023 की अवधि में निगम के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्य

(ए) फ़िल्म निर्माण

फ़िल्म निर्माण, वृत्तचित्र फ़िल्में और बाल फ़िल्में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फ़िल्म सामग्री विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी) योजना के तहत आती हैं।

कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान फ़िल्म निर्माण से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां की गईं :

1. मुजीब–द मेकिंग ऑफ ए नेशन (बांग्ला) वर्तमान में पोस्ट–प्रोडक्शन के तहत, यानी डिजिटल इंटरमीडिएट (डीआई) रंग सुधार, दृश्य प्रभाव (वीएफएक्स), और ध्वनि डिज़ाइनिंग पूरी कर ली गई।
2. श्री हाओबम पबन कुमार द्वारा निर्देशित जोसेफकी मचा मणिपुरी फ़ीचर फ़िल्म। प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी और फ़िल्म पोस्ट–प्रोडक्शन सफलतापूर्वक पूरे किए गए।
3. एनएफडीसी की पहली ऐनिमेशन फ़ीचर फ़िल्म पेड़ पे कामरा (हिन्दी) के सह–निर्माण समझौते पर सह–निर्माता पेपरबोट स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए और फ़िल्म प्री–प्रोडक्शन के अधीन है।
4. एनएफडीसी को आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए फ़ीचर फ़िल्म, वृत्तचित्र और ऐनिमेशन शृंखला के निर्माण के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से 5.32 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

- हिन्दी ऐनिमेशन शृंखला *भारती और बिबो* (भारती और उसका जादुई कीड़ा)। सह–निर्माता पपेटिका मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ सह–निर्माण समझोते पर हस्ताक्षर किए गए। पायलट एपिसोड का निर्माण चल रहा है।
- एनएफडीसी द फोर्थ वॉल एंड बियॉन्ड द ग्लैमर नामक वृत्तचित्र फ़िल्म के निर्माण के लिए सह–निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।

5. एनएफडीसी को वृत्तचित्र फ़िल्मों के निर्माण के लिए 145 आवेदन प्राप्त हुए हैं और बाल फ़िल्मों के निर्माण और सह–निर्माण के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है।

6. एनएफडीसी को पूर्वोत्तर क्षेत्र के फ़िल्म निर्माताओं के लिए पूर्वोत्तर भाषाओं में फ़ीचर फ़िल्म, वृत्तचित्र फ़िल्म और ऐनिमेटेड लघु फ़िल्म के निर्माण के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से 8.39 करोड़ रुपये के लिए स्वीकृति आदेश प्राप्त हुआ है। एनएफडीसी ने इसके लिए अलग व्यवस्था की है।

7. एनएफडीसी ने सुश्री इंद्राणी द्वारा निर्देशित बांग्ला फ़ीचर फ़िल्म छाड़ का निर्माण किया, जिसने कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, 2022 में विशेष जूरी पुरस्कार जीता।

(बी) वितरण, सिंडिकेशन और ओटीटी

फ़िल्म वितरण विभाग को सात प्रमुख कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे कि नाट्य वितरण, सिंडिकेशन, भारत के सिनेमा ओटीटी, निर्यात, संगीत वितरण और अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म

बांग्लादेश के माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री डॉ. हसन महमूद और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर फ्रांस में 75वें कान फेस्टिवल के तीसरे दिन फ़िल्म मुजीब : द मेकिंग ऑफ़ ए नेशन के ट्रेलर का उद्घाटन करते हुए।

समारोह और विपणन। एनएफडीसी फ़िल्म प्रदर्शन और वितरण के सभी अद्यतन तरीकों का प्रभावी ढंग से दोहन करके दर्शकों को सिनेमा दिखाने में सफल रहा है। एनएफडीसी फ़िल्मों को www.cinemasofndia.com ओटीटी प्लेटफॉर्म सालभर स्ट्रीम करता है और दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है।

एनएफडीसी द्वारा किए गए कार्यः

- **वायाकॉम 18 प्रा. लिमिटेड** के साथ एनएफडीसी की छह हिन्दी फ़िल्मों के लिए पांच साल की अवधि के लिए औपचारिक रूप से एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग सौदा।
- दुनिया भर में एसवीओडी अधिकारों के लिए गैर-एक्सक्लूसिव आधार पर 12 महीने की अवधि के लिए आईएन10 मीडिया के **एपिक ऑन** ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ 60 फ़िल्मों के लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया।
- सीमित क्षेत्रों में एसवीओडी अधिकारों के लिए गैर-एक्सक्लूसिव आधार पर प्रत्येक शीर्षक के लिए 18 महीने की अवधि के लिए **एमयूबीआई** ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के साथ औपचारिक रूप से 37 फ़िल्में डील करती हैं। एनएफडीसी, एमयूबीआई के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग साझा करता है।
- एनएफडीसी की मणि कौल की चार फ़िल्मों के लिए **ईडी डिस्ट्रीब्यूशन**, फ्रांस के साथ एक निर्यात सौदे को औपचारिक रूप दिया। फ्रांस में इन शीर्षकों का विमोचन जनवरी 2023 के दौरान किया गया।
- आईआईएम-अहमदाबाद के साथ उनकी **बर्ड परियोजना** के लिए एक समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया। उन्होंने फ़िल्मों के 'समान भाषा सबटाइटलिंग' के लिए कुल छह शीर्षक (एनएफडीसी से पांच और सीएफएसआई से एक) का चयन किया है।

एनएफडीसी ने महामारी के दौरान चार नई फ़ीचर फ़िल्मों का निर्माण और सह-निर्माण किया। डेब्यू निर्देशकों की दो फ़िल्में अपने फ़ेस्टिवल जर्नी में हैं। बंगाली फ़ीचर फ़िल्म **छाड़ (द टेरेस)** (निर्देशकः इंद्राणी) की मार्चे डु कान 2022 में बाज़ार में स्क्रीनिंग हुई और 28वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड भी जीता। **कोरांगी नुन्ची (हू विल मैरी थॉमस?)** (निर्देशकः के. जयदेव) डायरामा फ़िल्म फ़ेस्टिवल, भारत में।

उप-महाद्वीप की बहुप्रतीक्षित फ़िल्मों में से एक तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक प्रमुख परियोजना, श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित भारत-बांग्लादेश सह-उत्पादन **मुजीब-द मेकिंग ऑफ ए**

नेशन का इंडिया पवेलियन में एक भव्य ट्रेलर रिलीज किया गया। कान फ़िल्म फ़ेस्टिवल 2022 इसके अलावा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक हाओबम पबन कुमार की फ़िल्म **जोसेफ की माचा (जोसेफ का बेटा)** पोस्ट–प्रोडक्शन के अंतिम चरण में है और जल्द ही अपनी फ़ेस्टिवल यात्रा शुरू करेगी।

53वें–इफ्फी के लिए, विभाग ने महान फ़िल्म निर्माता सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि के रूप में एक ऑनलाइन फ़िल्म पोस्टर डिज़ाइन प्रतियोगिता का समन्वय और आयोजन किया। प्रतियोगिता का विषय 'द वन एंड ओनली रे' था। 53वें इफ्फी में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिष्ठित हस्तियों को तीन विजेता फ़िल्म पोस्टर डिज़ाइन प्रस्तुत किए गए।

75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो (सीएमओटी) प्रोग्राम को एनएफडीसी द्वारा अब तक के सबसे पहले आउटरीच प्रयास के हिस्से के रूप में लागू किया गया था। 53–घंटे की फ़िल्म निर्माण चैलेंज की विजेता फ़िल्म को भारत के 22,000 स्कूलों के लगभग दो करोड़ स्कूली बच्चों के विशाल समूह के सामने प्रदर्शित किया गया था, जो कि सीएमओटी का एक घटक था। इसके अलावा, फ़ेस्टिवल में 'गाला प्रीमियर्स और स्पेशल स्क्रीनिंग्स' का प्रदर्शन किया गया।

वितरण विभाग दुनिया भर के सभी प्रमुख फ़िल्म बाज़ारों में अपना प्रतिनिधित्व जारी रखता है और मार्चे डू कान, अमेरिकी फ़िल्म बाज़ार (एएफएम), यूरोपीय फ़िल्म बाज़ार (ईएफएम) आदि जैसे सभी प्रसिद्ध बाज़ारों में एनएफडीसी ब्रांड का निर्माण करता है और सूची–ए में शामिल फ़ेस्टिवल प्रोग्रामर, अंतरराष्ट्रीय बिक्री एजेंट / वितरक और प्रतिष्ठित पत्रकार और संभावित साझेदारी और सामग्री बिक्री के लिए स्काउट के साथ अच्छे संबंध कायम करता है।

(सी) फ़िल्म बाज़ार, फ़िल्म समारोह, पटकथा लेखक प्रयोगशाला

मार्चे डू फ़िल्म 2022 में भागीदारी (17-25 मई, 2022)

मार्चे डु फ़िल्म (कान फ़िल्म बाज़ार) कान फ़िल्म महोत्सव का व्यापारिक प्रतिरूप है और दुनिया का सबसे बड़ा फ़िल्म बाज़ार है। एनएफडीसी फ़िल्म बाज़ार ने 'गो टू कान' कार्यक्रम में भाग लिया और वर्क–इन–प्रोग्रेस लैब 2021 की पांच फ़िल्मों के पिच वीडियो दिखाए।

फ़िल्म बाज़ार में को–प्रोडक्शन मार्केट 2021 (नवंबर) में जिन पांच प्रोड्यूसर के प्रोजेक्ट थे, उन्होंने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

एनएफडीसी फ़िल्म बाज़ार (नवंबर 20-24, 2022)

फ़िल्म बाज़ार, अंतरराष्ट्रीय और दक्षिण एशियाई फ़िल्म बिरादरी के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक मंच है। बाज़ार फ़िल्म निर्माण, उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में दक्षिण एशियाई सामग्री और प्रतिभा की खोज, समर्थन और प्रदर्शन पर केंद्रित है। फ़िल्म बाज़ार दुनिया भर के फ़िल्म खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक अभिसरण बिंदु है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विश्व सिनेमा की बिक्री को सुविधाजनक बनाना है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर पणजी, गोवा में 53वें आईएफएफआई के दौरान एनएफडीसी फ़िल्म बाजार, 2022 का उद्घाटन करते हुए।

2007 में अपनी शुरुआत से लेकर, फ़िल्म बाज़ार दक्षिण एशिया के वैश्विक फ़िल्म बाज़ार में विकसित हुआ है, हर क्रियाकलाप के साथ दक्षिण एशियाई और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी में वृद्धि हुई है। 20–24 नवंबर, 2022 को इफ्फी–53 के साथ बाजार का आयोजन किया गया। फ़िल्म बाज़ार 2022 में 39 देशों के कुल 1,407 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सह-उत्पादन बाज़ार 2022

वर्ष 2007 में शुरू फ़िल्म बाज़ार का सह–उत्पादन बाज़ार का उद्देश्य, भारतीय निर्माताओं को वित्तीय सहायता, स्थान समर्थन,

या पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाओं के रूप में अपनी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय सह-निर्माता खोजने के लिए एक मंच प्रदान करना था। इस वर्ष, 11 देशों, अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, नेपाल, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत से 14 भाषाओं में 20 परियोजनाओं को बाज़ार में प्रस्तुत करने के लिए चुना गया था। इस साल पहली बार फ़िल्म बाज़ार ने सह-निर्माण समझौते को ध्यान में रखते हुए स्पेन से एक वेब सीरीज *ला प्रिंसेस डे कपूरथला (द प्रिंसेस ऑफ कपूरथला)* के लिए एक प्रोजेक्ट आमंत्रित किया था। फ़िल्म बाज़ार ने भारत में फ्रांसीसी दूतावास के साथ अपने सहयोग को जारी रखा, जिसने विकास और फ्रेंच अनुवाद के लिए एक प्रोजेक्ट (भारत से किस्सा-ए-सर्कस) को फ्रांसीसी संस्थान के सहयोग से 'द फ्रेंच इंस्टीट्यूट अवार्ड' प्रदान किया।

वर्क-इन-प्रोग्रेस लैब

वर्क-इन-प्रोग्रेस लैब चयनित फ़िल्म निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों के एक प्रतिष्ठित पैनल के सामने अपनी फ़िल्म के रफ कट को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें फ़िल्म समारोह के निदेशक, फ़िल्म समीक्षक, निर्माता और संपादक शामिल होते हैं। ये सलाहकार फ़िल्म निर्माता को फ़िल्म के एक पूर्ण अंतिम कट को हासिल करने में मदद करने के उद्देश्य से संपादन पर मूल्यवान सुझाव देते हैं। वर्क-इन-प्रोग्रेस लैब केवल रफ कट में फिक्शन फ़ीचर के लिए खुला है। प्रत्येक वर्ष इस लैब के लिए अधिकतम पांच फ़िल्मों का चयन किया जाता है।

व्यूइंग रूम

द व्यूइंग रूम एक वीडियो लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है, जो फ़िल्म फ़ेस्टिवल में जाने, वैश्विक बिक्री, वितरण के संभावित भागीदारों और फिनिशिंग फंड की तलाश में फ़िल्मों को प्रदर्शित करने के लिए है। व्यूइंग रूम ने 2022 की सबसे हालिया भारतीय और दक्षिण एशियाई फ़िल्मों को प्रस्तुत किया जो या तो पूरी हो चुकी थीं या संपादन और पोस्ट-प्रोडक्शन के अंतिम चरण में थीं।

ज्ञान शृंखला

ज्ञान शृंखला में फ़िल्म उद्योग के प्रमुख निर्णय निर्माताओं और बाज़ार संचालकों के साथ विशेष रूप से तैयार की गई प्रस्तुतियां, व्याख्यान और पैनल चर्चा शामिल हैं। शृंखला में बदलती सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं के माध्यम से सामग्री का विकास, शैलियों का विस्तार, वितरण के पारंपरिक और अभिनव मंच, विभिन्न उभरती सह-उत्पादन संभावनाएं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संधियां, और विभिन्न फ़िल्म समारोहों और बाज़ारों को नेविगेट करने की कला जैसे विषयों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है (किंतु, यहीं तक सीमित नहीं है)।

बाज़ार स्क्रीनिंग

मार्केट स्क्रीनिंग (पहले उद्योग स्क्रीनिंग के रूप में जाना जाता था) फ़िल्म निर्माताओं और प्रोड्यूसर को अंतरराष्ट्रीय बिक्री एजेंटों, वितरकों, उत्पादकों, एग्रीगेटर्स और बाज़ार में भाग लेने वाले फ़िल्म फ़ेस्टिवल प्रोग्रामर को अपनी फ़िल्मों को प्रदर्शित करने के लिए एक स्थान प्रदान करता है। मार्केट स्क्रीनिंग में पहली बार दिखाई गई कुछ फ़िल्में नई भाषाओं योरूबा, छत्तीसगढ़ी और रूसी में थीं।

प्रदर्शनी स्टॉल

फ़िल्म बाज़ार के माध्यम से फ़िल्म बाज़ार में मीडिया कंपनियों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, विपणन करने और बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग के अवसरों की एक शृंखला प्रदान किया जाता है। प्रदर्शनी स्टॉल कंपनियों को अपनी खुद की जगह बनाने में सक्षम बनाते हैं, जहां वे अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संभावित भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए आमने-सामने बैठकें कर सकते हैं।

राज्यों और देश के मंडप

फ़िल्म बाज़ार 2022 में बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 13 राज्य सरकारों की भागीदारी देखी गई। देश के मंडप रूस, फ्रांस और दुबई द्वारा लिए गए थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों जैसे एनएफएआई, एनएमआईसी, डीपीडी, बेसिल और प्रसार भारती के भी फ़िल्म बाज़ार में अपने पवेलियन थे। भारतीय उद्योग परिसंघ, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप इंडिया और इन्वेस्ट इंडिया जैसे उद्योग हितधारकों द्वारा भी मंडप लिया गया।

बुक टू बॉक्स ऑफिस

इस साल, पहली बार, फ़िल्म बाज़ार ने बुक एडाप्टेशन पर एक कार्यक्रम पेश किया, जहां भारत के शीर्ष प्रकाशकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध निर्माताओं, ओटीटी प्लेटफार्मों के प्रतिनिधियों, बिक्री एजेंटों और बाज़ार में भाग लेने वाले दुनिया भर के वितरकों के लिए अपनी पुस्तकों का चयन किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली प्रकाशन कंपनियों ने उन पुस्तकों की एक सूची का चयन किया जो उन्हें लगा कि वे स्क्रीन के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

स्क्रीनराइटर्स लैब (एसडब्ल्यूएल)

पिछले कुछ वर्षों में, एनएफडीसी ने भारतीय सिनेमा के विकास के लिए आवश्यक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की है। फ़िल्म विकास के शासनादेश के तहत, एनएफडीसी पटकथा लेखन पर मुख्य ध्यान केंद्रित करता है, ताकि योग्य आकर्षक कथाओं और कहानियों का पोषण किया जा सके। एनएफडीसी लैब्स, 2007 में शुरू हुई, भारतीय फ़िल्म निर्माताओं के लिए पहले से ही क्षेत्र में स्थापित या फ़िल्म और/या मीडिया अध्ययन के बाद अपने करियर के विकास के लिए पेशेवर प्रगति का एक माध्यम प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। प्रत्येक वर्ष, छह पटकथा लेखक अपनी लिपियों के विकास के लिए इस गहन कार्यक्रम का प्रशिक्षण हैं।

मीडिया प्रोडक्शन

विज्ञापन, फ़िल्म निर्माण और संचार

प्रोडक्शन शुरू किया गयाः एनएफडीसी ने विभिन्न प्लेटफार्मों में विज्ञापन संचार के निर्माण और प्रसार के लिए एक विश्वसनीय एकीकृत मीडिया सेवा प्रदाता के रूप में विभिन्न मंत्रालयों के बीच एक प्रतिष्ठित नाम अर्जित किया है। अपनी व्यवस्थित और कुशल कार्य प्रक्रिया के कारण, एनएफडीसी मौजूदा और नए ग्राहक मंत्रालयों से समान रूप से व्यवसाय को निरंतर सकारात्मक तौर पर सुरक्षित रखता है और सरकार के लिए संचार के नए रुझानों में शीर्ष पर बना रहता है।

एनएफडीसी का प्राथमिक लक्ष्य विज्ञापन में तालमेल सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के संचार को क्रियान्वित करने के व्यवसाय को अपनाना है, जिससे जनता के साथ बेहतर पहुंच हो।

एक बड़ा और बेहतर चहुमुखी गुलदस्ताः वन स्टॉप शॉप इफेक्टः एनएफडीसी ने अपनी सेवाओं के गुलदस्ते में विविधता ला दी है और विज्ञापन के अपरंपरागत स्वरूपों जैसे वर्चुअल इवेंट्स और प्रदर्शनियों, कॉफी टेबल बुक्स (भौतिक और ई-पुस्तकों दोनों), नुक्कड़ नाटकों, ऑन-ग्राउंड प्रदर्शनियां, इंटरैक्टिव/इमर्सिव वीडियो में प्रवेश किया है, जो सरकारी संचार को दोतरफा प्रक्रिया बना सकते हैं और मैसेजिंग की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। इस वर्ष के कुछ मुख्य आकर्षण सीएसआईआर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए 75 आई-कनेक्ट इवेंट थे, जो 12 मई, 2022 से 12 अगस्त, 2022 तक एक विशेष वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 60 दिनों तक चले। आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए भी विशेष पहल की गई, जहां आयुष मंत्रालय के लिए दो कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 के 75 दिन और 50 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए। कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले की प्राचीर और शिवसागर, असम से आयोजित किए गए।

वर्तमान कैलेंडर वर्ष में, अधिकृत उत्पादन विभाग ने लगभग 55 ग्राहक मंत्रालयों को लगभग 170 परियोजनाओं के लिए इसके विभिन्न वर्टिकल्स के तहत निम्न सेवा प्रदान कीः

- फ़िल्म/ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन
- इवेंट मैनेजमेंट
- विज्ञापन अभियान

- ग्राफिक डिज़ाइन/प्रिंट कार्य
- नुक्कड़ नाटक

कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए विभाग द्वारा प्राप्त की गई कुल आय 56 करोड़ रुपये है।

एनएफडीसी की लगभग 85 प्रोजेक्ट कार्य के विभिन्न चरणों में हैं, जिनका अगले कैलेंडर वर्ष के लिए अनुमानित मूल्य लगभग 28 करोड़ रुपये है। 2023 की पहली तिमाही में शुरू की जाने वाली कुछ प्रतिष्ठित परियोजनाओं में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से स्मार्ट सिटी योजना पर नई फ़िल्में, आयुष्मान भारत पर चहुँमुखी अभियान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के लिए कई फ़िल्में और रेडियो कार्यक्रम, इन्वेस्ट इंडिया के लिए, ओडीओपी के लिए फ़िल्मों की विशेष श्रृंखला हैं।

एनएफडीसी ने संबंधित संस्थानों के लिए फ़िल्मों के विकास के लिए भारत के चुनाव आयोग और लोकसभा सचिवालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

एनएफडीसी सक्रिय रूप से ओटीटी स्पेस के लिए निर्माण करने पर विचार कर रहा है और प्रमुख ओटीटी प्लेटफार्मों में से एक के साथ साझेदारी करके भारत में चुनावों पर एक वेब श्रृंखला शुरू करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के साथ सक्रिय चर्चा कर रहा है।

एनएफडीसी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से फ़ीचर फ़िल्म, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म और ऐनिमेटेड शॉर्ट फ़िल्म के निर्माण के लिए 8.39 करोड़ रुपये का स्वीकृति आदेश प्राप्त हुआ है।

एनएफडीसी ने फ़ीचर फ़िल्म, वृत्तचित्र और लघु ऐनिमेशन फ़िल्म के निर्माण और सह-निर्माण के लिए पूर्वोत्तर की भाषाओं में उत्तरपूर्वी फ़िल्म निर्माताओं से आवेदन प्राप्त करने के लिए अलग विंडो खोली है।

(ई) क्षेत्रीय कार्यालय - दक्षिण

(i) समग्र शिक्षा के तहत, तमिलनाडु राज्य शिक्षा विभाग के साथ, एनएफ़डीसी ने राज्य के 37 जिलों के 278 स्कूलों में 11,120 छात्रों के लिए मल्टीमीडिया कैरियर मार्गदर्शन कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया।

एनएफडीसी ने तमिलनाडु में 250 बेरोज़गार दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए तमिलनाडु राज्य के दिव्यांगजन कल्याण विभाग की योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण की पेशकश की है।

तमिलनाडु आदि द्रविड़ आवास विकास निगम (टीएडीएचसीओ): एनएफडीसी ने इस योजना के माध्यम से मीडिया में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 71 लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया है।

सरकार द्वारा प्रायोजित कौशल प्रशिक्षण के अलावा, 40 अपात्र उम्मीदवारों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शुल्क का भुगतान करके कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

डिजिटल मीडिया सेवाएं

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में, एनएफडीसी ने निम्नलिखित ग्राहकों को डिजिटल मीडिया सेवाएं प्रदान की हैं:
- आईआरसीटीसी - डिजिटल मीडिया सर्विसेज और सोशल मीडिया प्रबंधन।
- नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड - सोशल मीडिया प्रबंधन।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) - सोशल मीडिया प्रबंधन।
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग - सोशल मीडिया प्रबंधन।
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान - सोशल मीडिया प्रबंधन।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (संस्कृति मंत्रालय) - आजादी का अमृत महोत्सव और डिजिटल अभियानों के हिस्से के रूप में एबीसीडी परियोजना के लिए सोशल मीडिया प्रबंधन।
- भारतीय खाद्य निगम - सोशल मीडिया प्रबंधन।

- श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा एनसीएस योजना - सोशल मीडिया प्रबंधन।
- डिजिटल मीडिया डिवीजन ने दिसंबर, 2022 के अंत तक 4.55 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल कर लिया है।

(जी) फ़िल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सरकार की 'कारोबारी सुगमता - ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' की नीति के तहत दिसंबर 2015 में एनएफडीसी में फ़िल्म फैसिलिटेशन ऑफिस (एफएफओ) की स्थापना की, ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट (फ़ीचर फ़िल्म, टीवी/वेब शो और सीरीज़ और रियलिटी टीवी/वेब शो और सीरीज़) को सुगम बनाया जा सके, जो भारत में फ़िल्म बनाने के इच्छुक हैं। फ़िल्म सुविधा कार्यालय की सेवाओं को 2019 में घरेलू फ़िल्म निर्माताओं तक बढ़ाया गया था। फ़िल्म सुविधा कार्यालय पोर्टल www.ffo.gov.in में देशभर में फ़िल्म बनाने की अनुमति के साथ-साथ भारत में फ़िल्म बनाने के लिए सूचना संसाधन को लेकर एकल-खिड़की सुविधा प्रणाली है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और एनएफडीसी के बीच समझौता

भारत को फ़िल्म निर्माण के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से एफएफओ के संचालन को जारी रखने के लिए एनएफडीसी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर 15 जून, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) में फ़िल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) की स्थापना होना सरकार की 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' की नीति के तहत दिसंबर 2015 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की निरंतरता में है। यह समझौता 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2024 तक तीन वर्षों के लिए लागू रहेगा।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू आवेदनों की प्रक्रिया

वर्ष 2022 के दौरान एफएफओ ने 31 परियोजनाओं के लिए अनुमति प्रदान की। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, कनाडा, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, कज़ाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, न्यूज़ीलैंड, नाइजीरिया, ईरान और ऑस्ट्रेलिया की 3 ऐनिमेशन परियोजनाएं, 11 टेलीविज़न शृंखला/रियलिटी शोज और 17 फ़ीचर फ़िल्में शामिल थीं। उपरोक्त में से एक फ़िल्म नामतः गर्ल्स विल बी गर्ल्स (इंडो-फ्रेंच) को द्विपक्षीय ऑडियो विज़ुअल को-प्रोडक्शन संधि के तहत आधिकारिक सह-निर्माण का दर्जा दिया गया है। कैलेंडर वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त अन्य उल्लेखनीय अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में क्रिस हेल्म्सवर्थ अभिनीत एक्सट्रैक्शन 2 शामिल है। कैलेंडर वर्ष 2022 में एफएफओ ने 32 घरेलू परियोजनाओं के लिए अनुमति प्रदान की। इसमें रेलवे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ अनुमति के लिए प्रत्येक के छह प्रोजेक्ट शामिल थे।

भारत में विदेशी फ़िल्मों के आधिकारिक ऑडियो-विज़ुअल को-प्रोडक्शन और शूटिंग के लिए प्रोत्साहन की घोषणा

भारत में विदेशी फ़िल्मों के आधिकारिक ऑडियो-विज़ुअल को-प्रोडक्शन और शूटिंग के लिए प्रोत्साहन की घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 18 मई, 2022 को मार्चे डू कान 2022 में इंडिया पवेलियन के उद्घाटन समारोह के दौरान की।

ऑडियो विज़ुअल सह-उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत, सभी योग्य परियोजनाओं के लिए, भारतीय सह-निर्माता योग्यता व्यय पर 30 प्रतिशत तक देय नकद प्रतिपूर्ति, बशर्ते अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक भारत में का दावा कर सकते हैं। हालांकि, प्रतिपूर्ति परियोजना के लिए वित्तीय योगदान के उनके संबंधित हिस्से के अनुसार उत्पादकों के बीच विभाजित की जाएगी। ऑडियो-विज़ुअल सह-उत्पादन पर भारत की आधिकारिक द्विपक्षीय सह-उत्पादन संधियों में से एक के तहत, परियोजना को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भाग लेने वाले देशों द्वारा "सह-उत्पादन" का दर्जा दिया जाना चाहिए। जिन परियोजनाओं को 1 अप्रैल, 2022 के बाद आधिकारिक सह-उत्पादन का दर्जा दिया गया है, वे प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।

भारत में विदेशी फ़िल्मों की शूटिंग के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत, सभी योग्य परियोजनाओं के लिए, अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म निर्माण कंपनी भारत में योग्यता व्यय पर 30 प्रतिशत तक देय नकद प्रोत्साहन का दावा कर सकती है, जो अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक है। इसके अलावा अतिरिक्त प्रतिपूर्ति के रूप

में 5 प्रतिशत बोनस का दावा किया जा सकता है, जो अधिकतम 50 लाख रुपये है। यह भारत में 15 प्रतिशत या उससे अधिक जनशक्ति को नियोजित करने के लिए दिया जाएगा। 1 अप्रैल, 2022 के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय (केवल वृत्तचित्रों के लिए) द्वारा शूटिंग के लिए अनुमत अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुतियों को पात्र माना जाएगा।

अभी तक प्रोत्साहन राशि के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से इंसेंटिव इवैल्यूएशन कमेटी द्वारा भुगतान के लिए स्वीकृत किए जाने से पहली फ़िल्म 'इनहेरिटेंस' की ऑडिट जांच की जा रही है और दूसरी, इंडो-फ्रेंच को-प्रोडक्शन 'गर्ल्स विल बी गर्ल्स' को अंतरिम मंजूरी मिल गई है।

भारत में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्मांकन स्थानों पर एक कॉम्पेंडियम का निर्माण

एफएफओ ने भारत के 75 प्रतिष्ठित फ़िल्मांकन स्थानों पर कॉम्पेंडियम के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। संग्रह को पुस्तक के रूप में और साथ ही एक डिजिटल प्रारूप में प्रकाशित किया जाएगा, जो एफएफओ वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगा। हार्ड कॉपी/डिजिटल प्रारूप (पेन ड्राइव) को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और घरेलू फ़िल्म बाज़ारों/फेस्टिवल के साथ-साथ उद्योग सम्मेलनों और कार्यक्रमों में लॉन्च और प्रसारित किया जाएगा। संग्रह में प्रति राज्य कम से कम दो स्थान होंगे और फ़िल्म निर्माण के लिए प्रासंगिक स्थान के बारे में जानकारी होगी।

68वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के तहत मोस्ट फ़िल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड 2020

एफएफओ राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के तहत मोस्ट फ़िल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड श्रेणी का चयन करता है। वर्ष 2020 के एमएफएफएस पुरस्कार के लिए 13 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। जूरी ने मध्य प्रदेश को मोस्ट फ़िल्म फ्रेंडली स्टेट 2020 के रूप में चुनने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को विशेष उल्लेख के लिए चुना गया था।

एनएफडीसी और इन्वेस्ट इंडिया के बीच समझौता

एनएफडीसी के तहत एफएफओ को संचालित करने के लिए एनएफडीसी और इन्वेस्ट इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझोता ज्ञापन के तहत, इन्वेस्ट इंडिया तीन साल की अवधि के लिए एफएफओ के सभी कार्यों का निष्पादन करेगा। यह सहयोग एफएफओ को इन्वेस्ट इंडिया की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू आउटरीच का लाभ उठाने में सक्षम करेगा, ताकि भारत को एक पसंदीदा फ़िल्मिंग गंतव्य के रूप में प्रभावी ढंग से बाज़ार में उतारा जा सके। यह ऑनलाइन अनुमति पोर्टल के सुधार और इसे राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत करने के कारण एफएफओ की ऑनलाइन उपस्थिति को भी मजबूत करेगा।

अंतरराष्ट्रीय आउटरीच

यूरोपीय फ़िल्म बाज़ार (ईएफएम): एफएफओ ने अपनी 'फ़िल्म इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन ईएफएम 2022 में भाग लिया। एफएफओ फ़िल्मों और प्रकाशनों को वर्चुअल इंडिया पवेलियन के माध्यम से प्रसारित किया गया। मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल कंटेंट हब एंड प्रेफर्ड फ़िल्मिंग डेस्टिनेशन' पर एक विशेष क्यूरेटेड फोकस सत्र आयोजित किया गया था।

मार्चे डू फ़िल्म, कान 2022 में भागीदारी: एफएफओ ने कान फ़िल्म मार्केट 2022 के आयोजन में भाग लिया, जो 17-25 मई, 2022 तक आयोजित किया गया था। एफएफओ ने अपनी 'फ़िल्म इन इंडिया' पहल और भारत सरकार की हाल ही में घोषित की गई प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा दिया। एफएफओ लोकेशंस की फ़िल्म इंडिया पवेलियन में विभिन्न स्क्रीन पर दिखाई गई। देश में फ़िल्मांकन को आसान बनाने की दिशा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल पर केंद्रित एक सत्र कान में इंडिया पवेलियन में आयोजित किया गया था, जिसमें विदेशी और घरेलू दोनों फ़िल्म निर्माताओं को देश में अपनी आगामी परियोजनाओं की शूटिंग करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

वेनिस प्रोडक्शन ब्रिज: वेनिस प्रोडक्शन ब्रिज (वीपीबी) वेनिस इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल का फ़िल्म बाज़ार है और 1-6 सितंबर, 2022 तक आयोजित किया गया था। 4 सितंबर, 2022 को एक राउंड टेबल आयोजित किया गया था, जिसमें एमडी, एनएफडीसी और एफएफओ हेड ने उत्सव में भाग लेने वाले इटली और अन्य देशों के फ़िल्म आयोगों के साथ बातचीत की

थी। समारोह स्थल पर 5 सितंबर, 2022 को 'इंडिया एज ए कंटेंट डेस्टिनेशन' शीर्षक से एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया।

टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सवः टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (टीआईएफएफ) 8-18 सितंबर, 2022 से टोरंटो में आयोजित किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और एनएफडीसी ने टीआईएफएफ उद्योग में भाग लिया, जो महोत्सव के लिए फ़िल्म बाज़ार है। एफएफओ ने प्रोत्साहन योजनाओं और भारत के विभिन्न स्थानों के बारे में चर्चा की। पैवेलियन के स्क्रीन पर एफएफओ 'लोकेशंस और इंसेंटिव्स' फ़िल्म भी दिखाई गई।

एनेसी फ़िल्म फ़ेस्टिवल और मिपकॉम कानः फ्रांस में आयोजित एनेसी फ़िल्म फ़ेस्टिवल और मिपकॉम कान में प्रोत्साहन और फ़िल्मोग्राफी पर एफएफओ के ब्रोशर प्रदर्शित किए गए।

फ़िल्म बाज़ार 2022 और इफ्फी-53ः एफएफओ ने 13 राज्यों की समन्वित भागीदारी के साथ फ़िल्म बाज़ार में भाग लिया, जिसमें भारत के विविध फ़िल्मांकन स्थानों का प्रदर्शन किया गया। भारत में शूट की गई विदेशी फ़िल्मों के साथ-साथ आधिकारिक सह-निर्माण के लिए हाल ही में घोषित प्रोत्साहन भी प्रदर्शित किए गए।

यूरोपीय फ़िल्म बाज़ार (ईएफएम) 2022 (हाइब्रिड मॉडल)

ईएफएम 2022 में एनएफडीसी की वर्चुअल भागीदारी थी, जहां सीआईआई के सहयोग से एक भारतीय मंडप स्थापित किया गया था। इसने भारत के सिनेमाघरों और उन खूबसूरत स्थानों की झलक पेश की, जो फ़िल्म निर्माताओं को भारत आने के लिए प्रेरित करते हैं।

ईएफएम 2022 में भारत का हस्तक्षेप

आठ फ़िल्मों - असम की दिमासा बोली में *सेमखोर;* मराठी में *बिटरस्वीट* और *गोदावरी;* तमिल में *कूझंगल; कालकोक्खो* बंगाली में; तेलुगू में *नाट्यम;* हिन्दी में *अल्फा बीटा गामा* और कन्नड़ में *डोलूकी बाज़ार* की स्क्रीनिंग की गई।

सत्यजीत रे के जन्मशती वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में, उनके द्वारा निर्देशित (एनएफडीसी द्वारा निर्मित) फ़िल्मों और उनके जीवन पर बने वृत्तचित्रों (भारत के तत्कालीन फ़िल्म प्रभाग द्वारा निर्मित) स्क्रीनिंग के माध्यम से उन्हें और श्रीमती लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई।

"इंडिया@75- भारत-जर्मन संबंधों का विकास और सह-निर्माण", "भारत को एक वैश्विक कन्टेन्ट हब और पसंदीदा फ़िल्मिंग गंतव्य बनाना", "यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय सामग्री का प्रचलन", "बर्लिनाले टैलेंट के आयोजक (2022 संस्करण के भारतीय प्रतिभागियों के साथ बर्लिनाले के प्रतिभा विकास कार्यक्रम के साथ गोलमेज सम्मेलन") पर चर्चा और सत्र।

कान फ़िल्म महोत्सव, लोकार्नो फ़िल्म महोत्सव, चेक फ़िल्म कोष, टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म कोष, यूरोपीय फ़िल्म प्रचार (ईएफपी) के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें।

मार्चे डू फ़िल्म/फेस्टिवल डे कान 2022ः इंडियाः कंट्री ऑफ ऑनर

मार्चे डू फ़िल्म के 2022 आयोजन में भारत 'कंट्री ऑफ ऑनर' था। एनएफडीसी ने फिक्की के सहयोग से मार्च में भारत की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सफलतापूर्वक अनेक क्रियाकलापों की योजना बनाई।

मार्चे डू फ़िल्म 2022 में भारत का हस्तक्षेप

17 मई को रेड कार्पेट पर उद्घाटन फ़िल्म के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत से फ़िल्म उद्योग के एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

इंडिया पवेलियन के उद्घाटन के मौके पर श्री ठाकुर ने सह-निर्माण को बढ़ावा देने और भारत में विदेशी फ़िल्मों की शूटिंग की सुविधा के लिए दो नई मौद्रिक प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गणमान्य व्यक्तियों और वैश्विक फ़िल्म निर्माण बिरादरी के सदस्यों के साथ इंडिया फोरम पैनल चर्चा सत्र का आयोजन इस बात पर केंद्रित था कि भारत दुनिया का कंटेंट हब की तैयारी किस प्रकार कर रहा है।

रॉकेट्री का विश्व प्रीमियरः द नम्बी इफेक्ट एक रेड कार्पेट

इवेंट के रूप में संपन्न हुआ। इसके अलावा, *गोदावरी* (मराठी), *अल्फा बीटा गामा* (हिन्दी), *बूम्बा राइड* (मिशिंग), *धुइन* (हिन्दी/मैथिली) और *ट्री फुल ऑफ पैरट्स* (मलयालम) की बाज़ार स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया।

अन्य उल्लेखनीय हस्तक्षेपः मुजीबः द *मेकिंग ऑफ ए नेशन* का ट्रेलर लॉन्च, "गोज टू कान" वर्क-इन-प्रोग्रेस सेक्शन के हिस्से के रूप में वर्तमान में निर्माणाधीन पांच फ़िल्मों की स्क्रीनिंग, सत्यजीत रे की पुनः निर्मित क्लासिक प्रतिद्वन्द्वी की स्क्रीनिंग, पांच युवा उद्यमी "स्टार्ट-अप पिचिंग सत्र" के हिस्से के रूप में और भारत के ऐनिमेशन उद्योग के ग्यारह सदस्य "ऐनिमेशन डे इनिशिएटिव" में शामिल।

टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव 2022

एनएफडीसी ने टोरंटो इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल (टीआईएफएफ) 2022 में अपनी छाप छोड़ी, जहां भारत को "स्टोरीटेलर्स की भूमि" के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक प्रदर्शनी स्थल स्थापित किया गया था। भागीदारी का फोकस विदेशी फ़िल्म निर्माताओं के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन योजनाओं को प्रस्तुत करना था।

टीआईएफएफ 2022 में भारत का हस्तक्षेपः

इंडिया पवेलियन में भारत को "अवसरों की भूमि" के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक चर्चा आयोजित की गई।

भारत-कनाडा सह-निर्माण समझौते में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फ़ीचर फ़िल्मों का सह-निर्माण, और आईएफएफआई और फ़िल्म बाज़ार में सक्रिय भागीदारी शामिल है, लेकिन यह इसी तक सीमित नहीं है।

300 से अधिक मेहमानों के लिए एक "सेलिब्रेट इंडियन सिनेमा इवनिंग कॉकटेल" का आयोजन किया गया था, जिसमें टीआईएफएफ में फ़िल्म निर्माण बिरादरी के प्रमुख सदस्य, उन देशों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिनके साथ भारत का सह-निर्माण समझौता है।

टीआईएफएफ उद्योग सम्मेलन के हिस्से के रूप में श्री एस.एस. राजामौली की विशेषता के बारे में एक वार्ता सत्र आयोजित किया गया था।

वर्तमान में कनाडा में सिनेमा की कला और व्यवसाय में लगी भारतीय-कनाडाई महिलाओं के लिए "सिनेमा में भारतीय महिलाएं" पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई।

सत्यजीत रे की पुनःनिर्मित क्लासिक द *आगंतुक* की स्क्रीनिंग और *ऑरोबोरोस, उड़ जा नन्हे दिल, गांधी एंड कंपनी* की मार्केट स्क्रीनिंग।

इंडिया पवेलियन में फ़िल्म आयोगों, फ़िल्म निधियों, निर्माताओं और फ़िल्म निर्माताओं के साथ 30 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं।

ताशकंद अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव 2022

ताशकंद अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव 2022 में, एनएफडीसी के गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय फ़िल्म उद्योग के पेशेवरों के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। एक पहल "इंडियन फ़िल्म डेज़" का आयोजन किया गया था, जहां *रेवा, महानती* और *शिवरिन्जिनम इनम सिला पेंगलम* की स्क्रीनिंग की गई थी। एनएफडीसी के गणमान्य लोगों ने बैठकों और विभिन्न सत्रों में भाग लिया, जिसमें ताशकंद फ़िल्म महोत्सव बिजनेस फोरम और राष्ट्रीय फ़िल्म विधान पर एक गोलमेज सम्मेलन शामिल रहा तथा अन्य बातें भी। सह-निर्माण प्रोजेक्ट पर एक प्रस्तुति और फ़िल्म निर्माता उमेश मेहरा द्वारा एक मास्टरक्लास का आयोजन किया गया।

कौशल विकास विभाग

दृढ़ और प्रतिबद्ध प्रयासों के कारण, 1 अगस्त, 2022 को एनएफडीसी को मीडिया और मनोरंजन उद्योग में कौशल और प्रतिभा विकास गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक पुरस्कार देने वाली संस्था और एक आकलन एजेंसी के रूप में दोहरा प्रमाणन प्राप्त हुआ। इस दर्जे ने संगठन को निजी प्रशिक्षण भागीदारों को संबद्ध करने, मूल्यांकन करने, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) का संचालन करने, प्रमाणन करने, विभिन्न प्रशिक्षण भागीदारों को सामग्री की बिक्री करने, राष्ट्रीय कौशल योग्यता

फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित करने, फ़िल्म और टेलीविज़न में उत्कृष्टता (सीओई) केंद्र खोलने की अनुमति दी है।

तब से, एनएफडीसी तीन प्रशिक्षण भागीदारों – नई दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु से संबद्ध है। ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में शामिल होने के लिए हैदराबाद स्थित हैमस्टेक कॉलेज ऑफ क्रिएटिव एजुकेशन (एचसीसीई) के साथ बातचीत चल रही है और ऐस फाउंडेशन मूल्यांकन एजेंसी के रूप में शामिल हो गया है।

एनएफडीसी ने डिजिटल स्टिल फोटोग्राफी, डिजिटल वीडियो एडिटर और मुख्य कैमरा सहायक के लिए पाठ्यक्रम और विस्तृत सामग्री विकसित की है और उन्हें एनएसक्यूएफ के साथ समन्वित किया है। अगले चरण में, विकास के लिए 50 पाठ्यक्रमों की पहचान की गई है। पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन करने के लिए एक एजेंसी को किराए पर लेने के लिए एक प्रस्ताव आमंत्रण (आरएफपी) दस्तावेज विकसित किया गया है, जो कानूनी टीम द्वारा अनुमोदित होने के बाद, एक एजेंसी को किराए पर लेने के लिए प्रयोग होगा।

एनएफडीसी ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से 100 महिला पटकथा लेखिकाओं के लिए वर्चुअल तौर पर पटकथा लेखन कार्यशालाओं का आयोजन किया। रिकॉग्निशन टू प्रायर लर्निंग (आरपीएल) गतिविधि का आयोजन नेटफ्लिक्स की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहल के रूप में किया गया था।

एनएफडीसी मार्च 2022 में जूनियर कौशल पहल के तहत छात्रों के लिए एक डिजिटल फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कौशल भागीदार के रूप में शामिल हुआ। सीबीएसई के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा जूनियर कौशल का आयोजन किया गया था।

इफ्फी-53/फ़िल्म बाज़ार 2022

75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो का दूसरा आयोजन इफ्फी-53 में लघु फ़िल्मों को समर्पित एक विश्वव्यापी नेटवर्क शॉर्ट्स टीवी के सहयोग से किया गया था, जो तकनीकी और प्रसारण सहायता प्रदान करते हुए कार्यान्वयन भागीदार के रूप में शामिल हुए। इस आयोजन ने भारतीय फ़िल्म बिरादरी के सदस्यों वाले चयन जूरी और ग्रैंड जूरी पैनल द्वारा पूरे भारत से 1000 से अधिक आवेदनों को आकर्षित किया। अंतिम 75 प्रतिभागियों को पांच टीमों में विभाजित किया गया था, और प्रत्येक टीम ने "53-घंटे के चैलेंज" में भाग लिया, 53-घंटे में एक लघु फ़िल्म का निर्माण किया, जिसमें "इंडिया@100" का अपना दृष्टिकोण दिखाया गया। एनएफडीसी ने 75 प्रतिभागियों के लिए किट बैग और मर्चेंडाइज डिज़ाइन किए, और एक फ़िल्म चैलेंज हब स्थापित किया गया, जो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो गतिविधि का केंद्र बन गया।

इस इफ्फी में, एनएफडीसी ने दर्शकों के लिए बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने वाले सिनेमा के लिए यूनिसेफ के साथ सहयोग किया है। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में, छह फ़िल्में *कफरनऊम, दोस्तोजी, सुमी, धनक, नानी तेरी मोरनी, उड़ जा नन्हे दिल* प्रदर्शित की गईं।

यूनिसेफ के सहयोग से, 'बाल फ़िल्मों को दर्शकों की मुख्यधारा में लाना' विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। घंटे भर के सत्र में शामिल पैनलिस्ट में भारतीय सिनेमा के ऐसे दिग्गज शामिल थे। जिन्होंने बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फ़िल्म सामग्री तैयार की है।

फ़िल्म बाज़ार के ज्ञान शृंखला खंड के हिस्से के रूप में, "एम एंड ई क्षेत्र में कौशल और प्रतिभा विकास को बढ़ाने में एनएफडीसी की भूमिका" पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई थी। एनएफडीसी के कौशल विकास विभाग को फ़िल्म उद्योग की हस्तियों के साथ नेटवर्किंग की अनुमति देने के लिए एक समर्पित प्रदर्शनी स्थान भी प्राप्त हुआ।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की परियोजनाएं

एनएफडीसी के साथ भारतीय फ़िल्म प्रभाग, एनएफएआई, डीएफएफ, सीएफएसआई के विलय के लिए सक्रिय भागीदारी की। इस दौरान, विलय के बाद तैनाती के लिए अन्य मीडिया इकाइयों में चार फ़िल्म मीडिया इकाइयों (जिन्हें विलय किया जा रहा था) के कर्मचारियों की मैपिंग के लिए एनएफडीसी कर्मचारी

प्रबंधन प्रणाली (एनईएमएस) के निर्माण की देखरेख की गई।

"मिशन लाइफ" के हिस्से के रूप में 5-10 मिनट की बच्चों की फ़िल्म के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना, जो व्यक्तिगत व्यवहारों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने की कथा की अगुवाई करती है।

"भारत के भीतरी इलाकों में फ़िल्मों को ले जाने के लिए ग्रामीण थिएटरों और सिनेमा ऑन व्हील्स का उपयोग", "भारत के सिनेमाघरों का पुनरुद्धार (एनएफडीसी का ओटीटी प्लेटफॉर्म)", "भारत में सामुदायिक रेडियो को कैसे मजबूत किया जाए", "आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विकसित किया गया खेल", और "सिनेमैटिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ब्रुनेई के साथ भारत का संभावित सहयोग", "भारत-यूके सह-उत्पादन समझौते को सक्रिय करने के तरीके", आदि जैसे विषयों पर तैयार किए गए शोध पेपर प्रस्तुत किए गए।

"बजट 2022 के कार्यान्वयन पर वेबिनार" श्रृंखला के भाग के रूप में "एवीजीसी में उद्योग-कौशल लिंकेज को मजबूत करना" पर पैनल चर्चा सत्र के लिए सहायता प्रदान की गई।

वितरण विभाग

कोविड-19 महामारी के कारण देशभर के थिएटरों को पूरी क्षमता से काम करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। परिस्थितियों को देखते हुए नाट्य विमोचन की योजना बनाना प्रतिकूल था। एनएफडीसी सामग्री के लिए दर्शकों की व्यस्तता बढ़ाने के लिए डिजिटल सिंडिकेशन के रास्ते पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। अनेक प्रस्तुतियों की नई खेप की रिलीज 2022-23 की अंतिम तिमाही के दौरान की गई।

छाड़ - द टैरेस जनवरी 2023 के दौरान प्रतिष्ठित 21वें ढाका इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल 2023 में प्रदर्शित की गई। ***जोसफ की माचा, कोरांगी नुंची और मुजीब - द मेकिंग ऑफ ए नेशन*** फ़िल्मों को चयन के लिए प्रमुख समारोहों में प्रस्तुत किया गया।

वर्षों से एनएफडीसी ने विभिन्न लाइसेंसदाताओं, सिंडिकेटरों, सामग्री प्लेटफार्मों और टेलीविज़न प्रसारकों के साथ अपनी साझेदारी कायम रखी है। विभाग ने इन भागीदारों के साथ अपनी प्रसिद्ध फ़िल्मों और करीबी सौदों और रणनीतिक बिक्री साझेदारी का लाभ उठाना जारी रखा। मानदंड संग्रह- न्यूयॉर्क, यूएस एनएफडीसी जानूस फ़िल्म्स के साथ समझौते को नवीनीकृत करेगा/जिसे अब यूएसए, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों के लिए एनएफडीसी और फ़िल्म डिवीजन के *पाथेर पांचाली* और अन्य सत्यजीत रे शीर्षकों के लिए मानदंड के रूप में जाना जाता है। विभाग ने फ़िल्म प्रभाग के सत्यजीत रे की चार वृत्तचित्रों और फ्रांस के क्षेत्र के लिए एनएफडीसी के सत्यजीत रे शीर्षकों के लिए कार्लोटा फ़िल्म्स, फ्रांस के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कायम किया और बातचीत की।

इसके अलावा, विभाग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन फ़िल्म फ़ेस्टिवल के लिए मास्टर क्लास शेड्यूल बनाने पर भी काम में जुटा रहा, जिसका आयोजन एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट्स (एससीओ सीएचएस) द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से 27 जनवरी से 31 जनवरी तक मुंबई, भारत में किया गया।

फ़िल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ)

यूरोपीय फ़िल्म बाज़ार 2023 में भागीदारी: बर्लिन, जर्मनी में आयोजित यूरोपीय फ़िल्म बाज़ार (ईएफएम) सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक फ़िल्म बाज़ारों और अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म उद्योग की सभाओं में से एक है। ईएफएम 16 से 23 फरवरी, 2023 तक आयोजित किया गया। एफएफओ ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय/एनएफडीसी की बड़ी भागीदारी के हिस्से के रूप में ईएफएम में भाग लिया। एफएफओ की भागीदारी प्रदर्शनी स्थल लेने और नेटवर्किंग के अवसरों में भाग लेने, स्थल विज्ञापन और प्रमुख व्यापार प्रकाशनों में विज्ञापन के साथ-साथ स्थल और भारतीय मंडप में नेटवर्किंग कार्यक्रमों के आयोजन और साझेदारी के माध्यम से हुई। एफएफओ ने भारतीय पवेलियन में ईएफएम में भाग लेने के लिए राज्य सरकारों को भी प्रोत्साहित किया। भागीदारी द्वारा भारत के विभिन्न फ़िल्मांकन स्थानों, प्रोत्साहन योजनाओं और भारत में फ़िल्मांकन में आसानी के लिए सरकार

की पहल और भारत को फ़िल्मांकन के एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला गया।

डिजिटल मीडिया अभियानः भारत की फ़िल्म प्रोत्साहन योजना को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए cinando.com जैसी व्यापार वेबसाइटों के साथ-साथ सोशल मीडिया और Google खोज पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक डिजिटल मीडिया अभियान कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली तिमाही में शुरू किया गया।

कौशल विकास, अंतरराष्ट्रीय प्रोत्साहन और विशेष प्रोजेक्ट

- एनएफडीसी के अंतरराष्ट्रीय प्रचार विभाग ने बर्लिनाले (फरवरी में) और हांगकांग फ़िल्मार्ट 2023 (मार्च में) में भारत की भागीदारी को सुविधाजनक बनाया।
- एनएफडीसी के कौशल और प्रतिभा विकास विभाग ने मार्च तक निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की-
- छत्तीसगढ़ में स्किल्स ऑन व्हील्स और सिनेमा ऑन व्हील्स गतिविधि।
- उत्तर पूर्व भारत में कौशल और प्रतिभा विकास गतिविधियों के लिए ऑटोडेस्क के साथ सहयोग।
- कौशल विकास पहलों के लिए प्रशिक्षण और संबद्धता भागीदारों के डेटाबेस को बढ़ाना।
- अमेजन और नेटफ्लिक्स के साथ आरपीएल गतिविधियों को अंतिम रूप देना।
- मिशन लाइफ पहलः 75 सीएमओटी को मिशन लाइफ के लिए फ़िल्म की अवधारणा बनाने का अवसर प्रदान किया गया, जिसका लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा के लिए दैनिक जीवन में किए जा सकने वाले पर्यावरण संरक्षण वाले कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना है।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत 28 नवंबर, 2022 को पणजी गोवा में 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर श्री चिरंजीवी को इंडियन फ़िल्म पर्सनेल्टी ऑफ़ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित करते हुए।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत के जी20 अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करते हुए।

7 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत की जी20 अध्यक्षता

भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारत ने 01 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक जी20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी ली है। इसका समापन 2023 में भारत में जी20 के शिखर सम्मेलन के साथ होगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत की जी20 प्रेसीडेंसी की ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार कर रहा है। मंत्रालय के अधीन केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) विदेश मंत्रालय के जी20 सचिवालय के लिए इसके विज्ञापन एवं ब्रांडिंग भागीदार की भूमिका निभा रहा है। इसमें लोक संपर्क गतिविधियां, मीडिया अभियान योजना और लोगो डिज़ाइन आदि शामिल है। मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाइयां जैसे- पत्र सूचना कार्यालय, दूरदर्शन समाचार, आकाशवाणी और न्यू मीडिया सेंटर इसके प्रचार के लिए विभिन्न ढंग से लगी हुई हैं। इसके लिए विशेष लेख, समाचार आधारित कार्यक्रम और सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है।

विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का दौरा

24 नवंबर, 2022 को अतिरिक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नेतृत्व में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक प्रतिनिधि मंडल और ब्रिगेडियर जनरल सलीम सईद ह्यूमेद अल शम्सियन की अध्यक्षता में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के प्रतिनिधि के बीच न्यू मीडिया सेंटर, रायसीना रोड, नई दिल्ली में एक बातचीत सत्र आयोजित किया गया। यह बातचीत 20-26 नवंबर, 2022 तक अध्ययन दौरे के लिए यूएई प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा के एक हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी। बातचीत का विषय 'राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों में मीडिया की भूमिका' था।

ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, दुबई

पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस 15 से 17 नवंबर, 2022 तक दुबई के अबू धाबी में आयोजित की गई। जिसका विषय था 'मीडिया उद्योग के भविष्य की रूपरेखा'। इसका आयोजन अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन कंपनी ने अमीरात न्यूज़ एजेंसी के साथ मिल कर किया। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मीडिया से जुड़े व्यक्तियों, विशेषज्ञों, नियामकों और प्रसारणकर्ताओं ने इस आयोजन में हिस्सा लेकर इसे एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन का रूप दिया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चन्द्रा ने ग्लोबल मीडिया कांग्रेस में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। इससे उन सभी बातों पर विचार-विमर्श जारी रखने में मदद मिली जो मंत्रालय ने मार्च, 2022 में दुबई एक्सपो में उठाए थे। इस विचार-विमर्श से भारत के दुनिया के सामने सकारात्मक समाचारों और एक कोमल शक्ति के रूप में उभरने के प्रयत्नों

24 नवंबर, 2022 को यूएई प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत

को और गति मिली।

भारत और यूनेस्को

भारत संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज विज्ञान, संस्कृति और जनसंचार के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यूनेस्को के 1981 में आयोजित आम सम्मेलन के 21वें सत्र में, विकासशील देशों में संचार कौशल बढ़ाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। इसका नाम था– 'इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ़ कम्युनिकेशन (आईपीडीसी)'। भारत ने इसकी संकल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश न केवल आईपीडीसी का एक सदस्य रहा बल्कि इसके अंतर-सरकारी परिषद (आईजीसी) में भी शामिल रहा। आम सम्मेलन के 35वें सत्र में आईजीसी के सदस्य के रूप में भारत का ससम्मान चयन हुआ। इसकी अवधि 2009 से 2013 तक थी।

भारत और शंघाई सहयोग संगठन

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसके गठन की घोषणा 15 जून, 2001 को शंघाई (चीन) में रूसी संघ द्वारा की गई थी। कज़ाकिस्तान गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य और उज्बेकिस्तान गणराज्य ने की। इसका नेतृत्व शंघाई फाइव मेकानिज़्म द्वारा किया गया।

भारत ने 17 सितंबर, 2022 से 25 जून, 2023 तक की अवधि के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एसीओ) की अध्यक्षता की जिम्मेदारी ली थी।

जनसंचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए संगठन के सदस्य देशों द्वारा 13 और 14 जून, 2019 को बिश्केक में जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे उसे भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 12 अगस्त, 2021 को अनुमोदित किया गया था। समझौते को लागू करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नामित किया गया है। मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को कई ऐसे पहलों/गतिविधियों के प्रस्ताव दिए हैं जिन्हें मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते के तहत विभिन्न मीडिया इकाइयों द्वारा कार्यान्वित किए जा सकते हैं।

अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)

अंतर-देशीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की ओर से संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (CEP) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में ये कार्यक्रम समझौते मास मीडिया प्रसारण और फ़िल्मों के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच वैचारिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने जिन देशों के साथ सीइपीएस पर हस्ताक्षर किए हैं, वे हैं- ग्रीस (23-03-2022) तुर्कमेनिस्तान (02-04-2022), पनामा (29-04-2022), डेनमार्क (30-04-2022), सेनेगल (01-06-2022), किर्गिस्तान (11-06-2022) और रोमानिया (01-07-2022)।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 28 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में 'नया वर्ष, नया संकल्प' विषय पर भारत सरकार के वर्ष 2023 के आधिकारिक कैलेंडर का विमोचन करते हुए।

सूचना एवं प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 4 जून, 2022 को 17वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए।

8 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं उसके संबद्ध/अंतर्गत कार्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व निम्नवत है : (1 जनवरी, 2023 तक)

वर्ग	कुल कर्मचारी (स्वीकृत)	कुल कर्मचारी (कार्यरत)	अनुसूचित जाति (प्रतिनिधित्व)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिनिधित्व)	अन्य पिछड़ा वर्ग (प्रतिनिधित्व)	अन्य (प्रतिनिधित्व)
ए	4,155	1,602	245	113	125	1,119
बी	23,010	9,851	1,517	982	1,262	6,090
सी	24,061	10,142	2,200	1,497	1,362	5,083
डी	23	6	5	0	0	1
कुल	**51,249**	**21,601**	**3,967**	**2,592**	**2,749**	**12,293**

नोट : विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का प्रतिशत स्वीकृत संख्या के आधार पर तय किया गया है।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 12 अगस्त, 2022 को आकाशवाणी द्वारा अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए।

9 सेवाओं में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के संबंध में समय-समय पर सभी मीडिया इकाइयों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालयों को सख्ती से इसे अमल में लाने के आदेश तथा दिशानिर्देश जारी किए जाते रहे हैं। मुख्य सचिवालय में दिव्यांगजनों के हितों की देखभाल के लिए एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। डीओपीटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर मंत्रालय में दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों को भरने की विशेष भर्ती प्रक्रिया जारी है।

मंत्रालय में वार्षिक आधार पर दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व का लेखा-जोखा तैयार कर डीओपीटी को प्रेषित किया जाता है। इस दिशा में 01/01/2023 को मंत्रालय में दिव्यांगजनों का समग्र प्रतिनिधित्व और सीधी भर्तियों एवं प्रोन्नति कोटा नीचे दिया गया है-

पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट-I

कार्यक्षेत्र में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व दर्शाती वार्षिक तालिका

(वर्ष 2022 के लिए, 01/01/2023 तक)

समूह	कर्मचारियों की संख्या						
	कुल पद	पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित पद	क	ख	ग	घ	ङ
समूह क	3,232	35	6	1	6	0	0
समूह ख	16,838	234	20	21	81	1	0
समूह ग और घ	17,931	350	17	7	38	0	0
कुल	**38,001**	**619**	**43**	**29**	**125**	**1**	**0**

(उपर्युक्त डेटा में दूरदर्शन महानिदेशालय का पीडब्ल्यूडी डेटा शामिल नहीं है।)

नोट :

क. नेत्रहीन अथवा कमजोर दृष्टि क्षमता वाले व्यक्ति।

ख. बधिर व्यक्ति।

ग. मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, एसिड अटैक पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास अथवा अन्य किसी भी प्रकार की चलन अंगों की दुर्बलता या विकार।

घ. ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी।

ङ. (क) से (घ) के अंर्तगत आने वाले व्यक्तियों में अनेक दिव्यांगताएं शामिल हैं। जिनमें प्रत्येक दिव्यांगता के लिए निर्धारित पदों में बधिरता और नेत्रहीनता भी शामिल है।

पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट-II

कैलेंडर वर्ष के दौरान नियुक्त दिव्यांगजनों की संख्या दर्शाने वाली सूची

वर्ष 2022 के लिए (01/01/2023 तक)

	पीडब्ल्यूडी के लिए सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत आरक्षित पदों की संख्या					सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत नियुक्तियों की संख्या								पीडब्ल्यूडी के लिए प्रमोशन कोटा के अंतर्गत आरक्षित रिक्त पदों की संख्या					प्रमोशन कोटा के अंतर्गत नियुक्तियों की संख्या							
	क	ख	ग	घ	ङ	कुल नियुक्तियां	पीडब्ल्यूडी के पदों पर कुल नियुक्तियां	क	ख	ग	घ	ङ	क	ख	ग	घ	ङ	कुल नियुक्तियां	पीडब्ल्यूडी के पदों पर कुल नियुक्तियां	क	ख	ग	घ	ङ
समूह क	5	2	4	3	1	53	2	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0
समूह ख	22	19	22	1	16	3	1	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0
समूह ग और घ	58	58	88	2	57	60	20	11	1	8	0	0	2	0	1	0	0	28	2	1	0	1	0	0
कुल	**85**	**79**	**114**	**6**	**74**	**116**	**23**	**12**	**1**	**10**	**0**	**0**	**3**	**0**	**8**	**0**	**0**	**32**	**6**	**1**	**0**	**5**	**0**	**0**

नोट :

(i) क (नेत्रहीन अथवा कमजोर दृष्टि क्षमता वाले व्यक्ति)

(ii) ख (बधिर व्यक्ति)

(iii) ग (मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, एसिड अटैक पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास अथवा अन्य किसी भी प्रकार की चलन अंगों की दुर्बलता या विकार)

(iv) घ (ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी)

(v) ङ (क से घ तक के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में अनेक दिव्यांगताएं शामिल हैं। जिनमें प्रत्येक दिव्यांगता के लिए निर्धारित पदों में बधिरता और नेत्रहीनता भी शामिल है)

नोट : समूह 'क' के पदों में तरक्की के लिए दिव्यांगजनों के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 23 जुलाई, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के समारोह में।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 18 मई, 2022 को कान फ़िल्म समारोह में इंडिया पवेलियन के उद्घाटन सत्र में। इस अवसर पर नवाजुद्दीन सिद्दीक़ी और दीपिका पादुकोण भी उपस्थित रहे।

10

राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में रोज़मर्रा के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने तथा संघ की राजभाषा नीति और इसके तहत बनाए गए राजभाषा नियमों का कार्यान्वयन करने के लिए मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) का हिन्दी अनुभाग निदेशक (रा.भा.) के एक पद, उप-निदेशक(रा.भा.) के एक पद, सहायक निदेशक (रा.भा.) के दो पद, वरिष्ठ अनुवादक के दो पद, कनिष्ठ अनुवादक के, तथा दो पद और अन्य सहायक कर्मचारियों के संस्वीकृत पदों के साथ कार्य कर रहा है। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है जिसकी नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में मंत्रालय और उसकी मीडिया यूनिटों में राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाती है और बैठक में लिए गए निर्णय/परामर्श सभी प्रभागों/स्कंधों को सूचित किए जाते हैं ताकि आधिकारिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया जा सके।

इस वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा 3 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें 96 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। वर्ष के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से दिनांक 14 से 29 सितंबर, 2022 तक हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। 14 सितंबर, 2022 को हिन्दी दिवस पर माननीय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री की ओर से मंत्रालय और उसकी मीडिया यूनिटों में एक हिन्दी संदेश परिचालित किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान मंत्रालय में हिन्दी और हिन्दीतर कार्मिकों के लिए कुल छह (06) प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताएं में 185 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 43 अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार विजेता बने। इसके अतिरिक्त मंत्रालय में सरकारी काम-काज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन हेतु प्रोत्साहन योजना प्रत्येक वर्ष लागू की जाती है। मंत्रालय में 16.12.2022 को हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह, 2022 आयोजित किया गया जिसमें सचिव, सूचना और प्रसारण द्वारा सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

इस वर्ष संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा मंत्रालय के 07 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 25 प्रतिशत अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा सम्बन्धी निरीक्षण के लक्ष्य को भी नवम्बर, 2022 में प्राप्त कर लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन संपन्न हो गया है और पुनर्गठन सम्बन्धी संकल्प दिनांक 3.11.2022 को जारी किया गया। इस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री तथा उपाध्यक्ष सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं।

मंत्रालय अपनी वेबसाइट को हिन्दी और अंग्रेजी में नियमित रूप से अपडेट कर रहा है।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 21 नवंबर, 2022 को गोवा में 53वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फ़िल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के अवसर पर 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो के लिए 53 आॅवर चैलेंज की शुरुआत करते हुए।

11 महिला कल्याण

राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार महिलाओं के लिए चल रही विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की देख–रेख/कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय ने 1992 में एक महिला सेल का गठन किया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले* में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार 16 मई, 2002 को इस सेल को पुनर्गठित किया गया जिसके अंतर्गत इसे कार्यस्थल पर यौन शोषण से जुड़े मामलों की शिकायत समिति के अधिकार दिए गए। 13 जनवरी, 2006 को वाईडब्ल्यूसीए से एक बाह्य विशेषज्ञ को महिला सेल के गैर–आधिकारिक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया।

बाद में, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के आधार पर 25 अक्टूबर, 2013 को महिला सेल का नाम बदलकर 'आंतरिक शिकायत समिति' कर दिया गया था।

अंतिम बार 18 अक्टूबर, 2021 को सर्कुलर नं. बी–11020/17/2011–एडमिन–III (खंड–II) के आधार पर समिति का पुनर्गठन किया गया था। सुश्री नीरजा शेखर, अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आईसीसी का अध्यक्ष नामित किया गया था। इसके अलावा, सुश्री कल्पना डेविड, राष्ट्रीय सचिव प्रशासन को भारत की वाईडब्ल्यूसीए की ओर से समिति की गैर–आधिकारिक सदस्य के तौर पर नामित किया गया। मंत्रालय की तीन अन्य महिला सदस्य एवं एक पुरुष सदस्य समिति के आधिकारिक सदस्य हैं।

आंतरिक शिकायत समितियां मंत्रालय की संबद्ध/अधीनस्थ एवं स्वायत्त इकाइयों में भी कार्यरत हैं। समय–समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की रोकथाम के संबंध में केंद्रीय लोक सेवा (आचार) नियम, 1964 के संबंध में जारी दिशानिर्देशों को मंत्रालय द्वारा अनुपालन हेतु सभी मीडिया इकाइयों को प्रेषित किया जाता है।

■■■

सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 4 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में एशिया-पैसिफिक (एशिया-प्रशांत) ब्रॉडक्रास्टिंग यूनियन ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 को सम्बोधित करते हुए।

12 सतर्कता संबंधी मामले

मंत्रालय का सतर्कता विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की समग्र देखरेख में काम करता है। मंत्रालय के सतर्कता विभाग की कमान संयुक्त सचिव/अपर सचिव स्तर के एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पास होती है जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुमोदन से मंत्रालय के संभाग प्रमुखों द्वारा की जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीवीओ के अधीन एक उप सचिव (सतर्कता), एक अपर सचिव (सतर्कता) एवं सतर्कता अनुभाग होता है। मंत्रालय का सीवीओ मंत्रालय एवं उसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा सीवीसी के साथ-साथ सीबीआई के बीच कड़ी का कार्य करता है। मंत्रालय के अधीनस्थ/संबद्ध और स्वायत्त कार्यालयों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पंजीकृत सोसाइटियों में भी, पृथक सतर्कता इकाइयां होती हैं। मंत्रालय का सीवीओ संबंधित एवं अधीनस्थ कार्यालयों, मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार सतर्कता गतिविधियों का समन्वय करता है।

भ्रष्टाचार की संभावना कम करने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए हैं। प्रक्रियाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित एवं औचक निरीक्षण किया जाता है। संवेदनशील पदों पर कर्मचारियों की अदला-बदली के प्रयास भी किए जाते हैं।

1 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान, 23 नियमित और 10 औचक निरीक्षण किए गए। इसके अलावा, केंद्रीय संचार ब्यूरो में 44 सीसीटीवी कैमरे लगवाने के साथ-साथ मीडिया इकाइयों के कुल 11 क्षेत्रीय कार्यालयों को निगरानी में रखा गया। साथ ही, 1 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों को विभिन्न स्त्रोतों से 166 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इनकी जांच की गई और 14 मामलों में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 06 मामलों के संबंध में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। 06 मामलों में बड़े जुर्माने के लिए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई। 20 मामलों में आर्थिक दंड लगाया गया है तथा 02 मामलों में नियमों के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत एक सप्ताह के भीतर प्रशासनिक कार्यवाही की गई।

सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों में 16 अगस्त, 2022 से 15 नवंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान 06 चिन्हित फ़ोकस क्षेत्रों: संपत्ति प्रबंधन, संपदा प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन, वेबसाइट रखरखाव और दिशानिर्देशों और परिपत्रों को अद्यतन किया गया।

मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों द्वारा 31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक एक सप्ताह का सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसकी थीम थी: 'भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत' यानी 'एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत' थी। मंत्रालय में जागरूकता सप्ताह के दौरान इस विषय पर विभिन्न आंतरिक गतिविधियों जैसे- निबंध लेखन, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी और पोस्टर निर्माण का आयोजन किया गया। मंत्रालय की मीडिया इकाइयों ने भी उत्साहपूर्वक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। प्रसार भारती ने जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए, जैसे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, डीडी न्यूज़ पर पैनल चर्चा, एफएम रेनबो पर लाइव फोन-इन कार्यक्रम, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़, डीडी 24X7 आरएलएस और क्षेत्रीय चैनल पर सीवीसी द्वारा प्रदान किए गए वन-लाइनर्स की स्क्रॉलिंग। राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड ने एक 'वेंडर्स मीट' आयोजित की, सतर्कता विषय पर दो लघु नाटक और उक्त विषय पर लघु फ़िल्मों की स्क्रीनिंग भी की। भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार ने स्लोगन कैंपेन चलाया। सत्यजीत रे फ़िल्म एंड टेलीविज़न संस्थान, केंद्रीय संचार ब्यूरो, पत्र सूचना कार्यालय, फोटो प्रभाग तथा भारतीय जनसंचार संस्थान ने भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों जैसे- वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया ताकि अधिकतम जन भागीदारी हो सके और भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ सके।

लोकसंपर्क यानी आउटरीच पहल के तहत, मंत्रालय ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय पर छात्रों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली का दौरा आयोजित किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के

सचिव की अध्यक्षता में सप्ताह के दौरान स्थानीय केबल ऑपरेटरों की एक बैठक भी आयोजित की गई थी। मंत्रालय के सतर्कता प्रकोष्ठ और इसकी मीडिया इकाइयों की विभिन्न गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करने वाला 'सतर्क' नामक एक सतर्कता जर्नल भी प्रकाशित किया गया था।

कैट मामलों के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

कैट निर्णय/ सतर्कता से संबंधित मामलों में प्राप्त करने/ कार्यान्वित आदेश के संबंध में

क्र.सं.	मीडिया इकाइयां/ अनुभाग	कैट से प्राप्त निर्णयों/ आदेशों की सं.	कार्यान्वित निर्णयों/ आदेशों की सं.
1.	एमआईबी	1	1
2.	सीबीएफसी	2	2

■■■

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के अवसर पर 31 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हुए।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 18 मई, 2022 को कान फ़िल्म फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए।

13 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण

नागरिक चार्टर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का नागरिक/उपभोक्ता घोषणा-पत्र मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर मौजूद है। मंत्रालय द्वारा अपने साझीदारों को प्रत्यक्ष दी जाने वाली निम्न 12 प्रमुख सेवाएं घोषणा-पत्र में शामिल की गई हैं:

(i) भावी लाइसेंस धारक को डीटीएच सेवाओं के लिए लाइसेंस निर्गत करना;

(ii) मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स को लाइसेंस निर्गत करना;

(iii) भावी लाइसेंस धारक को एचआईटीएस सेवाओं के लिए लाइसेंस निर्गत करना;

(iv) भारत में कार्य के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) एजेंसियों का पंजीकरण;

(v) अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए टीवी चैनलों द्वारा टेलिपोर्ट्स की स्थापना;

(vi) भारत से अपलिंक्ड किए गए टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए मंजूरी प्रदान करना;

(vii) विदेश से अपलिंक्ड टीवी चैनलों का डाउनलिंकिंग के लिए मंजूरी करना;

(viii) नई एजेंसी द्वारा अपलिंकिंग के लिए मंजूरी देना;

(ix) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए अनुमति देना;

(x) विदेशी पत्रिकाओं/जर्नलों/नियतकालिक पत्रों/नई पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों को विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी में विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रकाशन के लिए स्वीकृति-पत्र निर्गत करना;

(xi) समाचार और समसामयिक घटनाओं से संबंधित विदेशी पत्रिकाओं/समाचार-पत्रों के भारतीय संस्करण को विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त संस्था/विदेशी निवेश प्राप्त/अप्राप्त संस्था द्वारा विदेशी समाचार-पत्र के प्रतिलिपि संस्करण के प्रकाशन के लिए स्वीकृति पत्र निर्गत करना;

(xii) शिकायत निवारण तंत्र; और

(xiii) फ़िल्म सुविधाकरण कार्यालय के माध्यम से फ़ीचर फ़िल्मों/रियलिटी शो/कमर्शियल टीवी धारावाहिकों की भारत में शूटिंग के लिए विदेशी निर्माताओं को फ़िल्म सुविधाकरण कार्यालय के माध्यम से स्वीकृति-पत्र प्रदान करना।

शिकायत निवारण तंत्र

मंत्रालय को प्राप्त होने वाली शिकायत याचिकाओं को कंप्यूटरीकृत केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में पंजीकृत कर संसाधित किया जाता है। प्राप्त सभी याचिकाओं को नियमों के अनुसार स्वीकार किया जाता है और पावती सूचना में शिकायत संख्या, उसके निपटान का अनुमानित समय और संपर्क सूत्र का ब्योरा लिखा होता है। शिकायत याचिकाएं संबंधित मीडिया इकाइयों/दफ्तरों/विभागों को शिकायत के निस्तारण हेतु भेजी जाती हैं। नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता को उचित उत्तर भेजने के निर्देश के साथ इन याचिकाओं की निरंतर निगरानी होती है जिसके अंतर्गत संबंधित विभागों/प्रखंडों को अनुस्मारक-पत्र भेजना और समीक्षात्मक बैठकें आदि करना शामिल होता है। मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी मीडिया इकाइयों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सामान्यतः एक कनिष्ठ प्रशासनिक दर्जे के अधिकारी को उस इकाई का लोक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में, संबंधित मीडिया इकाइयों/कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी मामले के शीघ्र निपटान के संबंध में बात करते हैं। याचिकाओं के अंतिम निस्तारण के संबंध में स्थिति की सूचना याचिकाकर्ताओं को डाक या सीपीजीआरएएमएस के जरिए भेजी जाती है।

जन शिकायतों के निपटान/निस्तारण के लिए तंत्र को सक्रिय करने संबंधी दिशानिर्देश प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग आदि से प्राप्त होते हैं जिन्हें सभी मीडिया इकाइयों/स्वायत्त निकायों आदि को समय-समय पर वितरित किया जाता है। शिकायतों के निस्तारण की मंत्रालय में शीर्ष स्तर पर और 'मासिक प्रगति' बैठकों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी निगरानी की जाती है।

शिकायत निवारण के लिए प्रस्तावित समय सीमा

क्रम संख्या	विषय	समय
1	शिकायतकर्ता को पावती/अंतरिम उत्तर जारी करना	3 दिन
2	संबंधित प्रशासनिक खंड/उत्तरदायी केंद्र तक शिकायत याचिका के स्थानांतरण में लगने वाला समय	7 दिन
3	शिकायतकर्ता से शिकायत या स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति जो भी बाद में प्राप्त हो, की तिथि से उसको दिये जाने वाले अंतिम उत्तर में लगने वाला समय	30 दिन

01.01.2022 से 20.12.2022 तक मंत्रालय में शिकायत की स्थिति

31/03/2022 तक आगे लाई गईं	प्राप्त शिकायतें (01.01.2022 से 20.12.2022 तक)	कुल शिकायतें	शिकायत निपटान (01.01.2022 से 20.12.2022 तक)	लंबित शिकायत 20.12.2022 तक
388	4,363	4,751	4,360	391

*21.12.2022 से 31.03.2023 तक के लिए शिकायतों की अनुमानित संख्या है- 1,111

मंत्रालय को प्राप्त अधिकांश शिकायतें निम्न श्रेणियों की होती हैं :

क्र.सं.	शिकायत श्रेणी	01.01.2022 से 20.12.2022 तक प्राप्त शिकायतों की दर
1	अन्य मंत्रालयों के विषय में याचिकाएं	18.54%
2	डीटीएच ऑपरेटरों एलसीओ/एमएसओ के खिलाफ शिकायतें	11.46%
3	अनिर्दिष्ट श्रेणी	11.07%
4	पेंशन मामले (पेंशन एवं अन्य देश भत्तों के निर्गमन में विलंब)	8.21%
5	प्रसारण विषयवस्तु समाचार एवं गैर-समाचार कार्यक्रम	6.85%
6	सलाह एवं प्रश्न	5.84%
7	विविध	4.97%
8	सेवा मामलेः अस्थायी कर्मचारी	4.24%
9	फ़िल्म विषयवस्तु के मामले	3.69%
10	डिजिटल मीडिया विषयवस्तु	3.51%
11	प्रेस पत्रकारों के मामले	3.07%
12	पंजीकरण और शीर्षक सत्यापन	2.84%
13	सेवा मामलेः स्थायी कर्मचारी	2.80%
14	प्रेस विषयवस्तु के मामले	2.64%
15	भ्रष्टाचार एवं कदाचार	2.15%
16	पेंशन मामलेः पेंशन का पुनर्निर्धारण	1.93%
17	प्रसारण विषयवस्तु विज्ञापन	1.76%
18	पेंशन मामले (पेंशन का गलत निर्धारण)	1.63%
19	सदाशयी नियुक्तियां	1.12%
20	कोविड-19 संबंधित मुद्दे	0.69%
21	प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं की सदस्यता	0.57%
22	शोषण और दुर्व्यवहार	0.30%
23	विज्ञापन और प्रचार मामले	0.07%
24	यौन शोषण	0.05%

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 04 दिसम्बर, 2022 को हिसार, हरियाणा में दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र का अवलोकन करते हुए।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 23 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर सम्बोधित करते हुए।

14 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों के संबंध में सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है ताकि प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सके। सूचना का अधिकार का मतलब इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना के अधिकार से है, जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में या उसके पास है। इसमें निम्न अधिकार शामिल हैं-

1. कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
2. दस्तावेज़ों या रिकॉर्ड की टिप्पणी, निष्कर्ष या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना;
3. सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना;
4. सीडी के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी प्राप्त करना या यदि ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण में संगृहीत होती है तो उसका प्रिंटआउट लेना।

मुख्य सचिवालय में सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आरटीआई से संबंधित कार्यों के समन्वय के लिए एक नोडल आरटीआई अनुभाग स्थापित किया गया था। यह अनुभाग आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वाले आवेदनों को एकत्रित करता है, वितरित करता है और विषय-वस्तु से संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/सार्वजनिक प्राधिकरणों को स्थानांतरित करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मंत्रालय तथा इससे संबंधित कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित सभी आवेदन, अपीलें और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्णय, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (आरटीआई सेल) से प्राप्त होते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 25 केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों और 20 अपीलीय प्राधिकारियों को जानकारी प्रदान करने और दायर अपीलों पर निर्णय लेने के लिए नामित किया है। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mib.gov.in पर उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार संबंधी वर्षवार प्राप्त आवेदन तथा अपीलें और उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा नीचे दी गई है:

वर्ष	प्राप्त आवेदनों तथा अपीलों की संख्या जिन पर कार्रवाई की गई
2019	1,424
2020	1,673
2021	1,512
2022	1,365

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ में वर्ष 2022 के दौरान **1,233** आवेदन और **132** अपीलें प्राप्त हुईं जिसमें से 954 आवेदन और 100 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं। आवेदकों को सूचना प्रदान करने के लिए सभी आवेदनों और अपीलों को संबंधित लोक प्राधिकरणों/सीपीआईओ को तुरंत स्थानांतरित/अग्रेषित कर दिया गया। 2022 की अवधि के दौरान आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क/निरीक्षण शुल्क के रूप में 4,424 रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ आगंतुकों से प्राप्त आरटीआई संबंधी सभी सवालों के जवाब भी देता है।

आरटीआई आवेदनों के लिए निस्तारण तंत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाती है और जो आवेदन इस मंत्रालय से संबंधित नहीं होते, उन्हें संबंधित मंत्रालय के लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। शेष आवेदन मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों को भेज दिए जाते हैं।

लंबित आवेदनों पर कार्रवाई के लिए बार-बार केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों को अनुस्मारक भेजे जाते हैं, ताकि आवेदक को जानकारी प्रदान करने में विलंब न हो।

आरटीआई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन और अपीलें मंत्रालय के संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों को ऑनलाइन भेजी जाती है। भौतिक रूप से प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों के त्वरित और समय पर निपटान

के लिए मंत्रालय के संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को स्कैन, अपलोड कर भेजी जाती है। सभी केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों को आवेदनों/अपीलों की स्थिति की जांच करने और उनका ऑनलाइन उत्तर भेजने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड प्रदान किए गए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सभी सूचनाएं स्वतः उपलब्ध कराने से संबंधित धारा 4 (b) (i) और 4 (b) (ii) के तहत दायित्वों को पहले ही पूरा कर लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना नियमावली को समय-समय पर संशोधित/अद्यतन किया जा रहा है। प्राप्त, अस्वीकृत तथा हस्तांतरित किए गए आवेदनों/अपीलों के आंकड़ों की त्रैमासिक रिपोर्ट, नियमित रूप से केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ/सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत निकायों द्वारा केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वे इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं।

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 28 नवंबर, 2022 को गोवा में 53वे अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए।

नई दिल्ली में 4 अक्टूबर, 2022 को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 में सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन।

15 लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का लेखा संगठन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, मुख्य लेखा प्राधिकारी के तौर पर मुख्य लेखा नियंत्रक और वित्तीय सलाहकार की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन लेखा नियंत्रक/उप लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक, मुख्यालय स्थित 03 प्रधान लेखा अधिकारियों और 14 वेतन एवं लेखा कार्यालयों, जिसमें केवल जीपीएफ तथा पेंशन के प्रयोजन से प्रसार भारती और उसकी क्षेत्र संरचना से जुड़े 06 वेतन व लेखा कार्यालय शामिल हैं, की सहायता से करते हैं। क्षेत्रीय आंतरिक लेखा परीक्षा दल चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में तैनात हैं, जिनके कार्यों की निगरानी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा मुख्यालय में की जाती है।

दायित्व

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन की समग्र जिम्मेदारियां निम्न हैंः

- मंत्रालय के मासिक खातों का एकीकरण और इसे लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनियोग खाते।
- केंद्रीय लेन-देन का विवरण।
- 'एक नज़र में लेखा' तैयार करना।
- केंद्रीय वित्त खाते जो लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय और लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं।
- अनुदानग्राही संस्थाओं और स्वायत्त निकायों को अनुदान सहायता प्रदान करना।
- सभी पीएओ और मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना, यदि आवश्यक हो तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक आदि जैसे अन्य संगठनों के साथ परामर्श करके।
- प्राप्ति बजट की तैयारी।
- पेंशन बजट की तैयारी।
- पीएओ/चेक आहरण डीडीओ के लिए/की ओर से चेक बुक प्राप्त करना और आपूर्ति करना।
- लेखा महानियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और मान्यताप्राप्त बैंक में समग्र समन्वय और नियंत्रण को प्रभावी करना।
- मान्यताप्राप्त बैंक, जैसे भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से की गई सभी प्राप्तियों और भुगतानों का सत्यापन और मिलान करना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ संभालना और शेष नकद राशि का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा इसके अनुदानग्राही संस्थानों, स्वायत्त निकायों आदि का आंतरिक लेखा परीक्षण।
- सभी संबंधित प्राधिकरणों/प्रभागों को लेखांकन की जानकारी उपलब्ध कराना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट समन्वय कार्य।
- नई पेंशन योजना की निगरानी और समय-समय पर पेंशन मामलों का पुनरीक्षण।
- खातों और ई-भुगतान का कम्प्यूटरीकरण।

- लेखा संगठन के प्रशासनिक और समन्वय कार्य।
- अनुदानग्राही संस्थानों/स्वायत्त निकायों में केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत पीएफएमएस को पेश करना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय में गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी)।

वेतन और लेखा विभाग विभागीय लेखा संगठन की मूल इकाई है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैः-

- नॉन-चेक आहरण डीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋण और सहायता अनुदान सहित सभी बिलों का प्री-चेक और भुगतान।
- प्रस्तावित नियम एवं कायदों के अंतर्गत सभी भुगतानों का सटीक और समयोचित निपटारा।
- रसीदों की सामयिक प्राप्ति।
- चेक आहरण डीडीओ को पाक्षिक लेटर ऑफ क्रेडिट देना और उनके वाउचर/बिलों का कार्य के पश्चात निरीक्षण।
- रसीदों और खर्चों का मासिक संकलन और चेक आहरण डीडीओ के खातों के साथ उन्हें संलग्न करना।
- विलयित डीडीओ के अतिरिक्त जीपीएफ खातों की देख-रेख और सेवानिवृत्ति लाभों को अधिकृत करना।
- सभी डीडीआर प्रमुखों का संधारण।
- बैकिंग व्यवस्था द्वारा ई-भुगतान के ज़रिए मंत्रालय/विभाग की सेवाओं को प्रभावशाली बनाना।
- प्रस्तावित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन।
- सामयिक, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और लाभकारी वित्तीय रिपोर्टिंग।

प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा प्राधिकारी को लेखांकन जानकारी और डेटा भी प्रदान किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदान के विभिन्न सब-हेड/ऑब्जेक्ट-हेड के तहत मासिक और क्रमिक व्यय के आंकड़े मीडिया प्रभाग के संयुक्त सचिव सहित मंत्रालय की बजट शाखा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों के निमित्त व्यय की प्रगति को साप्ताहिक रूप से सचिव तथा अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार के साथ-साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है, जो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के व्यय की बेहतर निगरानी के प्रयोजनों से अनुदान को नियंत्रित करते हैं।

लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के भवन निर्माण अग्रिम और सामान्य भविष्य निधि खातों जैसे लंबी अवधि के अग्रिमों के खातों का भी रखरखाव करता है।

अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन के अधिकार का सत्यापन और प्रमाणीकरण वेतन व लेखा कार्यालयों द्वारा सेवा विवरणों और कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा पेश किए गए पेंशन काग़ज़ातों के आधार पर किया जाता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभ और भुगतान जैसे- ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन के बराबर नकद राशि के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना के तहत भुगतान, सामान्य भविष्य निधि आदि डीडीओ द्वारा उपयुक्त जानकारी/बिल प्राप्त होने पर वेतन व लेखा कार्यालयों द्वारा जारी किए जाते हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ

आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों का लेखा-परीक्षण करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनंदिन कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। मुख्य लेखा प्राधिकारी और वित्तीय सलाहकार के अधीन समग्र मार्गदर्शन में काम करने वाले आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ ने एक कुशल और प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षण परंपरा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तरीके से शासन संरचनाओं को मजबूत करने, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय के अधीन भारत भर में 531 विभिन्न मीडिया इकाइयां (प्रसार भारती-459 और गैर-प्रसार भारती-72) हैं जो आंतरिक लेखा के समीक्षा क्षेत्र में आती हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन 35 दफ्तरों का लेखा परीक्षण किया गया था।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसार भारती में 01.12.2021 तक और 01.12.2022 तक के बकाया लेखा परीक्षण की स्थिति निम्न हैः

I. प्रसार भारती				
क्षेत्र	**दिनांक 01.12.2021 तक बकाया पैरा**	**पैरा को 01.12.2021 से 30.11.22 तक बढ़ाया गया**	**पैरा 01.12.21 से 30.11.22 तक गिरा**	**01.12.2022 को कुल बकाया पैरा**
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई)	557	109	152	514
पश्चिम क्षेत्र (मुंबई)	202	125	7	320
उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली)	207	137	17	327
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	451	259	139	571
कुल (I)	**1,417**	**630**	**315**	**1,732**
II. गैर-प्रसार भारती				
क्षेत्र	**दिनांक 01.12.2021 तक बकाया पैरा**	**पैरा को 01.12.2021 से 30.11.22 तक बढ़ाया गया**	**पैरा 01.12.21 से 30.11.22 तक गिरा**	**01.12.2022 को कुल बकाया पैरा**
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई)	327	99	92	334
पश्चिम क्षेत्र (मुंबई)	563	30	36	557
उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली)	412	105	48	469
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	294	76	49	321
कुल (II)	**1,596**	**310**	**225**	**1,681**
कुल योग (I + II)	**3,013**	**940**	**540**	**3,413**

आईआरएलए (व्यक्तिगत रनिंग लेजर अकाउंटिंग सिस्टम)

वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) दूसरे मंत्रालयों के अन्य विभागीय पीएओ के साथ अस्तित्व में आया। (आईआरएलए) प्रणाली (ग्रुप-ए अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत क्रियाशील खाता-बही लेखा प्रणाली) का विचार एक केंद्रीय प्रणाली में सभी सेवा और भुगतान विवरण रखने से उत्पन्न हुआ ताकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती के अधिकारियों, जिनका भारत में कहीं भी स्थानांतरण हो सकता है, अपना वेतन सुविधापूर्वक प्राप्त कर सकें। वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) देशभर के विभिन्न शहरों में स्थित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती (दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो) के कार्यालयों के सेवा और वेतन रिकार्ड का रखरखाव कर रहा है। प्रसार भारती में तैनात आईआरएलए अधिकारी वेबसाइट https://accounts.prasarbharati.org पर लॉग इन कर के वेतन पर्ची आय कर फॉर्म-16 और जीपीएफ स्टेटमेंट आदि देख सकते हैं और अन्य आईआरएलए अधिकारी पीएफएमएस के ईआईएस मॉड्यूल में उपरोक्त सुविधाएं (आयकर फॉर्म-16 को छोड़कर) प्राप्त कर सकते हैं।

बैंकिंग व्यवस्था : भारतीय स्टेट बैंक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पीएओ और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए मान्यताप्राप्त बैंक हैं। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा संसाधित (प्रोसेस्ड) ई-भुगतान विक्रेताओं/लाभार्थियों के बैंक खाते के पक्ष में सीएमपी, एसबीआई, हैदराबाद के माध्यम से किए जाते हैं। कुछ मामलों में, पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी किए गए चेक भुगतान के लिए मान्यताप्राप्त बैंक की नामित शाखा को प्रस्तुत किए जाते हैं। गैर-कर रसीद

पोर्टल (एनटीआरपी) के अलावा, रसीदें संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा मान्यताप्राप्त बैंकों को भी भेजी जाती हैं। मान्यताप्राप्त बैंक में किसी भी बदलाव के लिए लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की विशिष्ट स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

प्रधान लेखा कार्यालय में कुल 14 वेतन एवं लेखा कार्यालय हैं जिनमें से प्रसार भारती से जुड़े 6 पीएओ हैं, प्रेस कार्यालय दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में दो-दो और नागपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में एक-एक पीएओ स्थित हैं। विभाग/मंत्रालय से जुड़े सभी भुगतान संबंधित पीएओ के साथ संलग्न पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) अपनी मांगों/बिलों को नामित पीएओ/सीडीडीओ के पास प्रस्तुत करते हैं, जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सिविल लेखा नियमावली, प्राप्ति और भुगतान नियमों तथा अन्य आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने के बाद चेक/ई-भुगतान जारी करते हैं। पीएमएस और ई-उच्च भुगतान के माध्यम से भेजे गए सभी भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचते हैं।

खातों का कम्प्यूटरीकरण : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन में खातों के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा लेखा कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के साथ शुरू हुई। प्रधान लेखा कार्यालयों में मासिक खातों के समेकन के लिए CONTACT नाम के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था। इस मंत्रालय में सभी पीएओ ने वाउचर स्तर के कम्प्यूटरीकरण सॉफ्टवेयर कॉन्टैक्ट का उपयोग किया। 2008 और उसके बाद से मासिक खातों को लेखा महानियंत्रक के कार्यालय में प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति के साथ पूरे किए गए विवरणों को पीएओ-वार समायोजन के बाद प्रस्तुत किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे विंडो आधारित ऐप्लिकेशनों का उपयोग मंत्रालय में जमा करने और अन्य एमआईएस प्रयोजनों हेतु शीर्षवार विनियोग खातों, केंद्र सरकार के वित्त खाते (सिविल) की सामग्री और मासिक व्यय व प्राप्ति विवरणों को तैयार करने के लिए भी किया जाता है।

ई-भुगतान पर पहल : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में ई-भुगतान प्रणाली 2011 से सफलतापूर्वक लागू की गई थी।

ई-भुगतान प्रणाली : चूंकि आईटी अधिनियम, 2000 डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज़ों को या अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों को मान्यता प्रदान करता है, तो लेखा महानियंत्रक ने डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक अनुदेशों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (ई-भुगतान) के लिए 'कॉम्पैक्ट' (COMPACT) नाम से एक सुविधा विकसित की थी। इसने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में सभी वेतन व लेखा कार्यालयों में चल रहे कॉम्पैक्ट ऐप्लिकेशन का लाभ उठाते हुए चेक के माध्यम से भुगतान की मौजूदा प्रणाली को बदल दिया था।

विकसित की गई ई-भुगतान प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं की पूरी तरह से सुरक्षित एक वेब आधारित प्रणाली थी, जिसने सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत सरकार से बकाए का भुगतान एक सुरक्षित संचार चैनल पर 'सरकारी ई-भुगतान गेटवे' कॉम्पैक्ट के माध्यम से कॉम्पैक्ट से जेनरेट किए गए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-अनुदेश के जरिए सीधे प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में धन जमा कर किया जाता था। इसकी शुरुआत करने के लिए आवश्यक कार्यात्मक और सुरक्षा प्रमाणीकरण एसटीक्यूसी निदेशालय से प्राप्त किए गए थे। इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार के सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों में लागू किया गया था।

जीईपीजी को आगे पीएफएमएस प्रणाली में अपग्रेड किया गया है, जो स्वीकृति की तैयारी, बिल संसाधन (प्रोसेसिंग), भुगतान, प्राप्ति प्रबंधन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, निधि प्रवाह प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए लेखा महानियंत्रक की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है।

डिजिटल हस्ताक्षर का पंजीकरण : वेतन और लेखा अधिकारी एनआईसी प्रमाणन प्राधिकरण से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करता है। एनआईसी प्रमाणन प्राधिकरण से प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षर एक यूएसबी टोकन में स्टोर किए जाते हैं जिन्हें आई-की कहा जाता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से पीएओ पीएफएमएस पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत करता है। संबंधित बैंक पीएफएमएस पोर्टल से पीएओ के डिजिटल हस्ताक्षर डाउनलोड करते हैं। बैंकों द्वारा पीएओ को प्रदान किए गए

ई-भुगतान स्क्रॉल के प्रमाणीकरण के लिए संबंधित बैंकों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर भी पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।

बिल जमा करना : आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) ई-भुगतान के लिए बिल के साथ प्राप्तकर्ता का मैंडेट फॉर्म और बैंक शाखा का आईएफएससी कोड, खाता संख्या, नाम, पता आदि विवरण वेतन व लेखा अधिकारी के पास जमा कराते हैं। कॉम्पैक्ट से एक टोकन नंबर जेनरेट किया जाता है और डीडीओ को सूचित किया जाता है।

बिल पर कार्यवाही : बिलों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से वेतन एवं लेखा कार्यालय में संसाधित किया जाता है।

डिजिटल हस्ताक्षर : पीएओ द्वारा बिल पास होने के बाद सुरक्षित आई-की का उपयोग करके यह हस्ताक्षरित होता है और सिस्टम द्वारा ई-भुगतान स्वीकृति जेनरेट की जाती है।

ई-स्क्रॉल : डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक स्क्रॉल सभी सफल ई-भुगतानों के लिए पीएफएमएस पर बैंक द्वारा जेनरेट और अपलोड किया जाता है। ई-स्क्रॉल पीएओ द्वारा डाउनलोड किए जाते हैं और मिलान तथा अन्य एमआईएस उद्देश्यों के लिए कॉम्पैक्ट सिस्टम में शामिल किए जाते हैं।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा लेखा महानियंत्रक कार्यालय (सीजीए) के व्यय विभाग द्वारा विकसित एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर ऐप्लिकेशन है। पीएफएमएस की विभिन्न मोड/कार्यों द्वारा क्रियान्वित आउटपुट/डिलिवरेबल्स में शामिल हैं (परंतु इन तक सीमित नहीं हैं)

- भुगतान एवं राजकोषीय नियंत्रण
- प्राप्तियों का लेखा (कर और गैर-कर)
- लेखा कार्यों का संकलन और राजकोषीय रिपोर्ट तैयार करना
- राज्यों की वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकरण

पीएफएमएस का प्राथमिक कार्य आज एक कुशल निधि प्रवाह के साथ-साथ भुगतान सह लेखा नेटवर्क की स्थापना करके भारत सरकार के लिए सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है।

पीएफएमएस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत भुगतान, लेखा और रिपोर्टिंग के लिए भी चैनल है। जैसे भारत सरकार का हर विभाग/मंत्रालय पीएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभार्थी (व्यक्तिगत या संस्था) को धनराशि अंतरित करता है।

मौजूदा समय में, पीएफएमएस के जरिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (जिनमें छह पीओ जीपीएफ और पेंशन के लिए प्रसार भारती से जुड़े हैं) के सभी 14 वेतन एवं लेखा कार्यालय सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

पीएफएमएस के विभिन्न माड्यूल

I. **पीएफएमएस का कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूलः** यह माड्यूल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में लागू किया गया है।

II. **पीएफएमएस का सीडीडीओ मॉड्यूलः** पीएफएमएस का सीडीडीओ मॉड्यूल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी चेक आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में विस्तारित किया गया है।

III. **मंत्रालय में गैर-कर राजस्व के संग्रह के लिए ऑनलाइन पोर्टल (भारतकोष)**

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एनटीआरपी 01 नवंबर, 2016 से कार्य कर रहा है।
- गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) का उद्देश्य भारत सरकार को देय गैर-कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नागरिकों/कॉर्पोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं को एक वन-स्टॉप विंडो प्रदान करना है।
- भारत सरकार के गैर-कर राजस्व में अलग-अलग विभागों/मंत्रालयों द्वारा एकत्रित प्राप्तियों का एक बड़ा समूह शामिल है। मुख्य रूप से ये प्राप्तियां लाभांश, ब्याज प्राप्तियां, स्पेक्ट्रम

शुल्क, आरटीआई आवेदन शुल्क, छात्रों द्वारा प्रपत्र/पत्रिकाओं की खरीद और नागरिकों/कॉर्पोरेट/अन्य/उपयोगकर्ताओं/द्वारा ऐसे कई अन्य भुगतानों के रूप में आती है।

- पूरी तरह से सुरक्षित आईटी व्यवस्था में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आम उपयोगकर्ताओं/नागरिकों को सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंकों में जाकर ड्राफ्ट बनवाने और फिर सरकारी कार्यालयों में जाकर इन साधनों को जमा कराने के झंझट से बचाने में मददगार होते हैं। यह इन साधनों के सरकारी खाते में प्रेषण में देरी से बचने में मदद करता है और यह इन साधनों के बैंक खातों में देरी से जमा होने की अवांछनीय प्रथाओं को समाप्त करता है।

- एनटीआरपी ऑनलाइन भुगतान तकनीकों जैसे- इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके पारदर्शी वातावरण में तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

- वित्तीय वर्ष (2021-22) की अवधि के लिए मंत्रालय के गैर-कर राजस्व का संग्रह 1,862.47 करोड़ रुपये है और इसमें से मद्रास उच्च न्यायालय के तिथि 28 जून, 2021 के निर्देशों के अनुसार एस टीवी नेटवर्क लिमिटेड को 53.39 करोड़ रुपये के राशि की वापसी के प्रभाव को छोड़कर। जिसमें से एनटीआर ई-पोर्टल पर भारतकोश के माध्यम से 1,830.36 करोड़ रुपये एकत्र किए गए।

- मौजूदा वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए मंत्रालय का गैर-कर राजस्व (01.04.2022-15.12.2022) तक 897.98 करोड़ रुपये है और इसमें से 886.88 करोड़ रुपये (लगभग 98.76%) को एनटीआर ईपोर्टल भारतकोश के माध्यम से एकत्रित किया गया।

मंत्रालय में नए बदलाव

I. स्वायत्त निकायों में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट्स (टीएसए) मॉड्यूलः स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों को 'तत्क्षण' सरकारी अनुदान जारी करने की सुविधा प्रदान करने और पीएसबी स्वायत्त निकायों/एजेंसियों के पास अप्रयुक्त अनुदानों के संचय से बचने के उद्देश्य से स्वायत्त निकायों को टीएसए सिस्टम के तहत लाया गया है। यह स्वायत्त निकायों/एजेंसियों को एकमुश्त नकद हस्तांतरण से भी बचाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी खाते से आहरण की सुविधा प्रदान करेगा।

टीएसए का उद्देश्य

- स्वायत्त निकायों के लिए निधियों को जारी करने के लिए 'तत्क्षण' सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार में बेहतर नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करके निधि प्रवाह की दक्षता में वृद्धि करना।

- ऋण की राशि को कम करके सरकार के ब्याज के बोझ को कम करना।

- सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों को उनके बैंक खातों में जारी धन की पार्किंग से बचाव।

टीएसए प्रणाली पहले से ही तीन स्वायत्त निकायों यानी प्रसार भारती, आईआईएमसी और पीसीआई में लागू की जा चुकी है और शेष 02 स्वायत्त निकायों यानी एसआरएफटीआई और एफटीआईआई में टीएसए का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है और यह चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा।

II. पीएफएमएस में इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) सिस्टम मॉड्यूलः केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 46वें नागरिक लेखा दिवस के अवसर पर केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रोसेसिंग सिस्टम लागू किया। यह व्यापक पारदर्शिता लाने और भुगतान की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए 'कारोबारी सुगमता और डिजिटल इंडिया इको-सिस्टम' का हिस्सा है। यह आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपना दावा ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान कर पारदर्शिता, दक्षता और फेसलेस-पेपरलेस भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देगा, जो तत्काल ट्रैक करने योग्य होगा।

पीएफएमएस का ई-बिल मॉड्यूल सीजीए कार्यालय द्वारा पीएफएमएस में विकसित किया गया है। पीएफएमएस केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के पीएओ/डीडीओ के उपयोग के लिए सीजीए कार्यालय के माध्यम से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक पेमेंट प्लेटफार्म है। संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया को पेपरलेस अवधारणा

में बदलने के लिए केंद्र सरकार की प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक बिजनेस प्रोसेस री–इंजीनियरिंग (बीपीआर) नई प्रणाली में शामिल है। ई–बिल प्रणाली का उद्देश्य भुगतान में लगाने वाले समय को कम करना और सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता तथा दक्षता को बढ़ाना है। यह एक नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण है, जिसमें दावेदारों और दावों को प्राप्त और संसाधित करने के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के पास व्यक्तिगत तौर पर पहुंच कायम करने की बाध्यता को कम किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 06 पीएओ में पीएफएमएस का ई–बिल मॉड्यूल पहले ही शुरू किया जा चुका है।

■■■

मंत्रालय का लेखा संगठन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में लेखा संगठन का ढांचा

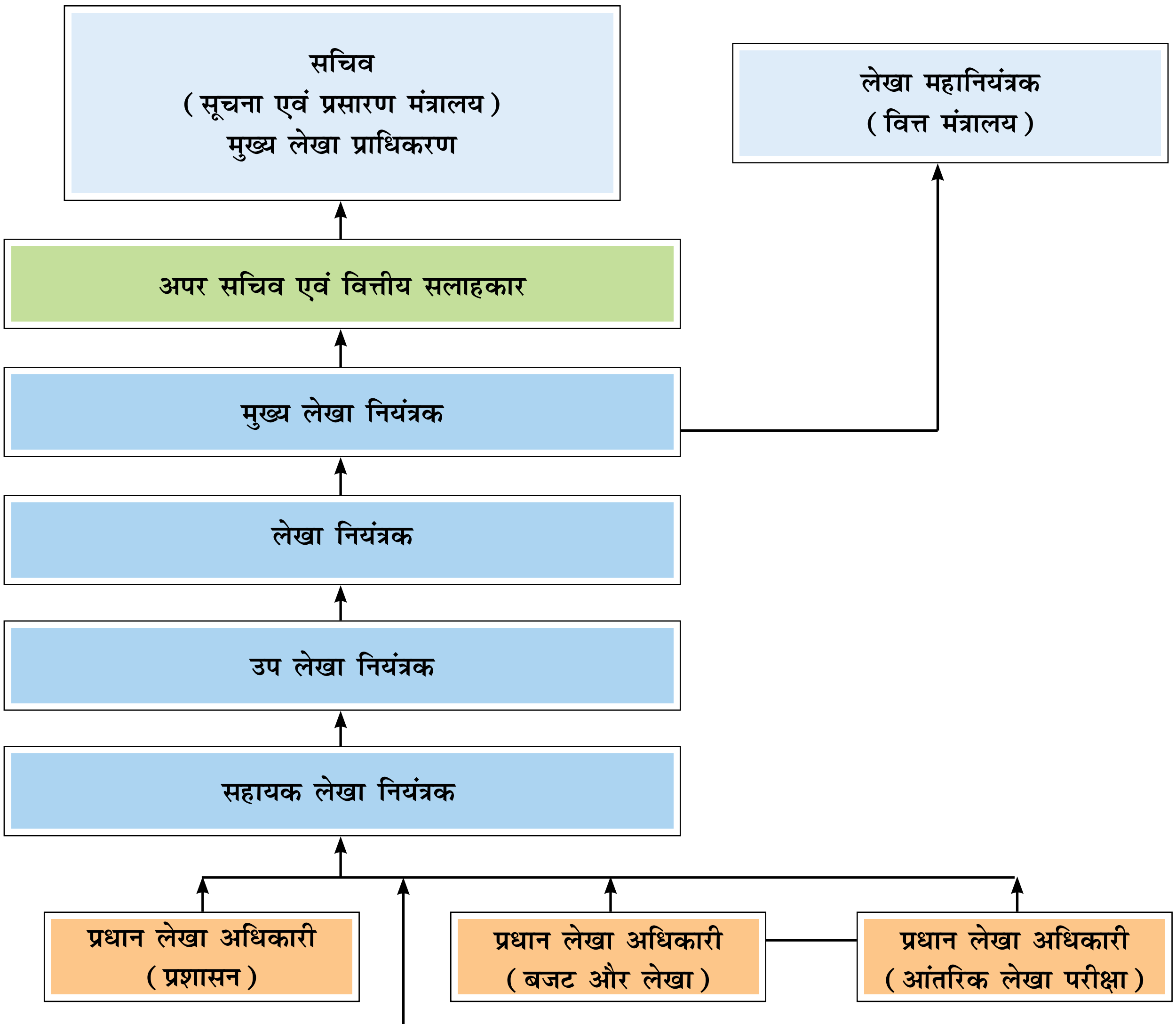

1. वेतन और लेखा कार्यालय (एमएस) नई दिल्ली
2. वेतन और लेखा कार्यालय (बीओसी आदि) नई दिल्ली पूर्व में पीएओ (डीएवीपी आदि)
3. वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) नई दिल्ली
4. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) नागपुर
5. वेतन और लेखा कार्यालय (एफडी) मुंबई
6. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) चेन्नई
7. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) लखनऊ
8. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) कोलकाता
9. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) नई दिल्ली
10. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) गुवाहाटी
11. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) चेन्नई
12. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) कोलकाता
13. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) मुंबई
14. वेतन और लेखा कार्यालय (एआईआर) नई दिल्ली
15. 21 वरिष्ठ लेखा अधिकारी विभिन्न क्षेत्रीय लोक संपर्क विभाग (आरओबी) में अपर महानिदेशक (क्षेत्रीय) के एनसीडीडीओ/सीडीडीओ और आईएफए के रूप में कार्यरत हैं।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 16 जुलाई, 2022 को भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के साथ। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा भी उपस्थित थे।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 15 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में धारावाहिक स्वराज : भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा के प्रोमो के लॉन्च के अवसर पर। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा और अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे।

16

लेखा पैरा

ए (सीएंडएजी) पैरा

01.04.2022 से 31.12.2022 तक के लिए सीएजी से प्राप्त लेखा पैरा की सूची

क्रम संख्या	रिपोर्ट संख्या एवं वर्ष	पैरा संख्या	कार्रवाई
1.	2022 की रिपोर्ट सं. 2 (चैप्टर 4 और 5)		प्रशासनिक तौर पर सरकार/एजेंसियों को आवंटित स्पेक्ट्रम का प्रबंधन

■■■

सूचना एवं प्रसारण और मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 04 जून, 2022 को मुंबई में 17वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृतचित्र फ़िल्म (60 मिनट से कम) के लिए निर्देशक एमी बरुआ की "स्क्रीमिंग बटरफ्लाइज़" को सिल्वर कोंच पुरस्कार से सम्मानित करते हुए। इस अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी भी उपस्थित थे।

17 कैट के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

वर्ष 2021-22 के लिए मंत्रालय के मुख्य सचिवालय और विभिन्न मीडिया इकाइयों के कैट मामलों के निर्णयों/आदेशों के कार्यान्वयन की जानकारी इस प्रकार हैः

क्रम संख्या	मीडिया इकाइयां	वर्ष 2021-22 के लिए कैट से प्राप्त आदेशों की संख्या	2021-22 में कार्यान्वित निर्णयों/आदेशों की संख्या
1.	केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	02	02
2.	एफटीआईआई	01	01
3.	महानिदेशक : आकाशवाणी	26	14
4.	महानिदेशक : दूरदर्शन	32	21
	कुल	**61**	**38**

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 21 नवंबर, 2022 को गोवा में भारत के 53वें अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रदर्शनी 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' में शिरकत करते हुए।

18 योजना परिव्यय

बजट अनुमान (2022-23)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संबंध में 2022-23 के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (अस्थायी) परिव्यय

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/योजना/मीडिया इकाई का नाम	बजट अनुमान (2022-23)
1	सूचना क्षेत्र (विकास संचार और सूचना प्रसार - डीसीआईडी)	184
2	फ़िल्म क्षेत्र (विकास संचार और फ़िल्मी सामग्री का प्रसार - डीसीडीएफसी)	127.16
3	प्रसारण क्षेत्र (मुख्य सचिवालय)	
ए	भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन (सीआरएस)	3.84
बी	प्रसार भारती (प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास - बीआईएनडी)	315
	कुल प्रसारण क्षेत्र	318.84
	कुल योग	**630**

योजना परिव्यय

बजट अनुमान (2022-23)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संबंध में 2022-23 के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना परिव्यय 630 करोड़ रुपये है।

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	जीबीएस
1.	सूचना क्षेत्र	184
2.	फ़िल्म क्षेत्र	127.16
3.	प्रसारण क्षेत्र	318.84
	कुल	**630.00**

पूर्वोत्तर अवयव 63 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय क्षेत्र योजना परिव्यय (जीबीएस) का 10 प्रतिशत दर्शाता है। 630 करोड़ घटक का विवरण इस प्रका है :

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	जीबीएस
1.	सूचना क्षेत्र	18.68
2.	फ़िल्म क्षेत्र	13
3.	प्रसारण क्षेत्र	31.32
	कुल	**63**

*सकल बजट सहायता

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव सुश्री नीरजा शेखर 24 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में सउदी अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के साथ।

19

इकाई-वार मीडिया बजट

मांग संख्या 61 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय				
मीडिया इकाई-वार बजट				
राजस्व अनुभाग				
श्रेणी-I केंद्र का स्थापना व्यय (गैर-योजना व्यय)				
				(रु. हजार में)
मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	वास्तविक अनुमान 2021-22	बजट अनुमान 2022-23	वास्तविक अनुमान 2022-2023	बजट अनुमान 2023-2024
मुख्य श्रेणी - '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं				
मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	8,54,485	9,75,900	11,28,300	11,05,600
मुख्य श्रेणी - '2205' - कला एवं संस्कृति (आमजन प्रदर्शनी हेतु सिनेमैटोग्राफिक फ़िल्मों का प्रमाणन)				
फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण	3,555	0	0	0
केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	1,01,675	1,32,000	2,26,460	2,79,900
कुल योग : मुख्य श्रेणी '2205'	**1,05,230**	**1,32,000**	**2,26,460**	**2,79,900**
मुख्य श्रेणी - '2220' - सूचना फ़िल्म और प्रचार				
फ़िल्म प्रभाग	4,43,707	5,68,900	3,77,700	0
फ़िल्म समारोह निदेशालय	1,16,035	1,20,000	91,660	0
भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय	65,091	92,000	71,600	0
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)	1,87,401	2,03,200	1,55,400	1,60,600
न्यू मीडिया विंग	15,885	20,800	17,000	17,600
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)	10,41,979	10,74,800	10,85,300	10,86,400
केन्द्रीय सूचना ब्यूरो	16,20,204	20,25,700	19,66,380	20,00,800
प्रकाशन विभाग	3,96,721	5,08,100	6,35,400	5,09,000
रोज़गार समाचार	71,114	600	0	0
भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक	77,024	79,500	88,000	1,23,600
निजी एफएम रेडियो स्टेशन	700	21,700	1,700	17,200
संचार के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान (आईपीडीसी)	0	2,100	0	1
एशिया पैसेफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) को योगदान	2,950	3,100	3,200	3,200

(रु. हजार में)				
मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	वास्तविक अनुमान 2021-22	बजट अनुमान 2022-23	वास्तविक अनुमान 2022-2023	बजट अनुमान 2023-2024
एसोसिएशन ऑफ मूविंग इमेजेस आर्काइविस्ट्स (एएमआईए) को वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान	33	40	40	40
एनएफएआई द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के लिए योगदान	222	260	260	259
कुल योग : मुख्य श्रेणी '2220'	**40,39,066**	**47,20,800**	**44,93,640**	**39,18,700**
कुल : केंद्र का स्थापना व्यय	**49,98,781**	**58,28,700**	**58,48,400**	**53,04,200**
मुख्य श्रेणी - '4220' - सूचना और प्रसार का पूंजी विवरण				
मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	0		0	1937
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)	0		0	28,163
प्रकाशन विभाग	0		0	20,500
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)	0			200
कुल योग : मुख्य श्रेणी '4220'	**0**	**0**	**0**	**50,800**
कुल : केन्द्र का स्थापना व्यय (आय + पूंजी)	**49,98,781**	**58,28,700**	**58,48,400**	**53,55,000**
श्रेणी-II केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं (योजना व्यय)				
सूचना क्षेत्र				
विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)				
सामान्य मुख्य श्रेणी '2220'	21,12,111	16,53,200	17,44,200	18,00,000
पूर्वोत्तर मुख्य श्रेणी '2252'		1,86,800	1,95,800	2,00,000
कुल (डीसीआईडी)	**21,12,111**	**18,40,000**	**19,40,000**	**20,00,000**
फ़िल्म क्षेत्र				
विकास संचार और फ़िल्म सामग्री का प्रसार (डीसीडीएफसी)				
सामान्य मुख्य श्रेणी '2220'	5,67,618	8,85,100	8,83,500	24,42,400
पूर्वोत्तर मुख्य श्रेणी '2252'		1,30,000	1,30,000	3,00,000
पूंजी मुख्य श्रेणी '4220'	2,10,900	2,56,500	2,56,500	2,57,600
कुल (डीसीडीएफसी)	**7,78,518**	**12,71,600**	**12,70,000**	**30,00,000**
प्रसारण क्षेत्र				
भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता				
सामान्य मुख्य श्रेणी '2220'	19,154	35,200	26,800	45,000

(रु. हज़ार में)				
मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	वास्तविक अनुमान 2021-22	बजट अनुमान 2022-23	वास्तविक अनुमान 2022-2023	बजट अनुमान 2023-2024
पूर्वोत्तर मुख्य श्रेणी '2252'		3,200	3,200	5,000
कुल	**19,154**	**38,400**	**30,000**	**50,000**
प्रसारण संरचना तंत्र विकास (बाइन्ड)				
सामान्य मुख्य श्रेणी '2221'	16,16,793	28,40,000	28,40,000	54,00,000
पूर्वोत्तर मुख्य श्रेणी '2252'		3,10,000	3,10,000	6,00,000
कुल (बाइन्ड)	**16,16,793**	**31,50,000**	**31,50,000**	**60,00,000**
कुल (प्रसारण क्षेत्र)	**16,35,947**	**31,88,400**	**31,80,000**	**60,50,000**
कुल केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं	**45,26,576**	**63,00,000**	**63,90,000**	**1,10,50,000**
इनमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र आवंटन	**0**	**6,30,000**	**6,39,000**	**11,05,000**
इनमें से पूंजी के तहत आवंटन	**2,10,900**	**2,56,500**	**2,56,500**	**2,57,600**
श्रेणी-III अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त संस्थाएं) (गैर-योजना व्यय)				
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी)	2,71,515	5,20,000	4,10,000	4,46,700
भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई)	1,18,450	2,71,800	1,05,600	1,82,100
बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई)	21,361	37,400	34,300	0
भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान, पुणे (एफटीआईआई)	4,26,723	5,53,900	6,85,300	6,47,500
सत्यजित रे फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई)	6,36,200	7,43,000	6,01,000	9,51,300
प्रसार भारती	2,62,90,259	2,55,52,900	2,76,45,100	2,80,83,600
राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	0	0	1,00,300	2,03,800
कुल - अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त संस्थाएं)	**2,77,64,508**	**2,76,79,000**	**2,95,81,600**	**3,05,15,000**
कुल - मांग सं. 61	**3,72,89,865**	**3,98,07,700**	**4,18,20,000**	**4,69,20,000**

■■■

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 16 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के तीसरे वार्षिक सम्मेलन के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए।

20

सांगठनिक ढांचा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संगठन चार्ट

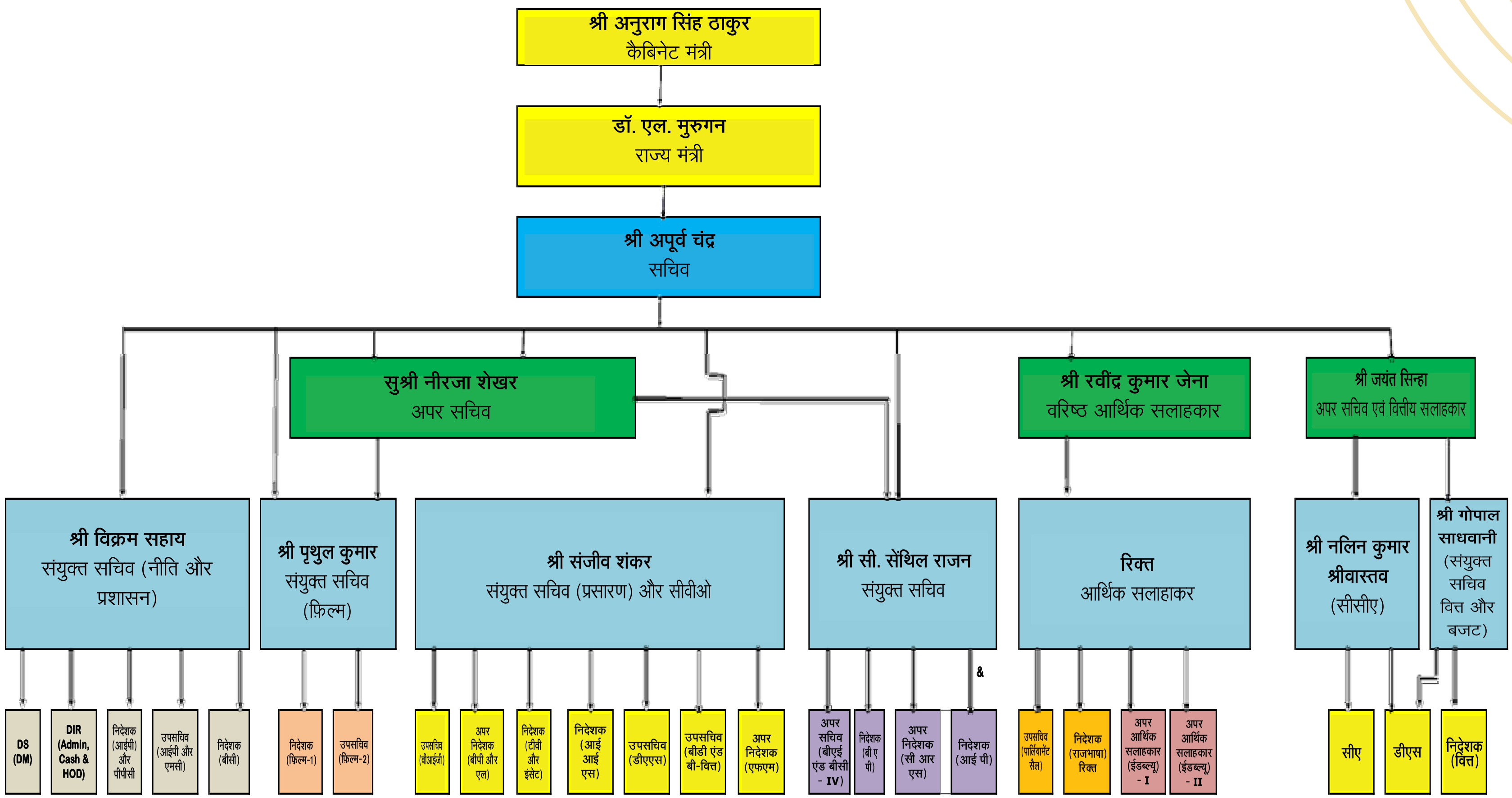

डीएम-डिजिटल मीडिया	एफएम - फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन
आईपी- सूचना नीति	बीएई एंड बीसी-IV - प्रसारण प्रशासन अभियांत्रिकी एंड प्रसारण सामग्री
पीपीसी - पॉलिसी प्लानिंग सैल	बीएपी - प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम
आईपी एंड एमसी - सूचना नीति और मीडिया समन्वय	सीआरएस - सामुदायिक रेडियो स्टेशन
वीआईजी- विजिलेंस	ओएल - राजभाषा
बीपी एंड एल - प्रसारण नीति और विधान	पार्लियामेंट - संसद
टीवी (इंसेट) - भारतीय सेटेलाईट टेलीविज़न	ईडब्ल्यू - वित्त विंग
आईआईएस - भारतीय सूचना सेवा	बीएंडए - बजट एवं लेखा
डीएएस - डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम	#प्रसार भारती और समुदायिक रेडिया स्टेशन से संबंधित मामले
बी(डी) एंड बी (वित्त) - प्रसारण विकास और बोर्ड	मीडिया युनिट सैल 1 एंड 2 से संबंधित मामले
बीसी- प्रसारण समग्री	@इफ्फी से संबंधित मामले

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पदनाम (2022-23)

सचिव	सचिव
एएस	अपर सचिव
एएस एंड एफए	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
एस ईए	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार (आर्थिक विंग)
जेएस (पी एंड ए)	संयुक्त सचिव (नीति और प्रशासन)
जेएस (बी)	संयुक्त सचिव (प्रसारण)
जेएस (एफ)	संयुक्त सचिव (फ़िल्म)
जेएस (ईडब्ल्यू)	संयुक्त सचिव (आर्थिक विंग)
आर्थिक सलाहकार	आर्थिक सलाहकार
सीसीए	मुख्य लेखा नियंत्रक
ओएसडी (सी एंड पीपीसी एंड आईपी एंड एमसी)	विशेष कार्य अधिकारी (समन्वय, नीति नियोजन प्रकोष्ठ, सूचना नीति और मीडिया समन्वय)
निदेशक (फ़िल्म-I)	निदेशक (फ़िल्म-I)
निदेशक (आईपी)	निदेशक (सूचना नीति)
निदेशक (बीसी)	निदेशक (प्रसारण सामग्री)
निदेशक/निदेशक (ओएल)	निदेशक/निदेशक (राजभाषा)
निदेशक (बीपीएंडएल)	निदेशक (प्रसारण नीति और विधान)
निदेशक (बीएपी)	निदेशक (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम)
उप सचिव (फिन.)	उप सचिव (वित्त)
उप सचिव (फ़िल्म)-II	उप सचिव (फ़िल्म-II)
डीएस (बी एंड ए)	उप सचिव (बजट और लेखा)
डीएस (कैश, एडमिन एंड एचओडी)	उप सचिव (नकद, प्रशासन और विभागाध्यक्ष)
डीएस (डीएएस)	उप सचिव (डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम)
डीएस (ईडब्ल्यू)	उप सचिव (आर्थिक विंग)
डीएस (विज. एंड पार्ल.)	उप सचिव (सतर्कता और पार्लियामेंट)
डीएस (बीएई एंड बीसी-IV)	उप सचिव (प्रसारण प्रशासन इंजीनियरिंग और प्रसारण सामग्री-IV)
अपर निदेशक (एफएम)	अपर निदेशक (फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन)
सीए	लेखा नियंत्रक
यूएस (एडमिन. I, II, III, IV एंड एचओओ)	अवर सचिव (प्रशासन I, II, III एवं कार्यालय का प्रमुख)
यूएस (आईआईएस)	अवर सचिव (भारतीय सूचना सेवा)
यूएस (एमयूसी-I)	अवर सचिव (मीडिया यूनिट समन्वय-I)
यूएस (एमयूसी-II)	अवर सचिव (मीडिया यूनिट समन्वय-II)
यूएस (प्रेस)	अवर सचिव (प्रेस)
यूएस (विजिलेंस)	अवर सचिव (विजिलेंस)
यूएस (कैश एंड पार्ल.)	अवर सचिव (कैश और पार्लियामेंट)
यूएस (एनएमसी एंड एनएमडब्ल्यू)	अवर सचिव (न्यू मीडिया सेल और न्यू मीडिया विंग)

यूएस (पीपीसी एंड आईपीएंडएमसी)	अवर सचिव (नीति नियोजन प्रकोष्ठ, सूचना नीति एवं मीडिया समन्वय)
यूएस (बीसी-I, II एंड III)	अवर सचिव (प्रसारण सामग्री-I, II और III)
यूएस (इनसेट-TV)	अवर सचिव (भारतीय उपग्रह टेलीविजन)
यूएस (डीएएस)	अवर सचिव (डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम)
यूएस (बीपी एंड एल)	अवर सचिव (प्रसारण नीति और कानून)
यूएस (बीडी एंड बी फिन.)	अवर सचिव (प्रसारण विकास और प्रसारण वित्त)
यूएस (बीएपी-I)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम-I)
यूएस (बीएपी-II)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम-II)
यूएस (बीए-ई)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन इंजीनियरिंग)
यूएस (बीएस-IV)	अवर सचिव (प्रसारण सामग्री-IV)
यूएस (एफ-I एंड III)	अवर सचिव (वित्त-I और वित्त-III)
यूएस (फिन-II)	अवर सचिव (वित्त-II)
यूएस (बी एंड ए)	अवर सचिव (बजट और लेखा)
यूएस (ईडब्ल्यू)	अवर सचिव (आर्थिक विंग)
यूएस (एफ (सी), एफ (एफ), एंड एफ (आई))	अवर सचिव (फ़िल्म प्रमाणन, फ़िल्म समारोह और फ़िल्म उद्योग)
यूएस (एफ (ए), एफ (एफटीआई) और एफ (पीएसयू))	अवर सचिव (फ़िल्म प्रशासन, फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान और फ़िल्म सार्वजनिक वित्त उपक्रम)
डीडी (ओएल)	उप निदेशक (राजभाषा)
डीडी (सीआरएस)	उप निदेशक (सामुदायिक रेडियो स्टेशन)
डीसीए	उप लेखा नियंत्रक
एडी (ओएल-1)	सहायक निदेशक (राजभाषा-1)
एडी (ओएल-2)	सहायक निदेशक (राजभाषा-2)
एस.ओ. (एडमिन-I)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-I)
एस.ओ. (एडमिन-II)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-II)
एस.ओ. (एडमिन-III)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-III)
एस.ओ. (एडमिन-IV)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-IV)
एस.ओ. (कैश)	अनुभाग अधिकारी (कैश)
एस.ओ. (संसद प्रकोष्ठ)	अनुभाग अधिकारी (संसद प्रकोष्ठ)
एस.ओ. (एमयूसी-I)	अनुभाग अधिकारी (मीडिया इकाई सेल-I)
एस.ओ. (एमयूसी-II)	अनुभाग अधिकारी (मीडिया इकाई सेल-II)
एस.ओ. (विजिलेंस-I एंड II)	अनुभाग अधिकारी (विजिलेंस-I) अनुभाग अधिकारी (विजिलेंस-II)
एस.ओ. (आईपी एंडएमसी)	अनुभाग अधिकारी (सूचना नीति और मीडिया समन्वय)
एस.ओ. (पीपी सेल)	अनुभाग अधिकारी (नीति योजना प्रकोष्ठ)
एस.ओ. (प्रेस)	अनुभाग अधिकारी (प्रेस)
एस.ओ. (आईआईएस-I)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय सूचना सेवा)-I
एस.ओ. (आईआईएस-II)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय सूचना सेवा)-II

एस.ओ. (एफ (एफ))	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म समारोह)
एस.ओ. (एफ (एफटीआई))	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म (फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान))
एस.ओ. (एफ (ए) डेस्क)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म (प्रशासन))
एस.ओ. (एफ (सी) डेस्क)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म (प्रमाणन))
एस.ओ. (एफ(आई) डेस्क)	अनुभाग अधिकारी फ़िल्म (उद्योग) डेस्क)
एस.ओ. (एफ (पीएसयू) डेस्क)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) डेस्क)
एस.ओ. (बीसी-I)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री-I)
एस.ओ. (बीसी-II)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री-II)
एस.ओ. (बीसी-III)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री-III)
एस.ओ. (बीसी-IV)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री-IV)
एस.ओ. (बी (डी))	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण (विकास))
एस.ओ. (बी (फिन))	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण (वित्त))
एस.ओ. (बीपी एंड एल)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण नीति और विधान-I) अनुभाग अधिकारी (प्रसारण नीति और विधान)
एस.ओ. (बीए-पी)-I	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण प्रशासन- कार्यक्रम-I)
एस.ओ. (बीए-पी)-II	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण प्रशासन- कार्यक्रम-II)
एस.ओ. (बीएई-I)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण प्रशासन अभियांत्रिकी-I)
एस.ओ. (बीएई-II)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण प्रशासन अभियांत्रिकी-II)
एस.ओ. (एफएम सेल)	अनुभाग अधिकारी (फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन सेल)
एस.ओ. (सीआरएस सेल)	अनुभाग अधिकारी (सामुदायिक रेडियो स्टेशन सेल)
एस.ओ. (इनसेट-टीवी I एंड II)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय उपग्रह टेलीविजन)-I अनुभाग अधिकारी (भारतीय उपग्रह टेलीविजन)-II
एस.ओ. (फिन-I एंड III)	अनुभाग अधिकारी (वित्त I और III)
एस.ओ. (फिन-II)	अनुभाग अधिकारी (वित्त II)
एस.ओ. (पीसी सेल)	अनुभाग अधिकारी (योजना समन्वय प्रकोष्ठ)
एस.ओ. (बी एंड ए)	अनुभाग अधिकारी (बजट और लेखा)
एस.ओ. (पीएमएस)	अनुभाग अधिकारी (प्रदर्शन प्रबंधन अनुभाग)
एस.ओ. (एनएमसी और एनएमडब्ल्यू)	अनुभाग अधिकारी (न्यू मीडिया सेल और न्यू मीडिया विंग)
एस.ओ. (आरटीआई सेल)	अनुभाग अधिकारी (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
एस.ओ. (सीपीजीआरएएमएस)	अनुभाग अधिकारी (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली)
पीएंडएओ	वेतन और लेखा अधिकारी
एस.ओ. (आरटीआई सेल)	अनुभाग अधिकारी (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
एस.ओ. (सीपीजीआरएएमएस)	अनुभाग अधिकारी (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली)
पीएंडएओ	वेतन और लेखा अधिकारी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार